असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

03 अगस्त, 2020

षोडश विधान सभा — सोमवार, तिथि 03 अगस्त, 2020 ई०

षोडश सत्र — 12 श्रावण, 1942(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

(व्यवधान)

श्री महबूब आलम: महोदय, प्राकृतिक आपदा से राज्य में बहुत लोग मरे हैं, महोदय ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: महबूब जी, कृपया आप बैठ जाइये । आप बिना स्वागत भाषण के ही बोलना चाहते हैं, कृपया आप बैठ जाइये ।

प्रारंभिक संबोधन

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, षोडश विधान सभा के 16वें और अंतिम सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है । आज जिस परिस्थिति में हम मिल रहे हैं उसकी गंभीरता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इस सत्र का आयोजन यहाँ ज्ञान भवन में किया जा रहा है । लगभग 100 साल पहले 1920-21 में हमारा अपना मुख्य विधान मंडल भवन बना था एवं तब से लगातार सभा की बैठकें उसी के सभा-वेश्म में होती आ रही थी । आज पहली बार विधान सभा की बैठक सभा-वेश्म में न होकर सम्राट अशोक कंवेन्शनल केन्द्र के इस ज्ञान भवन सभागार में आहूत किया गया है । यह अपने आप में विशेष एवं असाधारण परिस्थिति का द्योतक है ।

आज बिहार के साथ पूरा देश एवं पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी के प्रकोप से त्रस्त है । विश्व भर के वैज्ञानिक एवं चिकित्सक अथक प्रयास के बावजूद कोरोना वायरस के संक्रमण का न तो इलाज खोज पाए हैं, और न ही इसके निरोध के टीके यानी वैक्सिन बनाने में अभी तक सफल हो पाए हैं । इस तरह यह संपूर्ण मानव जाति एवं विज्ञान के लिए चुनौती बना हुआ है ।

आपको स्मरण होगा कि पिछले फरवरी-मार्च के बजट सत्र को भी बीच में ही 16 मार्च, 2020 को इस महामारी के फैलते स्वरूप के कारण हमने स्थगित कर दिया था । आज स्थिति और भी गंभीर हो चुकी है । हमारे कई विधायक एवं मंत्री भी संक्रमित हुए हैं । हम सबों के लिए ऐसी परिस्थिति में चुनौतियाँ और भी बढ़ जाती हैं क्योंकि अपने को सुरक्षित रखते हुए हमें अपने दायित्वों का भी निर्वहन करना है । हमें पूरी उम्मीद एवं विश्वास है कि हम सभी मिल-जुलकर इस परिस्थिति का मुकाबला करने में सक्षम एवं सफल होंगे । यहाँ भी

इस ज्ञान भवन के भूतल पर ही कोरोना जाँच के लिए आज विशेष मेडिकल टीम मौजूद है । जो भी माननीय सदस्य चाहें तो अपनी जाँच करा सकते हैं । साथ ही, सरकार की तरफ से मास्क एवं कोरोना के संबंध में करणीय एवं अकरणीय (डूज एवं डोन्ट्स) की एक छोटी पुस्तिका भी है, जो आप जाते समय अवश्य ले लेंगे ।

माननीय सदस्यगण, वैसे तो यह सत्र 4 दिनों के लिए निर्धारित है जिसमें सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों तरह के कार्यों का निष्पादन होना है परन्तु परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए बीते शुक्रवार यानी 31 जुलाई, 2020 को दलीय नेताओं की बैठक में कुछ निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं, जिन्हें अभी सदन में आपके समक्ष रखा जाएगा । साथ ही, एक और सूचना देनी है कि विशेष परिस्थिति होने के कारण हम लोग आज भोजनावकाश का अन्तराल भी नहीं करेंगे और सारी कार्यवाही लगातार जारी रहेगी ।

मैं आशा करता हूँ कि सदन संचालन में आप सब माननीय सदस्यों का पूर्ण सहयोग पूर्व की भाँति ही प्राप्त होगा ।

<u>अध्यासी सदस्यों का मनोनयन</u>

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-12 (1) के अधीन मैं निम्न सदस्यों को षोडश बिहार विधान सभा के षोडश सत्र के लिए अध्यासी सदस्य मनोनीत करता हूं :-

1- श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह - स०वि०स०
2- श्री मोहम्मद नेमतुल्लाह- स०वि०स०
3- श्री रामचन्द्र सहनी- स०वि०स०
4- श्री रामदेव राय- स०वि०स०
5- श्रीमती प्रेमा चौधरी- स०वि०स०

<u>समितियों का गठन</u>

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-219 (1) के अधीन मैं षोडश बिहार विधान सभा के षोडश सत्र के लिए कार्य-मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार करता हूं:-

1- अध्यक्ष,	बिहार विधान सभा	सभापति
2- श्री नीतीश कुमार,	मुख्यमंत्री	सदस्य
3- श्री सुशील कुमार मोदी,	उप मुख्यमंत्री	सदस्य
4- श्री श्रवण कुमार,	मंत्री, संसदीय कार्य	सदस्य
5- श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,	मंत्री, ऊर्जा	सदस्य
6- श्री प्रेम कुमार,	मंत्री, कृषि	सदस्य

7- श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता, विरोधी दल सदस्य

8- श्री सदानन्द सिंह, स०वि०स० सदस्य

विशेष आमंत्रित सदस्य

1- श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी - स०वि०स०

2- श्री महबूब आलम - स०वि०स०

3- श्री राजू तिवारी - स०वि०स०

नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान के अनुच्छेद-213 के खंड (2) (क) के अनुसार महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित निम्न अध्यादेशों की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखता हूं:-

(1) बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2020

(2) बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020

(3) बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020

(4) बिहार कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020

(5) बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) अध्यादेश,2020

(6) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2020

(7) बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2020

(8) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (बिहार संशोधन) अध्यादेश, 2020

(9) औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) अध्यादेश, 2020

(10) कारखाना (बिहार संशोधन) अध्यादेश, 2020

अध्यक्ष: सभा सचिव ।

सभा सचिव: महोदय, षोडश बिहार विधान सभा के पंचदश सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित निम्न 03 (तीन) विधेयकों का विवरण सदन पटल पर रखता हूं जिस पर महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अनुमति प्रदान की गयी है:-

क्रमांक	विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि
1.	बिहार विनियोग विधेयक, 2020	05.03.2020

2.	बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2020	08.03.2020
3.	बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2020	19.03.2020

टर्न-2/सत्येन्द्र-यानपति-धिरेन्द्र/03-08-2020/

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' 1-दिनांक 04, 05 एवं 06 अगस्त, 2020 के लिए निर्धारित बैठकें नहीं हों ।

2-मंगलवार, दिनांक 04 अगस्त, 2020 के लिए निर्धारित राजकीय विधेयकों का व्यवस्थापन आज ही इस प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत हो । तत्पश्चात् बुधवार, दिनांक 05 अगस्त, 2020 के लिए निर्धारित वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांगों का निष्पादन हो एवं संबंधित विनियोग विधेयक का व्यवस्थापन हो ।

3-दिनांक 04, 05 एवं 06 अगस्त, 2020 के लिए सभी स्वीकृत प्रश्नों एवं ध्यानाकर्षण को संबंधित विभागों को इस निर्देश के साथ भेजा जाय कि इसका उत्तर 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से सभा सचिवालय को उपलब्ध करवा दिये जायें ।

4- दिनांक 06 अगस्त, 2020 के लिए सभी स्वीकृत गैर सरकारी संकल्पों को समीक्षार्थ बिहार विधान-सभा की गैर सरकारी विधेयक एवं संकल्प समिति को सौंप दिये जायें ।

5- आज ही वित्तीय कार्य के व्यवस्थापन के उपरांत राज्य में कोरोना एवं बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर दो घंटे का विमर्श हो ।''

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्रश्न यह है कि

''1-दिनांक 04, 05 एवं 06 अगस्त, 2020 के लिए निर्धारित बैठकें नहीं हों ।

2-मंगलवार, दिनांक 04 अगस्त, 2020 के लिए निर्धारित राजकीय विधेयकों का व्यवस्थापन आज ही इस प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत हो । तत्पश्चात् बुधवार, दिनांक 05 अगस्त, 2020 के लिए निर्धारित वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांगों का निष्पादन हो एवं संबंधित विनियोग विधेयक का व्यवस्थापन हो ।

3-दिनांक 04, 05 एवं 06 अगस्त, 2020 के लिए सभी स्वीकृत प्रश्नों एवं ध्यानाकर्षण को संबंधित विभागों को इस निर्देश के साथ भेजा जाय कि इसका उत्तर 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से सभा सचिवालय को उपलब्ध करवा दिये जायें ।

4- दिनांक 06 अगस्त, 2020 के लिए सभी स्वीकृत गैर सरकारी संकल्पों को समीक्षार्थ बिहार विधान-सभा की गैर सरकारी विधेयक एवं संकल्प समिति को सौंप दिये जायें ।

5- आज ही वित्तीय कार्य के व्यवस्थापन के उपरांत राज्य में कोरोना एवं बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर दो घंटे का विमर्श हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

औपचारिक कार्य

अध्यक्षः प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उपमुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद-205 के अनुसरण में बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम 2020 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावे वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो खर्च होने की संभावना है उसके संबंध में, मैं प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्षः प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उपमुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के परिणाम बजट की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्षः प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उपमुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के उपलब्धि प्रतिवेदन की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्षः प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नंद किशोर प्रसाद, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(ए) (2) के तहत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्षः माननीय सभापति, लोक लेखा समिति ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 239 के तहत लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या

695,696,698,699,700,701,702,703 एवं 705 की एक एक प्रति को सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्षः माननीय सभापति, शून्यकाल समिति ।

श्री रामप्रीत पासवानः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत शून्यकाल समिति का 93वां एवं 94 वाँ प्रतिवेदन की एक एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्षः माननीय सभापति, याचिका समिति ।

श्री फैयाज अहमदः अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211(1) के तहत षोडश बिहार विधान-सभा की याचिका समिति का प्रतिवेदन संख्या 17,18,19,20,21,22 एवं 23 की एक एक प्रति को सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्षः माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति ।

श्री श्याम बहादुर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत राजकीय आश्वासन समिति का वित्त विभाग से संबंधित 271वाँ प्रतिवेदन पथ निर्माण विभाग से संबंधित 281 वाँ प्रतिवेदन, लघु जल संसाधन विभाग से संबंधित 282वाँ प्रतिवेदन, नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित 283वाँ प्रतिवेदन, जल संसाधन विभाग से संबंधित 286 वाँ प्रतिवेदन तथा शिक्षा विभाग से संबंधित 285वाँ एवं 287वाँ प्रतिवेदन की एक एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्षः माननीय सभापति, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति ।

श्री सुबोध रायः अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति का प्रथम प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्षः माननीय सभापति, अल्पसंख्यक कल्याण समिति ।

श्री मुजाहिद आलमः अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत अल्पसंख्यक कल्याण समिति का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं गृह विभाग से संबंधित प्रथम प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

टर्न-3/मधुप-अभिनीत/03.8.2020

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब विधायी कार्य ।

विधायी कार्य

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2020

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार करते हुए इसके सभी तीन खंडों को प्रस्तावना एवं नाम सहित विधेयक का अंग बनाया जाए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार करते हुए इसके सभी तीन खंडों को प्रस्तावना एवं नाम सहित विधेयक का अंग बनाया जाए ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक के सभी तीनों खंड, प्रस्तावना तथा नाम इस विधेयक के अंग बने ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2020 स्वीकृत हो ।''

महोदय, मुख्य रूप से बिहार पहला राज्य है जिसने लोक शिकायत अधिकार अधिनियम का निर्णय लिया । चूंकि गरीब-गुरबा लोगों को राशन-कार्ड या अनाज मिलने की शिकायत होती थी, उसके लिए उनको परेशानी होती थी । इस संशोधन के द्वारा इसी को इसमें सम्मिलित किया गया है और बाकी यह मेरा भाषण रेकॉर्ड के लिए मैं प्रस्तुत करता हूँ ।

अत: मेरा आग्रह है कि इसे पारित किया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी जो अपना लिखित वक्तव्य सदन पटल पर रखेंगे वह कार्यवाही का हिस्सा बनेगा ।

(माननीय मंत्री का लिखित वक्तव्य)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : राज्य के लोगों को समय पर लोक सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 लागू है । इस अधिनियम के अंतर्गत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की राशन कार्ड से संबंधित विभिन्न सेवाएं भी शामिल हैं । बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम में अधिसूचित सेवाओं के रूप में शामिल रहने के कारण इससे संबंधित मामलों पर बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के अंतर्गत सुनवाई नहीं हो पाती थी । राशन कार्ड से संबंधित विषय आम लोगों से सीधे जुड़े रहने के कारण काफी संवेदनशील है और इनसे संबंधित कोई फायदा या अनुतोष प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदन पर या ऐसा अनुतोष प्रदान करने में विफलता या विलम्ब की स्थिति में इसकी सुनवाई कर उसका निराकरण कराने के लिए प्रभावकारी फोरम का होना आवश्यक समझा गया । इसके लिये तुरंत कार्रवाई की गई तथा बिहार राज्य विधान मंडल के सत्र में नहीं रहने के कारण बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 में संशोधन करने के लिए बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2020 प्रख्यापित कर बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अधीन राशन कार्ड से संबंधित मामलों को भी लाया गया । इससे लोगों को राशन कार्ड से संबंधित शिकायतों की सुनवाई एवं निराकरण का एक सशक्त विकल्प प्राप्त हुआ है । इस अध्यादेश को अधिनियमित किये जाने हेतु ''बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2020'' को पुर:स्थापित और पारित करने हेतु बिहार विधान मंडल में उपस्थापित किया जा रहा है ।

बिहार सरकार द्वारा दिनांक- 5 जून, 2016 को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को लागू किया गया है । इससे नागरिकों को उनकी शिकायतों की सुनवाई एवं निवारण का वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ है । ऐसा

अधिकार प्रदान करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है । सभी अनुमंडलों, जिलों एवं राज्य मुख्यालय के सभी विभागों में लोक शिकायत निवारण कार्यालय स्थापित किए गए हैं जहाँ परिवाद पर सुनवाई की जाती है । यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शिकायतों की सुनवाई निरपेक्ष और समर्पित प्राधिकार के द्वारा की जाती है तथा शिकायतकर्ता एवं उस शिकायत का निराकरण करने वाले पदाधिकारी को आमने-सामने बैठाकर और बराबरी का दर्जा देकर शिकायत का निराकरण कराया जाता है । इससे परिवादी एवं लोक प्राधिकार के बीच शक्ति समरूपता स्थापित हुई है । यह अपने आप में जागरूकता, सामाजिक चेतना तथा बदलाव का कारक बना है और आम जनता में इससे संतोष का भाव उत्पन्न हुआ है । जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है । यद्यपि यह कानून पूरी आबादी को लाभान्वित करता है, मगर यह समाज के गरीब और अभिवंचित वर्गों के लिए बहुत मददगार साबित हुआ है । इस अधिनियम के क्रियान्वयन को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है । बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिनांक-31.07.2020 तक 7,72,093 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें 6,96,745 का सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया है और शेष का निष्पादन प्रक्रियाधीन है । परिवाद निवारण में रूचि नहीं लेने वाले 589 लोक प्राधिकारों पर 14.63 लाख रुपए की शास्ति अधिरोपित की गयी है जबकि 325 लोक सेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा रही है ।

(माननीय मंत्री का लिखित वक्तव्य समाप्त)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2020 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2020 स्वीकृत हुआ ।

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार करते हुए इसके सभी तीन खंडों को प्रस्तावना एवं नाम सहित विधेयक का अंग बनाया जाए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार करते हुए इसके सभी तीन खंडों को प्रस्तावना एवं नाम सहित विधेयक का अंग बनाया जाए ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक के सभी तीन खंड, प्रस्तावना तथा नाम इस विधेयक का अंग बने ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 स्वीकृत हुआ ।

बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020'' को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020'' को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार करते हुए इसके सभी पंद्रह खंडों को प्रस्तावना एवं नाम सहित विधेयक का अंग बनाया जाए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार करते हुए इसके सभी पंद्रह खंडों को प्रस्तावना एवं नाम सहित विधेयक का अंग बनाया जाए ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक के सभी पंद्रह खंड, प्रस्तावना तथा नाम इस विधेयक के अंग बने ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020'' स्वीकृत हो।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020'' स्वीकृत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 स्वीकृत हुआ ।

टर्न-4/आजाद-अंजली/03.08.2020

बिहार कराधान विधि (संशोधन) विधेयक,2020

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार कराधान विधि (संशोधन) विधेयक,2020 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कराधान विधि (संशोधन) विधेयक,2020 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' बिहार कराधान विधि (संशोधन) विधेयक,2020 पर विचार करते हुए इसके तीनों खंडों को प्रस्तावना एवं नाम सहित विधेयक का अंग बनाया जाय । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

'' बिहार कराधान विधि (संशोधन) विधेयक,2020 पर विचार करते हुए इसके तीनों खंडों को प्रस्तावना एवं नाम सहित विधेयक का अंग बनाया जाय । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक के तीनों खंड, प्रस्तावना तथा नाम इस विधेयक के अंग बने ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' बिहार कराधान विधि (संशोधन) विधेयक,2020 स्वीकृत हो । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

'' बिहार कराधान विधि (संशोधन) विधेयक,2020 स्वीकृत हो । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2020 स्वीकृत हुआ ।

बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक,2020

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2020 पर विचार करते हुए इसके चारों खंडों को प्रस्तावना एवं नाम सहित विधेयक का अंग बनाया जाय । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2020 पर विचार करते हुए इसके चारों खंडों को प्रस्तावना एवं नाम सहित विधेयक का अंग बनाया जाय । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक के चारों खंड, प्रस्तावना तथा नाम सहित इस विधेयक का अंग बने।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2020 स्वीकृत हो । ''

महोदय, ये जो चार विधेयक हैं, इन चारों विधेयकों पर जो मेरा लिखित भाषण है, मैं इसे सदन की मेज पर उपस्थापित करता हूँ, इसे सदन की कार्यवाही का हिस्सा बना लिया जाय ।

(माननीय उप मुख्यमंत्री का लिखित वक्तव्य - परिशिष्ट-1 द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो अपना लिखित उत्तर सदन पटल पर इन विधेयकों के संबंध में रखा है, वे सभी कार्यवाही का हिस्सा बनेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2020 स्वीकृत हो । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक,2020 स्वीकृत हुआ ।

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन एवं विधिमान्यकरण)विधेयक,2020

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक,2020 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक,2020 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

पुर:स्थापित करने की अनमुति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020 पर विचार करते हुए इसके पाँचों खंडों को प्रस्तावना एवं नाम सहित विधेयक का अंग बनाया जाय । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020 पर विचार करते हुए इसके पाँचों खंडों को प्रस्तावना एवं नाम सहित विधेयक का अंग बनाया जाय । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक के पाँचों खंड, प्रस्तावना तथा नाम सहित इस विधेयक के अंग बने ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020 स्वीकृत हो । ''

महोदय, इसके जो तथ्य हैं और क्यों इसको लाया गया है, क्या इसका मतलब है, यह मैं लिखित सदन पटल पर रख देता हूँ ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी जो लिखित वक्तव्य सदन पटल पर रख रहे हैं, वह कार्यवाही का हिस्सा बनेगा ।

(माननीय मंत्री का लिखित वक्तव्य)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-73 के खंड (ड.) में 'अवर निरीक्षक' के पद से अन्यून पंक्ति का कोई पुलिस पदाधिकारी को बिना वारंट के किसी जगह, किसी समय रात या दिन प्रवेश कर निरीक्षण, तलाशी करने तथा किसी दस्तावेज नमूने, उपकरण, परिवहन, पशु, सामान, मादक द्रव्य, कच्चे माल या किसी अन्य संबंधित चीज का निरीक्षण, तलाशी लेने एवं अभिग्रहण करने की शक्ति प्रदान की गयी है । धारा-78 की उपधारा-(2) के अधीन पुलिस पदाधिकारी जो अवर निरीक्षक से अन्यून पंक्ति का हो को इस अधिनियम के अधीन किसी दंडनीय अपराध का अन्वेषण करने की शक्ति प्रदान की गई है ।

बिहार राज्य में पुलिस थाना और पुलिस चौकी की कुल संख्या 1259 है । बिहार राज्य में 17535 स्वीकृत अवर पुलिस निरीक्षक की संख्या के विरूद्ध 8669 पुलिस अवर निरीक्षक पुलिस कार्यरत हैं, जिनमें से केवल बिहार पुलिस के 4661 अनुसंधान इकाई में तथा शेष 4008 पुलिस अवर निरीक्षक विधि व्यवस्था में कार्यरत हैं ।

राज्य सरकार की मद्यनिषेध नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु की जा रही छापेमारी के दौरान प्राप्त अनुभवों एवं कार्यरत पुलिस बल को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि पुलिस अवर निरीक्षक से न्यून पंक्ति के सहायक अवर निरीक्षक को भी निरीक्षण, तलाशी करने, अभिग्रहण करने तथा दंडनीय अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति प्रदान की जाय ताकि किसी भी मामले में त्वरित कार्रवाई हेतु कार्यरत पुलिस बल का उपयोग किय जा सके ।

राज्य में मद्यनिषेध से संबंधित कांडों की अधिकता एवं पुलिस अवर निरीक्षकों की अपर्याप्त संख्या में उपलब्धता के कारण पुलिस सहायक अवर निरीक्षकों को उक्त कार्यों के लिए अधिकृत करने हेतु बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करना आवश्यक हो गया था । तदआलोक में मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 02.07.2020 को पारित बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या-04, 2020) अधिसूचित किया गया है ।

राज्य में लागू मद्यनिषेध नीति को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने हेतु बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-73 एवं 78 में संशोधन हेतु पारित बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या-04, 2020) को विधेयक के तौर पर सदन के समक्ष माननीय सदस्यों के विचारण एवं पारित करने हेतु उपस्थापित किया जा रहा है ।

(माननीय मंत्री का लिखित वक्तव्य समाप्त)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020 स्वीकृत हो । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक,2020 स्वीकृत हुआ ।

टर्न-5/शंभु-हेमन्त/03.08.20

बिहार लोक कार्य विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2020

अध्यक्षः प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्रीः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्षः प्रश्न यह है किः

''बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्रीः महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्षः यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

प्रभारी मंत्री ।

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्रीः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार करते हुए इसके दोनों खंडों को प्रस्तावना एवं नाम सहित विधेयक का अंग बनाया जाय ।''

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि :

''बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार करते हुए इसके दोनों खंडों को प्रस्तावना एवं नाम सहित विधेयक का अंग बनाया जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक के दोनों खंड, प्रस्तावना तथा नाम इस विधेयक के अंग बने ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्षः प्रभारी मंत्री ।

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्रीः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 स्वीकृत हो ।''

महोदय, बहुत छोटा सा संशोधन है, हमलोगों ने जो ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्य के कार्यकाल और उनको हटाने का जो नियम है उसको और ज्यादा पारदर्शी बनाया है, केवल इसी के लिए संशोधन है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

''बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 स्वीकृत हो,''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 स्वीकृत हुआ ।

<u>बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, 2020</u>

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

''बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री: महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष: यह पुर:स्थापित हुआ ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार करते हुए इसके दोनों खंडों को प्रस्तावना एवं नाम सहित विधेयक का अंग बनाया जाए ।''

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि :

''बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार करते हुए इसके दोनों खंडों को प्रस्तावना एवं नाम सहित विधेयक का अंग बनाया जाए ,''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक के दोनों खंड, प्रस्तावना तथा नाम इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष : अब स्वीकृति का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र : अरे घबराये हुए हैं ये कितना और करेंगे ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्षः प्रभारी मंत्री ।

श्री राम नारायण मंडल, मंत्रीः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन (संशोधन) विधेयक, 2020 स्वीकृत हो ।''

श्री भाई वीरेन्द्रः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो प्रस्ताव दे रहे हैं ।

अध्यक्षः इनको माइक दे दीजिए ।

श्री भाई वीरेन्द्रः सर, ये काम करे तब न इसको 5-6 बार दबाना पड़ता है ।

अध्यक्षः आप बोलने में मास्क हटा लीजिए न ।

श्री भाई वीरेन्द्रः हमारी आवाज तो पूरा सदन सुन रहा है । सर, कहने का मतलब है कि माननीय मंत्री जी जो भी प्रस्ताव ला रहे हैं उसको हम सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उसको विस्तार से बताना चाहिए कि क्या बिहार के लिए कर रहे हैं और क्या आम आवाम के लिए कर रहे हैं, केवल अपने आप समझ रहे हैं और हमलोग कुछ नहीं समझ रहे हैं, संशोधन की जानकारी भी हमलोगों को नहीं हुई ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि :

''बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, 2020 स्वीकृत हो ।''

माननीय मंत्री जी बोलेंगे क्या ? भाई वीरेन्द्र जी के आग्रह को माननीय मंत्री जी ने मान लिया है ।

श्री राम नारायण मंडल, मंत्रीः महोदय, बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम, 11/2010) की धारा-3 के तहत सक्षम प्राधिकार अर्थात संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की पूर्वानुमति से राज्य में कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजनों में सम्परिवर्तन फीस के साथ उपयोग किये जाने का

प्रावधान है। उक्त अधिनियम की धारा-4 के तहत कृषि भूमि के प्रत्येक दखलकार या स्वामी को सरकार के द्वारा समय-समय पर क्षेत्रों के लिए यथा अधिसूचित बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत गैर-कृषि प्रयोजन के लिए सम्परिवर्तन फीस भुगतान का प्रावधान किया गया है। तथापि, अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत सम्परिवर्तन फीस में छूट का प्रावधान है, जिसके तहत उद्योग विभाग, बिहार सरकार के द्वारा इस संबंध में यथा अधिसूचित उद्योग से जुड़े मामले, मुद्दे और नीति में सम्परिवर्तन अनुमान्य होगा, परन्तु इसमें सम्परिवर्तन फीस देय नहीं होगी । लेकिन, उद्योग विभाग, बिहार सरकार के स्तर से निर्गत बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2016 की कंडिका-6.22 में औद्योगिक इकाइयों के लिए सम्परिवर्तन फीस की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार औद्योगिक इकाइयां भूमि सम्परिवर्तन शुल्क स्वयं भुगतान कर उत्पादन में आने के बाद इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकती है । जबकि, उद्योग विभाग, बिहार सरकार के स्तर से निर्गत उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्रों के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की कंडिका-3.2.1 के अधीन उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र की इकाइयों के भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में छूट दिये जाने का प्रावधान है।

अतः राज्य में कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन फीस के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से निर्गत बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 तथा उद्योग विभाग के स्तर से निर्गत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 एवं उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्रों के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के एतद् संबंधी प्रावधानों में अन्तर्निहित विरोधाभास को दृष्टिगत रखते हुए इस विषय पर उद्योग विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) की धारा-7 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने का प्रस्ताव है । अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक भूमि का सम्परिवर्तन- उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित उद्योगों से संबंधित कृषि भूमि का गैर-कृषि भूमि में सम्परिवर्तन, समय-समय पर, सक्षम प्राधिकार की पूर्व अनुमति से स्वीकृत किया जा सकता है परन्तु, अपेक्षित फीस, जो भी हो, का भुगतान उद्योग विभाग की प्रचलित नीति के अनुरूप किया जायेगा ।

टर्न-6/ज्योति-पुलकित/03.08.2020

अध्यक्ष : अब तो स्पष्ट हो गया ।

श्री सदानंद सिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक बात की जानकारी माननीय मंत्री जी से लेनी थी कि यह कृषकों की कृषि भूमि के सम्परिवर्तन की बात है, अधिग्रहण की बात है और इन्होंने उद्योग विभाग की जो चर्चा की कि उद्योग विभाग के आलोक और निर्देशानुसार उसकी कीमत तय की गयी है, वह कीमत क्या है, कई गुणी हैं जैसे डा0 मनमोहन सिंह के कार्यकाल में चार गुणी हो गयी तो क्या उस स्वरुप में हमलोग कृषकों को मूल्य दे रहे हैं ?

अध्यक्ष : मूल्य के लिए जो कानून बना हुआ है उसी हिसाब से ना निर्धारित होंगे ।

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने सारी बात स्पष्ट कर दी है । सारी बात आपके सामने रख दी हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है और बाकी चीजों को भी स्पष्ट कर देंगे ।

श्री सदानंद सिंह : क्या स्पष्ट किया है ?

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

'' बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिर्वतन) (संशोधन) विधेयक, 2020 स्वीकृत हो । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, 2020 स्वीकृत हुआ ।

बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

'' बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार करते हुए इसके सभी छः खंडों को प्रस्तावना एवं नाम सहित विधेयक का अंग बनाया जाय ।''

श्री सदानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं पुरःस्थापित करता हूं वह नहीं कहना चाहिए । उनको कहना चाहिए कि मैं पुरःस्थापित करने का आग्रह करता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

'' बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार करते हुए इसके सभी छः खंडों को प्रस्तावना एवं नाम सहित विधेयक का अंग बनाया जाय।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक के सभी छः खंड प्रस्तावना तथा नाम सहित इस विधेयक के अंग बने ।

अब स्वीकृति का प्रस्ताव ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 स्वीकृत हो । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

'' बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 स्वीकृत हो । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 स्वीकृत हुआ ।

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन)(बिहार संशोधन) विधेयक, 2020

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

'' ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन)(बिहार संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

'' ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार करते हुए इसके चारों खंडों को प्रस्तावना एवं नाम सहित विधेयक का अंग बनाया जाए । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

'' ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार करते हुए इसके चारों खंडों को प्रस्तावना एवं नाम सहित विधेयक का अंग बनाया जाए । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक के चारों खंड प्रस्तावना तथा नाम सहित इस विधेयक के अंग बने ।

अब स्वीकृति का प्रस्ताव ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

'' ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020 स्वीकृत हो । ''

महोदय, 1972 के ठेका अधिनियम के अंतर्गत यह जो विधेयक आया है इसमें छोटे ठेकेदार जो बीस लेबर वाले ठेकेदार को लाईसेंस लेना पड़ता था वह अब 20 वाले ठेकेदार की जगह अब लाईसेंस लेने के लिए, अनुज्ञप्ति के लिए 50 श्रमिक जो रखेंगे उन्हें ही इस अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है इसलिए महोदय, यह जनोपयोगी विधेयक है इसलिए आग्रह है कि इसको स्वीकृत किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020 स्वीकृत हो । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

ठेका श्रम (विनियिमन और उत्सादन) (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020 स्वीकृत हुआ ।

टर्न-7/राजेश/मुकुल/3.8.20/

औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

''औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष: यह पुर:स्थापित हुआ ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

''औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार करते हुए इसके चारों खंडों को प्रस्तावना एवं नाम सहित विधेयक का अंग बनाया जाय ।''

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार करते हुए इसके चारों खंडों को प्रस्तावना एवं नाम सहित विधेयक का अंग बनाया जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक के चारों खंड, प्रस्तावना तथा नाम इस विधेयक के अंग बने ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

''औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020 स्वीकृत हो।''

अध्यक्ष महोदय, चूंकि कोविड-19 को लेकर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का जो यह नियम लाया गया है । चीन और अन्य देशों में जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं वे भारत में निवेश करना चाहती हैं । हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय की उद्योग के विकास की जो नीति है, उसके तहत ये जो बड़े उद्योगपतियों के लिए, ये जो छोटे उद्योग वाले थे, वह 100 मजदूर, 100 मजदूर के लिए उन्हें अनुज्ञप्ति की

जरूरत थी विवाद के लिए, जो फैक्ट्री बंद करेंगे, तो 100 मजदूर को अनुज्ञप्ति के आधार पर उन्हें परमिशन लेनी थी, अब 300 मजदूर वाली कम्पनी ही इस दायरे में आयेगी और बड़ी कम्पनी निवेश करने में इस अधिनियम से प्रभावित होगी । इसलिए महोदय, इसे स्वीकृत करने की कृपा करें ।

श्री भाई वीरेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, एक भी औद्योगिक घराने के लोग यहां नहीं आयें और 15 साल से ये लोग केवल भाषण दे रहे हैं कि औद्योगिक घराने के लोग यहां आना चाहते हैं, यहां उद्योग फैलाना चाहते हैं और यहां बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं।

अध्यक्ष: भाई वीरेन्द्र जी, उसी की व्यवस्था हो रही है, कृपया आप बैठ जाइये ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020 स्वीकृत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020 स्वीकृत हुआ ।

कारखाना (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

''कारखाना (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''कारखाना (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष: यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

''कारखाना (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार करते हुए इसके चारों खंडों को प्रस्तावना एवं नाम सहित विधेयक का अंग बनाया जाय।''

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''कारखाना (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार करते हुए इसके चारों खंडों को प्रस्तावना एवं नाम सहित विधेयक का अंग बनाया जाय।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक के चारों खंड, प्रस्तावना तथा नाम सहित इस विधेयक के अंग बने ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

''कारखाना (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020 स्वीकृत हो।''

अध्यक्ष महोदय, ये कारखाना अधिनियम जो है, इसमें 20 श्रमिकों का लाइसेंस लेना पड़ता था, तो अब 20 की जगह 40 श्रमिक रहने पर ही लाइसेंस की आवश्यकता है इसलिए महोदय, यह जनोपयोगी विधेयक है, इसे स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''कारखाना (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020 स्वीकृत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कारखाना (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020 स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

श्री भाई वीरेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, एक सूचना देना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र, मनेर में जो एलाइनमेंट पहले से था, उसको बदल दिया गया है । रिंग रोड जो पटना से मनेर होते हुए बिहटा और सरमेरा रोड में मिलना था उसको मनेर के पहले से ही मोड़ दिया गया है । मनेर सूफी-संतों की धरती है, तीन नदियों का संगम है और वह पर्यटक स्थल भी है और सरकार द्वारा हमेशा वहां पर सूफी महोत्सव भी मनाया जाता है ।

अध्यक्ष: भाई वीरेन्द्र जी, अभी माननीय मंत्री जी सप्लीमेंट्री पुट करेंगे और सप्लीमेंट्री का विनियोग भी होगा, उसमें हम आपको समय देंगे, उसमें आप अपनी बात को रख लीजियेगा ।

टर्न-8/सत्येन्द्र-यानपति-धिरेन्द्र/03-08-2020/

वित्तीय कार्य

अध्यक्षः माननीय मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विभिन्न विभागों के संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 के उपबंध के अतिरिक्त विभिन्न मांगों के अन्तर्गत कुल 227,77,32,09,000/-(दो सौ सताईस अरब सतहत्तर करोड़ बत्तीस लाख नौ हजार)रू0 से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''विभिन्न विभागों के संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 के उपबंध के अतिरिक्त विभिन्न मांगों के अन्तर्गत कुल 227,77,32,09,000/-(दो सौ सताईस अरब सतहत्तर करोड़ बत्तीस लाख नौ हजार)रू0 से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभी मांगें स्वीकृत हुईं ।

बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2020

अध्यक्षः प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्रीः मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

अध्यक्षः प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उपमुख्यमंत्री: मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष: यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उपमुख्यमंत्री: मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2020 पर विचार करते हुए इसके तीनों खंडों एवं अनुसूची को प्रस्तावना तथा नाम सहित विधेयक का अंग बनाया जाय ।''

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2020 पर विचार करते हुए इसके तीनों खंडों एवं अनुसूची को प्रस्तावना तथा नाम सहित विधेयक का अंग बनाया जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक के तीनों खंड, अनुसूची, प्रस्तावना तथा नाम इस विधेयक के अंग बने।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उपमुख्यमंत्री: मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2020 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष: आप बोलना चाह रहे थे वीरेन्द्र जी ।

श्री भाई वीरेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, चूंकि मनेर विधान सभा के हम एम0एल0ए0 हैं और मनेर सूफी-संतों की धरती रही है पर्यटक स्थल भी है और तीन नदियों का संगम है, तट पर बसा है मनेर और वहां सूफी महोत्सव सरकार के द्वारा हर साल मनाया जाता है और रिंग रोड पहले प्रस्तावित था कि मनेर होकर बिहटा सरमेरा रोड में मिलेगा लेकिन उस प्रस्ताव को कैंसिल करके और शेरपुर से ही उसको मोड़ दिया गया है मनेर की जनता काफी उनसे दुखित है और मैं आग्रह करूंगा आसन से माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं और माननीय मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं हमने इनलोगों को पत्र भी दिया है और विरोध भी जाहिर किया है और मैंने मांग की है कि जो प्रस्ताव पहले थे रिंग रोड का मनेर होते हुए, बिहटा होते हुए सरमेरा में मिलाना उसका प्रस्ताव आज वो लाएं और निश्चित रूप से आश्वासन दें कि हम इसको करने का काम करेंगे । चूंकि मनेर सूफी-संतों की धरती है वहां तीन नदियों का संगम है, पर्यटक स्थल है । वहां आज भी रोज पर्यटक आते हैं और वहां के लोगों के साथ अगर अन्याय होता है तो यह आसन से मैं आग्रह करूंगा कि सरकार को निर्देशित करें ।

अध्यक्ष: और कोई माननीय सदस्य ? संक्षिप्त में ।

श्री आलोक कुमार मेहता: समस्तीपुर जिला जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती रही है और वहां कृषि और कृषि आधारित उद्योगों की भारी संभावना है, कृषि कार्य में लोग लगे हुए हैं जरूर, उसी के मद्देनजर पिछले तीन वर्ष पहले आई0सी0डी0पी0 योजना के तहत लगभग साढ़े तीन सौ करोड़ रुपए की मंजूर दी गई थी कि वो समस्तीपुर जिला के अंदर सभी पंचायतों में पैक्स के माध्यम या दूसरे सहकारी संस्थाओं के माध्यम से छोटे छोटे उद्योग लगाने की उसमें कार्रवाई की जाए। आई0सी0डी0पी0 योजना के तहत बहुत तरह की सुविधा थी उसमें बहुत ऋण जो था वह ब्याज रहित ऋण था और उसके बाद अनुदान भी था लेकिन ये क्या परिस्थिति बनी कि पिछले तीन वर्षों के अंदर अभी तक उस पैसे का डिस्बर्सल नहीं हुआ और उस जिला में एक पैसा नहीं गया बल्कि चंद दिनों करीब दो तीन महीना पहले, चार महीना पहले हमें ये पता चला कि विभागीय प्रधान सचिव ने उसमें रोक लगाने की कोई नोटिस दे दी । मैंने माननीय मंत्री जी से भी बात की, माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि नहीं नहीं वह पैसा जाएगा और आजतक वह पैसा मात्र पांच साल के लिए उसको खर्च करना होता है, आज तीन वर्ष बीत गए लेकिन आजतक वह पैसा नहीं गया इसलिए हमारा अनुरोध है माननीय सदन, माननीय अध्यक्ष जी और अध्यक्ष जी के संरक्षण में माननीय विभागीय मंत्री से और विभाग से कि तत्काल उस पैसे का डिस्बर्सल कर के जिला में भेजा जाए ताकि वहां पर वहां की जागरूक जनता जो सहकारिता से जुड़ी हुई है वह हर पंचायत में किसी न किसी तरह का उद्योग लगाकर आज की इस विकट परिस्थिति में रोजगार का सृजन कर सके और कृषि आधारित उद्योग या अन्य उद्योगों के माध्यम से जिला के विकास में अपना योगदान दे सके । धन्यवाद महोदय ।

अध्यक्ष: और कोई माननीय सदस्य।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष: अच्छा पहले महबूब आलम जी को बोल लेने दीजिए ललित जी ।

श्री महबूब आलम: महोदय, अभी एस0टी0ई0टी0 के तहत लड़कों की जो परीक्षा ली गयी है, उसमें प्रश्न पत्र लीक होने की जो बात कही गयी थी उसके अध्यक्ष जो आनंद किशोर जी हैं उन्होंने क्लीयर कहा है कि किसी किस्म का कदाचार या किसी किस्म का परीक्षा पत्र लीक नहीं हुआ है तो उस परीक्षा का रिजल्ट महोदय 15 मई को दिया जाना था लेकिन 16 मई को पूरी परीक्षा बिहार की रद्द कर दी गयी है

टर्न-9/मधुप-अभिनीत/03.8.2020

...क्रमशः...

श्री महबूब आलम : महोदय, मैं माँग करता हूँ कि परीक्षा का रिजल्ट दिया जाय ।

साथ-ही-साथ, बलरामपुर में पिछले बाढ़ में 6963 प्रभावित लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है । पिछले विधान सभा सत्र में यह बात उठी थी और महोदय ने आग्रह किया था मंत्री जी को कि इसकी जाँच करके तमाम बाढ़ प्रभावित लोगों को इसका मुआवजा दिया जाय ।

अध्यक्ष : श्री ललित कुमार यादव जी ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, पूरा बिहार नहीं 14 जिला में कम से कम हमलोग बाढ़ इलाके से आते हैं, नेता प्रतिपक्ष हमलोगों की तरफ से अपनी बात को रखेंगे लेकिन हमलोग दरभंगा जिला से आते हैं, अभी बाढ़ की विभीषिका से बिहार के 14 जिला तो प्रभावित हैं लेकिन सबसे ज्यादा सरकारी आंकड़ा भी बता रहा है कि दरभंगा जिला बाढ़ से प्रभावित है । महोदय, नाव के सहारे से ही बहुत गाँव के लोग हाट-बाजार या एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं लेकिन मुख्य समस्या है, सरकार की जो नीति है, जो सरकार सड़क बनाती है, जगह-जगह सड़क पर 4 फीट, 5 फीट पानी चल रहा है । महोदय, लोग बाढ़ से त्रस्त हैं और सड़क में खामियाँ जो रह गई हैं, सरकार की नीति में जो खामी रह गई, अनेक जगह सड़क टूट गई है । हमलोगों के इलाके में बाढ़ भी सब साल नहीं आता है जिसके कारण लोग नाव भी नहीं रखते हैं । जब भी कमला नदी या कोसी नदी का पानी आता है तो नाव का सहारा लोग लेते हैं । अभी सड़क जगह-जगह पर टूट गई है, अभी रास्ता अवरूद्ध है, लोगों का हाट-बाजार तक जाना बंद है । सूखा राहत भी वहाँ बाढ़ प्रभावित इलाका में नहीं बाँटा गया है ।

(व्यवधान)

महोदय, दूसरी बात यह कि खाते में जो राशि हस्तांतरित की जा रही है, कब की सूची है, कौन सी सूची है, किस सूची के आधार पर बाँट रहे हैं, आधे से कम लोगों को राशि जा रही है ।

महोदय, हम सरकार से माँग करते हैं कि इतना संवेदनशील मामला है, लोग बाढ़ की विभीषिका से त्रस्त हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किये हैं.....

अध्यक्ष : ठीक है । नेता प्रतिपक्ष भी बोलने वाले हैं । श्री मो0 नेमतुल्लाह ।

श्री ललित कुमार यादव : वे बोलेंगे लेकिन हम बाढ़ प्रभावित इलाके से आते हैं, विशेषकर उत्तर बिहार के लोग अभी तक बाढ़ से निजात नहीं पाये हैं । हम माननीय मुख्यमंत्री जी से माँग करते हैं कि अंतिम समय है, अब तो ध्यान दीजिये ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी बाँध के पास एक स्कूल में गये थे, प्रोग्राम था बरौली प्रखंड हमारे गोपालगंज जिला में । ठीक उसी के सामने बाँध टूट गया । करोड़ों रूपया इनके प्रोग्राम में वहाँ खर्चा हुआ लेकिन उस बाँध पर इन लोगों की नजर नहीं पड़ी जिसकी वजह से पूरा बरौली, मांझा प्रखंड, बैकुंठपुर.....

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : पूरा पानी-पानी हो गया, लोग डूब गये । आज तक लोग त्राहिमाम कर रहे हैं । मैंने कार्यस्थगन प्रस्ताव भी दिया है ।

अध्यक्ष : श्री नीरज बबलू ।

श्री नीरज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर बात मैं रखने जा रहा हूँ, पूरा बिहार ही नहीं, पूरे देश की इज्जत का सवाल है । महोदय, आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों महाराष्ट्र में बिहार और देश के उभरते हुए कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की मुम्बई में निर्मम हत्या कर दी गई और उसे आत्महत्या करार दिया गया । महोदय, आये दिन लगातार देश से आवाज उठ रही है कि इस मामले को जाँच के लिए सी0बी0आई0 को सौंप दिया जाय, सी0बी0आई0 को सौंप दिया जाय ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : जरा सुन लीजिए, इम्पौर्टेन्ट चीज है जरा सुन लीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नेमतुल्लाह जी, आपने अपनी बात कह दी, जहाँ बाँध टूटा है उसकी भी सूचना दे दिये, सरकार जरूर देखेगी, उसकी कार्रवाई करेगी । अब दूसरे लोगों को भी तो बोलने दीजिए। अब आप बैठ जाइये । आपका नाम अभी इसी चेयर पर आने वालों की सूची में हम डाले हैं ।

श्री नीरज कुमार सिंह : महोदय, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले पर पूरा देश थमने का नाम नहीं ले रहा है, पूरे देश से सी0बी0आई0 जाँच की माँग उठ रही है और पिछले दिनों उनके पिता ने बिहार में एफ0आई0आर0 दर्ज कराया, उसको लेकर बिहार पुलिस महाराष्ट्र गई, महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ किस तरह मिसबिहेव किया, धक्का देकर उन्हें वैन में बैठाया गया और इतना ही नहीं, जब यहाँ के आई0पी0एस0 अधिकारी महाराष्ट्र गये हैं वहाँ जाँच करने के लिए तो आप देख रहे हैं पूरे टी0वी0 चैनल पर, पूरे देश में यह खबर चल रही है, उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया एक बड़ा बहाना बनाकर कि जाँच न हो, बिहार पुलिस इस केस की जाँच न करे, हत्या का मामला सामने नहीं आये, इसमें बड़े-बड़े लोग, हम समझते हैं कि

महाराष्ट्र सरकार के बड़े अधिकारी हों या बड़े नेता हों या सरकार से जुड़े लोग, कहीं न कहीं इसमें बुरी तरह इनवॉल्व हैं । पूरा देश, पूरा परिवार और हम भी उसी परिवार से हैं, तो सबलोग चाहते हैं, पूरे देश की भावना है आज के डेट में, पूरा देश उसके परिवार के साथ खड़ा है, पूरा देश उसके परिवार के साथ बना हुआ है ।

इसलिये हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार इस केस को हर हाल में सी0बी0आई0 को सौंपे ताकि इसकी निष्पक्ष जॉच होकर वास्तविकता सामने आ जाय, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाय ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, नीरज बबलू जी ने जिस बात को उठाया है, नीरज बबलू जी हमलोगों के कलिग हैं, सही कहा इन्होंने कि सुशांत सिंह राजपूत उभरते हुए सितारे थे । हालॉकि इनके भाई भी हैं और हमलोग चाहते हैं कि न्याय मिले, जस्टिस मिले । पूरा बिहार नहीं बल्कि पूरा हिन्दुस्तान जानना चाहता है कि मौत का कारण क्या है । राष्ट्रीय जनता दल पहली पार्टी है जिसने इस मामले में सी0बी0आई0 जॉच की मॉग की थी और हमलोग परिजनों से भी मुलाकात किये थे उनके पिताजी से, उनकी बहन से और हमलोगों का साफ था कि हमलोग उनके परिवार के साथ हैं ।

नीरज बबलू जी से हम इतना कहना चाहते हैं कि सुशील मोदी जी डिप्टी सी0एम0 हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, आप ही की डबल इंजन की सरकार है और पूरा देश जानना चाहता है कि क्या वजह है, इसकी निष्पक्ष जॉच हो तो सरकार इनकी है, ये लोग आखिर क्यों इतना विलम्ब कर रहे हैं ? आप विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जी से मिलकर बात कीजिये और हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा था कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर जो राजगीर में फिल्मसिटी बन रहा है उसका नामकरण किया जाय, हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी इसपर संज्ञान लेते हुए आज ही घोषणा कर दें कि नामकरण सुशांत सिंह राजपूत जी के नाम पर होगा ।

अध्यक्ष : श्री संजय सरावगी ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला में भीषण बाढ़ का प्रकोप है, भीषण बाढ़ वहॉ आती है और इस बार भी बहुत भीषण बाढ़ है । सरकार और प्रशासन की तत्परता से लगभग 2 लाख ग्रामीण परिवारों को 6-6 हजार रू0 की राशि चली गई लेकिन दरभंगा शहर का 20 वार्ड पूरा डूबा हुआ है, 10-12 फीट पानी कई वार्डों में घरों के उपर से क्रॉस कर रहा है लेकिन अभी तक दरभंगा शहर के किसी भी बाढ़ प्रभावित के खाते में पैसा नहीं जा रहा है जो कि दरभंगा नगर निगम की शिथिलता है ।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि स्पेशल व्यवस्था करके जल्द से जल्द दरभंगा शहर के भी लगभग 30 हजार ऐसे परिवार हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं और 10 दिन से कई वार्ड कम्पलीट डूबा हुआ है, निश्चित रूप से वहाँ भी सरकार का राहत कार्यक्रम चले, वहाँ भी लोगों को 6-6 हजार की राशि जाय । महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह और अनुरोध करना चाहता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सब आदमी का तो नहीं हो पायेगा न । अब सुदामा प्रसाद जी, आप बोलिये । एक-एक मिनट में अगर बोलिये तो हम अधिकतम आदमी को सामंजित कर लेंगे लेकिन जब शुरू करते हैं वे अगले आदमी की चिंता छोड़ देते हैं ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय.....

अध्यक्ष : माइक ऑन करिये न । माइक को क्यों पकड़े हुये हैं ? माइक छोड़कर बोलिये न ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, प्रशासन ने रघुपति गोप, पूर्व विधायक पीरो का और कॉमरेड रामनरेश राम जी का स्मारक सहार में बनाने के लिए उनका चरपोखरी में प्रस्ताव भेजा था, जमीन का अभिलेख भी भेजा था लेकिन मंत्रिमंडल सचिवालय ने माननीय पूर्व विधायक रघुपति गोप जी का स्मारक की तो वहाँ स्वीकृति दिया लेकिन रामनरेश जी का नहीं दिया । आपसे आग्रह है कि इसकी स्वीकृति दिलवा दी जाय । महोदय, जमीन उपलब्ध करायी गयी है ।

अध्यक्ष : श्री लाल बाबू राम । एक-एक मिनट में बोलिये ।

माइक ऑन करिये और जो नहीं बोल रहे हैं और उनके माइक में अगर लाल-बत्ती जल रही है तो कृपया उसको बंद कर दीजिए, नहीं तो दूसरे को बोलने में असुविधा होती है ।

टर्न-10/आजाद-अंजली-सुरज/03.08.2020/

श्री लाल बाबू राम : महोदय, सकरा विधान सभा क्षेत्र के मुरौल प्रखंड में बूढ़ी गंडक है । बूढ़ी गंडक कल प्रशासन द्वारा जबरन बांध काट करके सकरा में मुरौल प्रखंड को पानी में डुबाने का काम किया है । स्थानीय लोग जब इसका विरोध किया तो लाठी चार्ज किया गया है । महोदय, सकरा विधान सभा में दो ब्लॉक है सकरा और मुरौल । दोनों प्रखंड पहले से ही वर्षा के पानी से .....

अध्यक्ष : आप जो चाहते हैं, उसको आप जल्दी बोल लीजिए न क्योंकि दूसरे को भी बोलना है ।

श्री लाल बाबू राम : वहां पर बाढ़ आयी हुई है, वहां पर किसी भी बाढ़ पीड़ितों के समक्ष बाढ़ राहत सामग्री नहीं बांटा जा रहा है । वहां पर जो स्थिति है, पानी भर जाने के कारण सारी सड़क बन्द है, नाव की व्यवस्था नहीं है महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे ।

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, छपरा जिला के मांझी प्रखंड के लिए एक पावर सबस्टेशन स्वीकृत हुआ । उसकी अधिसूचना निकल गई । जमीन भी गैर-मजरूआ आम खोजी गयी और जमीन मिली नहीं । महोदय, सरकार जमीन खरीद करके भी पावर सबस्टेशन लगाती है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मांझी पावर सबस्टेशन के लिए जमीन खरीद करके स्वीकृत पावर सबस्टेशन को बनाया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र जी । एक-एक मिनट में ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, खासकर के मोतिहारी के संदर्भ में हम बतलाना चाहेंगे कि बाढ़ की विभीषिका आज वहां के लोगों को बेघर कर दिया है, पूरी फसल क्षतिग्रस्त हो गयी है । सरकार की तरफ से वहां पर कोई देखने नहीं गये, सरकार को जो काम करना चाहिए, वह नेता विरोधी दल जाकर के करने का काम किये और लोगों को जो राशन पहुँचानी चाहिए, वह दिये । महोदय, उसमें हम मुख्य रूप से यह बतलाना चाहेंगे कि वहां पर बाढ़ के दिनों में सर्प निकलने से कई लोगों की सर्पदंश से मृत्य हो गई है .....

अध्यक्ष : श्री राजेश जी ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, एक सूचना है .....

अध्यक्ष : आप सूचना दे नहीं रहे हैं , कहानी कहने में समय बीता रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, जरूरी सूचना है । वहां सिविल सर्जन का तबादला, जब रिटायर्ड करते हैं सिविल सर्जन तो उनकी जगह पर, ...

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइए । इसीलिए न कह रहे थे कि जब अपना समय मिलेगा तब दूसरे की चिन्ता भूल जाइयेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, सिविल सर्जन की जगह पर, महोदय, एक मिनट के लिए .....

अध्यक्ष : राजेश जी को बोलने दीजिए । सिर्फ राजेश जी, जो मांग चाहते हैं, वह कह दीजिए। स्थिति को पूरा चित्रित करने के लिये समय अभी उतना उपलब्ध नहीं है । इसलिए अब आप बैठ जाइए ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला के टंडवा थाना से सटे पश्चिमी सनसागर सोनारछाप के पास होलिया नदी पर प्रस्तावित पुल सरकार के यहां तीन साल से लंबित है और ग्रामीण कार्य विभाग .....

अध्यक्ष : जो चाहते हैं, वह मांग कीजिए न । चलिए श्री राहुल तिवारी ।

श्री राजेश कुमार : महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग इसको शीघ्र स्वीकृत करावे ।

श्री राहुल तिवारी : अध्यक्ष महोदय, हमारे शाहपुर विधान सभा क्षेत्र में एक गंभीर समस्या है, उसके बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ । मेरे यहां एक बांध है जो कोईलवर से बक्सर की तरफ जाती है । उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र के लालू डेरा पंचायत में वह 1980 के बाढ़ के बाद कम से कम 200 मीटर टूट गया है, कई दफा मैंने सदन में सवाल उठाया है, जिसके चलते सरकार के खजाने का, जनता का पैसा खर्च हो जाता है क्योंकि हरेक दो-तीन साल में 50 करोड़, 60 करोड़ सरकार का खर्च होता है, अगर उस बांध को बना दिया जाता है तो सरकार के खजाने पर बोझ भी नहीं बढ़ेगा और बांध की मरम्मत भी हो जायेगी।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी जी ।

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं हमलोगों के साथी माननीय सदस्य श्री नीरज बबलू जी ने जो बात उठायी है, उसको लोक जनशक्ति पार्टी जो बिहार के लाल हमलोगों के कलाकार सुशांत जी की मृत्यु पर सी0बी0आई0 जॉच की मांग करती है और हमारे नेता भी इस मांग को उठाये हैं ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र में बांध दो पार्ट में बंटा हुआ है । बांध के ऊधर बाढ़ आती है और इस बार बहुत ज्यादा बाढ़ आयी है, कहीं-कहीं तो बाढ़ ओवरफ्लो हुआ है, उसका वीडियो लेकर के अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करा दिया हूँ और भविष्य में सरकार के द्वारा आश्वासन मिला है कि हो जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है, माननीय सदस्य श्री कमरूल होदा जी ।

श्री कमरूल होदा : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गेराबाड़ी कृषि कॉलेज बना है, उसके बीचो-बीच एक ड्रेन गया हुआ है, उस ड्रेन को अभी कृषि प्रशासन ने बन्द कर दिया है और उससे हजारों एकड़ जमीन में पानी लगा हुआ है। अगर वहां पर ड्रेन को खोल दिया जाय, ड्रेन से पानी निकल करके सीधे महानन्दा में पानी जाती है । यदि ड्रेन को खोल दिया जाय, सुलिस गेट को खोल दिया जाय तो हजारों एकड़ जमीन में जो पानी लगा हुआ है, उससे बचाया जा सकता है.....

अध्यक्ष : ठीक है, माननीय सदस्य श्री रामविलास पासवान । कमरूल जी, अब आप बैठ जाइए। रामविलास पासवान जी, माईक ऑन कीजिए ।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, पीरपैंती विधान सभा क्षेत्र में रानी दियरा गांव जो है, वहां लाखों घर बेघर हो गया है । उसको पुनर्वासित करने के लिए पुनः आग्रह करना चाहता हूँ कि उन लोगों को अतिशीघ्र जमीन मुहैय्या कराकर के पुनर्वास कराने का आग्रह करता हूँ । मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि पीरपैंती में जो पावर प्लांट लगना

था और बिहार सरकार के द्वारा किसान की जो प्रोब्लम थी, छोटी-मोटी प्रोब्लम सौल्व करके वहां पर पावर सब-स्टेशन बन जाता । अभी रोजगार की बात हो रही थी महोदय, सभी को रोजगार मिलना चाहिए था .....

अध्यक्ष : अब रामविलास जी बैठ जाइए, माननीय सदस्य श्री विनोद प्रसाद यादव । अपना समय नहीं मिला था तो कितना परेशान थे, अब आप कितना को परेशान कर रहे हैं । अब आप बैठ जाइए । सिर्फ जो चाहते हैं, वह कह दीजिए । पूरे विस्तार से कहना शुरू कीजियेगा तो पूरा समय नहीं मिलेगा ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महादेय, मैं नीरज बबलू जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और सी0बी0आई0 जॉच की मांग का समर्थन करता हूँ ।

महोदय, मैं सूचना देना चाहता हूँ जो पैक्स अध्यक्ष हैं बिहार के, उनको 31 जुलाई तक चावल जमा करने के लिए सरकार से निर्देश प्राप्त हुआ था और ....

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, हमलोगों के नेता ने मांग कर दिया है सी0बी0आई0 जॉच के लिए, डबल इंजन की सरकार है, जॉच का आदेश दें .....

अध्यक्ष : आप तो बोलते ही रहते हैं, अभी आप कहां बोल रहे हैं ?

माननीय सदस्यगण, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए न । विनोद जी स्थान ग्रहण कीजिए न । मैं समझ सकता हूँ, छोटा सत्र है, अंतिम दिन है, आखिरी समय में हमलोग पहुँच रहे हैं, हमारे लगभग सभी माननीय सदस्यों को कुछ न कुछ कहना है । अभी हमलोग जो अनुपूरक व्यय विवरणी है, उसके संबंध में ही विचार कर रहे हैं । इसलिए आपलोग अभी भी देख रहे हैं, दो-तीन दर्जन लोग बोलने वाले हैं और, अभी तो सुन लीजिए न । होता है कि शुरू कीजियेगा तो दूसरे की चिन्ता नहीं कीजियेगा । हमको सारे सदन की चिन्ता करनी है । इसलिए आप सबलोग अपने-अपने क्षेत्र के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं, वह लिखकर दे दीजियेगा, हम सदन की तरफ से, आसन की तरफ से सब सरकार को उचित और कारगर कार्रवाई के लिए अग्रसारित कर देंगे, सरकार से भी कहेंगे कि वह उन सबको देखेगी और कार्रवाई करेगी ।

टर्न-11/शंभु-हेमंत/03.08.2020

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अब सरकार का उत्तर, प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2020-21 का प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरणी बिहार विधान मंडल में आज उपस्थापित किया गया है। प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरणी में 22 हजार 777....

अध्यक्ष: अब सत्यदेव जी बैठ जाइये, आप तो बोल चुके ।

श्री विजय प्रकाश : महोदय, हमलोग नए सदस्य हैं एक मिनट मौका दिया जाए । हमलोग नए सदस्य हैं अंतिम सत्र है एक मिनट दिया जाए, महोदय ।

अध्यक्ष: अब कोई नया नहीं हैं आप तो सदस्य के साथ बोल रहे हैं ।

श्री विजय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मौका दिया जाय ।

श्री सदानंद सिंह: अध्यक्ष महोदय, आप भी इस बात से सहमत हैं कि सिर्फ यह आखिरी दिन नहीं है । अब हमलोगों का 5 साल का कार्यकाल भी पूरा हो गया और फिर कोई सत्र होने वाला नहीं है और आज भी जितने विधायिका के कार्य थे वो करीब-करीब समापन की स्थिति में हैं और थोड़ा सा है, वक्त दीजिए लोगों को, दो मिनट-एक मिनट बोल लेंगे समस्याओं के संबंध में अच्छा रहेगा, अध्यक्ष महोदय। यह एक सहृदयता की बात होगी । अध्यक्ष महोदय, इतना निष्ठुर मत बनिये, लोगों को दीजिए ।

अध्यक्ष: सदानंद बाबू, आप खुद साक्षी हैं कि आसन हमेशा सदस्यों की भावना की न सिर्फ कद्र करता है बल्कि उनके साथ चलता है लेकिन जो आपने कहा सभी सदस्यों को एक मिनट समय दीजिए, आसन को कोई एतराज नहीं है लेकिन ये दायित्व आप ग्रहण करिये कि एक मिनट में बात समाप्त हो जाएगी । चलिये हमको कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट में कौन समाप्त करेंगे । बोलिये, नीरज जी बोलिये ।

(व्यवधान)

श्री सदानंद सिंह : हम ही शुरू करते हैं एक मिनट ।

अध्यक्ष: अरे, बैठिये न । अब देखिये, बोलिये । अब 5 मिनट बोलने की भूमिका बनती है ।

श्री नीरज कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरे बरारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुरसेला में सर्वोदय आश्रम में एक कॉलेज है, उसकी अपनी भूमि है, भवन है, हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि वह अतिपिछड़ा इलाका है, अल्पसंख्यक इलाका है सरकार उसको मंजूरी दे । सरकार की नीतियों के हिसाब से भी डिग्री कॉलेज का निर्माण होना है, इसलिए मैं आपसे पुन: विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं ।

अध्यक्ष: बोलिये रंजू जी ।

डा0 रंजु गीता: अध्यक्ष महोदय, अत्यधिक वर्षा के कारण और नेपाल की नदियों का पानी आने के कारण सीतामढ़ी जिला संपूर्ण रूप से बाढ़ प्रभावित हो गया है । बाजपट्टी, नामकुर, बोकरा सहित हमारे सीतामढ़ी जिले के सभी प्रखंड़ों को बाढ़

प्रभावित घोषित करते हुए, बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत दी जाए और नीरज सिंह बबलू की बातों का समर्थन करते हुए, मैं अपनी बातों को समाप्त करती हूँ, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि होने के साथ-साथ एक माँ हूँ ।

अध्यक्षः चलिये, अवधेश बाबू ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन में हमारे प्रतिपक्ष के नेता और माननीय विधायक ने सुशांत सिंह के मामले में विस्तृत रूप से बताया है । मेरा विचार है अध्यक्ष महोदय, सारे दल के लोग बिहारवासी हैं और हम बिहारवासियों की एक ही मांग है कि सर्वसम्मति से विधान सभा में सुशांत सिंह के केस के लिए सी.बी.आई जांच करवाने के लिए प्रस्ताव दिया जाय ।

अध्यक्षः श्रीमती आशा जी ।

श्रीमती आशा देवी : अध्यक्ष महोदय, दानापुर विधानसभा में सरारी पंचायत के अध्यक्ष की जो हत्या हुई है । सर बहुत सीधे-सादे आदमी थे वो बैठे हुए भूंजा फांक रहे थे, तीन व्यक्ति आये और उनको गोली मार कर चले गए, इसपर सी.बी.आई. की जांच हो । अध्यक्ष महोदय, प्रशासन कहता है कि नाम दिया जाए । नाम दिया जाता है लेकिन अपराधी गवाही नहीं देने देते हैं । सर कोर्ट में बहुत परेशान करते हैं । इस पर सी. बी.आई. जांच करवायी जाए और इसमें देखा जाए कि इसमें कौन हैं, सर । दानापुर विधानसभा क्षेत्र में जौ-गेहूँ की तरह अपराधी उपज रहे हैं इस की भी जांच की जाए, क्यों इस तरह हो रहा है सीधे-सीदे आदमी की हत्या हो रही है।

अध्यक्षः अनिल जी बोलिए ।

श्री अनिल सिंह : अध्यक्ष महोदय, झारखण्ड बॉर्डर से लेकर बख्तियारपुर तक एन0एच0-31 का अविलंब फोरलेन का निर्माण कराया जाय ।

अध्यक्षः ठीक है, रविन्द्र जी प्रारंभ करें ।

श्री रवीन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, जीविका के माध्यम से उनका नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, इसमें प्वाइंट नं. 1- बहुत लोग इसमें बच गए हैं जिनका कार्ड पर नाम नहीं है । दूसरा प्वाइंट है कि जो लोग थंब इम्प्रेशन से राशन ले रहे थे कार्ड में नाम है उनलोगों के राशन कार्ड में थंब इम्प्रेशन नहीं लिए थे, उनको राशन नहीं मिल रहा है तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहेंगे कि गरीबों के हित का ये मामला है इस पर विचार करेंगे कि गरीब राशन से वंचित न रहें ।

अध्यक्षः श्री रामदेव राय जी ।

श्री रामदेव रायः अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिले के चमथा में लोग बाढ़ से डूब रहे हैं । आप जानते हैं कि डूब रहे हैं इसलिए उनको राहत दिलवाने की व्यवस्था सरकार से करवायी जाए ।

अध्यक्षः ठीक है सत्यदेव जी, अब तो बोल लिए । नवाज आलम जी ।

श्री सत्यदेव रामः अध्यक्ष महोदय, खाद्य सुरक्षा कानून के तहत नियम है 5 किलो अनाज लाभुकों को देने का, लेकिन महोदय, पूरे बिहार में 4 किलो अनाज दिया जाता है। महोदय, तो आज भुखमरी के समय में गरीबों के सामने संकट आया है । हम सबका सम्मान करते हैं कि वो 5 किलो का 5 किलो अनाज गरीबों को दिया जाए और बिहार के 4 लाख शिक्षकों को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए । सरकार इसपर गंभीरता से विचार करे ।

श्री समीर कुमार महासेठः अध्यक्ष महोदय, रैयाम सकरी चीनी मिल के लिए आपसे आग्रह करते हैं कि वह 15 साल तो लगातार चला, लेकिन ये 15 साल नहीं चला पाए, कम से कम सोचा जाए, साथ ही राज्य स्वास्थ्य समिति में उर्मिला इंटरप्राइजेज के द्वारा बाहर से जो लोग लिए जाते हैं पूर्व की भांति उन लोगों को जो रोजगार मिलता था उसे लागू किया जाए, कम से कम जो डाटा ऑपरेटर हैं उनको लिया जाए ।

अध्यक्षः ठीक है बोलिए ।

श्री अमित कुमारः अध्यक्ष महोदय, हमारे सीतामढ़ी में एक मात्र शुगर फैक्ट्री है । पहले जो किसानों का भी भुगतान नहीं होता था इधर 11 मई से लगातार दो महीनों के लॉकडाउन के कारण बंद कर दिया गया है जो भी लोकल इंप्लाई थे उनको रोक दिया गया है, बाहर के लोग काम कर रहे हैं जरा उसको अपने संज्ञान में लें तथा सुशांत सिंह के केस में जो है विधान सभा से पारित हो, हम सब मिल कर उसको पारित करें और सी.बी.आई. जांच हो, तीसरा पूरे सीतामढ़ी जिले को बाढ़ घोषित किया जाए, धन्यवाद ।

अध्यक्षः बोलिए, अब बोलिए ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादवः अध्यक्ष महोदय, पिपरा विधानसभा सहित पूरे पूर्वी चंपारण में बूढ़ी गंडक के चलते और भारी बारिश के चलते बाढ़ प्रभावित सभी जिले हैं और जो बारिश के पानी से गांव घिरे हैं, जहां नाव चल रही है वहाँ लोगों का आवागमन बाधित है उसको प्रशासन बाढ़ नहीं मान रही है । हम आग्रह करेंगे कि बाढ़ के पानी से जो बाढ़ आयी है जिससे आवागमन बाधित है, गाँव डूबा हुआ है उसको भी बाढ़ प्रभावित माना जाए और उचित मुआवजा देने की मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री विजय प्रकाश : महोदय, लघु सिंचाई का लगातार जो भी काम जमुई जिला में हो रहा है आज से कुछ दिन पहले एकरुआघाट पर जो दो करोड़ का डैम था, उसके उद्घाटन से पहले ही वह ढह गया । उसी तरह से कलस्टर में इंदिरा आवास के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़ा हॉल में बड़ा बड़ा चाबी देकर उद्घाटन करने का काम किए थे । सभी इन्दिरा आवास को कलस्टर में बनाने की बात थी डिमोलिश करके लेकिन पैसा जाने के बाद भी वह आज तक काम नहीं हो पाया है । महोदय, कलस्टर में यह किया गया था और दूसरी चीज अभी जमुई जिला में बड़े पैमाने पर बालू के साथ बलात्कार किया जा रहा है सरकार और प्रशासन के माध्यम से । माननीय मुख्यमंत्री जी को पाँच दिन पहले चिट्ठी भी लिख कर दिए थे । चीफ सेक्रेट्री से बात हुई थी और मंत्री जी से बात हुई थी जो मैसेज दिए थे उसको अभी तक नहीं देखा गया है । महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है जो मैसेज दिया जाता है उसको भी नहीं देखा जाता है ।

अध्यक्ष : ठीक है । हो गया विजय जी ।

श्री शकील अहमद खाँ : महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करुंगा कि सीमांचल कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया ये चारों जिले कोसी, महानंदा और गंगा से जुड़े हुए हैं और सैलाब हर साल आता है तो वहाँ सैलाब आया हुआ है उन चारों जिलों को बाढ़ घोषित किया जाय, नंबर वन और दूसरा सेंटर की गलत नीतियों की वजह से जितने मायग्रेंट लेबर बिहार आए हुए हैं, उनके रोजगार सृजन का काम बिहार सरकार करें । धन्यवाद ।

श्री सदानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नीरज जी, नेता प्रतिपक्ष और अवधेश बाबू और माननीय सदस्यों ने जिन भावनाओं के साथ आपसे आग्रह किया है यह राज्य का सवाल है, देश का सवाल है, आपसे विनती करेंगे कि एक प्रस्ताव निश्चित रुप से बिहार विधान सभा की ओर से जाय, सुशांत की हत्या या आत्म हत्या है उसकी जाँच सी.बी.आई. करे । दूसरा आग्रह मेरा था कि एन.एच. 80 जो भागलपुर का मुख्य पथ है उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गयी है, हमने कई बार माननीय मंत्री जी से आग्रह किया पिछले चार-पाँच वर्षों से परेशान हो गए हैं । हमारे वित्त मंत्री जी वहाँ से सांसद रहे हैं उन्होंने भी देखा है, मेरा आग्रह होगा, मेरी विनती होगी कि उसपर ध्यान दीजिये । कल 9 घंटे लग गये हमको जिस सरकार के द्वारा यह कहा जाता है कि मुख्यालय पहुंचने में सिर्फ पाँच घंटे लगेंगे, कल 9 घंटे का समय लगा ।

अध्यक्ष : अब सरकार का उत्तर होगा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन निमयावली के नियम 179 में अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान है और फिर जब यह पास हो जाता है तो विनियोग विधेयक पारित करने का प्रावधान है । चूँकि मैं माननीय वित्त मंत्री के उत्तर में सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ कि बार बार सरकार कहती है कि हमारे बजट का आकार यह है, हमारे बजट का आकार यह है तो इसमें स्पेसिफिक है कि खर्चा करने की कब जरुरत पड़ गयी, कौन सी नयी स्कीम है, उसको भी बतला दें और दूसरा यह जरुर बतावें कि आप प्रति वर्ष जो आपका अनुदान है, प्रथम अनुपूरक है और जो मूल बजट उससे हर साल कितना पैसा लैप्स करते हैं और कितना पैसा रंग-रोगन, डेंटिंग पेन्टिंग और साज-सज्जा में खर्च करते हैं, यह हम जानना चाहते हैं वित्त मंत्री जी से ।

अध्यक्ष : ठीक है, क्या है सुभान जी बोलिये ।

श्री अब्दुस सुभान : अध्यक्ष महोदय, हमलोग पूर्णिया जिला के वायसी अनुमंडल से आते हैं वायसी विधान सभा वहाँ कनकई, महानंदा, परवान नदी की बाढ़ और इस वर्ष 16-17 और 2019 से भी ज्यादा खतरनाक बाढ़ आयी लेकिन वह क्षेत्र बाढ़ घोषित नहीं हो रहा है । नदी के कटाव से लोग प्रभावित हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर रही हैं, सरकार की एक भी नाव नहीं गयी है, कितने लोग डूब कर मर गए । दरअसल पिछली बार नाव का पैसा भी नहीं दिया गया ।

श्री मुनेश्वर चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सारण जिला में चिरान और लोदीपुर गांव जो गरखा विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है महोदय, 22 दिनों से आज दो सौ घर पानी में डूबे हुए हैं और जल निकासी के अभाव में घर में लोग कैद हैं । आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि जितना जल्द हो उनको जल जमान से मुक्त कराया जाय ।

डा0 रामानंद यादव : अध्यक्ष महोदय, फतुहा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत फतुहा प्रखंड में कोरोना वायरस से काफी लोग संक्रमित हो रहे हैं, न वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था है, न क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था, न ईलाज हो रहा है । फतुहा प्रखंड से लोग एन.एम. सी.एच. आते हैं तो उनको भर्त्ती नहीं किया जाता है । उसी तरह सदर प्रखंड के जल्ला और संपतचक में काफी लोग संक्रमित हो रहे हैं आपके माध्यम से मेरी मांग होगी कि कोरोना वायरस संक्रमित लोगों के लिए स्वास्थ्य केन्द्र में जगह नहीं है तो बगल के स्कूल में क्वारंटीन सेंटर खोलकर ईलाज किया जाय ।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, मधेपुरा जिला के आलमनगर प्रखंड और चौसा प्रखंड के सैकड़ों घर के लोग तबाह हैं । एक महीना से, बीस दिन से लेकर दो महीना से लेकिन मैं तीन दिन में कम से कम दर्जनों गांव घूमा हूं और वहाँ राहत का कोई

काम नहीं चल रहा है जो दुखद बात है । आपदा प्रबंधन विभाग का एस.ओ.पी. है कि अगर 72 घंटा तक किसी के घर में पानी है तो सरकार उसको भोजन करायेगी और 7 दिन और 10 दिन से ज्यादा जल घेराव हुआ है तो सरकार कौम्यूनिटी कीचन की व्यवस्था करेगी । दूसरी बात महोदय, हमारे इलाके के खेतों में 60 परसेंट से लेकर 100 परसेंट तक धान की फसल नष्ट हो चुकी है और मकई की भी वही स्थिति है । हमारे जिला में मकई अधिप्राप्ति केन्द्र जल्द से जल्द खुले ।

श्री आफाक आलम : अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ मामला है यह हम बोलना चाहते हैं कि जितने भी हमारे माननीय सदस्य है सब के स्वास्थ्य में कहीं न कहीं गड़बड़ी है और कोरोना की जो मार पड़ रही है उसमें कहीं भी बिहार के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है । मेरे पूर्णिया जिला में अध्यक्ष महोदय, मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसकी व्यवस्था साफ चरमरा गयी है । जितनी मशीनें आ रही हैं उनको रखने की जगह नहीं है । उसको ठीक किया जाय । अभी स्थिति ऐसी है कि वहाँ से मरीज आते हैं तो पटना आते आते मर जाते हैं । स्वास्थ्य विभाग में सुधार किया जाय, लोग मर रहे हैं ।

अध्यक्ष : अब बैठिये न हो गया ।

श्री आफाक आलम : कोरोना की मार पड़ रही है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि यहाँ से जो सामान मेडिकल कॉलेज के लिए जा रहा है उसको रखने की समुचित जगह नहीं है । उसका इंतजाम किया जाय ।

अध्यक्ष : अभी आफाक जी आप बोल ही रहे हैं । श्री रामदेव यादव जी बोलिये ।

श्री रामदेव यादव : अध्यक्ष महोदय, लॉकडाउन के समय में बांका जिला में लगातार हत्यायें हो रही हैं । कटोरिया क्षेत्र में बिना मास्क लगाए हुए एक आदमी को चार किलोमीटर पुलिस रपेटती रही और वह आदमी गाछ में टकरा कर मर गया जबकि पुलिस को रपेटना नहीं है और दूसरा नंगे तार से गांव के मंजेश यादव की हत्या हो गयी, उनको मुआवजा मिलना चाहिए ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, पिछले महीने की 24 तारीख को गोपालगंज के बैकुंठपुर में 7 जगह बांध टूट गया, बरौली में तीन जगह बांध टूट गया । बैकुंठपुर और बरौली विधान सभा के सभी गांव डूब गए इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि दोनों विधान सभा क्षेत्रों के सभी गावों को मुआवजा दिया जाय तथा उच्च स्तरीय जॉच की मांग भी करता हूं । वहाँ पदाधिकारी सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाय ।

श्री मुद्रिका प्रसाद राय : अध्यक्ष महोदय, सारण जिलान्तर्गत तरैया प्रखंड, पानापुर प्रखंड, इसुआपुर प्रखंड, मसरख, मरौढ़ा ये पूरी तरह से जल मग्न हो गये हैं और मिथिलेश

तिवारी जी जो बोल रहे है बांध टूटने का जो जिक्र कर रहे हैं बांध से जो पानी आ रहा है सारण जिला के सारे प्रखंडों को बहा कर ले जा रहा है अबतक स्थिति यह है कि किसी घर में चूल्हा नहीं जल रहा है और भोजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और न ही नाव की कोई व्यवस्था है ।

टर्न–13/ राजेश/मुकुल/3.8.20/

श्रीमती सावित्री देवी: अध्यक्ष महोदय, हमने सदन में चकाई बी0डी0ओ0 को हटाने के लिए आवेदन दिया है लेकिन अभी तक वह हटा नहीं है । मैं सदन से मांग करती हूँ कि सुन्नी चॉद बी0डी0ओ0 को हटाकर किसी दूसरे बी0डी0ओ0 को दिया जाय ।

श्री विरेन्द्र कुमार सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि दाउदनगर अनुमंडल को जिला बनाया जाय ।

अध्यक्ष: आपलोग एक–एक मिनट बोलते जाइये । हम सभी को मौका देंगे ।

श्री रामानुज प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, आपके संज्ञान में है कि हमारे सारण जिला और सोनपुर का टोपो लैंड का इशू बहुत ही भाईटल है और जब इसपर सर्वे का काम शुरू हुआ टोपो लैंड बिहार में तो बहुत ही अफसोस के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि जब मैंने विभाग में संपर्क किया, माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं कि हमारा ही जिला आपके कहने पर, आपने कहा कि समिति बनेगी और टोपो लैंड पर काम होगा, सारे गरीब सफर कर रहे हैं, किसी को भी राशन, किरासन नहीं मिल रहा है, सरकार से मिलने वाली कोई भी देय राशि से हमारे क्षेत्र के लोग और जिला के लोग वंचित रह रहे हैं ।

श्रीमती पूनम देवी यादव: अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिला बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और खगड़िया जिला में 70 हजार लोग प्रभावित हैं और मेरे विधान सभा क्षेत्र खगड़िया में तीन पंचायत प्रभावित हैं । खगड़िया प्रखंड के उत्तरमारक और खगड़िया प्रखंड के रहिमपुर उत्तरी, दक्षिणी एवं मध्य और मानसी प्रखंड के अमनी के यारपुर और पूर्वी ठाठा, पश्चिमी ठाठा एवं खुटिया पंचायत ये तमाम जो टोला है, प्रखंड है, प्रभावित है और वहॉ बाढ़ के दिनों में ज्यादातर वहॉ पर जब बाढ़ का पानी आता है तो मैय्यर कहा जाता है । वहॉ पर मेडिकल टीम की आवश्यकता है और बार–बार, हर साल जो बाढ़ आ जाती है तो वहॉ पर एक बड़ा बॉध बने, क्योंकि वहॉ पर हर साल लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं । इसलिए वहॉ पर कम्युनिटी किचन की आवश्यकता है और पिछले साल जो बाढ़ आयी थी उसका भी मुआवजा नहीं मिला और इस बार भी जहॉ–जहॉ पर बाढ़ आयी है वहॉ पर तेजी के साथ मुआवजा और राहत दिलवायी जाय । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

श्री विजय कुमार विजयः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा, क्योंकि कई बार हमने उनको लिखित में भी दिया है और उनके कार्यक्रम में भी उठाया था कि मुंगेर में गंगा नदी पर जो सड़क पुल बन रहा है उसमें एक संपर्क पथ मुंगेर शहर के लोगों की सुविधा के लिए बनाया जाय । दूसरी बात कि उनके निर्देश पर जिला प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जमीन की सूची भेज दी है लेकिन अभी तक यहाँ से उसपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तीसरी बात सदर प्रखंड का टीकारामपुर पंचायत का बुरी तरह से बाढ़ से कटाव होता रहता है, कई वर्षों से इसके लिए हम कहते रहे हैं । मेरी मांग है कि उसकी सुरक्षा की जाय ।

श्री रामप्रीत पासवानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि जिस गरीब का राशनकार्ड नहीं बना है, उसका राशनकार्ड शीघ्र बनवा दिया जाय ।

श्रीमती भावना झाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि मधुबनी जिला पूरा का पूरा बाढ़ और जल जमाव से ग्रसित है .....

अध्यक्षः आप सभी लोग लिखकर दे दीजियेगा ।

श्रीमती भावना झाः महोदय, लेकिन मैं आपके माध्यम से मांग करती हूँ कि पूरे मधुबनी जिला को बाढ़ ग्रस्त घोषित किया जाय ।

श्री केदार नाथ सिंहः अध्यक्ष महोदय, मशरख की 11 पंचायत बिल्कुल डूब गयी हैं । महोदय, हमने 9.30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारण के समाहर्ता को निदेश दिया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। इसलिए आग्रह होगा कि राहत कार्य चलाया जाय ।

श्री यदुवंश कुमार यादवः महोदय, 20 तारीख को पिपरा थाना के तेतराही गॉव में जल से डूबे हुए लोगों ने जल निकासी की मांग की लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा जो जल निकासी की मांग करने वाले गरीब, दलित, महिलाओं को रात में 10 बजे दरवाजे को तोड़कर ....

अध्यक्षः आप लिखित दे दीजियेगा ।

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रमः अध्यक्ष महोदय, अभी जो राशन कार्ड बना है, उस राशन कार्ड से इस कोरोना काल में किसी को राशन नहीं मिल रहा है । इसलिए मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि नये राशनकार्ड से सभी को अनाज मिले ।

श्रीमती समता देवीः अध्यक्ष महोदय, गया जिला के बाराचट्टी विधान सभा का मुख्य मार्ग जो एक प्रखंड को दूसरे प्रखंड से जोड़ता है । इसका आर0डब्लू0डी0 से टेंडर हो चुका था, उस टेंडर को रद्द किया गया, यह कहते हुए कि आर0सी0डी0 कहता है कि मेरा रोड है, जबकि पथ निर्माण विभाग कहता है कि हमारा रोड है । इन दोनों

विभागों की आपसी लड़ाई के कारण रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा है । इसलिए हम आपसे चाहेंगे कि यह मुख्य रोड जो नहीं बन रहा है, वह बन जाना चाहिए ।

श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी: अध्यक्ष महोदय, वर्षा और ओलावृष्टि से अभी तक इनपुट अनुदान जमुई जिला को नहीं मिला है और सिकंदरा प्रखंड में निर्माणाधीन कुंडघाट का जल्द से जल्द काम पूरा करवाया जाय और सिकंदरा विधान सभा में सिकंदरा-खैरा पी0एच0सी0 को एफ0आर0यू0 का दर्जा दिलवाया जाय ।

श्री सुनील कुमार: अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी शहर में पूरा जल जमाव है, आवागमन ठप है और यह सीतामढ़ी मॉ सीता की जन्मभूमि है और मंदिर के प्रांगण में पानी है । इसलिए पूरे सीतामढ़ी शहर से जल निकाला जाय और गन्ना किसानों के बकाये पैसे का शीघ्र भुगतान करवाया जाय, जो पॉच साल से बकाया है ।

श्री गुलाब यादव: अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला को बाढ़ग्रस्त जिला घोषित किया जाय । पूरे जिला में पानी भरा हुआ है, बार-बार हम जिला प्रशासन से इस बात को उठा रहे हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है .....

अध्यक्ष: इसीलिए हम कहते हैं कि आपलोग लिखकर दे दीजिये ।

श्री जफर आलम: अध्यक्ष महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र में चिनावे नदी का पानी, कोशी का पानी, कमला का पानी सारी नदियों का पानी वहीं पर डंप करता है, एक गॉव ही नहीं बल्कि हजारों गॉवों का बाढ़ का पानी है । लेकिन गरीब लोगों को अभी तक पॉलिथीन तक नहीं मिला है और जिनका घर कटाव के कारण बह गया उनको आज तक मुआवजा तक नहीं मिला है, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि गरीबों को अनाज एवं मुआवजा का वितरण किया जाय ।

श्री अभय कुमार सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, गया जिले के टेकारी में मोरहर नदी है और माननीय मुख्यमंत्री जी 2016 में यात्रा के दौरान मंच से वहॉ पर दोनों पैन के मुहाने पर वीयर बॉध बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुई थी, तत्पश्चात् सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है, डी0पी0आर0 वगैरह बनकर लगभग एक वर्ष से विभाग में लंबित है, इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि सिंचाई के दृष्टिकोण से देखते हुए उस योजना को जल्द से जल्द पूरा कराने का कष्ट किया जाय ।

श्री तारकिशोर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, कटिहार नगर निगम क्षेत्र में बुडको के द्वारा जल निकासी हेतु स्ट्रॉम वाटर ड्रैनेज योजना फेज-1 प्रस्तावित है सरकार के समक्ष और यह एक अरब 94 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होना है । आपके माध्यम से आग्रह है कि सरकार कटिहार नगर निगम क्षेत्र से जल निकासी की व्यवस्था की जाय ।

श्री महेश्वर प्रसाद यादवः अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिला में बाढ़ की भारी विभीषिका है । मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से छः हजार रुपया दिया जा रहा है लेकिन अफसर लोग इसे तेजी से लागू नहीं कर रहे हैं, इसके लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।

श्री नौशाद आलमः अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला के मेरे विधान क्षेत्र में छिंगीमारी, घनटोला, दिघल बैंक, चूलिया, भटगॉव में पिछले महीने से कई बार पानी घुसा है, क्योंकि बोर्डर इलाका है लेकिन अभी तक राहत सामग्री कुछ भी नहीं मिली है । इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे इलाके में राहत सामग्री का वितरण किया जाय ।

श्री सुभाष सिंहः अध्यक्ष महोदय, गंडक बराज से पानी गोपालगंज जिला को प्रभावित करता है। महोदय, मैं बता देना चाहता हूँ कि गन्ना काश्तकारों की स्थिति यह है कि धान गेंहू की तो फसल क्षति का हमेशा कुछ न कुछ भुगतान मिलता है लेकिन आज तक गन्ना काश्तकारों को क्षतिपूर्ति नहीं मिल पाई है । गोपालगंज में गन्ना महीनों से पानी में डूबकर सड़ रहा है । अकेले गोपालगंज चीनी मिल में 50 से 60 लाख क्विंटल क्रशिंग करता है । सिधावलिया फैक्ट्री में 60 से 65 लाख क्विंटल क्रशिंग करता है और सासामूसा में 25 से 30 लाख क्रशिंग होती है । पूरे जिले में डेढ़ करोड़ क्विंटल से अधिक गन्ना का नुकसान हुआ है । किसानों का कैश क्रॉप गन्ना ही है । इसी की आय पर गन्ना किसान शादी ब्याह से लेकर सब कुछ निर्भर है । एक साल तक किसान अपने खून पसीने से गन्ने की फसल को सींचता है इसलिये इसकी भरपाई की जाय, इसकी क्षतिपूर्ति की जाय, यही आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूं ।

टर्न-14/सत्येन्द्र/03-08-2020

श्री संजीव चौरसियाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि दीघा विधान सभा के अंतर्गत 724 एकड़ का जो जमीन का है, वहाँ आए दिन जो अतिक्रमण के नाम पर आवास बोर्ड के द्वारा अधिग्रहण का जो काम चलता है, वहाँ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए जो हक के हकदार हैं बिना मुआवजा के घेरने का प्रयास होता है और सुशांत सिंह राजपूत जो मेरे विधान सभा क्षेत्र के हैं, हम चाहते हैं कि इस विधान सभा को सर्वसम्मति के साथ सी.बी.आई. को इंक्वायरी के लिए प्रस्ताव भेजना चाहिए । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्षः श्री मेवालाल चौधरी जी ।

श्री मेवालाल चौधरी: अध्यक्ष महोदय, तारापुर विधान सभा के तारापुर नगर पंचायत की घोषणा अभी भी सरकार के पास लंबित है । महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय को जल्द से जल्द तारापुर नगर पंचायत घोषित हो ।

अध्यक्ष: ठीक है । अब अंतिम वक्ता के रूप में श्री भोला जी मात्र एक मिनट में, 45 सेकेंड में खत्म करिये ।

श्री भोला यादव: अध्यक्ष महोदय, बाढ़ से पूरा उत्तर बिहार त्राहिमाम कर रहा है और..

अध्यक्ष: आप अपना एरिया वाला न बोलिये ।

श्री भोला यादव: हमारे विधान सभा का 37 पंचायत पूरा अस्त-व्यस्त है लेकिन हरेक साल बाढ़ आती है, इसका कोई स्थाई समाधान अभी तक नहीं ढूंढा गया है । महोदय, मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार और केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि नेपाल से वार्ता करके सरकार इसका स्थायी समाधान निकालें ।

अध्यक्ष: ठीक है, शक्ति जी, 30 सेकेंड में।

श्री अत्री मुनी ऊर्फ शक्ति सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, हिलसा प्रखंड मुख्यालय के पास जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, वह अनुदान की जमीन पर बना है जो राम बाबू नि:संतान थे उन्होंने इसके लिए दिया था जमीन । 40 वर्षों तक वह चला, उसको भू-माफिया द्वारा रजिस्ट्री करा करके उसको तोड़ दिया गया, चूंकि नि:संतान थे उनके संतान का कोई दूसरा वारिस का दूर से लगाव से जोड़-जोड़ करके रजिस्ट्री करवाया गया था सरकार का पैसा लगा हुआ था यह तो दुर्भाग्यपूर्ण है महोदय इस पर कार्रवाई हो ।

अध्यक्ष: ठीक है । अब सभी माननीय सदस्यगण अपने-अपने माईक की लाल बत्ती बंद कर लीजिए, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री ।

(व्यवधान)

अब जवाब होने दीजिए। अब जो बच गए है वह लिखकर दे दीजिएगा ।

श्री भाई वीरेन्द्र: सरकार के जवाब होने के पहले मैं सदन से मांग करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी 5 तारीख को अयोध्या जा रहे हैं, पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है ये प्रस्ताव लाया जाए कि उनको नहीं जाने दिया जाए, रोका जाए, विधान सभा से यह प्रस्ताव पास किया जाए ।

सरकार का उत्तर

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2020-21 का प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरणी बिहार विधान मंडल में आज सुबह उपस्थापित किया

गया है और प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरणी में 22 हजार 777 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है जिसमें स्कीम मद में 5 हजार 332 करोड़ , स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 17 हजार 304 करोड़, कुल मिलाकर 22 हजार 777 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । अध्यक्ष महोदय, कोरोना और इस लॉकडाउन के कारण पूरी दुनिया घोर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है, चाहे वो पूरी दुनिया हो या भारत हो या बिहार हो, चूंकि लॉकडाउन के कारण लंबे समय तक व्यापार उद्योग बंद पड़े रहे तो राज्यों की आमदनी का एक बहुत बड़ा स्रोत है टैक्स, उसमें राज्यों को और केन्द्र को उसमें भारी कमी का सामना करना पड़ा । अध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन को बताना चाहूँगा कि जहाँ अप्रैल, 2020 में पिछले साल के अप्रैल की तुलना में 81 परसेंट कम राजस्व संग्रह हुआ, मई महीने में 42 परसेंट कम राजस्व संग्रह हुआ, जून महीने में 15 परसेंट कम राजस्व संग्रह हुआ पिछले साल के जून की तुलना में और जुलाई के अंदर 8.34 परसेंट कम राजस्व का संग्रह हुआ है पिछले साल जुलाई की तुलना में, अगर अप्रैल, मई, जून, जुलाई अगर इस चार महीने को ले लें तो पिछले साल जितना राजस्व संग्रह हुआ था बिहार के अंदर उसकी तुलना में 33.61 प्रतिशत कम राजस्व का संग्रह हुआ है । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूँगा कि पिछले साल 2019-20 में अप्रैल, मई, जून के अंदर जहाँ बिहार में 11 हजार 171 करोड़ रू0 का टैक्स संग्रह हुआ था वहाँ इस बार 2020 में लॉकडाउन के कारण केवल 7 हजार 416 करोड़ रू0 का राजस्व संग्रह हुआ है यानी 3 हजार 754 करोड़ रुपया का कम राजस्व संग्रह हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय लेकिन हमारी सरकार का एक फैसला है कि हम अपने कर्मचारियों को वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं करेंगे और मैं सदन को जानकारी देना चाहूँगा कि अप्रैल, मई, जून इस तीन महीने में राजस्व संग्रह कम होने के बावजूद हमलोगों ने अपने कर्मचारियों को, कान्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को कुल मिलाकर 10 हजार 732 करोड़ रुपया वेतन के रूप में हमलोगों ने भुगतान किया है। जबकि अध्यक्ष महोदय, देश के जो संपन्न राज्य हैं आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल इन राज्यों ने कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर दी, किसी ने 30 परसेंट, किसी ने 20 परसेंट यहाँ तक कि कई राज्यों ने पेंशन के भुगतान में भी 50 प्रतिशत की कटौती कर दी और एक राज्य केरल ने तो एक अध्यादेश जारी कर दिया कि प्रत्येक महीने, प्रत्येक माह में 6 दिन के वेतन की कटौती की जाएगी लेकिन अध्यक्ष महोदय, सारी कठिनाइयों के बावजूद हमलोगों ने न वेतन में कोई कटौती की है और न कोई पेंशन में कटौती की है और जैसा मैंने बताया कि 10 हजार 732 करोड़ रुपया हमलोगों ने 3 महीने में वेतन के रूप में वितरित किया है ।

पेंशन के मद में 6 हजार 168 करोड़ रुपया पेंशन के रूप में दिया गया है, ब्याज के भुगतान में 2 हजार 959 करोड़ रुपया हमलोगों ने ब्याज का भुगतान किया है, हमलोगों ने जो कर्ज लिया था उस कर्ज के किस्त के भुगतान में 1816 करोड़ रुपये खर्च किया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि राजस्व संग्रह में कमी के बावजूद हम बिहार के किसी कर्मचारी के वेतन और पेंशन में हम किसी प्रकार की कटौती नहीं होने देंगे और अध्यक्ष महोदय, हमलोगों ने जो खर्च किया है अभी तक पिछले तीन-चार महीनों में अगर 31 जुलाई तक का लें तो हमने कुल बजट का 22 प्रतिशत हमलोगों ने खर्च किया है जो 46 हजार 537 करोड़ रुपया होता है । अध्यक्ष महोदय, सिद्दिकी साहब बहुत वरिष्ठ हमारे नेता हैं और सदन को यह मालूम है कि राज्य की आमदनी का तीन ही जरिया है- स्टेट ऑन टैक्स यानी राज्य का अपना कर राजस्व, जो हम कर्ज लेते हैं वह दूसरा स्रोत है और तीसरा स्रोत है कि केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से के रूप में जो राजस्व हमको प्राप्त होता है और चौथा है केंद्र प्रायोजित योजनाओं में हमको जो राशि प्राप्त होती है अनुदान के रूप में, यही चार स्रोत है राज्यों के आमदनी का और जो पहला स्रोत है जिसका मैंने जिक्र कर दिया कि राजस्व संग्रह में 33 प्रतिशत से और ज्यादा की कमी का हमको सामना करना पड़ा है लेकिन अध्यक्ष महोदय, उसके बावजूद बिहार देश का पहला राज्य है जिसने लॉकडाउन ऐलान होते ही घोषणा की थी कि जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी जो डॉक्टर्स हैं जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको हम एक माह के मूल वेतन के बराबर हम समतुल्य वेतन देंगे । बिहार देश का पहला राज्य है जिसने सारी कठिनाइयों के बावजूद 252 करोड़ रुपया की स्वीकृति प्रदान की है और एक महीने का जो मूल वेतन है वो हम स्वास्थ्य के जो डाक्टर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको बिहार सरकार देने का काम करेगी तो अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, बिहार ने इस कोविड के दौरान बिहार सरकार ने करीब 8 हजार 538 करोड़ रुपया हमलोगों ने कोरेंटाईन पर, आने वाले श्रमिकों पर और बाकी लोगों पर खर्च करने का काम किया है (क्रमशः)

टर्न-15/मधुप/03.8.2020

...क्रमशः...

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : मैं सदन को बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा.....

(व्यवधान)

इतना ही नहीं, 84 लाख से ज्यादा जो पेंशनधारी हैं.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं बोलूंगा । मुझे बोलने दिया जाय ।

अध्यक्ष : वह दे दीजिये ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : नहीं महोदय, मैं बोलूंगा । बोलने दिया जाय ।

अध्यक्ष : बोलिये न ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र की सरकार और बिहार की सरकार दोनों ने मिलकर लगभग 20 हजार करोड़ रू0 से ज्यादा केवल कोरोना के दौरान गरीबों को देने का काम किया है । एक भी गरीब नहीं होगा जिसके खाते में 3 हजार रूपये से कम केन्द्र और बिहार की सरकार ने नहीं देने का काम किया होगा । अध्यक्ष महोदय, केवल बिहार के अन्दर 8 करोड़ 71 लाख गरीबों को तीन-तीन महीने का राशन केन्द्र के द्वारा मुफ्त में दिया गया, 15 किलो चावल दिया जा चुका है और अगले 5 महीने के अंदर हरेक गरीब को 25 किलो चावल या गेहूं केन्द्र की सरकार के द्वारा दिया जायेगा । अध्यक्ष महोदय, अगर इन सारे केन्द्र और राज्य ने कोरोना के दौरान जो गरीबों की मदद की है चाहे वह नगद भुगतान के रूप में या अनाज के रूप में अगर इन सारी राशि को जोड़ दिया जाय तो 25 हजार करोड़ रू0 से ज्यादा की राशि केन्द्र और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर बिहार के गरीबों के खाते में देने का काम किया है ।

अध्यक्ष महोदय, हमलोगों ने यह भी तय किया है कि अगर हमको और अधिक कर्ज लेने की आवश्यकता होगी तो हम कर्ज लेंगे । अभी तक हमने करीब 5 हजार करोड़ रू0 का कर्ज लिया है और इस साल हमलोगों को कुल मिलाकर बिहार सरकार को 19,384 करोड़ रू0 कर्ज लेने का प्रावधान है । भारत की सरकार ने 0.5 परसेंट और कर्ज लेने की अनुमति प्रदान की है यानी कुल मिलाकर 22,500 करोड़ रू0 कर्ज लेने की हमको केन्द्र ने अनुमति प्रदान किया है । हम 5 हजार करोड़ रू0 कर्ज ले चुके हैं । अध्यक्ष महोदय, ये ''ऋणम् कृत्वा घृतम् पीवेत'' नहीं है कि ऋण लेकर घी पीयो । यह वह सरकार है जो अगर कर्ज लेती है तो उसको खर्च करके दिखलाती है । अध्यक्ष महोदय, हम बिहार के अंदर किसी भी निर्माण के काम को बाधित नहीं होने देंगे, हम कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में कोई कटौती नहीं होने देंगे और चाहे बाढ़ पीड़ित हो या कोरोना पीड़ित हो, हम किसी को भी

राहत से वंचित नहीं होने देंगे । इसलिये जो भारत सरकार ने करीब 22,500 करोड़ रू0 से ज्यादा की हमको अनुमति प्रदान की है, हम केन्द्र की सरकार से आग्रह करेंगे कि बिहार को और अधिक कर्ज लेने की अनुमति प्रदान की जाय । मैंने पत्र लिखा है केन्द्रीय वित्त मंत्री को कि हमको और अधिक कर्ज लेने की अनुमति प्रदान की जाय । अध्यक्ष महोदय, हमारे जितने कंट्रेक्टर्स हैं उनके भुगतान में भी कोई कटौती नहीं होने देंगे ताकि निर्माण का काम अबाध गति से चलता रहे ।

अध्यक्ष महोदय, आज के इस द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी के माध्यम से, हमलोगों ने सेकंड सप्लीमेंट्री में जो प्रावधान किया है जिसका मैंने संक्षेप में जिक्र किया था, मैं सदन से आग्रह करूंगा कि सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बिहार वह राज्य है जो डिगेगा नहीं, बिहार हिलेगा नहीं । हम गरीबों की सेवा के लिए समर्पित हैं और भाई वीरेन्द्र जी ने अभी जिस बात का जिक्र किया, मैं बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि 5 अगस्त का दिन 500 वर्षों के बाद यह दिन दुनिया के इतिहास में आया है जब भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण के शिलान्यास काम प्रारम्भ अयोध्या में होने जा रहा है । मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि हमलोग तो वहाँ नहीं जा पायेंगे लेकिन अपने-अपने टी0वी0 चैनल पर उस ऐतिहासिक क्षण को छोड़ियेगा नहीं, अपने टी0वी0 को 12 बजे ऑन करके उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने का काम कीजियेगा ।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन से आग्रह करूंगा कि सदन इस विनियोग विधेक को अपनी स्वीकृति प्रदान करने का काम करे । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2020 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2020 स्वीकृत हुआ ।

सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज सभा के प्रारम्भ में दलीय नेताओं की बैठक में हुए निर्णय को माननीय सदस्य, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी जी ने आपके समक्ष रखा था । आप सबों ने उसकी स्वीकृति दी थी और उस प्रस्ताव के अनुसार अब राज्य में कोविड-19 महामारी एवं बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर विमर्श होगा ।

विमर्श के लिए कुल दो घंटे का समय उपलब्ध है और अभी 1:30 बज रहा है यानी 3:30 बजे हमलोग इस विमर्श को समाप्त करेंगे । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जा रहा है और इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा ।

क्रम सं0	दल का नाम	समय
1.	राष्ट्रीय जनता दल	- 30 मिनट
2.	जनता दल (यूनाईटेड)	- 15 मिनट
3.	भारतीय जनता पार्टी	- 10 मिनट
4.	इंडियन नेशनल कांग्रेस	- 10 मिनट
5.	सी0पी0आई0 (एम0एल0)	- 05 मिनट
6.	लोक जनशक्ति पार्टी	- 05 मिनट
7.	हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	- 02 मिनट
8.	ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन	- 02 मिनट
9.	निर्दलीय	- 06 मिनट
10.	सरकार को उत्तर के लिए	-लगभग 35 मिनट

अब बाढ़ और कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति पर विमर्श प्रारम्भ हो रहा है । नेता विरोधी दल, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देते हैं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया । अभी सुशील मोदी जी बोल रहे थे कि कर्ज और ले सकते हैं, लेंगे । बिहार के लोग कर्जदार हो चुके हैं । लालू जी जब सत्ता में थे, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 1990 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो आपको पता होगा महोदय कि गाँधी मैदान और पटना का रेलवे स्टेशन गिरवी रखा हुआ था । 2005 में जब सत्ता सौंपकर गये नीतीश जी को तो बिहार प्रोफिट में आ गया, उनको पता होना चाहिए, यह जानकारी होनी चाहिए ।

महोदय, आज भयावह स्थिति पूरे बिहार में बनी हुई है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग भूखे हैं, बेरोजगार हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लाशों का ढेर लगा हुआ है और कोई सुनने वाला नहीं है । सरकार के लोग नदारद हैं, अदृश्य हैं, गायब हैं ।

..क्रमशः...

टर्न-16/आजाद/03.08.2020

..... क्रमशः .....

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : हम अफवाह मियां नहीं हैं । हम अफवाह नहीं फैलाते हैं । हम तथ्यों पर बात करते हैं, साक्ष्य पर बात करते हैं, डेटा पर बात करते हैं, आंकड़ों पर बात करते हैं और कोई मेरा उपजाया हुआ आंकड़ा नहीं है, जो सरकारी एजेंसियां हैं, उन आंकड़ों पर हम बात करना चाहते हैं । हमलोगों को बड़ी उम्मीद रहती है । एक नौजवान होने के नाते, एक बिहार का और बिहारी होने के नाते सब की कामना है कि यह जो देश में, दुनिया में जो महामारी पैदा हुई है इसमें हम सब मिलकर के लड़ें । यहां जितने सदस्य हैं हम सब का दुश्मन कोरोना है, बाढ़ है यह जानना चाहिए । यहां कोई पक्ष-विपक्ष नहीं । हम चाहते हैं बिहार को सुरक्षित रखना, मिलजुलकर के काम करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं और इस विपदा की घड़ी में मैं ये मानता हूं कि जितने जन-प्रतिनिधि यहां बैठे हैं वे भी कोरोना योद्धा हैं । अभी कोरोना योद्धा किनके बारे में कहा जाता है डॉक्टर्स के बारे में, नर्सों के बारे में, पुलिसकर्मियों के बारे में, इसेंसियल सर्विस जो करते हैं उनको कोरोना योद्धा बोला जाता है । यानी अपनी जान को हथेली में खेलकर के वह जनता की, देश की सेवा कर रहे हैं । मैं बताना चाहता हूं कि हम जितने जन-प्रतिनिधि हैं, यह हमलोगों की नैतिक जिम्मेदारी है , विपदा की घड़ी में, दुख की घड़ी में, इस महामारी में, इगो को छोड़कर के मिलजुल कर के देश को सुरक्षित बनाने का काम करें, लोगों के दुख-दर्द को बांटने का काम करें, मलहम लगाने का काम करें और इस महामारी से लड़ा ही न जाए बल्कि लड़ाई को जीता जाए यह मैं कहना चाहता हूं महोदय । इसमें हम सब जन प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, एम0एल0 हैं सब का योगदान है । कहां मजदूर लोग जहां भी फंसे, हम सब लोगों के पास फोन आता रहा, हमलोगों ने कैसे राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने, हम लोगों ने तो बकायदा कॉल सेंटर चालू किया, बकायदा सेंटर्स लगाएं, जो मजदूर जहां फंसे हुए थे, उनको लगभग राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने डेढ़ लाख मजदूरों को जो है बिहार के बाहर राशन बंटवाने का काम किया । उसमें सहयोग कुछ

निजी संपर्क का भी रहा और कुछ सहयोग जो है वहां की राज्य सरकार का भी रहा और हम देखिए बीजेपी के नेताओं को तो नहीं कहेंगे लेकिन कई जगह भले ही विचारधारा हमारी अलग है लेकिन विपदा की घड़ी में कुछ बीजेपी के कार्यकर्त्ताओं से भी हमने मांग की थी उस राज्य में, उन लोगों ने भी मदद पहुंचाया, तो यह लड़ाई जो है मिलजुल कर के लड़ना है लेकिन महोदय मनोबल कब टूटता है, कब टूटता है डॉक्टर्स हों, नर्स हों, पुलिसकर्मी हों इनका लीडर कौन है बिहार का मुख्यमंत्री है । कौन चलाता है बिहार का मुख्यमंत्री है और जब दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री, जब दूसरे राज्यों में जाकर के विपदा की घड़ी में बाहर निकल कर के लोगों का अरेंजमेंट में, व्यवस्था में कि क्या लड़ाई होगी, क्या लड़ाई की तैयारी होगी, क्या स्वरूप होगा इंतजाम में लोगों की सेवा में जब दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री निकलता है, सेवा करता है तो हम लोगों का बिहार के लोगों का मनोबल टूट जाता है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री अब तो 136 दिन हो गया, आज आए हैं विधानसभा में लेकिन नदारद हैं, हो सकता है कि वो सी0एम0 हाउस में बैठकर के समीक्षा करते रहे हों लेकिन मेरा मानना है कि अगर मुख्यमंत्री बाहर निकलते और लोगों की सेवा करते, इंतजाम करवाते तो जो कोरोना योद्धा हैं उनका भी मनोबल जो है ऊंचा होता , लड़ाई में और तेजी आती और कोरोना को हराते । लेकिन मुख्यमंत्री जी जिक्र करते हैं कि भाई हम तो नियम कानून को मानने वाले लोग हैं हम तो नियम कानून को मानते हैं । बताइए जब कोरोना में लॉकडाउन है, लॉकडाउन है तो हम बाहर कैसे निकलें, अच्छी बात है । आप नियम मानने वाले हैं, हम भी नियम मानने वाले हैं लेकिन जब मेरी आंखों के सामने कोई भूखा मर रहा हो, कोई रोड पर कट रहा हो स्टेट में तो हमारी मानवता इंसानियत जो है वो जागती है कि हमारा फर्ज बनता है कि उनको रोटी और राशन देने का काम करें । उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम करें । यह हमारा दायित्व है महोदय और लॉकडाडन, जो कोरोना योद्धा हैं उसके लिए क्या लॉकडाडन ? तब तो ये हवाला कल को डॉक्टर बोलेंगे कि हमको भी नियम कायदा मानना है, लॉकडाउन का पालन करना है तब कैसे चलेगा देश, तब देश कैसे सुरक्षित होगा । तब पुलिस वाले बोलेंगे हम तो नहीं निकलेंगे रोड पर । मैं यह कहना चाह रहा हूं स्पष्ट रूप से भले ही मुख्यमंत्री अधिकारियों के कहने पर दिशा-निर्देश देते रहे हों लेकिन इतनी कन्फ्यूज सरकार और कोई राज्य में इस कार्यकाल में हम लोगों ने नहीं देखा । महोदय, हमारे पास ये टाइम लाइन है, लगातार इस विपदा की घड़ी में राष्ट्रीय जनता दल ये टाइम लाइन लगातार 13 मार्च से महोदय सरकार को सजेशन सुझाव देती रही है प्रोडक्टिव, महोदय सुझाव देने के काम को पोजेटिव रूप से, सकारात्मक रूप से हम लोगों ने सुझाव दिया कि भाई इन चीजों पर अमल करना चाहिए । रिजल्ट ऑरियेन्टेड सुझाव हम लोगों ने देने काम

किया। चाहे वह ट्रेन की बात हो, देने में सहयोग की बात हो, आर्थिक रूप से हो या बस की बात हो, मजदूरों को वापस लाने की बात हो, पूरी तरीके से हमलोगों ने यह मेरा पूरा आंकड़ा है, सबूत के साथ हम बोल रहे हैं, हमलोगों ने लगातार जो है हमारे पार्टी कार्यालय ने प्रदेश अध्यक्ष जगदा जी ने तो यह भी कहा कि हमारी पार्टी का दफ्तर भी ले लीजिए कोरोना में, क्वांरटाइन सेंटर बनाइए, आइसोलेशन सेंटर बनाइए लेकिन हम लोगों को अच्छा लगता है कि बीजेपी का जो रिजॉट मुख्यालय हर जिला-जिला बना है, वे लोग भी दे देते हैं क्वांरटाइन में और सरकार लेकर के लोगों की सेवा में लगाती तो जो लोग अस्पताल में भटक रहे हैं, रोड पर छींक रहे हैं, लाशों का ढेर लगा हुआ है तो ये नौबत नहीं आती महोदय । अब देखिए हमारी लगातर जो मांग हम लोग करते रहें हैं कि भाई मजदूरों को जो है आप लाइए, लेकिन दुख है कि पहला ऐसा राज्य है य0पी0 का लोग अपने लोगों को लेकर आ गया, महाराष्ट्र के लोग, गुजरात के लोग अपने लोगों को लेकर आ गया । बस भेजा, झारखंड के लोग तो प्लेन भेजा लेकिन अपने बिहार के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम किसी भी श्रमिक मजदूरों को, श्रमिकों को जो बिहार के ही हैं उनको हम किसी भी कीमत पर बिहार की धरती पर घुसने नहीं देंगे । वहां लोगों को खाने का ठिकाना नहीं, भूख से मर रहे हैं, रहने का ठिकाना नहीं है, मकान मालिक भगा रहा है, फैक्ट्री मालिक काम से निकाल दिया है और बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम तो घुसने नहीं देंगे लेकिन हमने जितने सुझाव दिए एक महीना बाद, दो महीना बाद, तीन महीना बाद, चार महीना बाद, उस सुझाव को मानना ही पड़ा । बस का इंतजाम किया गया, ट्रेन की व्यवस्था कराई गई, मजदूरों को लाया गया, ये सारे सुझाव तो हमलोग लगातार कहते रहें । आखिर उसी बात को मानना पड़ा तो मेरा यह सवाल उठता है कि जो मौजूदा सरकार डबल इंजन की है जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का और इस सरकार का जो नेतृत्व करते हैं उनकी कोई दूरदर्शिता नहीं है महोदय, कोई दूरदर्शिता नहीं है लड़ने की यह हम लोग कहना चाहते हैं महोदय । दुख की बात, दुख की बात तब आती है महोदय जब हमारा मुख्यमंत्री बिहार सरकार की दिल की उपज है मजदूरों के खिलाफ निकल आता है ये चिट्ठी है जिसको हमने प्रेस कांफ्रेंस कर के भी फाड़ा था सुन लीजिए आप सब लोग, आप लोगों को चुनाव में जाना है और बिहार सरकार मुख्यमंत्री क्या चिट्ठी लिखवा रहे हैं पढ़ के हम सुना देते हैं कि पत्रांक दिनांक- 29.5.2020 बिहार पुलिस मुख्यालय विधि व्यवस्था प्रभाग विषय - बिहारी प्रवासी मजदूरों की भारी आमद के कारण गंभीर विधि व्यवस्था की समस्या होने की आशंका के संबंध में , चिट्ठी में लिखा है महोदय, विगत दो माह में बिहार राज्य में भारी संख्या में स्थानीय नागरिकों का आगमन हुआ है और सरकार की कृपा से नहीं, पंद्रह सौ किलोमीटर चलकर, दो हजार

किलोमीटर चल कर कई लोग बेचारे मर गए रोड अक्सीडेंट में मर गए, ट्रेन से कट कर मर गए । आगे सुनिए महोदय, जो अन्य राज्यों में श्रमिक के रूप में कार्यरत थे गंभीर आर्थिक चुनौतियों के कारण वे सभी परेशान एवं तनावग्रस्त थे, यह बिहार सरकार की चिट्ठी है, मान रही है कि सभी गंभीर चुनौतियों के कारण परेशान और तनावग्रस्त थे वह हमारे बिहार के लोग थे ।

..... क्रमशः .....

टर्न-17/शंभु-हेमन्त/03.08.20

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल (क्रमशः): गरीब थे, मजदूर थे, तनावग्रस्त थे क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि उनको लाया जाय, पहुंचाया जाय, अपने राज्य बुलाया जाय । लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री मना कर देते हैं । आगे सुनिये, मान रहे हैं कि तनाव में हैं, तनावग्रस्त हैं, परेशान हैं । सरकार की अथक कोशिशों के बावजूद राज्य के अन्दर सभी को वांछित रोजगार मिलने की संभावनाएं कम हैं । अब श्रवण कुमार जी यहां बैठे हैं, बार-बार इंटरव्यू देते हैं कि हम सब को रोजगार देंगे, सबको रोजगार देंगे । सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि जितने मजदूर हैं उन सबको रोजगार दो । कहां गया रोजगार ? जो आये थे वे फिर जा रहे हैं । हरियाणा की बस, पंजाब की बस वापस ले जा रही हैं । ये स्थिति बनी हुई है । आगे सुनिये । सरकार मान रही है कि वह सभी वांछितों को रोजगार नहीं दे सकती। ये तो चिट्ठी है । लिखतम के आगे वक्तम काम नहीं करता । ये जो ऊंची-ऊंची एड़ी करके भाषण दे रहे हैं इससे कुछ नहीं होता । भाषण नहीं राशन और काम चाहिए । आगे सुनिये इस कारण स्वयं एवं अपने परिवार का भरण-पोषण करने के उद्देश्य से ये अनैतिक एवं विधि विरुद्ध गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं । अपने भाई को, गरीबों को आप चोर कह रहे हैं, अपराधी कह रहे हैं । इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती, महोदय । इनको आप अपराधी, चोर कह रहे हैं । लगभग 40 लाख की संख्या में । 40 लाख की अगर हम लोगों की पांच से तुलना भी कर लें तो कितने करोड़ों में संख्या हो जाती है लोगों की । उनके परिवार भूखे मर रहे हैं, बिना अपराध के मर रहे हैं । अपने बेटे के, पिता के, पति के इंतजार में है कि आयेगा तो कुछ मिलेगा । ये बिहार के लोग और वो भी अपनी ही सरकार कह रही है कि चोर हो, अपराधी हो, गुंडे हो । तो ये परिस्थिति किसने पैदा की, किसलिए पैदा हुई ? किसलिए होती है सरकार, किसलिए होता है नेता, किसलिए होता है मंत्री, किसलिए होता है अधिकारी ? हम सब लोग सेवक और हम लोग भाग रहे हैं । उन लोगों को चोर बोल रहे हैं । आप लोग उसी महान

जनता को चोर बोल रहे हैं जिसने चुनकर आप लोगों को यहां भेजा है । शर्म नहीं आयी आप लोगों को, सरकार को शर्म नहीं आयी, लज्जा नहीं आयी । महोदय, माफी तक नहीं मांगी गयी । माफी मांगने से क्या होता है । जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है वही तो माफी मांगता है और जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती वह तो रेंगता है । कम से कम माफी तो मांग लेते । किसी ने भी सामने आकर के माफी नहीं मांगी । आगे सुनिये । इस विधि-व्यवस्था की स्थिति का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है । यह समस्या सीमित क्षेत्र में अथवा व्यापक पैमाने पर उत्पन्न हो सकती है । इस परिस्थिति का सामना करने के लिए अनुरोध है कि स्थानीय परिदृश्य को देखते हुए कार्य योजना तैयार कर ली जाय ताकि आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जा सके । कौन सी आवश्यकता ? लाठी मारने की आवश्यकता ? एक तो चोर कह रहे हो, बेईमान कह रहे हो, खाना नहीं दे रहे हो, ला नहीं रहे हो। लोग मर रहे हैं, भूखे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हो और कहते हो कि चोरी करेगा। ये स्थिति किसने उत्पन्न की और ऊपर से कितना क्राइम बढ़ गया, कितना बढ़ गया ? बढ़ा कि नहीं बढ़ा ? क्या है आपका स्पष्ट बताओ न भाई । हम लोग तो जानना चाहते हैं और आप लोग लाठी पिटवा रहे हैं । बेचारे ठेले वाले पर लाठी, जो मजदूर आया उस पर लाठी । आपकी क्या व्यवस्था थी ? सबने वीडियो देखी होगी । जो सरकार में सब विधायक लोग हैं दिल पर हाथ रखकर कहिये गांव में लोग घुसने देते थे ? बोलने देते थे ? मानवता के लिए, इंसानियत के लिए थोड़ा सोचिए । महोदय, क्या-क्या वीडियो हम लोगों ने नहीं देखी । न बस है, न बस में सोशल डिस्टेंसिंग, न पहुंचाना, न क्वारंटाइन कराना और क्या कहा गया था कि पैसा देंगे-पैसा देंगे । ट्रेन का पैसा नहीं दिया, रोडवेज का पैसा नहीं दिया । ट्रेन का पैसा नहीं मिला, क्वारंटाइन के बाद पैसा देंगे । हम लोगों की मांग थी कि दस-दस हजार रुपये लोगों को दो । रोजगार दो, अब तो सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर आ गये । बिहार सरकार का आंकड़ा लगभग 40 लाख मजदूर हैं, जो बिहार आये हैं और ये ही सरकार ठप्पा लगा रही है कि हमने पलायन रोक दिया है । कहां आपके 15 साल में पलायन रुका भाई, कहां पलायन रुका ? जाकर किस हिसाब से वोट मांगेंगे ? ठीक है, हां ये लोग बातों के बल पर, अफवाह फैला कर के लोगों को इधर से उधर करना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं । लेकिन यह सही नहीं है । इसलिए सही नहीं है कि क्या वाकई में जिन लोगों ने हमको चुनकर भेजा है वह आज सड़क पर हैं, भूखे हैं, नंगे हैं । कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है । लोग बाढ़ से मर रहे हैं । घरबार छिन गया, मवेशी छिन गये, सबकुछ छिन गया । जरा सोचिये, क्या इंसानियत के नाते सरकार को, मुख्यमंत्री जी को नहीं आना

चाहिए ? जाकर मुआयना नहीं करना चाहिए ? जब मुख्यमंत्री निकलते हैं तो किसी की हिम्मत है कि रोड पर कोई और गाड़ी आ जाय। वैसी व्यवस्था बना कर निकलिये । हम लोग तो 90 दिन चिल्लाये कि 100 दिन हो जायेंगे तो हम लोग ढिंढोरा पिटवायेंगे । तो मधुबनी गये दिखावे के लिए वहां भी पूरा पर्दा लगा कर चले गये । अपने ही विकास पर शर्मा गये ? क्या था पर्दे के पीछे, क्या था पर्दे के पीछे ? जानना चाहते हैं, बिहार की जनता जानना चाहती है । 15 साल तक मौका दिया । किसलिए मौका दिया ? क्या काम किया आपने ? आंकड़े बताएं ? महोदय, हम चाहते हैं कि कोरोना की लड़ाई लड़ने से पहले बिहार में इनकी 15 साल की स्थिति को जानिये । अस्पतालों की, चिकित्सा की क्या व्यवस्था है ? माननीय सदस्यों को पता होना चाहिए और इस सदन के माध्यम से हम बिहार की जनता को कहना चाहते हैं । महोदय, मैं जो आंकड़ा रखना चाहता हूं, ये आंकड़ा NHRM का है, ये आंकड़ा नीति आयोग का है, ये आंकड़ा यूनिसेफ का है, ये मेरा नहीं है, नीति आयोग का है । थोड़ा सुनिये । अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिये । बहुत तारीफ कर रहे थे, इतना बजट हो गया है, इतना खर्च करेंगे, पैसा ले रहे हैं, सुनिये जरा । 2005 में कुल 101 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे । आज 15 साल में महज 49 नये केंद्र स्थापित किये गये हैं । मतलब प्रति वर्ष सिर्फ 3 केंद्र की स्थापना की गयी है । पिछले 2 साल में कोई भी नये स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना नहीं की गयी है । 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में चालू स्वास्थ्य केंद्र एचसीएस, सीएचसीएस की कुल संख्या 12086 थी, जोकि 2019 में घटकर 11958 हो गयी है । मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, शिशु मृत्यु दर 38000 में से 38 है, जोकि राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है । पांच साल में कम उम्र के बच्चों में Stunting और अंडर वेट का प्रतिशत 42 फीसदी है जो पूरे देश में सबसे ज्यादा और खराब है । जो शून्य से लेकर चार वर्ष तक के बच्चों का एज ग्रुप है उसमें 40 प्रतिशत बच्चों के खून में आयरन की कमी है । पूरे देश में मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत बिहार में है । यह हम नहीं कह रहे हैं, बिहार में नीति आयोग कह रहा है । अब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तय मानक है सेंटर पर थाऊजेंड पोपुलेशन आबादी स्वास्थ्य केंद्र पर बिहार आखिरी पायदान पर है डॉक्टर मरीज अनुपात में यानी जो मानक है उसके अनुसार बिहार में एक हजार पर एक डॉक्टर चाहिए । आपको पता है बिहार में कितना है ? 3207 लोगों पर एक डॉक्टर है, ये एक हजार पर एक होना चाहिए । बहुत शर्म की बात है । यह तो शहर का है, ग्रामीण इलाकों की तो और भी स्थिति खराब है । ग्रामीण इलाकों में 17685 लोगों पर एक डॉक्टर है । ये व्यवस्था है आपकी । महोदय, फार्मासिस्ट जो

पद है, वह 2049 रिक्वायरमेंट है और जो वेकेंट है 1762 है । अब 86 प्रतिशत ही वेकेंट है, खाली है पद, सुन लीजिए । स्पेशलिस्ट सीएचसी 600 रिक्वायरमेंट है तो 518 खाली है, 86.3 खाली है । रेडियोग्राफर 150, रिक्वायरमेंट 149 है । यानी 99.3 खाली है । लेबोरेट्री टेक्नीशियन, रिक्वायरमेंट है 2049 और 1438 खाली है यानि 70.1 फीसदी खाली है । नर्सिंग स्टाफ, रिक्वायरमेंट है 2049 और 1319 खाली है यानि 44.7 परसेंट खाली है । (क्रमशः)

टर्न-18/ज्योति-पुलकित/03.08.2020

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल (क्रमशः) : ये व्यवस्था है आपकी, इसी के लिए विकास पुरूष ? इसलिए वो तो तब, जब डबल इंजन की सरकार हो केन्द्र में यहां-वहां, यहां विशेष पैकेज डबल इंजन यही ना ? अब सुनिए, मेरा नहीं है, आप ही लोगों का नीति आयोग है न ? सुनिये कोई नहीं डिस्टर्ब - हम तो आंकड़ा पर बोल रहे हैं हम अपनी बात पर नहीं बोल रहे । एन.एच.आर.एम द्वारा जारी रिपोर्ट कार्ड में पिछले 15 साल में बिहार का सबसे खराब प्रदर्शन रहा, ये केन्द्र सरकार की रिपोर्ट है महोदय, एन.एच.आर.एम की रिपोर्ट है महोदय, क्या रिपोर्ट है कि 15 साल में बिहार का सबसे खराब प्रदर्शन रहा, बिहार को जो राशि आवंटित हुई उसका आधा भी खर्च नहीं कर पाए और कर्ज लेने की बात करते हैं, कर्ज लेंगे क्या बात है ? कुपोषण सबसे ज्यादा बिहार में है, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का रहा है, ये तो प्रधानमंत्री का स्पेशल है स्कीम, इसमें बिहार सबसे पीछे रहा आयुष्मान भारत में, सबसे खराब प्रदर्शन यानी भारत सरकार कह रही है, सबसे खराब प्रदर्शन सुनिये आगे बिहार का रहा है जिसकी वजह से केन्द्र सरकार ने एक भी पैसा इस साल आवंटित नहीं किया, 2019 की रिपोर्ट है, केन्द्र सरकार पैसा नहीं दे रही है बिहार सरकार को ये कह के कि सबसे खराब प्रदर्शन है, पैसा ही खर्च नहीं करते हो तो हम क्या दें तुमको पैसा, ये है रिपोर्ट, स्वास्थ्य पर पर-कैपिटा खर्च सबसे कम बिहार में ही है। प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती सबसे अधिक मरीज बिहार के ही हैं अगर बिहार में सबसे ज्यादा पेशेंट प्राइवेट में जाने लग जाए तो आप समझ जाइए कि आपका पूरा सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो चुका है, कोलैप्स कर चुका है सब प्राइवेट में जा रहा है, इलाज करा रहा हैं, मानते हैं कि नहीं इस बात को कि आपके क्षेत्र में ज्यादा जाता है कि नहीं प्राइवेट में तो ये बताया जा रहा है ओवर ऑल परफॉर्मेंस में बिहार ने सुधार की जगह गिरावट दर्ज की है, ओवर ऑल परफॉर्मेंस स्कोर निचले पायदान पर है । नीति आयोग के अनुसार बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई सुधार

नहीं हुआ कि इनपुट प्रोसेस इंडेक्स मानक में भी बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब है, रहा है और पिछले वर्ष की तुलना में 17.6 घटा है जो कि बहुत शर्मनाक है। बिहार का टीकाकरण हो महोदय, रिपोर्ट देखिएगा तो आप हक्के-बक्के हो जाइएगा, चौंक जाइएगा, और हम हक्के-बक्के इसलिए कह रहे हैं महोदय, चौंक इसलिए जाएंगे लोग कि अभी मंगल पांडे जी कह रहे थे कि केन्द्र की टीम आयी तीन सदस्यों वाली बिहार की तारीफ की है, अब सुनिये बिहार की तारीफ जरा सुनिये पता नहीं मंगल पांडे जी कौन-सी भाषा उनको समझ आती है, ये समझने की जरूरत है हम लोगों को सुनिए वो देख रहे होंगे कहीं से भी महोदय, अंग्रेजी में है तो हम अनुवाद कर सकते हैं, सुन लीजिए, तारीफ की गयी, बिहार की तारीफ सुननी चाहिए और आपकी सरकार की तारीफ हो रही, सुनिये Members were aghast मतलब भयावह हक्का-बक्का हो गए, जितने मेम्बर थे भयावह स्थिति देखकर, What they saw in Patna as they visited multiple hospital जब आये देखें बहुत सारे अस्पताल तो हक्के-बक्के हो गए, Including bodies of covid-19 patients lying unattended on beds and in corridors. आये तो देखे तो अस्पताल में देखे तो भाई अस्पताल में लाशें जो बेड पर पड़ी हैं, कोरीडॉर में पड़ी हैं, बॉलकोनी में पड़ी हुई हैं, हक्का-बक्का हो गए भाई ये कोविड-19 का पेसेंट है महामारी, जो चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं आगे सुनिए with attendants of the patients यानी उसके जो रिश्तेदार थे moving in around the Covid-19 wards without any restrictions तो उनके परिजन थे वो अंदर बाहर घुस करके बेचैन थे, बुला रहे थे, पुकार रहे थे, चीख रहे थे लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था, दूसरा सुनिए The Doctors are not going near the covid-19 patients बिहार के डॉक्टर कोविड-19 पेशेंट्स के पास नहीं जा रहे हैं, ये मेरा नहीं कहना है यह जो टीम आई थी, रिपोर्ट तीन सदस्यों की टीम वो कह रही हैं, क्यूं नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको पी.पी.ई. किट उपलब्ध नहीं कराए, शर्मनाक और ये भी कह रहे थे सुशील मोदी जी कोविड-19 के लिए भी हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, कितने हजार करोड़ रूपये ये किसके पास जा रहे हैं ये तो आपकी भारत सरकार कर रही है, और स्वास्थ्य मंत्री राज्य के बिहार के ही हैं । बात अब सुनिए आगे As the whole system has broken down अब इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है पूरा सिस्टम ही टूट गया, फट गया । And the Doctors fear if they

get infected no one will take care of them यानी डॉक्टर इसलिए नहीं जा रहे है कि पी.पी.ई किट नहीं है अगर हम चले जाएंगे तो हमको ही हो जाएगा तो इलाज कौन करेगा डॉक्टर का, इस वजह से नहीं । ये केन्द्र की रिपोर्ट है As per Union government sources the Bihar Government is just not spending money on fighting covid-19 मतलब केन्द्र सरकार कह रही है कि बिहार सरकार कोविड–19 में कोरोना के लिए पैसा ही खर्च नहीं कर रही है । अरे भाई, अद्भुत है डबल इंजन की सरकार, उसी की सरकार और कह रही है कि पैसा ही खर्च नहीं कर रही है और हमको आश्चर्य है कि पैसा नहीं खर्च कर रही तो आप तो केन्द्र के तो आप लोग क्यों नहीं करवा दे रहे हो भाई, डॉयरेक्ट यानी आप इंतजार में हो कोई नहीं करेगा तो केन्द्र सरकार सोती रहेगी, लोग मरते रहेंगे । महोदय, थोड़ा देखिए हमेशा सहयोग करते रहे हैं ।

अध्यक्ष : अब आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, थोड़ा बढ़ा दिया जाए बहुत ही गंभीर एक घंटा, दो घंटा भी कम लगता है, अभी तो शुरू ही किये हैं महोदय, They are not purchasing rapid antigen kits. The Centrel government recently gave 10 thousands such kits for free to The Bihar Government, but the require at least for 4 lakhs such kits. यानी भारत सरकार ने 10,000 खाली किट दिया है । बिहार की आबादी 12–13 करोड़ और केन्द्र सरकार दे रही है 10,000 वो भी राज्य सरकार नहीं खरीद रही, फ्री में दे रही है 10,000 कीट और राज्य सरकार कोई भी एंटीजन किट जो है लगभग चार लाख की जरुरत है तो वो खरीद नहीं रही है । ''How can they do of mass testing." तो हम लोग लगातार कह रहे है ट्रेस करना पड़ेगा बीमारी को, आंकड़ा जो है, संख्या जो है वो बढ़ाने की जरुरत है, ट्रेस कीजिए चेन को तोड़ना है और लॉकडाउन का जो महोदय, पीरियड होता है । लोग सोचते हैं कि कोराना आएगा, कोरोना चला जाएगा, लॉकडाउन ही उपाय है ठीक है लेकिन Lockdown as a pause button काम करता है । आपको समय देता है अपनी कमियों को दूर करने का और अपनी तैयारी करने का और हॉफ ऑफ द प्रीप्रेशन यानी आधी लड़ाई आप जीत गए, हमारी तैयारी अगर हो गई तो आधी लड़ाई जो है हम जीत गए, समझिये । अगर फुल प्रीप्रेशन हमारा पूरा हो गया तो आपकी आधी लड़ाई हम जीत गए, यह समझिये महोदय, तो यहां कोई तैयारी ही नहीं की गई, चार महीने हो गए, 16 मार्च

को हम लोगों ने पिछला सत्र जो है वो बंद किया था और मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे मास्क मत लगाइए, मास्क मत लगाइए, जो बेचारा बांट रहा था उसको भी डांट फटकार दिये । इसलिए कहते हैं दूरदर्शिता की कमी, हम शुरू दिन से कह रहे है कि मास्क बांटो, सेनेटाइज करो लेकिन मेरी बात कोई नहीं मानता, ऐसे चलेगा क्या, हम तो आपको सहयोग करना चाह रहे हैं भाई, आप कह रहे है कि बंद करो पॉलिटिकल एक्टिवीटी, हम पॉलिटिकल बंद कर दिए यानी आगे का रिपोर्ट महोदय, सुनिये In such a difficult time ये इम्पोर्टेंट हैं, लोगों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, In such a difficult time files related to appointment of 4 thousands doctors and 6 thousands nursing staff are shuttling between the minister and secretary of state health departments for months. इसका मतलब है कि कई महीनों से एक तो डॉक्टर की ऐसी कमी है, हम तो बता दिये भाई 3200 शहर का है, 3200 पर एक डॉक्टर है और 17,000 पर ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर है, एक तो ऐसे ही कमी है रिक्त पद है डॉक्टर का, नर्स का । डॉक्टर का चार हजार और नर्स का छह हजार वो खाली है, केन्द्र सरकार कहती है नियुक्ति ही नहीं की जा रही है, पद जो है भरा ही नहीं जा रहा, क्योंकि मंत्री से लेकर के सेक्रेटरी तक फाईल जो है वो घूम रही है ऊपर-नीचे, नीचे ऊपर ।

(क्रमशः)

टर्न-19/राजेश-मुकुल/03.08.2020

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल (क्रमशः): इस तरह से कैसे लड़ेंगे आप कोरोना से, केवल भाषण से या वर्चुअल रैली से । अब तो बीजेपी कार्यालय में भी लोग पाये गये हैं, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री जी जो हैं, वे भी पाये गये हैं तो कर लो वर्चुअल रैली । वर्चुअल रैली कीजिए भाई कीजिए, अच्छी बात है । रिस्पोंस तो मिल ही गया होगा, एक लोग, दो लोग, तीन लोग, मतलब भी जान जाइये कि वर्चुअल रैली क्या है ? हम लोग वर्चुअल और डिजिटल का इस्तेमाल कर रहे हैं कोरोना के लोगों को मदद पहुंचाने की, मजदूर को मदद पहुंचाने की, बाढ़ के लोगों को मदद पहुंचाने की तो ये लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं हमको वोट चाहिए, वोट दे दो, 15 साल, 15 साल, इस पर होगा काम ? शर्म आती है, महोदय, हम क्या-क्या नहीं बोले हैं, अगर सारा डेटा देखियेगा तो सर्च रेट जो है बिहार का, पांच गुना बढ़ चुका है, पांच गुना बढ़ चुका है सर्च रेट, बढ़ने की दर को सर्च रेट कहते हैं महोदय, पांच गुना बढ़ गया, पॉजिटिविटी रेट जो है 12.80 प्रतिशत है, देश में सबसे ज्यादा आपका पॉजिटिविटी रेट है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव

पाये जा रहे हैं बिहार में । सबसे कम टेस्ट होने के बावजूद और आप देखिए नम्बर ऑफ डेथ्स 225 है । आप जुलाई का सिर्फ बोल रहे हैं, इन्क्रिज इन फर्टेलिटी रेट जो है, चार गुना बढ़ गया, डिक्लाइन इन रिकवरी रेट यानी 11.50 जो है, वह आपका डिक्लाइन हो गया रिकवरी रेट । हम तो कह रहे हैं कि जैसे आप संख्या बढ़ाइयेगा वैसे आपका रिकवरी रेट कम होगा । अब हमको एक चीज बताइये कि बिहार सरकार बोलती है कि बिहार के लोग रिकवर कर रहे हैं । बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, बोलती है न ? अब ये आंकड़े कह रहे हैं कि यानी टेस्ट की संख्या बढ़ाई गई, तो पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ गया, मृत्यु दर भी इन्क्रिज हो गयी और रिकवरी रेट में भी डिक्लाइन आया है । हम तो शुरू से ही बोल रहे हैं कि जिस दिन 1 लाख पर आइये, पता चल जायेगा महोदय, दिक्कत क्या है कि ये लोग जो डाटा को मैनूपुलेट कर रहे हैं, अब देखियेगा स्वास्थ्य मंत्री जी आये हैं, उनका स्वागत है, बड़े भाई हैं, हम इनको पूरा सहयोग करेंगे महोदय, श्री मंगल पाण्डेय जी आये हैं, मुख्यमंत्री जी सुन रहे होंगे, मैं इनसे पूछना चाहूंगा श्री सुशील कुमार मोदी जी तो भाग गये, श्री सुशील कुमार मोदी जी दिनांक 07.07.2020 को 6 बजकर 25 मिनट पर ट्वीट करते हैं, दूसरी तरफ रोजाना 9 हजार से ज्यादा सैम्पल लिये जा रहे हैं और श्री सुशील कुमार मोदी जी कह रहे हैं कि 9 हजार सैम्पल लिये जा रहे हैं और आप देखियेगा कि जो आंकड़ा सामने आया है उसके बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि 7 जुलाई, 2020 को उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि 9 हजार से ज्यादा सैम्पल की रोजाना जांच हो रही है, जबकि उसी दिन बिहार सरकार के अधिकारी प्रेस रिलीज जारी करके कहते हैं कि 5,168 जांच होने की पुष्टि की गई थी । तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम किसका आंकड़ा सही मानें, स्वास्थ्य विभाग का मानें, डिप्टी सी.एम. का मानें या केन्द्र सरकार का मानें ? आप देखिये, मैं आपको एक आंकड़े का एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि आंकड़ों की हेरा-फेरी कैसे हुई है । दिनांक 31.07.2020 को जारी कोविड बुलेटिन में कुल एक्टीव केसेज की संख्या 50,987 है, दिनांक 01.08.2020 को जारी कोविड बुलेटिन में कुल एक्टिव पॉजिटिव केसेज जो हैं, उसकी संख्या 54,508 है यानी दिनांक 31.07.2020 को जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें 50,987 केस और दिनांक 01.08.2020 को जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें 54,508 केस है यानी 24 घंटे में नये मरीजों की संख्या 3521 की आई लेकिन इसको बताया गया 2502 । मेरे एम.एल.ए. और एम. एल.सी. जब जांच करवाने गये हैं उनका 20 दिनों से रिपोर्ट ही नहीं आ रही है और अद्भुत तो तब लगता है मान लीजिये मंगल पाण्डेय जी, अभी तक अपना

टेस्ट ही नहीं करवाये हैं, उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आयेगी, बिहार के कई जिलों में ऐसा हुआ है, जिसने अपना टेस्ट ही नहीं करवाया, उसकी भी रिपोर्ट कैसे आ सकती है, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि मेरी रिपोर्ट नेता प्रतिपक्ष को कहां से मिली है ? ये झूठ बोल रहे हैं । मेरी रिपोर्ट नेता प्रतिपक्ष को कहां से मिली है, जरा ये इसके बारे में हमें बतायें ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी की रिपोर्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूं ।

अध्यक्ष: मंत्री जी, जब आपके बोलने का समय आयेगा तब आप बोलियेगा ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने मेरी रिपोर्ट के बारे में अभी बोला है कि मंगल पाण्डेय जी की रिपोर्ट आई है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, मैंने एक उदाहरण दिया है ।

अध्यक्ष: माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आप अपना जवाब बाद में दीजियेगा ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, नेता विरोधी दल ने गलत उदाहरण दिया है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने कोविड टेस्ट नहीं करवाया और उसकी रिपोर्ट आ गई, मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर रिपोर्ट कैसे आ गई ? आप यह बात भी नहीं समझ पा रहे हैं । हम किसको समझाएं, किसको सुझाव दें ? इनको यहां पर बैठे-बैठे इतनी मामूली बात समझ में नहीं आई, सब लोगों को समझ में आ गया लेकिन केवल इनको नहीं समझ में आया, ये टिक-टॉक देखेंगे, तो यही न होगा अध्यक्ष महोदय, 1 जुलाई, 2020 को बिहार का कोरोना टेबल में 13वां स्थान था और वहीं 1 अगस्त, 2020 को 7वां स्थान हो गया, जिस प्रकार का संक्रमण फैला, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट राष्ट्रीय औसत से ज्यादा इस महीने के आखिरी तक बिहार टॉप थ्री तक पहुंच जायेगा, हम तो कह रहे हैं कि बिहार की स्थिति बड़ी भयावह बनी हुई है ।

अध्यक्ष: आपका 40 मिनट का समय पूरा हो गया ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, मैं अभी तो बाढ़ के विषय पर बोला ही नहीं हूं । अभी मैं दो-चार आंकड़े देना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, यह आखिरी सत्र है और यह इस कार्यकाल का आखिरी सत्र है ।

अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, आप तो शुरू से ही आसन को सहयोग करते रहे हैं, अब 5-7 मिनट में आप अपनी बात समाप्त कर दीजिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय, अब समय क्यों घटाया जाये, जिसको कोरोना होना होगा उसको तो हो ही जायेगा । आप 1–2 घंटा समय बढ़ा दें ताकि बिहार का भला तो हो जाये, उद्धार हो जाये । अब तो बहुत से लोग अंदर–बाहर कर लिये हैं और जांच में जिसको कोरोना होना होगा, उसको होगा । ये लोग जांच में रेपिड एन्टीजेन टेस्ट कर रहे हैं । रेपिड एन्टीजेन टेस्ट का जो एक्यूरेसी रेट है, वह ऑथेंटीक नहीं है । किसका ऑथेंटीक है तो आर.टी.–पी.सी.आर. का है और ये लोग आज बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि 30,000 और 35,000 टेस्ट हो रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि उस टेस्ट का क्या मतलब है जब उसकी रिपोर्ट ही ऑथेंटीक नहीं आती है । आपने आर.टी.–पी.सी.आर. टेस्ट कितने करवाये हैं इसके बारे में बतायें, केन्द्रीय टीम भी तो सलाह दी थी कि आर.टी.–पी.सी.आर. टेस्ट होना चाहिए । ये देखिए श्री लव अग्रवाल जी का सुझाव, उन्होंने क्या–क्या कहा है, हमने उसका अनुवाद कर दिया है और बाद में रिकॉर्डिंग में सुन लीजियेगा, आपके काम आयेगा । महोदय, स्थिति जो है वह बहुत ही भयावह है । महोदय, बिहार पहला राज्य है कि जहां स्वास्थ्य विभाग में तीसरा प्रधान सचिव मिला है, कोई राज्य है क्या जहां पर प्रधान सचिव भी शायद बदला गया हो ? मतलब चेहरे पर धूल है और आईना बदलते जा रहे हैं, यही बात हो गई, बताइये ये स्थिति बनी हुई है महोदय और हम तो ज्यादा कुछ टेस्टिंग वगैरह के बारे में नहीं कहेंगे लेकिन आप से इतना जरूर हम चाहेंगे कि सबसे छोटे सदस्य हैं पूरे हाउस के और लगातार हम लोगों के ऊपर कटाक्ष किया जाता है और हम तो भाग्यशाली हैं कि श्री सुशील कुमार मोदी जी जैसे अनुभवी नेता जो हैं, हमसे बुजुर्ग जो हैं, वह हम पर कटाक्ष करते हैं, हम तो भाग्यशाली हैं कि वह हम पर कटाक्ष करते हैं लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा आचरण देखना चाहिए । कुछ लोग तो डायरेक्ट कहते हैं लेकिन कुछ लोग जो हैं वह कहलवा देते हैं लेकिन सबसे छोटे हम हैं और हमारा तो सब लोगों के प्रति सम्मान है लेकिन ये सरकार में बैठे हुए लोग क्या बोलेंगे जब 15 साल में इनकी कुछ उपलब्धि ही नहीं रही, कोई एचीवमेंट ही नहीं है और कोई सकारात्मक काम ही नहीं किया हो, तो ये लोग हम पर ही न कटाक्ष करेंगे, हम तो क्रिटीशिज्म से भागते नहीं हैं, हम तो अपनाते हैं लेकिन हां जनता के हित में हो, पॉजिटिव हो और सकारात्मक हो, हम यह चाहते हैं । महोदय, हम देखेंगे कि ये लोग भूत काल और पास्ट की बात करते हैं और हम भविष्य या फ्यूचर की बात करना चाहते हैं लेकिन उन लोगों को इतिहास के बासी पन्ने जो हैं वह उनको मुबारक हो, ज्यादा कुछ नहीं उथल–पुथल, उल्टा–पुल्टा लोग बोलते रहे हैं लेकिन अब समय आ गया है कि हम लोग मिलकर सकारात्मक

राजनीति करें, विकास के प्रति हम लोग सोचें, गुड एजुकेशन सिस्टम बनायें और बेहतर अस्पताल बनायें, ये होना चाहिए । भगवान ने तो हमको सब कुछ दिया, हमसे भाग्यशाली कौन हो सकता है जिसके माता-पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे हों और हमारी कोई चाह भी नहीं है, हम नेता प्रतिपक्ष भी बन गये, डिप्टी सी.एम. भी बन गये और हमारे मुख्यमंत्री जी की कृपा से हम लीडर ऑफ अपॉजिशन भी हो गये यानी यह पांच साल का कार्यकाल जो हुआ और हमको जो अनुभव हुआ है, वह लगभग 20 साल का हो गया है । जहां सी.बी.आई. केस हुआ, ई.डी. केस हुआ, आई.टी. केस हुआ, डिप्टी सी.एम. बने, विपक्ष के नेता बने और कई ऐसे जो यहां सदस्य बैठे हैं, उनसे भी हमको सीखने का मौका मिला, तो हम सब लोगों को धन्यवाद भी देंगे ।

टर्न-20/सत्येन्द्र/03.08.20

अध्यक्ष: चलिए, अब कंक्लूड कर दीजिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : कांग्रेस के और माले के लोगों ने भी समय दिया है आपको लिख के दिए हैं थोड़ा पांच-पांच मिनट उनलोगों का मिलेगा तो दस मिनट हो जाएगा। लेकिन महोदय हमारी नीति और सिद्धांत में थोड़ा इनलोगों से अंतर है महोदय हम टिकाऊ हैं, लड़ाकू हैं और ये लोग बिकाऊ हैं और डरपोक हैं। महोदय अब क्या-क्या नहीं हम बोलें लेकिन पंद्रह साल में 57 घोटाले हुए, एन. सी.आर.बी में जो है बिहार का अपराध का आंकड़ा जो है 15 सालों में बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है साढ़े चार गुना जो है अपराध बढ़ गया है 2005 से, ये एन.सी.आर.बी मेरे अंडर तो नहीं है 57 घोटाले हुए लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं, किसी पर कुछ नहीं होता है महोदय और हम तो लगातार ये कहते हैं कि सुशांत सिंह का सीबीआई जांच हो तो रामाश्रय कुशवाहा का भी सीबीआई जांच हो। जो मर्डर हुआ था रामाश्रय कुशवाहा मर्डर जो गोपालगंज में हुआ था उसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए । हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं कुछ लोग, यह भी होना चाहिए महोदय अब महोदय ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बाढ़ को लेकर के अगर हम चर्चा करें तो लगभग 14 से 15 जिले जो हैं बाढ़ से प्रभावित हैं, 113 प्रखंड, 1060 पंचायत लगभग 54 लाख आबादी इससे प्रभावित हैं बाकी जो घर-बार डूब गया कुछ नहीं है सबलोग जो रोड पर आकर के रहते हैं, हम जा सकते हैं पीड़ितों से मिल सकते हैं । अभी हम मधुबनी गये, दरभंगा गये, चंपारण गये, तिरहुत गये, गोपालगंज की स्थिति आप देख लीजिए, छपरा प्रमंडल देख लीजिए वहां भयावह स्थिति बनी हुई है महोदय लेकिन अभीतक

जो है मुख्यमंत्री हमारे कहने के बाद जो एक हेलिकॉप्टर जाता है, मुख्यमंत्री जी को डर है कोरोना का तो भाई हेलिकॉप्टर तो है न, पायलट है वही बैठ के चल जाते अब तटबंध जो है टूट रहा है चंपारण का, सारण का हो, पुल पुलिया टूट रहा है एप्रोच रोड टूट रहा है, लोगों को खाने की व्यवस्था नहीं कराई गई है और 54 लाख प्रभावित हुए हैं आबादी महोदय, मात्र राहत शिविर 19 लगाया गया है और 1385 कम्युनिटी किचन यानी आप इंतजाम कर सकते हैं केवल 29 हजार लोगों का तो ये कहां से रिकवर करिएगा 54 लाख, ज्यादा से ज्यादा राहत शिविर चलाना चाहिए कटे पुल जो हैं उस पर यातायात कैसे हो तैयार हो उसपर होना चाहिए और हमने मांग भी की थी जितने बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके खाते में डालिए 20-20 हजार रुपया, प्रति व्यक्ति डालिए 20-20 हजार रुपया, पैसा तो आपलोग खर्च ही नहीं कर रहे हैं आखिर जा कहां रहा है पैसा, किसी को समझ में नहीं आ रहा है महोदय इसीलिए लगातार हम यह कहते रहे हैं कि बाढ़ जो है भ्रष्टाचार, मतलब बाढ़ जो है उसको नियंत्रण करना चाहिए था तो ये लोग निमंत्रण दे रहे हैं प्रो-एक्टिव काम करना चाहिए था बाढ़ आ जाएगा तो हाथ पैर हिलाएंगे। अरे भाई पहले आपकी व्यवस्था क्या थी, क्या तैयारी थी, कैंप लगाते, सूखा जगह पर ले जाते, खाने पीने की व्यवस्था कराते, इलाज की व्यवस्था कराते, मवेशी के चारे की व्यवस्था कराते, अभी इतनी बड़ी आबादी जो है दरभंगा हो, मधुबनी हो, शिवहर हो, आपका सीतामढ़ी हो, पूरा चंपारण बेतिया हो, बगहा हो, गोपालगंज हो, छपरा का इलाका हो, मुजफ्फरपुर का इलाका हो और भी छूट गए होंगे लेकिन सबलोग प्रभावित हो रहे हैं महोदय। अब तो गंगा का जलस्तर भी बढ़ रहा है लेकिन आप एक बात जानते हैं आपदा आती है तो कितने लोग को पता है कि बिहार में आपदा मंत्री कौन हैं? कोई नाम भी जानता है या देखा भी है आपदा की घड़ी में, ऐसे तो नहीं देखता है कम से कम आपदा की घड़ी में तो मौका मिल जाता, पता चल जाएगा कितने विधायकों को भी पता नहीं होगा कि आपदा मंत्री कौन हैं ये सच्चाई है, एक भी बैठक में हमने नहीं देखा मुख्यमंत्री जी के साथ, मंगल पांडे जी को धन्यवाद देते हैं कि चार महीने में आप पहली बार गए थे एनएमसीएच, चार महीने बाद आपको याद आया, एनएमसीएच जाना है पी पी ई किट पहनकर के ..

श्री मंगल पांडेय, मंत्री: नेता प्रतिपक्ष को तो अभी तक याद नहीं आया। मुझसे उम्र में बीस साल छोटे होंगे । मैं तो पांच दिन गया पीपीई किट पहनकर, एक दिन आप भी चले गए होते, मरीजों से मिल लिए होते तो अच्छा होता ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः तो आप समझ रहे हैं महोदय, यानी मान लिये कि पांच बार गए तो ताली मारें स्थिति देखे हैं आपके जाने के बाद तो और पोजिटिविटी रेट बढ़ गया।

श्री मंगल पांडेय, मंत्रीः आप तो एक दिन भी नहीं गए। मैं अभी भी कहूंगा कि आप पी0पी0ई0किट पहनकर जा करके मरीज का हालचाल लीजिये।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दलः ठीक है, महोदय चार बार गए। कोई मापदंड है, कितनी बार जाना चाहिए ?

(व्यवधान)

अध्यक्षः बोलिये-बोलिये तेजस्वी जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिये । आपस में बातचीत जैसे कहने का सिलसिला मत करिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः मंगल पांडे जी से मेरी कोई दुश्मनी हो ही नहीं सकती है किसी विषय में लेकिन आज हम यहां नेता प्रतिपक्ष हैं महोदय वे स्वास्थ्य मंत्री हैं बताइए कि हमने कौन सा कटाक्ष किया है । ये तो हमलोगों पर निजी हमला बोलते हैं हमने कौन सा निजी हमला बोला इतनी देर में, कौन सा निजी हमला बोला महोदय, चार बार गए, पांच बार गए, कब गए तब चार महीना बाद गए तो महोदय कंक्लूड करेंगे, दो से चार मिनट ज्यादा हम नहीं लेंगे । महोदय हम आपको बताए कि हमारा जो एक्सपीरिएंस लगभग जो है पांच साल में बीस साल का हो गया हमको तो महोदय हम तो गंगा और गंडक की मिट्टी में पले बढ़े और महोदय माता-पिता ने बिहार की जनता का दर्द बांटना हमको सिखाया । अब वो काम कर रहे हैं, चाहे पीड़ितों के बीच जाना हो या न जाना हो या कुछ गलती भी हुई तो उसको हम सुधारने की कोशिश किए लेकिन बात होती है कि ये लोग गलती मानते ही नहीं हैं । इनलोगों से आजतक पंद्रह साल में कोई गलती हुई ही नहीं है, कोई गलती नहीं हुई, कोई गलती नहीं हुई चाहे बालिका गृह, मुजफ्फरपुर हो या कुछ हो कोई गलती नहीं हो सकता आपलोगों से सृजन घोटाला हो नहीं सकता, गलती हमलोगों से ही हो सकती है है न, हमलोग ही गाली खाएं, ठीक है सीबीआई, ईडी हम पर ही मुकदमा करेगा । ठीक है हमपर कर रहा है या किसी पर परिवार के लोगों पर आपलोग तो कितना 57 घोटाले हुए कितने लोगों पर हुआ, कितने लोगों पर हुआ, कोई आंकड़ा बता दे तो कोई नहीं बता सकता महोदय हालांकि जितना इनलोगों की आलोचना का धार तेज होगा उतनी ही मेरी रफ्तार तेज पकड़ेगी महोदय तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए सारे विषयों को लाए हैं हमलोग लेकिन बाढ़ में पन्नी हो या कुछ हो, कुछ कहां मिलता है। महोदय हम

बस इतना चाहते हैं हमलोगों ने जो भाषण है सरकार का सुना था पिछले सत्र में आपको बताए हैं हम कौन से सत्र में, 16 तारीख को सुने थे हमलोग, मुख्यमंत्री जी विडियो कॉन्फ्रेसिंग भी आप कराए हैं महोदय 40 दिन बाद, 45 दिन बाद । आपको हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप सजग रहे, कंसर्न थे मैटर को लेकर के लेकिन उसके बाद कब हुआ, ऑल पार्टी मीट कब हुई, बुलाना चाहिए था न, विपक्ष जो है सरकार का ही अंग है न और यह तो हम विधानसभा में देखे हैं लिखा हुआ है- विपक्ष जो है वह सरकार का अंग है । सुझाव लेते, राय लेते अगर आप से नहीं संभलता है महोदय तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे लेकिन सिर्फ गोल-गोल उत्तर देने से नहीं होगा । हमारा कोई व्यक्तिगत किसी से नहीं है । ये लोग करते रहें जो करना है लेकिन भैया हम हाथ जोड़कर के नीतीश जी बाहर निकलें और देख लें, हाथ जोड़ते हैं आप बाहर निकलिए बिहार के लोगों को बचाइए महोदय बस हम इतना ही कहकर बात को विराम देते हैं । जय हिन्द-जय बिहार ।

अध्यक्ष: अब श्री मेवालाल चौधरी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: पटल पर हम अपना कुछ डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं ।

(माननीय नेता विरोधी दल द्वारा दिये गये कागजात -परिशिष्ट-2 द्रष्टव्य)

अध्यक्ष: दे दीजिए । नेता प्रतिपक्ष महोदय जो कागजात या अपना लिखित वक्तव्य दे रहे हैं वह कार्यवाही का हिस्सा बनेगा । नेता प्रतिपक्ष करीब 50 मिनट बोल गए हैं जो समय निर्धारित था उसके हिसाब से राजद, कांग्रेस और सीपीआई में, ठीक है अभी तो समय है हम कहां कह रहे हैं । श्री मेवालाल चौधरी ।

टर्न-21/मधुप-संगीता/03.8.2020

श्री मेवालाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया आज कोरोना के बारे में बोलने के लिए । महोदय, हम थोड़ा-सा साईंस की बात कर देते हैं । हमलोग कोविड-19 की बात कर रहे हैं, यह पूरे विश्व का ऐसा वायरस है जो सिंगल स्ट्रैंडर्ड आर0एन0ए0 वायरस है ।

अध्यक्ष : श्री मेवालाल जी, आप 10 मिनट में घड़ी देखकर स्वयं समाप्त कर दीजिएगा और अपना माईक ऑफ कर दीजिएगा ।

श्री मेवालाल चौधरी : तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडर्ड आर0एन0ए0 वायरस है । अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा हाइली म्यूटेट करता है वेरिएशन बहुत जल्दी करता है, जैसे ही एक

इन्वायरनमेंट से दूसरे इन्वायरनमेंट में जाएगा, इसकी वेरिएशन होती रहती है इसलिए इसको हमलोग कहते हैं बड़े हाइली म्यूटेट हैं और सौभाग्यवश जो भी म्यूटेशन हो रहा है अभी तक जो भी वैज्ञानिक रिपोर्ट कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, वह वेरीलेंसी इसमें धीरे-धीरे कम होती जा रही है । अध्यक्ष महोदय, यहां पर एंटीजन और आर0टी0पी0सी0आर0 की बात की गई है । एंटीजन एक क्विक टेस्ट है जो एंटीबॉडी को इंडीकेट करता है कि आदमी के शरीर में उस वायरस का एंटीबॉडी डेवलप हो गया है और आर0टी0पी0सी0आर0 एक बड़ा काम्प्लीकेटेड प्रोसेस है अध्यक्ष महोदय, उसके लिए हमलोग ब्लड का सैंपल लेकर आर0एन0ए0 आइसोलेट करते हैं आर0एन0ए0 आइसोलेट करके प्राइमर डिजाइन करते हैं प्राइमर डिजाइन करने के बाद उसको हमलोग वेरिफाई करते हैं।

महोदय, ये सारी बातें साईंस की हुईं । हम थोड़ी-सी बात करना चाह रहे हैं कि जब ये कोविड-19 पूरे विश्व में महामारी है यह कोई बिहार की बात नहीं है पूरा विश्व इससे तबाह है पूरा विश्व इससे जूझ रहा है पर जो इंतजामात बिहार में किया गया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जरूर इसको सदन के सामने रखना चाहिए ।

(इस अवसर पर माननीय सभापति, श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह ने आसन ग्रहण किया)

महोदय, जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ जितने भी हमारे श्रमिक भाई दूसरे राज्यों में थे, मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, केंद्र सरकार के प्रयास से सभी श्रमिकों को हमलोग बिहार लाए । हम उनके क्वारंटाइन का ब्लॉक स्तर पर इंतजाम किए, शायद पूरे देश का ये पहले मुख्यमंत्री हमारे बिहार के थे जो पूरे क्वारंटाइन सेंटर को विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने से मॉनीटर करते थे । सभापति महोदय, किसी भी राज्य का मुखिया अगर अपने से किसी चीज को मॉनीटर करते हैं तो वैसी चीज में गति आ जाती है और उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है वह अच्छी तरह से हो जाता है। महोदय, इतना ही नहीं जितने भी श्रमिक भाई यहां पर आए उनके लिए इंतजाम उनके खाने का, रहने का इंतजाम जो भी इंतजाम हो सरकार के द्वारा किया गया था ।

महोदय, मुझे याद है नोबेल विजेता प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी ने कहा था कि कोरोना के चलते देश की आबादी का एक बड़े हिस्से के आर्थिक व्यवस्था में खराब स्थिति में आने की संभावना है । वैसी स्थिति में ये अच्छा होगा कि देश की आबादी के एक बड़े हिस्से के हाथों को सीधे पैसा पहुंचाया जाए और मुझे खुशी है सभापति महोदय कि हमारे मुखिया आदरणीय नीतीश बाबू ने यह फैसला लिया

कि जितने भी प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं, हरेक के अकाउंट में हजार-हजार रुपये सीधे उनके एकाउंट में ट्रांसफर किया गया ताकि उनको किसी तरह की परेशानी न हो । महोदय, कोरोना के समय हमारे जितने भी सामाजिक पेंशनधारी थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे, जिनकी छात्रवृत्ति रूक गई थी, जितना फसल क्षति किसान को हुआ था, मुझे खुशी है कि सामाजिक पेंशन, सुरक्षा पेंशन भी उनको दिया गया और सरकार अपने कोष से तकरीबन एक हजार करोड़ से ज्यादा सामाजिक पेंशन में पैसा दी, छात्रवृत्ति के लिए तकरीबन तीन हजार करोड़ पैसा दिया गया और फसल क्षति मुआवजा के लिए तकरीबन 578 करोड़ रुपया भी किसानों को दिया गया चूंकि एग्रीकल्चर एक कन्टीन्यूअस प्रोसेस है सालों भर उसमें काम होता रहता है किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, उनको फसल क्षति का मुआवजा तुरंत उनके एकाउंट में भेज दिया गया । पुनः हमारे नोबल विजेता प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी ने यह भी सुझाव दिया था कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं हो उन्हें राशन कार्ड भी बनवा दिया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला लिया कि ग्रामीण स्तर पर जीविका दीदी के माध्यम से वैसे लोगों को चिन्हित करें जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और उनको राशन कार्ड बनवाया गया । महोदय, तकरीबन 8 लाख 88 हजार राशन कार्डविहीन परिवारों के नए राशन कार्ड बनाये गये जिसके कारण उन्हें राशन मिलने लगा । इसके अलावा हमारे मुखिया आदरणीय नीतीश बाबू ने यह भी फैसला लिया कि जिन आदमी का किसी कारणवश अगर राशन कार्ड नहीं बनता है उन्हें भी राशन दिया जाएगा और उन्हें मुफ्त में राशन दिया जाएगा और उनके साथ उनको एक-एक हजार रूपया की भी सहायता दी जाएगी । महोदय, आज के दिन में अभी तक 1 करोड़ 35 लाख राशन कार्डधारी को बैंक खाते में तकरीबन एक-एक हजार रूपया भेज दिया गया है । मुख्यमंत्री जी ने श्रमिक भाइयों के लिए रोजगार की व्यवस्था की भी योजना बनायी, रोजगार नीति में भी कुछ फैसला लिया गया और उन्होंने कहा कि हम उनलोगों की आवश्यकतानुसार स्किल मैपिंग करेंगे उनकी दक्षता को पहचान करके उनके अनुसार उनको रोजगार प्रोवाइड करेंगे, हमलोग उनको रोजगार भी देंगे और रोजगार सृजन हेतु लगभग 43 लाख 11 हजार योजना के अंतर्गत अबतक सभापति महोदय, 2 करोड़ 52 लाख से ज्यादा मानव दिवस यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर मानव दिवस सृजित किया गया । महोदय, आज अब तक 2 लाख 64 हजार नए जॉब कार्ड बन चुके हैं और अगर इसको देखेंगे अभी तक सरकार अपने कोष से जो खर्च किया है कोरोना से लड़ने हेतु तकरीबन 8 हजार 538 करोड़ और हाल में जो फैसला लिया गया है सब-डिविजन लेवेल पर भी टेस्टिंग की सुविधा हो ताकि

जितने भी कोरोना से ग्रसित और संक्रमित लोग हैं हमलोग उनको ट्रैक कर सकें, हमलोग उनको फौलो कर सकें और एग्जैक्टली हमलोग उनको लोकेट करके उनका अच्छा उपचार कर सकें इससे आने वाले दिनों में हमलोग कोरोना से ही निजात पा सकते हैं । महोदय, हम अपने स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे जो एक प्लाज्मा थेरेपी का कंसेप्ट दिल्ली के माफिक हमलोग बिहार में चालू किए हैं । महोदय, यह क्रॉस प्रोटेक्शन है हमलोग एगेंस्ट एंटी बॉडी एगेंस्ट एंटी बॉडी को बॉडी में डाल रहे हैं और यह क्रॉस प्रोटेक्शन से कोविड-19 को कंट्रोल करने में बहुत हद तक सहायक हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जितने भी कोरोना से पेशेंट ठीक हो जाते हैं जेनरेसली और अपने इच्छानुसार वे डोनेट करेंगे प्लाज्मा ताकि आने वाले भविष्य में जितने को भी कोरोना हो उसका उपचार हो सके ।

महोदय, हम थोड़ी-सी अपने विधानसभा के बारे में आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि तारापुर में एक सब-डिविजन हॉस्पीटल है बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है लेकिन डॉक्टर के अभाव में पेशेंट लोगों को वहां के डॉक्टर भागलपुर रेफर कर देते हैं । हम आपके माध्यम से आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वहां पर कुछ डॉक्टर्स को जल्द से जल्द पोस्टिंग कर दिया जाए । ...क्रमशः...

टर्न-22 आजाद/03.08.2020

.....क्रमशः .....

श्री मेवालाल चौधरी: मेरा दूसरा निवेदन आपके माध्यम से होगा कि तारापुर विधान सभा क्षेत्र में 2 ए.एन.एम. स्कूल की भी स्थापना हो चुकी है, हमलोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि उसका उद्घाटन करेंगे । हम जानते हैं कि आपकी व्यस्तता बहुत है । हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमलोगों का भी सौभाग्य हो, अगर आपके पास समय नहीं हो तो पत्र के माध्यम से जो कंसर्न ऑफिसर हों उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया जाय कि क्षेत्रीय विधायक से भी उसका उद्घाटन कराकर के कार्य शुरू हो । धन्यवाद सभापति महोदय ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, आज आपने मुझे बोलने का अवसर दिया यह षोडश विधान सभा का अंतिम सत्र का आज अंतिम दिन है । सर्वप्रथम मैं आपके

माध्यम से पूरे सदन को और पूरे बिहार को शुभकामना दे रहा हूं कि आज रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार है । महोदय, मेरी पार्टी ने मुझे बाढ़ पर बोलने का अवसर दिया है । बिहार इस बार भीषण बाढ़ कि विभीषिका से जूझ रहा है । एक लंबे अंतराल के बाद अतिवृष्टि और बाढ़ के पानी से बिहार बेहाल और एक तरह से तबाह हो रहा है । लेकिन महोदय मुझे याद है कि अभी नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे कि जब हमारी सरकार थी तो बाढ़ में क्या व्यवस्था सरकार करती थी और इस सदन के अधिकाधिक माननीय सदस्यों को याद होगा कि आदरणीय लालू प्रसाद जी जब इसी बिहार के मुख्यमंत्री थे और बिहार में जब 2003 में बाढ़ आयी थी तो उन्होंने कहा था कि बाढ़ आ गयी है गरीब भाई अब मछली मार-मार के खाइए, अनाज का कोई उपाय नहीं है । आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस समय के बोले थे कि इतना पानी तो हमारा पशु पी जाएगा । बिहार में जो पानी है, वह हमारा पशु पी जाएगा लेकिन बिहार में कोई व्यवस्था बाढ़ की नहीं हुई थी और आज बिहार की सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी, सुशील कुमार मोदी जी एक-एक बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए कम्युनिटी किचन सहित सूखा राशन पहुंचाने का और अन्य सामग्रियों की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि बाढ़ प्रभावित लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो और आज के दिन में बिहार में बाढ़ है इसको बेहतर तरीके से स्वीकार किया जा सकता है लेकिन बिहार की सरकार ने एक बेहतर व्यवस्था के माध्यम से बिहार के सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अतिवृष्टि और जल-जमाव के क्षेत्रों में सरकार के माध्यम से और अन्य माध्यम से भी बेहतर सहयोग कर रही है । इसको कहने में कहीं अतिशयोक्ति नहीं है । महोदय मुझे तो समय कम दिया गया है । मैं आपके माध्यम से सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं । सरकार का जो नौर्म्स है बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ प्रभावितों को, बाढ़ पीड़ितों को सहयोग किया जाएगा । लेकिन इस बार अतिवृष्टि के चलते काफी जल-जमाव हो गया है और जो सरकार के नौर्म्स और नियम हैं, सरकार के द्वारा कहा जाता है कि सात दिनों तक लगातार अगर कहीं पानी जमा रहता है तो उसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाएगा । लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि सात दिनों से अधिक अतिवृष्टि होने के चलते जल-जमाव हो गया है और जिन क्षेत्रों में जल-जमाव हो गया है, लगातार लंबे समय से जल-जमाव हो रहा है बाढ़ पीड़ितों को जिस प्रकार से सहयोग और सहायता दी जा रही है, जल-जमाव वाले क्षेत्रों में भी, जल-जमाव से प्रभावित लोगों को भी सहयोग उसमें दिया जाय । महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसल सहयोग के रूप में फसल क्षति के रूप में धान की फसल की क्षति के लिए तो

किसानों को भुगतान किया जाता है लेकिन इस बार जो उत्तर बिहार का जो मेजर इलाका है चाहे पूर्वी चंपारण हो, पश्चिमी चंपारण हो, गोपालगंज, सीवान, छपरा, समस्तीपुर और अन्य इलाके हों जहां बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती है और इस बार गन्ने की खेती पूरी तरह से प्रभावित है । गन्ने की फसल बर्बाद हो रही है । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि गन्ने की खेती जो बर्बाद हो रही है, गन्ने की फसल जो बर्बाद हो गई है उन किसानों को भी कृषि इनपुट के माध्यम से, फसल सहायता के माध्यम से सहयोग दिया जाए ताकि वह किसान अपने अगले बार की खेती करने में उन्हें सहयोग और सहूलियत मिल सके । महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सरकार को कहना चाहूंगा कि इस बाढ़ के चलते और अतिवृष्टि के चलते गांव में गरीब भाइयों के बीच में कई लोग सर्पदंश के शिकार हो रहे हैं और सर्पदंश के जो शिकार हो रहे हैं न तो उन्हें आपदा प्रबंधन विभाग से कोई राशि दी जा रही है, न उन्हें वन विभाग से कोई राशि दी जा रही है । जबकि वन विभाग ने सर्प को वन्य जीव घोषित किया है और उसमें 5 लाख रुपए उनको आपदा के रूप में या उनको सहयोग के रूप में देने का प्रोविजन किया है तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार सर्पदंश को भी या तो आपदा के माध्यम से वैसे व्यक्तियों को राशि मुहैया कराए या वन्य जीव.....

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: बस एक मिनट में महोदय, या वन्य जीव प्राणी के रूप में उन्हें सहयोग प्रदान करें । महोदय, पूरे बिहार के साथ-साथ हमारे कल्याणपुर विधानसभा और पूर्वी चंपारण जिला में भी बाढ़ की विभीषिका है । मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन और आग्रह करूंगा कि पूरे पूर्वी चंपारण जिले को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाय और सभी किसान भाइयों को जिनका फसल नुकसान हुआ है, जिनके चारे समाप्त हो गए हैं, जिनके मवेशी की क्षति हो गई है उन्हें भी सहयोग राशि दी जाए । आपने मुझे बोलने का समय दिया, सभी भाइयों ने मुझे सुना, इस सदन के माध्यम से पूरे बिहार के भाइयों को बहुत-बहुत धन्यवाद एवं शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): माननीय सदस्य राजू तिवारी, 5 मिनट में आप समाप्त करेंगे।

श्री राजू तिवारी: सभापति महोदय, मुझको बोलने के लिए मौका दिया गया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ।

सभापति महोदय, आज बिहार बाढ़, बारिश और कोरोना से कराह रहा है । एक तरफ हम पूर्वी चंपारण जिले से आते हैं जहां गंडक में नेपाल से भारी बारिश की तबाही हमलोग झेल रहे हैं और हमको लगता है 20 से 25 दिन में लगातार बारिश की वजह से भी जो बांध से इधर हमलोग हैं, उधर भी फसल डूब गया है । बाढ़ के पानी और बारिश के पानी में कोई अंतर नहीं है । महोदय, मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में बाढ़ की विभीषिका जिस समय थी । दुर्भाग्य से गोपालगंज का बांध टूट गया नहीं तो हमलोग के यहां बाढ़ से करीब एक बित्ता पानी ऊपर आ गया था जिसको गांव के नौजवान, मैं धन्यवाद देता हूं अपने क्षेत्र के नौजवानों का जो बोरा के ऊपर बोरा रखकर के और मिट्टी साइड में डालकर के बांध को बचाया । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि ऐसे नौजवानों को भी चिन्हित किया जाए जिन्होंने अपने गांव का बांध बचाया । इस बार बुजुर्ग से पूछने पर पता चला रात-दिन मैं भी उनके साथ बांध में था और बाढ़ के साथ-साथ रोज बारिश हो रही थी । इस भयावह घड़ी में वहां के नौजवानों ने जो काम किया है वह बधाई के पात्र हैं । सरकार से मैं मांग करूंगा कि ऐसे नौजवानों को चिन्हित किया जाए और उनको पुरस्कृत किया जाए, जो इस विषम परिस्थिति में अपने गांव की, अपने क्षेत्र की बांध को बचाने में लगे रहें । मैं रात-रात भर उन लोगों के साथ था, यह देखकर मुझे अपार खुशी हुई कि हमारे क्षेत्र में ऐसे नौजवान हैं जो ऐसी परिस्थिति में बाढ़ से या किसी भी महामारी से मुकाबला कर सकते हैं । बारिश की वजह से भी यही हाल है, फसल तबाह है । अब हमारे साथी बोल रहे थे कि गन्ना की फसल डूब गयी है। हमलोग गन्ना क्षेत्र से आते हैं । गन्ना की फसल लगभग 100 प्रतिशत चौपट हो गयी है । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि ऐसे जो गन्ना किसान हैं, उनको भी कुछ लाभ, कुछ मुआवजा दिया जाय । पूरा मेरा विधान सभा क्षेत्र अरेराज प्रखण्ड, पहाड़पुर प्रखण्ड, संग्रामपुर प्रखण्ड लगभग बारिश और बाढ़ के पानी से डिस्टर्ब है । रही बात कोरोना की तो आज कोरोना हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी कोरोना महामारी में पहले भी चिंता व्यक्त कर चुके हैं । अचानक बिहार में कहां से आयी, कैसे आयी सब लोग जानते हैं लेकिन कोरोना की महामारी अभी बिहार में चरम पर है । मैं सरकार की तारीफ करता हूं । मेरे यहां अनुमंडल अरेराज में पी.पी.ई किट सब कुछ है लेकिन मैं अपने मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि डॉक्टर नहीं निकल रहे हैं ये दुर्भाग्य की बात है । सब कुछ रहते हुए सरकार के डॉक्टर मरीज जिसका चिन्हित हो जा रहा है कोरोना का पेशेंट है वहां जाने से कतरा रहे हैं । मैं आपको बता देना

चाहता हूं कि 20-25 दिन पहले मेरी माँ को कोरोना हुआ था । मंत्री जी दो-दो बार हाल-चाल लिए लेकिन मैं होम क्वारंटाइन करा करके अपनी माँ का इलाज करा रहा था । मंत्री जी तीन-तीन बार फोन किए । मैं धन्यवाद देता हूं इस सदन में मंत्री जी को लेकिन मेरे अरेराज रेफरल अस्पताल में आपके माध्यम से मैं मंत्री जी का शिकायत भी कर रहा हूं कि डॉक्टर को बोला कि एक बार दिन में आ करके ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए थोड़ा लेकिन दुर्भाग्य है कि कोई नहीं आया । मुझे डी. एम. से शिकायत करनी पड़ी । उसके बाद एक असिस्टेंट आया जो लैब टेकनिशियन है वो आया, डॉक्टर नहीं आया ऐसे चिन्हित किया जाए, ऐसे डॉक्टरों को जो सरकार की बदनामी करवा रहे हैं महोदय । केंद्र सरकार के द्वारा हमारे बिहार में कोरोना की महामारी जब शुरू हुई थी तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत अच्छा इंतजाम किए थे मैं चूंकि दो-तीन स्टेट मैं आया-गया हूं, जानता हूं कि सब स्टेट से बेहतर हमारे मुख्यमंत्री जी का था लेकिन कुछ ऐसे पदाधिकारी जरूर हैं जो सरकार की किरकिरी करा रहे हैं, उनको भी चिन्हित करने की आवश्यकता है ।

..... क्रमशः .....

टर्न-23/शंभु-हेमन्त/03.08.20

श्री राजू तिवारी(क्रमशः): जिस समय बाहर से हमारे मजदूर आ रहे थे, उस समय हमारे यहां खाने की व्यवस्था बढ़िया थी । हमारे यहां जहां पर क्वारंटाइन सेंटर था उनके पास बिस्तर था, उनको थाली दी गयी थी, उनको सोने के लिए मच्छरदानी दी गयी थी। सब तरह की व्यवस्था थी ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री राजू तिवारी: महोदय, मैं बस समाप्त करता हूं । बाढ़ की विभीषिका में आपके माध्यम से सरकार को मैं एक-दो चीजों में अपनी राय देना चाहता हूं कि हमारे यहां डुमरिया घाट पुल है । करीब उसमें 20 पाया हैं लेकिन मैंने जाकर वहां स्वयं देखा कि सिर्फ चार-पांच पाया से पानी डिस्चार्ज हो रहा है । वहां पर गाद हो गया कि क्या हो गया मैं नहीं जानता । सरकार उस पर ध्यान दे । पानी का डिस्चार्ज जब तक नहीं होगा तब तक नेपाल से पानी आयेगा । हमारा जिला हो या गोपालगंज जिला हो हमेशा बर्बाद होते रहेंगे । इसलिए सरकार उस पर अपने इंजीनियर के माध्यम से जांच कराये और पानी को डिस्चार्ज जल्दी-जल्दी कराये, जिससे नेपाल से जो पानी हर साल आता है उससे हम लोगों को जो कष्ट होता है उससे हम लोगों

को मुक्ति मिले । महोदय, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): माननीय सदस्य, श्री तारकिशोर प्रसाद दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री तारकिशोर प्रसाद: माननीय सभापति महोदय, कोरोना के इस वैश्विक संकट पर सरकार की ओर से वाद-विवाद में मुझे बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए मैं अपने नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं । ज्ञान भवन में सदन की कार्यवाही यह इस बात को दर्शाती है कि कोरोना के मामले में सरकार और आसन कितना गंभीर है । इसके लिए मैं आसन के प्रति आभार प्रकट करता हूं । मैं सर्वप्रथम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, उपमुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि नेतृत्व वर्ग की ओर से माननीय उपमुख्यमंत्री जी ने बिहार के कई कोरोना पीड़ित साथियों से दूरभाष पर बात करके उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया है । विगत 24 घंटे में सरकार के द्वारा 36 हजार कोरोना सैंपल की जांच की गयी । 6 लाख से अधिक लोगों की जांच हो चुकी है । यह इस बात को दर्शाता है कि सरकार कोरोना के प्रभाव के प्रति कितनी गंभीर है । महोदय, इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने मुकम्मल तैयारी की है । लेकिन जो जमीनी हकीकत है उसमें मेरे कुछ ऐसे सुझाव हैं जिससे मुझे लगता है कि अगर सरकार उन सुझावों को स्वीकार करती है तो बहुत बेहतर व्यवस्था की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं । जो आइसोलेशन केंद्र हैं उसमें प्रत्येक दिन डॉक्टर के द्वारा...

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री तारकिशोर प्रसाद: प्रत्येक मरीज को विजिट किया जाय और मरीज को डॉक्टर का मोबाइल नम्बर भी उपलब्ध कराया जाय अगर उसे किसी प्रकार की परेशानी हो तो सीधे उससे बात कर सके । जो वार्ड है उस वार्ड में डॉक्टर का मोबाइल नम्बर भी स्टीक किया हो जिससे वह सीधे अपने डॉक्टर से बात कर सके ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी ।

श्री तारकिशोर प्रसाद: सभापति महोदय दो मिनट ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री तारकिशोर प्रसाद: एक जो सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है कि अगर किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति का निधन हो जाता है, जहां अभी परंपरागत रूप से दाह संस्कार का स्थल है। जो वहां की आबादी है उसका विरोध कर रही है । उसका निश्चित रूप से निर्धारण हो और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो परंपरागत रूप से लाश जलाने का

काम करते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाय और उसकी राशि का भी निर्धारण किया जाय । कटिहार में जो आइसोलेशन वार्ड हैं उनको बढ़ाने की आवश्यकता है और कटिहार में जो ICU पूर्व से संचालित था वह विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव में बंद हो गया है ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): माननीय सदस्य श्री सिद्दिकी साहब ।

श्री तारकिशोर प्रसाद: मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसको पुन: चालू कराया जाय..

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): कृपया दो मिनट में आप अपनी बात रख लें । सरकार का उत्तर होगा दो मिनट में बात रख लीजिए ।

श्री तारकिशोर प्रसाद: और अंत में सभापति महोदय मैं धन्यवाद देता हूं कटिहार जिला के स्वास्थ्य और जिला प्रशासन को कि पूरे बिहार में.....

(व्यवधान)

श्री अवधेश कुमार सिंह : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): सिद्दिकी साहब ।

श्री अवधेश कुमार सिंह: आप सुन तो लें । कांग्रेस का दस मिनट समय है । कहां दिया है आपने?

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): आपकी तरफ से लिख कर आ गया था कि मेरा समय विरोधी दल के नेता को दे दिया जाय ।

श्री अवधेश कुमार सिंह: किसने लिखकर दिया है ?

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): आपने लिखकर दिया है ।

श्री अवधेश कुमार सिंह: किसने लिखकर दिया है ? ऐसा होता है क्या ?

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): आपके नेता सदानन्द बाबू ने लिखकर दिया है ।

श्री अवधेश कुमार सिंह: नहीं, नहीं । संसदीय कार्य मंत्री से जो मीटिंग हुई थी । उसमें हुआ था कि बात अपनी कहनी है । उसको कहने के लिए हमको मौका चाहिए । समय बढ़ाने की भी बात हुई थी ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): आप बोलिए सिद्दिकी जी ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: सभापति महोदय, आपने मुझे समय देकर बड़ी कृपा की है कि मैं भी बाढ़ और कोरोना की समस्या के बारे में आपका ध्यान और सरकार का ध्यान आकृष्ट कर सकूं । महोदय, हमारे यहां मिथिला में एक बड़ा पोपुलर उसको फिकरा भी कह सकते हैं और एक कहावत मशहूर है । वो कहावत है मैथिली में कि थेथड़ा रे थेथड़ा रे की करै छी, लात जुत्ता खाय छी निक्कै रहै छी । ये हमारे यहां मिथिला में है । महोदय, चूंकि अब लगता है कि हम लोग तो एक तरह से बाढ़ के

आदी हो गये हैं । इस वजह से कि बाढ़ हर साल आनी है । बाढ़ आयी, घर डूबा, आदमी मरा, नाव नहीं है, खाना नहीं है, सड़कें टूटी हैं, लोग छप्पर पर पनाह लिए हुए हैं, सांप के काटने से लोग मर रहे हैं, लोग पानी में डूब कर मर रहे हैं । यह कोई इसी साल का नहीं है । हर साल होना है और विधान सभा में इस पर स्पेशल डिबेट हो जाती है पर अगले साल फिर वही बात । महोदय, मैंने इसीलिए कहा कि हम लोग आदी बन गये हैं । अभी तो ऊपर-नीचे दोनों सरकार हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर कहते रहे हैं और यह बात सही भी है कि इस बार तो वर्षा हुई है जिसकी वजह से नदी में उबाल आ गया । महोदय, मगर हमारे यहां जब नेपाल पानी छोड़ता है तो हमारे यहां बारिश नहीं होने के बावजूद हम लोग बाढ़ पीड़ित हो जाते हैं । जब हम लोग बाढ़ पीड़ित हो जाते हैं तो हर साल चाहे मेरी सरकार हो, आपकी सरकार हो, इनकी सरकार हो, वही रोना । ये निदान कर रहे हैं, ये एक क्विंटल बांट रहे हैं या छः हजार रुपया बांट रहे हैं, मगर जान का कोई मोल नहीं है। जिस महिला को नाव नहीं मिली डिलीवरी के लिए केवटी में, असराहा में वे केले का थम्ब बनाकर हॉस्पिटल जा रही हैं । वे लोग जो खाना खाने को मोहताज हैं । आप कम्युनिटी किचन चलाकर कितने आदमी को खिला पायेंगे ? महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने भी यह मुद्दा उठाया है, हम लोग भी उठाते रहे हैं कि हमारे यहां जो बाढ़ आती है । नेपाल से बैराज के द्वारा जो पानी ऑवर फ्लो किया जाता है या छोड़ा जाता है । जो हम हर साल रोड बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, दूसरा इन्फ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं वह सब नेपाल का पानी लेकर डूब जाता है । अब तो सरकार है केंद्र की और बिहार की भी और हमेशा हमारा जो बना-बनाया ध्वस्त हो जाता है । (क्रमशः)

टर्न-24/ज्योति-पुलकित/03.08.2020

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी (क्रमशः) : हमेशा हमारा जो बना बनाया या जो ध्वस्त हो जाता है उसकी क्षतिपूर्ति ना केन्द्र सरकार करती है और ना कोई दूसरा करता है, महोदय अब मैं बता दूं महोदय, बहुत संक्षेप में कि अभी जो बाढ़ आई है पूर्वी चम्पारण में, पश्चिमी चम्पारण में, गोपालगंज में, सिवान में, सारन में, वैशाली में, मुजफ्फरपुर में, शिवहर में, सीतामढ़ी में, मधुबनी में, दरभंगा में, शिवहर, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, खगड़िया, पूर्णिया, समस्तीपुर, कटिहार आदि । महोदय, अब इसमें जो लोग मर गए और कितने लोग प्रभावित हैं, किस रूप में प्रभावित है, हम नेता प्रतिपक्ष के साथ दरभंगा और मधुबनी, केवटी, सिंघवाड़ा, मधेपुर, मुजफ्फरपुर का एरिया, वैशाली का एरिया अब हम बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि बोलता है मगर

हमारा काम हैं बोलना, हमारा काम हैं आपको आइना दिखाना, हमारा काम है जो कमी है उसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना, हमारा दायित्व है, अब हॉस्पिटल की क्या स्थिति, क्या नई स्थिति अब ये सब हर साल बोलते हैं, मगर इसका वही ढाक के तीन पात हो जाता है महोदय, अब जो महोदय कोरोना और बाढ़ दोनों पर एक ही साथ बहस रख दी गयी । महोदय, यह दुनिया में बीमारी आई है, ठीक बात है मगर क्या है जब भी कि कोई आफत, कोई महामारी आती है देश में तो यह महामारी तो यह आफत न जात देखता है, न धर्म देखता है, न ऊँच देखता है, न नीच देखता है और इसमें ऐसी महामारी में अगर कोई आदमी किसी तरह की राजनीति करता है तो उसको यहां सजा नहीं मिलेगी तो ऊपर जरुर मिलेगी । अब महोदय, मैं कहना नहीं चाहता था बड़ा दुखी मन से कहना पड़ता है। एक टाइम ऐसा आया कोरोना के बारे में कुछ लोगों ने और मोदी मीडिया से लेकर और कुछ संगठन के लोगों ने कहा कि जमात ने फैला दिया । अब कौन-कौन जमात वाले लोगों से कौन-कौन लोग प्रभावित हो रहे हैं। पुजारी भी हो जा रहे हैं, गृह मंत्री जी भी हो जा रहे है और फलाने मंत्री भी हो जा रहे हैं तो जमात को भी हो सकता है, पुजारी को भी हो सकता है हमको भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है इसमें बीमारी या राष्ट्रीय आफत कोई भेदभाव नहीं देखता मगर जो लोग इस तरह का निकृष्टतम काम करते हैं उनको कोई दर्द नहीं है, महामारी खत्म होने से । महोदय, आप भी तो औरंगाबाद के हैं, जो पहला टाइम था लॉकडाउन का महोदय, मैंने सारी तस्वीर संग्रह करके रखी है कि भाई औरतें चल रही हैं रोड पर, रोड पर प्रसव करती हैं और फिर उठकर सात किलोमीटर चल जाती हैं । 12 साल की बच्ची करीब 1400 किलोमीटर चलकर आती है, डेस्टीनेशन प्वाइंट पर पहुंचना होता है 19 किलोमीटर पहुंचना है मर जाती है । बेगूसराय का आदमी आता है दिल्ली से बनारस में दम तोड़ देता है तो लोग सफर में मर गये किस तरह से मर गये यह आपसे छुपा हुआ नहीं है । महोदय, अब मैं इतना ही कहूँगा कि जो कोरोना है इसका फैलाव होगा और इसका फैलाव जब होगा तो हम तो कह रहे हैं ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब आप समाप्त कर दीजिए ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : यहाँ जो हम लोग बैठे हैं हूजुर, सुना है अभी कि चार आदमी को निकल गया पॉजिटिव, यहां जो जांच करवा कर आये हैं और फिर हम लोग फाइनली जाएंगे तो कितने आदमी का निकलेगा ये अलग बात हैं । मगर बीमारी में कोई भी किसी तरह की राजनीति करता है तो हम हो या आप हो या कोई हो

उससे बड़ा गंदा आदमी कोई दूसरा नहीं हो सकता है । इस वजह से कोरोना में सांप्रदायिक सौहार्द्र से, मिल्लत से, हिम्मत से और एकजुट होकर राष्ट्र को एक साथ होकर जब लड़ाई लड़ेंगे कोरोना से तो मरेंगे-मरेंगे मगर हम विफल नहीं होंगे।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : ठीक है, समाप्त किया जाए ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : महोदय, मैं अंत में इतना ही कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ कि डबल इंजन वाली सरकार नेपाल सरकार से बात करके और अगर नेपाल सरकार मदद नहीं करती है तो केन्द्र सरकार जिम्मेदारी ले कि जब हिमालय की विभिन्न नदियों से पानी निकलकर हमारे यहां आता है तो यह राष्ट्रीय प्रॉब्लम है और राष्ट्रीय प्रॉब्लम है तब फिर भारत सरकार को बिहार में बाढ़ और इस तरह की जो महामारी है इसमें विशेष अटेनशन देने की जरुरत हैं यही कहकर हम अपनी बात खत्म करते हैं, धन्यवाद ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : सभापति महोदय, सदन के अंतिम सत्र में एक नई परिपाटी की शुरुआत हुई है, इसके लिए आसन को हम बधाई देते हैं कि कांग्रेस नेशनल पार्टी है उसके जो सी.एल.पी.ए के लीडर लिखते हैं पत्र में कि हमारा कुछ समय दे दिया जाए राष्ट्रीय जनता दल को और आसन की ओर से कहा जाता है कि आपका समय नहीं है । यह एक बेहद दुखद और खेद का विषय है और आज कोरोना की महामारी है, सभापति महोदय, भाई लोग जरा शांति से सुनो ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अवधेश बाबू का नाम भी नहीं पुकारा गया अध्यक्ष महोदय, जबर्दस्ती बोल रहे हैं ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : ये देखिये इस राज्य के संसदीय मंत्री इतनी असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये क्या मामला है ?

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : आप अपनी बात रखिये ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात रखूंगा मगर संसदीय मंत्री को भी कहिये कि असंसदीय भाषा का प्रयोग ना करें । हम कोरोना के संबंध में कुछ बातें बताना चाहते हैं । सदन में सत्तर साल के भी इस सदन में थे, 15 साल के भी सदन में थे और 15 साल के सदन में हैं, ये तीनों सदन में रहे हैं । जब भी सरकार उठती है तो पिछले 15 साल के इतिहास उनके एम.एल.ए गिनाते हैं, उनके मंत्री गिनाते हैं और जब अभी होता है तो आज के दिन आगे बढ़कर सत्तर साल गिनाने लगते हैं, मैं सिर्फ दो-चार बिंदुओं के आगे आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि क्या उन सत्तर सालों में पटना पी.एम.सी.एच बना, क्या कोई हॉस्पिटल नालंदा मेडिकल कॉलेज बना, श्री कृष्ण सिंह मेडिकल कॉलेज बना, मगध अनुग्रह नारायण सिंह मेडिकल कॉलेज बना? ये 15 साल के लोग उस बने हुए

धरोहर में आप क्या किये हैं ये मुझे बताइए । आज कोरोना की महामारी है । हम सिर्फ मगध मेडिकल कॉलेज की ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि पूरे मगध मेडिकल कॉलेज में कोरोना का आप स्टेज बनाए हो, एल-1, एल-2, एल-3 और मगध मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 9 आई.सी.यू बेड हैं । चार जिले हैं वहां के मंत्री है प्रेम कुमार जी, झेले हैं, झेल रहे हैं बगल में औरंगाबाद, अरवल, नवादा, जहानाबाद के गरीब मजदूर, किसान पीड़ित होकर आ रहे हैं और उनका इलाज नहीं हो रहा हैं हम जानना चाहते हैं सरकार से और खासकर से बिहार के मुखिया से जिस पर आस्था और विश्वास था कि बिहार के विकास की बागडोर लिये हुए है, बिहार में एक नया इंकलाब लायेंगे मगर आज कोरोना के मामले में बिहार फीसड्डी हो गया है । आज सभापति महोदय, आप औरंगाबाद जिले के हो, आप औरंगाबाद का बताओ वहां का आई.सी.यू बनकर तैयार है। वर्षों-वर्षों से बना हुआ है, हॉस्पिटल में जंग लगा हुआ है, उस आई.सी.यू को चालू कराने की जवाबदेही किस पर थी और अब जब बात होती है जब हमारे लोग खड़ा होते हैं तो कभी सत्तर साल तो कभी पन्द्रह साल ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अरे भाई, आप इस पन्द्रह साल में बिहार में मेडिकल प्रोफशनल में क्या किये, कितने डॉक्टर बहाल किये, कितने नर्सों को बहाल किया ? इस पर सोचो, आज कोरोना से जूझ रहे हैं, गरीब मजदूर हॉस्पिटल पर भटक रहे हैं, उसका इलाज नहीं हो रहा है, उसकी जांच नहीं हो रही है, अच्छे-अच्छे परिवार के लोग लाईन में लगे हैं ।

(क्रमशः)

टर्न-25/राजेश/मुकुल

श्री अवधेश कुमार सिंह (क्रमशः): श्री मंगल पाण्डेय जी सीने पर हाथ रखकर कहें कि कोई ऐसा दिन है जिस दिन 50 आदमियों का इनके पास फोन न आता हो कि मेरे परिवार को एम्स में रखवा दें, मेरे परिवार को नालंदा मेडिकल कॉलेज कॉलेज में रखवा दें और ये कहते हैं कि वहां पर व्यवस्था नहीं है । हम यह जानना चाहते हैं कि एम्स की स्थापना किसने की या आई.जी.आई.एम.एस. की स्थापना 70 साल में हुई या 15 साल में हुई, यह हम जानना चाहते है ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, पावापुरी में मेडिकल कॉलेज बना, बेतिया में मेडिकल कॉलेज बना, दरभंगा में मेडिकल कॉलेज बना कि नहीं बना ।

अध्यक्षः अवधेश बाबू, अब आप अपनी बात समाप्त कर दीजिये । आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री अवधेश कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुझे 2-3 मिनट का समय चाहिए । मैं 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा ।

अध्यक्ष: नहीं एक मिनट । अवधेश बाबू, चलिये, हम कम्परमाइज करते हैं ।

श्री अवधेश कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बुद्धिजीवी थे, हमारे नेता राहुल गांधी, जब 30 जनवरी, 2020 को केरल में पहला कोरोना मरीज मिला तो 11 फरवरी, 2020 को हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने ट्वीट करके देश के प्रधानमंत्री को सचेत किया था कि देश में महामारी आ रही है और उसके कारण देश की अर्थव्यवस्था गिर जायेगी, हम आज बिहार के मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आप दूरदर्शी मुख्यमंत्री थे, अगर आप श्री राहुल गांधी जी के दिनांक 11 फरवरी, 2020 के उस ट्वीट को संज्ञान में लिये होते, तो बिहार की आज यह हालत नहीं हुई होती, मैं मंगल पाण्डेय जी से केवल यह कहना चाहता हूं .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अवधेश बाबू हो गया एक मिनट । आपका समय हो गया ।

श्री अवधेश कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लीजिये । आज गया में लोग मर रहे हैं, मानपुर पटवा टोली में हम नाम गिनाते हैं, श्री प्रेम कुमार जी वहां के विधायक हैं, ये ईमानदारी से बतायें कि वहां पर जितने हमारे समाज के लोगों की मौतें हुई हैं, उनके नाम सूची में क्यों नहीं हैं ?

अध्यक्ष: अवधेश बाबू, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री अवधेश कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, थोड़ा रहम कीजिए ।

अध्यक्ष: अवधेश बाबू, हम आप पर रहम ही कर रहे हैं और हम रहम करके ही आपसे कह रहे हैं कि आप अपने स्थान पर बैठ जाइये ।

श्री अवधेश कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम पर रहम नहीं किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुन लीजिए । बिहार में बाढ़ आई है, महागठबंधन की सरकार में भी बाढ़ आई थी और उस समय महागठबंधन के तमाम मंत्री हर जिले में बैठे हुए थे और बाढ़ से जूझ रहे थे, कटिहार के हम प्रभारी मंत्री थे, पक्ष और विपक्ष दोनों विधायक यहां पर बैठे हुए हैं, उस बाढ़ के समय में जब गांव में हम जाते थे और पानी में घुसकर जाते थे और उन मजदूर, किसान, गरीबों की मदद करते थे और किचन चला रहे थे और अध्यक्ष महोदय, आज कैसी किस्मत है कि रोम जल रहा था और नीरो वंशी बजा रहा था .....

(व्यवधान)

अध्यक्षः ठीक है । अवधेश बाबू, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री अवधेश कुमार सिंहः अध्यक्ष महोदय, आज बिहार बाढ़ से तबाह है और बिहार के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सो रहे हैं ।

अध्यक्षः अवधेश बाबू, अब आप अपनी सीट पर बैठ जाइये । माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य ललित बाबू, आपलोगों ने अपना समय नेता प्रतिपक्ष को दे दिया तो फिर आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री महबूब आलमः अध्यक्ष महोदय, सी0पी0आई0एम0एल0 को समय दिया जाये ।

अध्यक्षः आप क्या कहना चाहते हैं, आप बोलिये । आपके पास 1 मिनट का समय है और आप जो बोलना चाहते हैं बोलिये, सीधे-सीधे बोलियेगा, भूमिका नहीं बांधियेगा ।

श्री महबूब आलमः महोदय, एक मिनट में कैसे होगा । अध्यक्ष महोदय, कोरोना की गंभीरता और उसके खतरे को देखते हुए हम सब विधायकों ने, 243 माननीय विधायकों ने सर्वसम्मति से कार्य-मंत्रणा समिति में आपने जो बजट सेशन था उसको स्थगित किया और इस कोरोना के ही खतरे को लेकर के ये चार दिनों का जो सेशन था जिसमें सरकार को 12 करोड़ जनता के सवालों का जवाब देना था, हम ही लोगों ने और आपने तय किया था कि इस सेशन को एक दिन का किया जाय । अध्यक्ष महोदय, हम जब इतने बड़े गंभीर खतरे को महसूस करते हैं और आज टाईम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टिंग है कि 53 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं । मैं समझता हूं कि उत्तर और पूर्वी बिहार की 1 करोड़ जनता बाढ़ से प्रभावित है । अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह बात जानना चाहता हूं कि सरकार ने कोरोना को आपदा घोषित किया है कि नहीं ? इन लोगों ने कोरोना जनित बीमारी से मरे हुये लोगों को एक पैसा भी मुआवजा देने का काम यह सरकार ने नहीं किया है ।

अध्यक्षः अब आप अपनी बात समाप्त कीजिये ।

श्री महबूब आलमः अध्यक्ष महोदय, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य दिया, उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि प्रवासी मजदूरों की दर्द और पीड़ा को बयां करने के लिए इनके पास शब्द नहीं हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि इनके पास उनकी दर्द और पीड़ा को बयां करने के लिए शब्द हैं, ये तो शब्दों के

जादूगर हैं, ये मन की बात करते हैं लेकिन मजदूरों के बारे में बात करने के लिए इनके पास समय नहीं है ।

अध्यक्षः अब आप वादा तोड़ रहे हैं ।

श्री महबूब आलमः अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में काफी लोग मरे हैं जैसे काजीटोला का काजी अनवर, तारिक को मरते हुए देखा लेकिन इनके लिए कोई मुआवजा की बात है कि नहीं महोदय । मैं सर्वसम्मति से इस सदन को स्थगित करने की मांग करता हूं .....(व्यवधान)

अध्यक्षः ठीक है, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग ।

श्री महबूब आलमः महोदय, मैं चाहता हूं कि बाढ़ में मरे हुए लोगों को 20-20 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाय और जो लोग कोरोना से मरे हैं उनको भी 20-20 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाय ।

अध्यक्षः अब आप बैठ जाइये । देखिये, आपने अपने बोलने का समय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को दे दिया था उसके बावजूद मैंने आपको बोलने का समय दे दिया है।

श्री महबूब आलमः अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप खुद इस बात का संज्ञान लें क्योंकि आप इतने संवेदनशील आदमी हैं ।

अध्यक्षः आप लिखकर दे दीजियेगा ।

श्री महबूब आलमः अध्यक्ष महोदय, आपने फोन से बात करके विचार-विमर्श किया, इसलिए मुझे आपसे बहुत उम्मीद है और आपसे गुजारिश भी है कि कोरोना बीमारी से जो लोग मर गये .....

(व्यवधान)

अध्यक्षः आपको हमसे जो उम्मीद थी उसको तो हमने पूरा कर दिया और बहस भी करा दिये हैं लेकिन हमको आपसे जो उम्मीद है ।

श्री महबूब आलमः अध्यक्ष महोदय, मेरे गांव का एक लड़का था उसका अनुमण्डल अस्पताल में इलाज नहीं होता है, उसका सदर अस्पताल में इलाज नहीं होता है तो उसको अनुमण्डल अस्पताल से सदर अस्पताल भेजा गया, उसके बाद उसे मधेपुरा भेजा गया, मधेपुरा से भागलपुर भेजा गया, भागलपुर से फिर कटिहार सदर अस्पताल भेजा, उसके बाद कटिहार, सदर अस्पताल से मधेपुरा, अस्पताल भेजा गया, इसके बावजूद भी एक बीमार का इलाज नहीं करवाया गया ।

अध्यक्षः आपका समय समाप्त हुआ । माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वह हमेशा इंटीग्रेटर रहा है । वर्ष 1987 से 2017, इससे पहले लोग बोलते रहे हैं कि हाईयेस्ट फ्लड लेवल गया है और इस बार दो पीक आया 11 और 12 जुलाई को और 19 से 21 जुलाई को और ये पीक जब

आया तो आपको पता है कि जो गंडक नदी है, मैं गंडक नदी से ही अपनी बात शुरू करता हूं कि वहीं पर यह प्रॉब्लम रहा है । जो गंडक नदी है उसका 90 परसेंट भाग जो कैचमेंट का है वह नेपाल में है और उसका 10 परसेंट भाग बिहार में है । 20 तारीख को गंडक नदी में नेपाल से वाल्मीकिनगर बैराज से 4 लाख 36 हजार क्यूसेक पानी निकला और उसी समय जो बिहार के साइड में इतनी बारिश हो रही थी जो मोतिहारी, चकिया वगैरह गोपालगंज के साइड में वाल्मीकिनगर के साइड में इन सब जगह 200 एम.एम. से ज्यादा बारिश हो रही थी और लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी जो बिहार में जो बारिश हुई वह भी वाल्मीकिनगर बैराज से निकल रहा था तो कुल मिलाकर 5 लाख 36 हजार क्यूसेक पानी गंडक में से निकल रहा था, 20 प्वाइंट ऐसे थे, जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी थी कि वहां पर जो सीपेज पाइपिंग हो रहा था उस सीपेज पाइपिंग को रात में दुरुस्त किया गया, कुछ जगह जो मैं देख रहा था और माननीय राजू तिवारी जी जिस डूमरिया घाट की चर्चा कर रहे थे उस डूमरिया घाट में 24.07.2020 को 6.00 बजे उच्चतम जल स्तर 2017 में था 64.10 और इस बार 24.07.2020 को 0.36 आया जो 26 से.मी. ज्यादा था, जो एक फीट पानी ऊपर जा रहा था, बांध का जो टॉप लेवल है उसके ऊपर पानी जाने लगा और कुछ जगह पानी ओवर-टॉप कर गया, इस वजह से इसमें दो-तीन जगह ब्रिच हुआ, इसी तरह से 24.07.2020 को सारण जिला में जो रेवा घाट है वहां भी वर्ष 1986 में जो हाईयेस्ट फ्लड लेवल था, वह 34 साल का रिकॉर्ड को तोड़ते हुये 55.41 मीटर को पार करते हुये 11 बजे अपराह्न में नया एच.एफ.एल. कायम किया 55.46, यहां भी 5 से.मी. ऊपर पानी निकला । इसमें एक बात जो और हुई कि वह यह थी कि यह उच्चतम जल स्तर 2 घंटे तक लगातार रहा और वह पानी वहीं पर कांस्टेंट स्टेटिक रहा और 38 घंटे के बाद ही पुराना जो उच्चतम जल स्तर था वह उस पर चला गया । इतनी देर अगर पानी रुका रहा तो बहुत जगह सीपेज पाइपिंग की प्रॉब्लम रही । वह तो नेपाल से स्टीप है, ऊपर से पानी गिरता है और यहां पर समतल है तो इस वजह से हम लोगों को 2-3 जगह प्रॉब्लम हुई । क्रमशः

टर्न-26/सत्येन्द्र-यानपति-धिरेन्द्र/03.08.2020/

श्री संजय कुमार झा, मंत्री (क्रमशः): यह नॉर्मल टाइम भी नहीं था, करोना के फेज में जब लॉकडाउन हुआ और जो हमलोगों का फ्लड फाइटिंग का काम होता है वह काम भी डिस्टर्ब हुआ उस समय । दस, पंद्रह, बीस दिन हमलोगों का काम जब तक मुख्यमंत्री जी ने दिया कि ये भी एसेंशियल काम में है और उसको इसमें काम शुरू

हो सकता है उसके बाद हमलोगों ने काम शुरू किया । सारी जगह लॉकडाउन था, सामान का मूवमेंट नहीं हो सकता था, मजदूर नहीं मिल रहे थे, हमारे सचिव हैं वो गुड़गांव, दमन जहाँ से समान आता है एंटी फ्लड फाइटिंग के काम का, वो फैक्ट्री वालों को रिक्वेस्ट करके, फैक्ट्री खोलवा करके तब सामानों को मंगवाये वहाँ से और जो भी हमारा काम था और वो हमलोगों ने उस काम को पूरा किया । 24 मार्च को, 24 जून को सी0एम0 भी जब नेपाल के 2-3 प्वाइंट पर जहाँ हमलोगों को आपको पता है कि नेपाल के साईड में भी जो फ्लड फाइटिंग का काम है एंटी इरोजन का काम है वो बिहार सरकार करती है । उस साइड में भी हम लोगों को 1-2 प्वाइंट पर प्रोब्लम हुआ, खुद मुख्यमंत्री जी 24 जून को मधुबनी के जयनगर में गए और उसके बीयर पर रहकर सारा काम वहाँ देखें, लास्ट ईयर कमला में बहुत जगह टूट गया था तो पहली बार हम लोगों ने आपको पहली बार हम लोगों ने इस बार कमला में आयरन सीट पाइलिंग का काम किया वो भी जाकर के देखे कि जहाँ हेबिटेशन है, जहाँ गाँव है जहाँ लोग रहते हैं तो कम से कम उसके आमने-सामने नहीं टूटे जिससे कम से कम जान-माल की कम क्षति हो । इसी तरह हमारा एक संस्था है यहाँ पर जल संसाधन विभाग जो पहली बार बड़ा इफेक्टिव काम किया । वह है एफ.एम.आई.एस.टी. (फ्लड मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट सपोर्ट सेंटर) और इस बार वो जो डेटा ऐनेलाईज करके देता है मैथेमेटिकल मॉडलिंग से वो सेंटर बना हुआ है वह 72 घंटा पहले ही हमलोग जिला प्रशासन को भी और जो हमारे विभाग के इंजीनियर हैं वहाँ पर उनको हमलोग उससे अवेयर करा देते हैं कि वेदर का क्या कंडीशन होगा । उसका एडवांटेज यह हुआ कि सब जगह अलर्ट होने से जान-माल की क्षति इस बार कम हुई । पता था कि बारिश का तो अपने कंट्रोल में नहीं है, इतनी बारिश हुई । लेकिन ये अलर्टनेस और उसका एक्यूरेसी 90 परसेंट माना गया है । इसी तरह जो दो-तीन और जगह है, मैं जो बूढ़ी गंडक है जो अधवारा ग्रुप का है जो बागमती का है, इन सब जगहों में आपको अभी भी हाइयेस्ट फ्लड लेवल है जो..

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को यह भी बताना चाहिए कि कितने लोगों की मौत हुई ? आँकड़ा तो बता नहीं रहे हैं और कितने लोग प्रभावित हुए । महोदय, ये माननीय मंत्री जी...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने कहा कि ये जो संस्था है 72 घंटे पहले बताती है और अलर्ट होने के कारण, लोगों के जान-माल का नुकसान कम होता है और बचाया गया लोगों को और पिछले बार से आँकड़ा कम है, यही कहा गया है न । नहीं-नहीं, आप कह रहे हैं कि जान-माल का जो नुकसान होना चाहिए जिस तादाद में उससे कम हुआ है । लेकिन तो आँकड़ा क्या

है, आँकड़ा तो बताइएगा ना कि कितने लोग प्रभावित हैं, कितने लोग मरे हैं, उसपर थोड़ा बता दीजिएगा तब बताईयेगा।

अध्यक्षः असल में बता देंगे कि मंत्री, जल संसाधन विभाग या सिंचाई विभाग बोल रहे हैं ये बाढ़ के आने से संबंधित होते हैं, ये स्थिति बताएंगे फिर आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री जी के यहाँ वो सारी चीजें होती हैं और फिर स्वास्थ्य मंत्री जी भी बोलेंगे, सब लोग अलग-अलग बोलेंगे ।

श्री ललित कुमार यादवः आपको लंबा अनुभव है महोदय ।

अध्यक्षः जो भी हैं, आपके साथ ही हैं ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता बोल रहे थे कि जो वो जानकारी मिली उसका फायदा ये हुआ कि कुछ जगह तो हमलोगों के कंट्रोल के बाहर था क्योंकि पानी ओवरटॉप कर गया, गोपालगंज में दो-तीन जगह । लेकिन उसी आँकड़ा के बेसिस पर बहुत जगह हम लोग उसको सेव किए और वहाँ सीवेज पाईपिंग जो हो रहा था, ऐसा 20 जगह है लंबा लिस्ट है उसी आँकड़ा के बेसिस पर बीसों जगह हमलोगों ने उसको बचाया है । अभी फिलहाल जो बूढ़ी गंडक है जो अधवारा ग्रुप है जो बागमती का रिवर है, खास करके जो समस्तीपुर जिला है वहाँ पर बहुत बड़ी समस्या पिछले एक सप्ताह से चल रही है, पानी वहाँ स्टेटिक है, वहाँ रूका हुआ है और सारे इंजीनियर विभाग के वहाँ पर आपको जो कहे हैं वहाँ पर समस्तीपुर, दरभंगा, वैशाली आदि जिलों में समस्या बरकरार है लेकिन उस हायाघाट के नीचे सिरनिया-सिरसिया तटबंध पर पिछले 9 दिनों से अत्यधिक जल-जमाव की स्थिति बनी हुई है । जल निकासी के अभाव में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य भी अवरूद्ध है लेकिन विभाग द्वारा स्थिति पर नजर रखी गई है । कल भी जो उनके जो डी.एम. वगैरह से बात किये, दो दिन पहले मुख्यमंत्री जी सारे डी.एम. से बात करके रिव्यू किए और ये जो जितना मैंने आपको बताया कि जो सीवेज पाईपिंग, क्षरण इन सारे चीजों को हमलोग रिपेयरिंग कर के ठीक कर रहे हैं, कुछ जगह समस्या हमलोगों को बूढ़ी गंडक में जरूर, कल मुजफ्फरपुर के पास भी हुआ है और मैंने बताया था आपको कि डुमरिया घाट, रेवा घाट, लालगंज इस सब में फर्स्ट टाइम ये इतना हाइयेस्ट फ्लड लेवल बना है कि पिछले 35 साल के रिकार्ड को तोड़ा है तो हम और ये तीन जगह के अलावा हमलोगों ने बहुत जगह जो गंडक का एरिया है वहाँ पर टूटने से बचाया, सारण में बचाया, लालगंज के एरिया में बचाया और रातभर लोग काम किए तभी ये जाकर बच पाया और जो समस्तीपुर की भी स्थिति है वहाँ भी हमलोगों ने अभी तक बचाकर रखा है एक-दो जगह....

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, अभी कहे कि बहुत लोगों को बचाया लेकिन हमको लगता है कि रिकार्ड तोड़ हो गया होगा जितना तटबंध टूटा है, पुल-पुलिया टूटा है, 29 दिन किया हुआ उद्घाटन का नया पुल जो हजारों का बनता है वो भी टूट जाता है, एप्रोच रोड भी ढह जाता है । हम मंत्री जी से जानना चाहेंगे, हमलोग डिमांड किए थे कि मुख्यमंत्री जी सर्वेक्षण कर लें हेलिकॉप्टर से फिर बाद में ये गए हैं उनसे पहले कितना बार आप लोग ने जाकर जायजा लिया है । मंत्री जी कितना दिन गायब रहे, आप तो मधुबनी और दरभंगा भी नहीं गए, आप तो कहीं नहीं गए, महोदय-महोदय, मुख्यमंत्री जी आयेंगे जवाब देने ? हम तो जानना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे या नहीं देंगे ?

अध्यक्षः ठीक है, बोलने दीजिए न।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय, हमको पता चलना चाहिए ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, बाई-रोड गए । 24 जून को जयनगर में जाकर के रिव्यू किया, इसी फ्लड का और नेपाल बार्डर भी गए । वहाँ से झंझारपुर गए ..

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी आएँगे ?

अध्यक्षः हाँ, आएँगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय, ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त कर देना चाहिए । (व्यवधान) हम लोग चाहेंगे, मुख्यमंत्री फिर गायब हो गये, मुख्यमंत्री जी आकर के जवाब दें ।

अध्यक्षः ठीक है, बोलिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः अभी आयें, मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य होगा या नहीं होगा हमलोग यह जानना चाह रहे हैं । XXX

श्री नंद किशोर यादव, मंत्रीः XXX

(व्यवधान)

(इस अवसर पर राजद के सर्वश्री ललित कुमार यादव, विजय प्रकाश एवं अन्य कई माननीय सदस्यगण वेल में आ गये।)

(व्यवधान)

अध्यक्षः अपनी-अपनी जगह पर बैठ जाइये ।

XXX - आसन के आदेशानुसार इन अंशों को विलोपित किया गया ।

टर्न–27/मधुप/03.8.2020

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । बैठ जाइये । (व्यवधान) बैठे–बैठे क्यों सबलोग बोल रहे हैं ? अब बैठ जाइये ललित जी ।

(व्यवधान)

बैठिए न । ललित जी, हम सबको कार्यवाही से निकालते हैं न । बैठिये न । हम सबको निकालते हैं न ।

माननीय सदस्यगण, एक मिनट सुनिये न । अगर किसी माननीय सदस्य ने चाहे सत्तापक्ष के हों या प्रतिपक्ष के हों, किसी अंदर के व्यक्ति या बाहर के व्यक्ति के प्रति असंसदीय बात कही होगी, वह प्रोसिडिंग से निकाल दिया जायेगा । अब चलिये । वह निकल जायेगा । अरूण जी, अपनी जगह पर जाइये न । मुन्ना जी। ललित जी । अरूण जी, चलिये अब आपलोग अपनी–अपनी जगह पर जाइये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : चलिये । अरूण जी । मुन्ना जी ।

अब हो गया । ललित जी, अब चलिये न, हो तो गया ।

(व्यवधान)

ललित जी । चलिये न अब हो गया ।

माननीय सदस्यगण, हमने आसन की तरफ से कहा है कि जो भी असंसदीय बात है, वह कार्यवाही में नहीं जायेगी, निकाल दिया जायेगा । अब तो अपनी जगह पर चलिये ।

(व्यवधान)

आपलोगों को जिस बात पर आपत्ति हो सकती है, कोई असंसदीय बात है, हमने कार्यवाही से निकाल दिया है, वह न कार्यवाही का हिस्सा बनेगा, न अखबार में या न मीडिया में जायेगा । अब तो जगह पर बैठ जाइये । आगे चलने दीजिये न ।

आज अंतिम दिन है, अंतिम दिन की दुआ, शुभकामना लेकर जाइये आगे काम देगा ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष : मंत्री जी अपना जारी रखिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, जितना ध्यान इन सभी लोगों का लालू जी का नाम जपने में लगता है उतना ध्यान अगर इनका पुल निर्माण, बाढ़ प्रबंधन में लग गया होता, कोरोना के बचाव में लग गया होता तो यह स्थिति बिहार की नहीं होती ।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, अब हो गया । आगे चलने दीजिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : मुख्यमंत्री तो थे नहीं, हमने तो सारी बात कही....

अध्यक्ष : उनको सब चीज की सूचना मिल गई होगी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी हैं, अब वे जानें क्या करना है नहीं करना है ।

अध्यक्ष : उनको सब सूचना मिल गई होगी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : जो मंत्री दोषी हैं, चाहे सिंचाई मंत्री हों चाहे स्वास्थ्य मंत्री हों चाहे पथ निर्माण मंत्री हों, भ्रष्टाचार की वजह से आज बिहार डूब रहा है, उनपर कार्रवाई होनी चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, आप जारी रखिये ।

(व्यवधान)

कृपा करके सभी माननीय सदस्यगण, आज अंतिम दिन है सबलोग अच्छे मूड में यहाँ से जाइये, आज अंतिम दिन है, अब सरकार का उत्तर होने दीजिए, हम आपको सधन्यवाद शुभकामना के साथ कार्यवाही समाप्त करेंगे । मंत्री जी को बोलने दीजिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जवाब दें । ऐसे मंत्री लोग का जवाब हमलोगों को नहीं सुनना है । अगर ये लोग जवाब देंगे तो हमलोग बहिष्कार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जवाब दें, बिहार की जनता को जवाब दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मंत्री जी, आप माईक ऑन करिये न ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए । इस तरह के जवाब का कोई मतलब नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, वहाँ हमलोग काम कर रहे हैं और 2-3 जगह पर काम चल रहा है । जितनी जगह है, सारे जगह हमारे इंजीनियर्स 24 घंटे....

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, जो दोषी हैं वे प्रवचन दे रहे हैं जिनपर कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों को जेल जाना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचारी लोग भाषण दे रहे हैं ।

टर्न-28 आजाद-अंजली-सुरज/03.08.2020

(व्यवधान)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : जो इंजीनियर हैं, वहां पर कंट्रोल करके रखा है । जो कोशी और कमला बलान का एरिया है, वहां पर कोई ऐसी स्थिति नहीं है । यही बात कहते हुए, एक बात हमारे साथी बोल रहे थे कि आपदा मंत्री कौन हैं .....

अध्यक्ष : आपदा मंत्री तो अभी बोलेंगे न ।

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : बोलेंगे, इनको अभी बता रहे हैं । आपकी तरह ये भी पहली बार जीतकर आये हैं । अति पिछड़ा समाज से आते हैं और इससे पहले वे जिला परिषद् के सदस्य जीतकर आ चुके हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपदा प्रबंधन मंत्री । बोलने दीजिए ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आज सत्र का अंतिम दिन है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी वक्तव्य देना चाहिए । इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वे एक शब्द बोलें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप माईक ऑन कीजिए ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपदा प्रबंधन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है । आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को ससमय राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिमत है कि आपदा पीड़ितों का राज्य सरकार के खजाने पर पहला हक है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माईक ऑन वही करें, जिनको हम कहते हैं सिर्फ बोलने के लिए, बाकी अपने मन से माईक ऑन नहीं कर लीजिए अपने मन से बैठे-बैठे ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री : महोदय, आपदा पीड़ितों को राज्य सरकार के खजाने पर पहला हक है । माननीय अध्यक्ष जी, इससे पहले भी जो कोरोना संक्रमण काल में मार्च से ही आपदा प्रबंधन विभाग जो बिहार के बाहर मजदूर थे, उनके खिदमत के लिए, उनके आने जाने के लिए भी सरकार पूरी तरह से आपदा प्रबंधन विभाग प्रयास किया, उनके आ जाने के बाद भी क्वांरटाइन के लिए व्यवस्था किया । दूसरी बात आपदा कोरोना के साथ-साथ बाढ़ का जो अभी स्थिति आ गया है । सरकार जून समय से

ही तत्पर है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 13 जून से ही की बाढ़ जो पिछले दिन हम लोग बाढ़ के रूप में किए थे लेकिन बाढ़ अब सैनिटाईजर, मास्क सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करना होगा। इसलिए एक नए रूप में बाढ़ की तैयारी की गई, साथ ही निष्क्रमण में वृद्ध, दिव्यांग, गर्भवती एवं धात्री महिला, बच्चों को प्राथमिकता दी गई । उनकी अलग-अलग व्यवस्था रखने के लिए भी पूरे तरह से निर्देशित किया गया विभाग को । मानसून अवधि के दौरान जून माह में समान वर्षापात 167.70 एम.एम. की अपेक्षा 305.90 एम.एम. वास्तविक वर्षापात दर्ज की गई, जो 82 प्रतिशत अधिक है समान वर्षा से । पुनः जुलाई माह में समान वर्षापात 349.00 एम.एम. की अपेक्षा 443.50 एम.एम. वार्षिक वर्षापात दर्ज की गई है जो 27 प्रतिशत अधिक है । साथ ही एन.डी.आर.एफ., एस.डी.आर.एफ. की टीम भी सभी जिलों में प्रतिनियुक्त की गयी है । सुपौल में एन.डी.आर.एफ. की दो टीम, मधेपुरा में एस.डी.आर.एफ. की एक टीम, सहरसा में एस.डी.आर.एफ. की एक टीम, पूर्णिया में एस.डी.आर.एफ. की दो टीम, किशनगंज में एन.डी.आर.एफ. की एक टीम, अररिया में एन.डी.आर.एफ. की एक टीम, कटिहार में एन.डी.आर.एफ. की एक टीम.....

(व्यवधान)

पढ़ा है, एम0ए0 पास हैं, ये आठवां पास नहीं हैं, एम0ए0 पास हैं । झोपड़ीवाला है लेकिन एक नम्बर हैं दिल से । ललित बाबू, उनको समझाइए ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्रीजी, इधर बोलिए न ।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री : प्रवासी की चिन्ता नीतीश कुमार को जितनी है, उतनी देश में किसी को नहीं है । दरभंगा में एन.डी.आर.एफ की दो टीम, एस.डी.आर.एफ. की एक टीम, मधुबनी में एन.डी.आर.एफ. की दो टीम, एस.डी.आर.एफ. की एक टीम, मुजफ्फरपुर में एन.डी.आर.एफ. की एक टीम, एस.डी.आर.एफ. की एक टीम, वैशाली में एक एस.डी.आर.एफ. की टीम लगायी गयी है । सीतामढ़ी में एस.डी. आर.एफ. की एक टीम, ईस्ट चंपारण में तीन एन.डी.आर.एफ की टीम लगायी गयी है । वेस्ट चंपारण में एक टीम एन.डी.आर.एफ और एक टीम एस.डी.आर.एफ. की लगायी गयी है । खगड़िया में दो एस.डी.आर.एफ. की टीम लगायी गयी है । भागलपुर में एक एन.डी.आर.एफ की टीम लगायी गयी है । गोपालगंज में तीन एन. डी.आर.एफ. और एक एस.डी.आर.एफ. की टीम लगायी गयी है । सारण में तीन एन.डी.आर.एफ. की टीम लगायी गयी है । सीवान में एक एन.डी.आर.एफ. की टीम और एक एस.डी.आर.एफ. की टीम लगायी गयी है । समस्तीपुर में एक एस.

डी.आर.एफ. की टीम लगायी गयी है । पटना में एक एन.डी.आर.एफ. और एक एस.डी.आर.एफ. की टीम लगायी गयी है । शिवहर में अभी एक एस.डी.आर.एफ. की टीम लगायी गयी है और दो रिजर्व है । रिजर्व में तीन एन.डी.आर.एफ. और दो एस.डी.आर.एफ. की टीम रखी गयी है । इस वर्ष जुलाई माह के द्वितीय सप्ताह में उत्तर बिहार एवं नेपाल के तराई क्षेत्रों में भारी वार्षिक वर्षापात के कारण उत्तर बिहार से होकर गुजरने वाली अधिकांश नदियां गंडक, बागमती, कमला, बलान, बूढ़ी गंडक, लखनदेई, ललबकिया आदि के जल स्तर में काफी वृद्धि हुई है । फलस्वरूप दिनांक- 13.07.2020 को सीतमढ़ी, शिवहर, सुपौल एवं किशनगंज के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई । पुनः जुलाई माह में तृतीय सप्ताह में भी नेपाल के तराई क्षेत्रों विशेषकर गंडक नदी के जलग्रहण में काफी अधिक वर्षापात दर्ज की गई जिसके कारण 14.07.2020 से 17.07.2020 के बीच में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज जिला बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हुए । बागमती, बूढ़ी गंडक, अधवारा समूह एवं कमला बलान आदि के नदियों में जलस्तर में काफी वृद्धि हुई जिसके कारण 14.07.2020 को दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर भी बाढ़ से प्रभावित हुए । वर्तमान में राज्य के 14 जिला शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, प0 चंपारण, किशनगंज, सुपौल, गोपालगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सीवान एवं मधुबनी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है । साथ ही दिनांक- 01.08.2020 को कुल 14 जिलों में 112 प्रखंडों के अन्तर्गत 1043 पंचायतों की लगभग 49,05,007 जनसंख्या प्रभावित हुई है । राज्य सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एन.डी.आर.एफ., एस.डी.आर.एफ. के सहयोग से बाढ़ में फंसे लगभग 4 लाख 90 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निष्क्रमित किया गया । गोपालगंज, दरभंगा एवं पूर्वी चंपारण के वैसे इलाके, जहां स्थानीय तौर पर नाव एवं मोटरबोट के माध्यम से पहुंचने में कठिनाई थी वहां के लोगों तक पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना के तीन हेलिकॉप्टर की मदद ली गई । दिनांक 25.07.2020 से 27.07.2020 तक तीस सॉर्टिज के द्वारा 16598 सूखा राहत पैकेट एवं एअर ड्रॉपिंग कराया गया । बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए अब तक 38 राहत शिविर खोले गए हैं, जिसमें 27402 लोगों को आवासित किया गया था । वर्तमान में संचालित है जिसमें 26732 लोग रह रहे हैं । इन शिविरों में सुबह का नाश्ता तथा दिन एवं रात का भोजन, शुद्ध पेयजल, साफ-सफाई एवं शौचालय की व्यवस्था की गई है । राहत शिविरों में रहने वाले लोगों के लिए वस्त्र तथा भोजन करने के लिए बर्तन की व्यवस्था की गई है । कोविड संक्रमण को देखते हुए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि राहत शिविरों में अनिवार्य रूप से मास्क का

उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग एवं भोजन की व्यवस्था में staggering का अनुपालन हो । जो लोग राहत शिविरों में नहीं आ रहे हैं उनके लिए उनके गांव-मुहल्ला के नजदीक ही किसी ऊंचे स्थल पर सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है, कुल 1340 सामुदायिक रसोई का संचालन किया जा रहा है, जिसमें आठ लाख बेरासी हजार लोगों को भोजन कराया जा रहा है । राहत शिविर तथा सामुदायिक रसोई का उपयोग कर रहे लोगों के लिए विशेष रूप से रैपिड एंटीजन टेस्ट्स की कार्रवाई की जा रही है ।

साथ ही इस वर्ष भी बाढ़ प्रभावित सभी परिवारों को ससमय निर्धारित मानदर के अनुरूप 6000 प्रति परिवार की दर से आनुग्रहिक साहाय्य राशि (gratuitous Relief) सीधे उनके बैंक के खातों में करने का निर्णय लिया गया है जिसमें दिनांक 01.08.2020 तक 1,93,889 बाढ़ पीड़ित परिवारों को 6000 रुपया की राशि उनके खाते में अंतरित की जा चुकी है । शेष बाढ़ पीड़ित परिवारों की राशि का शीघ्र ही नियमित रूप से भुगतान हो रहा है । अब तक बाढ़ से 13 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिसमें दरभंगा-7, पश्चिम चंपारण-4, मुजफ्फरपुर-2 । बाढ़ के पश्चात एस.ओ.पी. के अनुरूप क्षति का आकलन कराया जाएगा । फसल क्षति हेतु सर्वेक्षण के पश्चात कृषि इनपुट अनुदान वितरित की जाएगी ।

महोदय, शेष इसको मान लिया जाए पढ़ा हुआ ।

(माननीय मंत्री का लिखित वक्तव्य - परिशिष्ट-3 द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री : धन्यवाद सर ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने जो अपना लिखित वक्तव्य सदन पटल पर रखा है, वह इनके भाषण और आज की कार्यवाही का हिस्सा बनेगा ।

माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

टर्न-29/शंभु-हेमंत/03.08.2020

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है और भारत समेत दुनिया के 200 से अधिक देश इससे प्रभावित हैं । विश्व की सभी अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं इस संकट से जूझ रही हैं। विश्व में कोविड-19 का पहला मामला दिनांक- 30.12.2019 को चीन के वुहान प्रांत से प्रतिवेदित हुआ था । भारत में सबसे पहले केरल राज्य में दिनांक-30.01.2020 को पहला मामला प्रकाश में आया । अध्यक्ष महोदय, जब बिहार में कोरोना के कोई मरीज नहीं मिले थे, उसी वक्त 13 मार्च को पहली बार माननीय

मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई और बैठक बुलाने के बाद राज्य के अंदर सभी शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल, खेलकूद के आयोजन, सभी सरकारी पार्क एवं सभी सरकारी सांस्कृतिक महोत्सव को बंद करने का निर्देश दिया ताकि इस कोरोना के फैलाव को हम रोक सकें और बिहार विधान मंडल का जो बजट सत्र था उस बजट सत्र को भी 16 मार्च, 2020 को स्थगित कर दिया गया था, महोदय । दिनांक 22 मार्च को देश में कोविड संक्रमण के मामले को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा सभी जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय एवं नगर-निकायों में लॉकडाउन का आदेश निर्गत किया गया । बिहार सरकार द्वारा भारत सरकार के लॉकडाउन से संबंधित आदेशों का सख्ती से अनुपालन किया गया। भारत सरकार द्वारा कुछ कतिपय ढील के साथ 1 जून से 30 जून तक अनलॉक-1 का आदेश दिया गया, जिसका बिहार सरकार द्वारा पूर्ण रूप से कार्यान्वयन किया गया । महोदय, बिहार सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा लागू अनलॉक-2 की शर्तों को कठोर करते हुए 16 से 21 जुलाई, 2020 तक विशेष रूप से लॉकडाउन लागू किया गया । अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में पहला कोविड-19 का मामला 22 मार्च, 2020 को प्रतिवेदित हुआ । कोविड-19 के शुरुआती मामलों में प्रायः वही मामले थे जिनका बाहर से यात्रा का इतिहास था, इस स्थिति को समझते हुए बिहार सरकार द्वारा सबसे पहले 15 मार्च, 2020 के बाद विदेश से बिहार राज्य आये सभी व्यक्तियों का सत्यापन किया गया एवं ऐसे सभी व्यक्तियों की जांच हेतु सैम्पल लिये गये । जो भी व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए उनकी गहन कॉन्टेक्टिंग की गई एवं सभी कॉन्टेक्ट की जांच कराई गई । मुंगेर, पटना, सिवान, बेगूसराय, नवादा इन सभी जगहों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में कन्टेंमेंट जॉन की स्थापना की गई । महोदय, पूरे बिहार राज्य में कोविड-19 के लक्षण की खोज करने एवं लक्षणयुक्त व्यक्तियों की जांच कराने हेतु घर-घर सर्वेक्षण का कार्य प्लस पोलियो के अभियान की तर्ज पर कराने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया और उस कार्य को संपादित किया गया । उक्त सर्वेक्षण में 3849 लोग लक्षणयुक्त पाए गए । महोदय, प्रखंड स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की गई । प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर में कोविड-19 के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सभी सुविधाएं मुहैया कराई गईं । महोदय, कुल 15036 क्वारंटाइन सेंटरों में 15 लाख 20 हजार से अधिक व्यक्तियों के रहने की समुचित व्यवस्था की गई । ये प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर 21 जून, 2020 तक क्रियाशील रहे । इस अवधि में कुल 59832 बाहर से आये व्यक्तियों की जांच कराई गई एवं उनमें से 5405 व्यक्ति कोविड-19

पॉजिटिव पाये गये । अब महोदय, बिहार के अंदर जो अभी कल शाम तक का आंकड़ा है, उस आंकड़े के अनुसार लगभग 57 हजार 270 संक्रमित व्यक्तियों में से 36 हजार 637 संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं । आज दोपहर में ये आंकड़ा और बढ़ा होगा, मैं इसलिए बता रहा हूं कि नहीं तो फिर नेता प्रतिपक्ष कहेंगे कि आंकड़े बदल कैसे गये ये कल तक का आंकड़ा था आज दोपहर में भी रिपोर्ट 4 बजे फिर हमारे विभाग से आयेगी तो निश्चित रूप से ये बढ़ा हुआ रहेगा इस प्रकार बिहार में जो रिकवरी रेट है वह 64 परसेंट है देश में भी लगभग इतना ही है । महोदय, बिहार राज्य में अब तक 322 लोगों की दुखद मृत्यु हुई और ये जो मृत्यु हुई हैं, जो मृत्यु दर बिहार में है महोदय वह 0.57 प्रतिशत, जबकि देश के स्तर पर देखते हैं तो राष्ट्रीय औसत जो इस दुखद मृत्यु दर की है कोरोना के कारण वह 2.15 है इसका मतलब कि जो देश की मृत्यु दर है उसकी चौथाई मृत्यु दर इस बिहार के अंदर है यह बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है । महोदय, इसमें 199 ऐसे लोग हैं जो कोविड-19 संक्रमण के अलावा विभिन्न प्रकार की अन्य गंभीर बीमारी भी उनको रही है । अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के निर्देश के आलोक में कोविड-19 के संपुष्ट मरीजों के इलाज हेतु राज्य में त्रिस्तरीय चिकित्सा सुविधा केन्द्र स्थापित किये गये । हल्के लक्षण वाले पॉजिटिव मरीजों के इलाज हेतु कुल-290 कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई है । इन केन्द्रों पर चिकित्सक, नर्स एवं पैरामेडिकल कर्मी की नियुक्ति की गई है । इन केन्द्रों में 33 हजार 437 बेड की क्षमता है । इन केन्द्रों में भर्ती मरीजों हेतु भोजन, पानी, दवाई, ऑक्सीजन, सिलेंडर, पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था की गई है । पहले भोजन की व्यवस्था के लिए 100 रुपये की राशि निर्धारित थी अब उसको बढ़ाकर 175 रुपये कर दिया गया है और शुद्ध सील बंद पेयजल के लिए 50 रुपये की अलग से व्यवस्था का प्रावधान किया गया है । महोदय, मॉडरेट लक्षण वाले मरीजों हेतु 93 डैडिकेटिड कोविड हैल्थ सेंटर बनाये गये, जिनमें हल्के लक्षण पाए जाते हैं वैसे लोगों के लिए ये केन्द्र बनाये गये हैं यहां पर 6304 बेड की व्यवस्था की गई है । इन केन्द्रों पर सभी बेड के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर अथवा गैस पाईप लाइन के माध्यम से मेडिकल ऑक्सीजन देने की व्यवस्था की जा रही है । सभी अनुमंडल स्तर पर अनुमंडलीय अस्पताल के अतिरिक्त ऑक्सीजनयुक्त 100 बेड वाले डैडिकेटिड कोविड हेल्थ सेंटर की स्थापना की जा रही है । प्रत्येक जिले में कोरोना मरीजों के सघन इलाज हेतु चार आई.सी.यू बेड वेंटिलेटर सहित तैयार किये जा रहे हैं । गंभीर रूप से बीमार मरीजों हेतु 10 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में डैडिकेटिड कोविड हॉस्पिटल की स्थापना की गई है जिसमें 3850 बेड की क्षमता है, महोदय।

अतिरिक्त आई.सी.यू बेड और वेंटिलेटर की भी उपलब्धता कराई गई है । निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की अनुमति दी गई है । बिहार राज्य के अंदर 153 निजी अस्पतालों में 3237 बेडों की व्यवस्था की गई है । राज्य में स्थापित 6 डिजी चिकित्सा महाविद्यालयों को आइसोलेशन सेंटर के रूप में चिन्हित कर कुल 720 बेड को कोरोना के मरीजों के इलाज हेतु आरक्षित किया गया है । अध्यक्ष महोदय, होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के स्वास्थ्य का निरंतर अनुश्रवण आशा एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से कराया जा रहा है । होम आइसोलेशन के दौरान अन्य आवश्यक दवाओं, दो मास्क, चिकित्सकीय सलाह पर्ची आदि की किट दी जा रही है तथा दूरभाष के माध्यम से उनकी जानकारी प्राप्त कर टेली मेडिसिन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सभी जिलों में ऐसे मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श एवं सहायता उपलब्ध कराने हेतु टोल फ्री नंबर के साथ मेडिकल हेल्प लाइन की भी व्यवस्था की गई है । अध्यक्ष महोदय, आप भी देख रहे होंगे अखबारों में हरेक जिले के लिए अलग से टोल फ्री नंबर जो बनाया गया है उसका विज्ञापन दिया जा रहा है ताकि आमजनों तक सभी बातें पहुंचाई जा सकें । मेडिकल हेल्प लाइन 102 नंबर वाली एंबुलेंस के अतिरिक्त निजी एंबुलेंस को....

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी आप एक मेरी बात सुन लीजिए । एक बार समेट करके बोल लेना ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। नेता प्रतिपक्ष आपके प्रति बहुत सम्मान करता हूं और मैं कह रहा हूं आपकी हर बात का जवाब दूंगा । मेरी बात आप सुन लीजिए । मैं सारी बातों का जवाब दूंगा। महोदय, मेडिकल हेल्प लाइन में, मैं जवाब दूंगा नेता प्रतिपक्ष को ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, कुछ नहीं, हम जानना चाहते हैं कि मंत्री जी ने अभी कहा होम आइसोलेशन जो है उसके उपचार के लिए लोगों को गाइड किया जा रहा है। मंत्री जी कहते हैं कि बिहार का रिकवरी रेट बहुत बढ़िया है, हम जानना चाहते हैं कि सरकारी अस्पताल में कितने लोग हैं और होम आइसोलेशन में कितने लोग हैं, क्योंकि मंत्री जी ने कहा है कि सभी का उपचार कराया जा रहा हैं तो इसलिए हम जानना चाहते हैं कि कितने होम आइसोलेशन हैं? और जब होम आइसोलेशन में ज्यादा संख्या होगी तो रिकवरी रेट में बिहार सरकार का क्या योगदान होगा ?

अध्यक्ष : ठीक है, मंत्री जी जारी रखिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, तब तो कोई योगदान नहीं होगा, लोग घर में बैठकर ठीक हो रहे हैं ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका भी जवाब दूंगा । मैं आपके मन में जो भी शंका हर शंका का जवाब दूंगा ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: मेरे मन में नहीं, बिहार के लोग जो झेल रहे हैं वही बात हम कह रहे हैं ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : महोदय, मैं हर प्रश्न का जवाब दूंगा, नेता प्रतिपक्ष को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ । महोदय, मेडिकल हेल्प लाइन में 102 नंबर वाली एंबुलेंस के अतिरिक्त निजी एंबुलेंस को भाड़े पर रखकर गर्भवती महिलाओं एवं गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को चिकित्सकीय सुविधा हेतु अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई । अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर चिकित्सकीय परामर्श तथा शिकायत निवारण हेतु टोल फ्री नंबर 104 संचालित है । कोरोना संक्रमण अवधि में कॉल की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए जिस कॉल सेंटर में पहले 20 लोग रहते थे इस कोरोना काल में उसकी कैपिसिटी बढ़ाकर 50 कर दी गई ।

(क्रमशः)

टर्न-30/ज्योति-पुलकित/03.08.2020

श्री मंगल पांडेय, मंत्री (क्रमशः) : और 104 कॉल सेंटर में मार्च 2020 से लेकर जुलाई, 2020 तक कोरोना से संबंधित एक लाख 32 हजार कॉल प्राप्त हुए और कॉल को अटेंड किया गया है, ये सब ऑन रिकॉर्ड है महोदय । राज्य स्तर से इंस्टीच्युशनल आइसोलेशन तथा होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना परियुक्त मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का निरंतर पर्यवेक्षण किया जा रहा है, महोदय । कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु राज्य के सभी जिलों में मरीजों एवं स्वास्थ्य कर्मियों हेतु पी.पी.ई. किट, थ्री प्लाई मास्क, एन-95 मास्क, सेनेटाइजर आदि प्रतिरक्षक सामग्रियों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है । स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना संक्रमित होने पर सरकार द्वारा उन्हें पेड आइसोलेशन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है । अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल को बनाये रखने हेतु सरकार द्वारा एक महीने के समतुल्य वेतन प्रोत्साहन राशि के रूप में तथा कर्त्तव्य के दौरान कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने की स्थिति में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत 50 लाख रुपये के इंश्योरेंस का प्रावधान किया गया । अध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल को बनाये रखने हेतु सरकार द्वारा जो एक महीने के समतुल्य वेतन प्रोत्साहन राशि

देने का निर्णय हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कल विभाग ने उसका आदेश भी जारी कर दिया है और राज्य के सभी चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों को ये एक महीना के समतुल्य हम उनको प्रोत्साहन राशि देंगे । महोदय, सभी अनुमंडलीय अस्पताल तथा जिला अस्पताल एवं विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में कुल 3,631 बेड को मेडिकल गैस पाईप से जोड़ने तथा सभी 9 मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट निर्माण की कार्रवाई की जा रही है । अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा इसकी आवश्यकता को देखते हुए 10,900 अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भी करा ली गई है । इस प्रकार राज्य में 16,310 बी टाइप और डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं । पूर्व में जहां राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं जिला अस्पतालों में कुल 341 वेंटिलेटर उपलब्ध थे महोदय, वर्तमान में उसे बढ़ाकर 861 की उपलब्धता सुनिश्चित करा दी गई है । मैं बताना चाहूँगा महोदय, कि जब पहले दिन बैठक हो रही थी कोरोना से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी और उपमुख्यमंत्री जी थे । मुख्यमंत्री जी ने पहली ही बैठक में कहा था कि तुरंत 100 वेंटिलेटर बढ़ाए जाए और फिर बाद में मुख्यमंत्री जी ने कहा 500 वेंटिलेंटर बढ़ाए जाए और मुझे सदन को आज बताते हुए इस बात में प्रसन्नता हो रही है कि आज 520 अतिरिक्त वेंटिलेटर, इस कोरोना काल में इस राज्य के अंदर लाये गये हैं और उनको मेडिकल कॉलेजों में भेजा जा रहा है । महोदय, ऑक्सीजन की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु लगभग साढ़े 6 हजार ऑक्सीजन कंसलटेटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है । इसमें से 750 ऑक्सीजन कंसलटेटर भारत की सरकार से आज से चार दिन पूर्व प्राप्त हो चुके हैं और उनको अस्पतालों में भेजने की कार्यवाई की जा रही हैं और शेष ऑक्सीजन कंसलटेंटर क्रय करने का कार्य किया जा रहा है । महोदय, कोविड मरीजों को नि:शुल्क दवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसेंशियल ड्रग लिस्ट को पुनरीक्षित कर कुल 36 अतिरिक्त दवाओं को ई.डी.एल. में सम्मिलित किया गया है चूंकि इन दवाओं की जिसकी जरुरत कोरोना के मरीजों को थी वो पूर्व के ई.डी.एल. लिस्ट में नहीं था और कोरोना के मरीजों को कठिनाई ना हो इसलिए ये दवाइयां इसमें जोड़ी गई । अध्यक्ष महोदय, जांच को सुगम बनाने तथा अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी देने हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा संजीवन मोबाइल ऐप विकसित किया गया है । मोबाइल ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जांच हेतु अपने को पंजीकृत कर सकता है तथा निकटतम केन्द्र पर जा कर कोरोना की जांच न्यूनतम समय में करा सकता है । साथ ही मोबाइल ऐप के माध्यम से निकटतम कोविड सेंटर तथा....

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, मजाक हो रहा है, हम लोगों ने वीडियो देखा है । लोग पॉजिटिव होकर रोड पर घूम रहे हैं ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : नहीं-नहीं, मैं आपको हर प्रश्न का जवाब दूँगा । आप एक-एक प्रश्न करिएगा मैं हर प्रश्न का जवाब दूँगा ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, लाश पड़ी हुई है उठाने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर के पास पी.पी.ई किट नहीं । लोग जो है पॉजिटीव होकर के रोड पर घूम रहे हैं कि कोई भर्ती कर लो, भर्ती कर लो ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करता हूँ, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ नेता प्रतिपक्ष से कोरोना संकट का समय है पूरी दुनिया लड़ रही है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ नेता प्रतिपक्ष आपसे मेरी बातों को सुन लीजिए और आपके हर प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं हूँ । मैं इस सदन में तब तक रहूँगा जब तक आपके हर विषय का जवाब न दे दूँ । महोदय, जांच को सुगम बनाने तथा अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी देने हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा संजीवन मोबाइल ऐप विकसित किया गया । मोबाइल ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जांच हेतु अपने को पंजीकृत कर सकता है । निकटतम जांच केन्द्र पर जाकर कोरोना की जॉच न्यूनतम समय में करा सकता है साथ ही मोबाइल ऐप के माध्यम से निकटतम कोविड केयर सेंटर तथा डैडिकेटिड कोविड हेल्थ सेंटर में उपलब्ध बेड के बारे में भी जानकारी उसको उस मोबाइल ऐप से मिल जाएगी ताकि मरीज को कहीं भटकना नहीं पड़े । महोदय, इस राज्य के अंदर चिकित्सकों की कमी थी, कमी है आगे भी हमको चिकित्सकों की नियुक्ति करनी है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ । पूर्व में जो चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती थी उसमें काफी समय लगता था मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मंत्री बनने के बाद आग्रह किया था, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत सहमति दी और बिहार तकनीकी सेवा आयोग का गठन किया महोदय, पहले जो चिकित्सकों की नियुक्ति में तीन साल, चार साल, पांच साल लगते थे, महोदय, आपको बताते हुए मुझे प्रसन्न्ता हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग का गठन किया और वहां पर विशेषज्ञ चिकित्सक, सामान्य चिकित्सक, ग्रेड 'ए' नर्स की नियुक्ति की अधियाचना भेजी गई और एक साल के अंदर 929 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति एक सप्ताह पहले कर दी गई है, महोदय । चार हजार और मेडिकल डॉक्टरों की काउंसलिंग का काम चल रहा है । 9,200 ग्रेड 'ए' नर्स के काउंसलिंग का काम पूरा हो गया है और अगले 30 दिनों के अंदर उसका भी परिणाम विभाग को प्राप्त हो जाएगा । उनकी नियुक्ति

की प्रक्रिया होगी । महोदय, कोविड की रोकथाम में सबसे महत्वपूर्ण इसकी जांच है । जांच बहुत ही महत्व रखती है । राज्य की स्थिति यह थी महोदय, कि 7 मार्च के पहले इस राज्य के अंदर एक भी कोविड की जांच नहीं होती थी । कोविड का जांच कराने के लिए वायोरोलॉजी लैब पुणे में जांच का सैम्पल भेजना पड़ता था । शुरुआती दिनों में 48 सैम्पल पुणे वायोरोलॉजी लैब में भेजने पड़े थे । 7 मार्च को आर.एम.आर.आई पटना में जांच प्रारंभ हुयी , चरणवार वर्तमान में राज्य के सभी जिलों एवं मेडिकल कॉलेजों में कोविड-19 की जांच की सुविधा आज उपलब्ध है। राज्य में वर्तमान में कोविड-19 की जांच हेतु उपलब्ध सभी माध्यमों आर.टी.पी.सी. आर टू नेट रेपिड एंटीजन किट आदि के माध्यम से जांच कार्य संपन्न किया जा रहा है और वर्तमान में इसे राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी मांग के आधार पर ये सभी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । महोदय, मैं कहना चाहता हूँ और सदन को और सभी माननीय सदस्यों को यह कोई सामान्य बात नहीं थी । बिहार की जो आधारभूत संरचनाएँ शुरु से रही है उसके बारे में सबको मालूम है । आज जो जांच 7 मार्च को शुरु हुयी इस राज्य के अंदर में आज इस सदन में मुझे बताते हुए इस बात की प्रसन्नता हो रही है कि आज इस राज्य में जांच का आंकड़ा प्रतिदिन 36 हजार पार कर गया है और 36 हजार से अधिक जांच हो रही है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आर.टी.पी.सी.आर हो रहा है या एंटीजन हो रहा है ? नहीं-नहीं आप बताइए, आप अभी बताइए कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं भाग रहे हैं और एक मिनट, आप ये भी बताइए कि तीन-तीन प्रधान सचिव क्यों बदले गये ? कोरोना योद्धा, अरे सब गलती कर रहे, चार महीने हो गये । ऐसे पदाधिकारी रखे जो गलतियाँ पर गलतियाँ करते रहे, इसका भी जवाब दीजिए ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : माननीय नेता प्रतिपक्ष को हर प्रश्न का जवाब मिलेगा । महोदय, अभी तक जो लगभग 6 लाख 12 हजार 400 ।

श्री तेजस्वी यादव, नेता विरोधी दल : मंगल जी जो अधिकारी देता है उसी को पढ़ देते हैं । हमें आंकड़े चाहिए कि जमीनी स्तर पर सही क्या है ? ....

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : मैं जमीनी बात कर रहा हूँ । मेरी बात सुन लीजिए, महोदय, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ सदन में नेता प्रतिपक्ष आपसे । कोरोना राजनीति का विषय नहीं है। कोरोना ...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : आप आर.टी.पी.सी.आर. बताईये ना कितना हुआ है और कितने दिन पहले तीस हजार हो रहा है । चार महीने से, पहले दिन से अबतक का बताईये ना ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैं आंकड़ा बता रहा हूँ । अब सुनें तब तो । आप पहले सुनिये तो नेता प्रतिपक्ष ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : आप उपलब्धि तो बताईये । सबसे कम जॉच नीति आयोग बोल रहा है जॉच कराने में आप फिसड्डी रहे हैं ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : सुनना नहीं चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष । 6 लाख 12 हजार जॉच हुयी है इस राज्य के अंदर में और जॉच में तीन लाख चौबीस हजार जॉच आर.टी.पी.सी. आर. से हुई हैं और टू नेट मशीन से 1 लाख 10 हजार टू नेट से हुए हैं और एंटीजन टेस्ट किट से 1 लाख ..

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, फिर से दुहरा दें आंकड़े ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : मैं फिर दुहरा रहा हूँ । आर.टी.पी.सी.आर.से 3,24,000 जॉच हुई है, टू नेट मिशन से 1 लाख 10 हजार जॉच हुई है और एंटीजन टेस्ट किट से 1 लाख 78 हजार जॉच हुई हैं । इसप्रकार आ.टी.पी.सी.आर. और टू नेट से जितनी जॉच हुई हैं उसका 72 प्रतिशत जॉच आर.टी.पी.सी.आर. और टू नेट से हुई है यह मैं बताना चाहता हूँ ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : बिना जॉच वाले का रिपोर्ट कितनी आयी है ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैं गंभीरता के साथ हर विषय से सदन को पूरी बात अवगत कराना चाहता हूँ । मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राज्य में जो कोविड-19 की जॉच हो रही है उसमें अब निजी क्षेत्रों का भी सहयोग अब लिया जा रहा है । कोविड-19 के इलाज में संलग्न निजी चिकित्सा संस्थानों को भी राज्य सरकार द्वारा रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से भी जॉच की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है । महोदय, रैपिड टेस्ट किट के बारे में विषय आया था । मैं उसके बारे में भी बताना चाहता हूँ । यह आई.सी.एम.आर. का कागज है, महोदय और आई.सी.एम. आर. का गाईडलाईन क्या है एंटीजन किट के बारे में मैं सदन के सामने एक बार पढ़कर बता देना चाहता हूँ ।

'' Where as a positive test should be considered as a true positive and does not need re-confirmation by R.T.P.C.R. Test '' यह मैं नहीं कहता यह आई.सी.एम.आर. का गाईडलाईन है और इसका अनुपालन पूरे देश को करना पड़ता है और यह सच्चाई मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : बेहतर जॉच एकुरेसी के बारे में क्या कहा गया है? आर.टी.पी.सी.आर. बेहतर है या एंटीजन बेहतर है ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, बहुत क्लियर है । मैं फिर एक बार दुहरा दे रहा हूँ Where as

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : Which is better ? Which test is more accurate ?

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : Where as a positive test should be considered as a true positive and does not need reconfirmation by R.T.P.C.R. test बहुत क्लियरली लिखता है और यह कागज मैं पढ़कर सुना रहा हूँ ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : Which test is accurate ? सवाल सीधा है।

टर्न–31/राजेश–मुकुल/3.8.20/

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, मैं आगे आपको कहना चाहता हूँ कि राज्य के अंदर सरकार की स्पष्ट मंशा है कि जिन व्यक्तियों को यह महसूस होता है कि उन्हें कोविड की जांच करानी है, उनके जांच के लिए नि:शुल्क व्यवस्था उपलब्ध हो, यह माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही स्पष्ट निर्देश है और आज राज्य के सभी प्रखंडों में नि:शुल्क जांच किया जा रहा है और जो भी जांच कराना चाहेंगे, उन सभी लोगों की जांच कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है .....

(व्यवधान)

महोदय, विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत सरकार द्वारा .....

(व्यवधान)

वर्तमान में बिहार सरकार इस मानक से आगे बढ़कर दोगुने से अधिक जांच कर रही है । महोदय, डब्ल्यू.एच.ओ. ने कहा है कि पर मिलियन 14 टेस्ट हर दिन होना चाहिए और उस हिसाब से बिहार की जो आबादी है उसके अनुसार लगभग 16,800–17000 जांच होनी चाहिए । आज दोगुने से भी अधिक जांच इस समय किया जा रहा है यह मैं बताना चाहता हूं । महोदय, पर्याप्त सामग्रियों के बारे में भी इस सदन में विषय उठाये जाते हैं मैं बताना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में 6,84,693 पी.पी.ई. किट आये हैं, 40,87,000 सर्जिकल मास्क आये हैं, 11,18,466 एन–95 मास्क आये हैं, 6,37,370 वी.टी.एम. आये हैं, रेपिड एंटिजेन टेस्ट किट 5,34,000 आये हैं इसके अलावा आर.टी.–पी.सी.आर. टेस्टिंग किट आये हैं, टूल एण्ड परफॉर्मिंग किट आये हैं, 10,452 पल्स ऑक्सिमीटर आये हैं । महोदय, एक–एक चीज की जानकारी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं । महोदय, इस

बीमारी के समय में एम्बुलेंस और शववाहन की भी बहुत आवश्यकता है । इस बीमारी के समय में नये परिचालित एम्बुलेंस के फ्लीट में 90 और नये एम्बुलेंस शामिल किया गया है, इसके अतिरिक्त अभी वर्तमान समय में 10 शव वाहन पटना के अंदर उपलब्ध कराये गये हैं । इसके अतिरिक्त 39 नये शव वाहन के क्रय करने का निर्देश दे दिया गया है । महोदय, हम सब लोग जानते हैं कि इस कोरोना से बचाव के लिए न तो कोई दवा बनी है और न ही इसे कोई रोक सकता है ।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, हम लोग यह आंकड़ा ले लेंगे लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कि बाढ़ से लोग त्रस्त हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों में दवा का वितरण नहीं किया जा रहा है ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः ललित जी, मैं बाढ़ के ऊपर भी आपको बताऊंगा । मैं किसी विषय पर और आपके जो अच्छे सुझाव होंगे उसका अनुपालन भी करूंगा यह भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं । महोदय, कोरोना की वैक्सीन बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सब लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगी हुई है, चाहे वह अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, चीन हो, फ्रांस हो या अपना भारत देश भी वैक्सीन का ट्रायल कर रहा है और सदन के साथ-साथ हम सब बिहारियों को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि पूरे देश में कुछ ही संस्थान हैं जहां पर वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है उसमें एक संस्थान अपने बिहार का एम्स, पटना भी है और वहां पर 15 जुलाई, 2020 से वैक्सीन के ट्रायल का काम शुरू हुआ था, सेकेण्ड फेज 31 जुलाई से शुरू हो गया है और यह हर बिहारी के लिए गर्व की बात है, कल जो वैक्सीन देश में बनेगा हम बिहारी भी देश के लोगों के सामने कह पायेंगे कि इस वैक्सीन में हमारा भी योगदान है । महोदय, प्लाज्मा थेरेपी भी बहुत ही महत्वपूर्ण थेरेपी है और यह देश में सभी जगह नहीं हो रहा है, केवल तीन जगहों पर जब यह थेरेपी शुरू हुई थी, उस समय एम्स, पटना के डायरेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बातचीत करके हमने एम्स, पटना के अंदर प्लाज्मा थेरेपी की व्यवस्था की शुरुआत की और आज के समय में उस प्लाज्मा थेरेपी के कारण कई लोगों की जान भी बची है और आज बिहार के अंदर उस थेरेपी से ट्रीटमेंट की जा रही है । महोदय, यह डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार मिलकर बिहार में कोरोना बीमारी को रोकने का काम कर रही है । भारत की सरकार और बिहार की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों पूरी ताकत और क्षमता के साथ बिहार के अंदर जो कोरोना का संक्रमण है, उससे लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं । भारत की सरकार से बहुत सी सामग्रियाँ मिली हैं, उसकी भी सूची मैं सदन के पटल पर रखना चाहूंगा लेकिन उसमें और समय लगेगा लेकिन

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक विषय कहा था, मैं उस विषय पर उनको जरूर अपनी बात से अवगत कराना चाहूंगा । महोदय, जो मरीज हैं होम आइसोलेशन में, क्या है, कैसे हैं, कितने हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई0सी0एम0आर0 की गाईडलाइन है, उस गाईडलाईन के अनुसार जब कोई मरीज कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो कोविड पॉजिटिव पाये जाने के साथ ही उसको तीन श्रेणी में बॉटा जाता है जिसकी चर्चा मैंने की है । सी.सी.सी. मतलब कोविड केयर सेंटर, दूसरा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर (डी.सी.एच.सी.) तीसरा है डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, इन तीन भागों में मरीजों को चिकित्सक बांटते हैं जिनके ए-सिंटोमेटिक होते हैं आप सब लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं कोई नया शब्द कह रहा हूं, मतलब जिनको लक्षण नहीं होता है उनको ए-सिंटोमेटिक बोलते हैं और वैसे लोगों के बारे में यह केवल आई. सी.एम.आर. का नहीं पूरी दुनिया के अंदर यह सलाह दी जाती है कि वैसे मरीज जिनमें लक्षण नहीं हैं, वे होम-आइसोलेशन में रहें और उनको जो कुछ आवश्यक उपचार चाहिए, वह उपचार दिये जायं और उन्हीं उपचारों के लिए मैंने जो टेलिफोन नम्बर बोला है, उन टेलिफोन नम्बरों से उन मरीजों से हाल-चाल पूछा जा रहा है और अब उन मरीजों तक दवाइयों की किट को भी भिजवाने की व्यवस्था की जा रही है । दूसरा उसमें स्टेज होता है जब मरीज में कुछ हल्के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं और उनको हम डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर (डी.सी.एच.सी.) में भेजते हैं, जहां पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध होती है और मैंने अभी बताया कि ऑक्सीजन की सुविधा हमारे 10 मेडिकल हॉस्पिटल में उपलब्ध है । ऑक्सीजन की सुविधा हमने जो डी.सी.एच.सी. 93 जगह पर बनाये हैं वहां पर उपलब्ध है । हम सब-डिवीजनल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सुविधा बहाल कर रहे हैं । इसके साथ ही साथ हमने साढ़े 16 हजार ऑक्सीजन सिलेंडर बी-टाइप और डी-टाइप इस राज्य के अंदर अस्पतालों में भेजने का काम किया है । पटना के अंदर भी मैं चाहूंगा नेता प्रतिपक्ष, एक दिन होटल अशोका में नीचे जाकर देख कर आयें कि वहां पर जो डी. सी.एच.सी. बना है, अगर ये इसे देखेंगे, तो इनको अंदाजा हो जायेगा । कंगनहाट पटना में डी.सी.एच.सी. बना है, ये वहां पर भी जाकर देखें । जब ये सारी व्यवस्थाओं को देखेंगे और उसके बाद भी अगर इनको वहां पर कोई कमी लगेगी, तो ये मुझे फोन करके बता सकते हैं ।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या बिहार की सारी आबादी पटना में ही है ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण दे रहा हूं नेता प्रतिपक्ष यहां पर तुरंत जा सकते हैं । ये दूसरी जगहों पर भी जाते हैं इसलिए आप वहां पर भी जाकर देख

सकते हैं । यदि इनको उस केन्द्र पर यदि कोई कमी नजर आती है, तो आप मुझे बता सकते हैं, यह सरकार का काम है, हम उसी काम के लिए हैं और हम उन व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे । लेकिन मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इस कोरोना की वैश्विक महामारी के समय में हम लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिहार के हर व्यक्ति की जान बराबर है और बिहार के हर व्यक्ति की जान बचाना हमारा काम है । नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वह मानते हैं कि इस सदन में विपक्ष भी सत्तापक्ष का अंग है । मैं आपको अपने सत्तापक्ष का अंग मानता हूं और आपको अपना सहयोगी भी मानता हूं । मैं मानता हूं कि इस राज्य के अंदर हम जो व्यवस्थाएं बना रहे हैं उनको बनाने में आपका सहयोग भी हमको चाहिए, आपके सुझाव चाहिए और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपने राज्य के हजारों-हजार चिकित्सकों को, हजारों-हजार पैरामेडिकल स्टाफ को और ए.एन.एम. को । मैं इस सदन में उन सारे लोगों को एक बार फिर से सलामी दूंगा । मैं जहां जाता हूं, उन लोगों को मैं सलामी देता हूं और मैं यहां पर फिर से सलामी देना चाहता हूं कि उन लोगों के कारण आज मरीजों की जान बच रही है । एन.एम.सी.एच. से हजारों मरीज स्वस्थ होकर गये हैं, क्या वहां के चिकित्सकों ने इलाज नहीं किया होता, क्या वहां के नर्सेज ने सेवाएं नहीं दी होतीं, क्या वहां के पैरामेडिकल स्टाफ ने सेवाएँ नहीं दी होती, तो उस एन.एम.सी.एच. से, आप सब लोग देखते होंगे कि अखबार में तस्वीरें छपती हैं कि रोज एन.एम.सी.एच. से कितने लोग स्वस्थ होकर निकलते हैं, अगर उन लोगों ने सेवा नहीं दी होती तो क्या मरीज वहां से स्वस्थ होकर जाते ? आज जान की बाजी लगाकर 5 महीने से हमारे राज्य के चिकित्सक, चिकित्साकर्मी, हमारे ए. एन.एम. दिन-रात परिश्रम कर रहे हैं, हम लोगों को तो उनको बार-बार सैल्यूट करना चाहिए .....

(व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष ने तो एक बार भी हमारे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और ए.एन.एम. के बारे में धन्यवाद नहीं दिया लेकिन हम उनसे आग्रह करेंगे कि राज्य के नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों को एक बार जरूर धन्यवाद दीजिए कि आज उन लोगों के कारण ही इस राज्य की हजारों जनता की जान बची है । चिकित्सक ही काम आते हैं, हमारे आपके सब के काम आते हैं और बेचारे चिकित्सक अपनी जान की बाजी लगाकर काम कर रहे हैं । महोदय, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे विषय हैं लेकिन समय के अभाव के कारण मैं अपने भाषण का अंश सदन पटल पर रखता हूं और इसे सदन की कार्यवाही का हिस्सा बना दिया जाय ।

अध्यक्ष: ठीक है, आप रख दीजिए ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः अंत में मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

(माननीय मंत्री का लिखित वक्तव्य- परिशिष्ट-4 द्रष्टव्य)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः महोदय, कोरोना योद्धाओं को हाथ उठाकर देने से नहीं होगा बल्कि उन्हें पी.पी.ई. किट देकर होगा ।

अध्यक्षः ठीक है, उस पर भी अमल करेंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः महोदय, मुझे दो बात और कहनी है कि सही सलामी देना डॉक्टर जो शहीद हुये हैं, अगर सलामी देना है, तो उन शहीद डॉक्टरों को जिन्होंने लोगों की जान बचाकर खुद शहीद हो गये, उनको आप एक-एक करोड़ का पैकेज दीजिए । तीसरी बात यह है कि इन्होंने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को तीन-तीन बार बदला क्यों, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है ?

अध्यक्षः ठीक है, माननीय नेता प्रतिपक्ष आपने भी इच्छा जाहिर की थी और मेरे ख्याल से सदन के सभी माननीय सदस्य उत्सुक होंगे । सदन नेता, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अगर इन विषयों पर अपना कुछ विचार रखना चाहें, तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे । माननीय मुख्यमंत्री ।

टर्न-32/सत्येन्द्र/03.08.2020

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं सब लोगों को बधाई देता हूँ और सभी माननीय सदस्यों का अभिनंदन मैं करता हूँ । अब ये तो कार्यकाल है अब उसका तो एक तरह से ये अंतिम सदन की कार्यवाही चल रही है और आज अनेक काम हुए । कई कानूनों को बनाया गया, 12 नहीं 13 कानून, सप्लीमेंट्री बजट पारित किया गया और जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उस पर भी चर्चा हुई है और यह स्वाभाविक है, चाहे वो कोरोना वायरस का मामला हो या बाढ़ का मामला हो तो इन सभी चीजों पर चर्चा हुई है, लोगों ने अपनी बात रखी है और यहाँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग ने, माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग ने सारी बातों को रख दिया है । मैं तो यही कहूंगा कि देखिये ऐसा वक्त है ये दुनिया भर में फैला हुआ है, ये कोई किसी राज्य का या अपने देश का ही सवाल नहीं है । ये तो दुनिया में फैला हुआ है और हमलोग शुरू से ही सचेत हैं । 16 तारीख को ही, मार्च में जो बजट सत्र था उसको स्थगित कर दिया गया था, सभी सदस्यों की सर्वसम्मति के साथ । सभी दलों की बैठक में आपने बातचीत की और 16 मार्च को ही हो गया और उस समय की जो स्थिति थी आज इतनी कठिन

स्थिति उस समय नहीं पता था । अपने यहाँ कहाँ मालूम था बिहार में, बिहार में तो छोड़ दीजिए देश में भी उतनी चर्चा नहीं थी और जब अचानक हुआ, इस बार आप देख लीजिए कि उसके बाद जब हमलोगों को इसके बारे में सारी बातों की जानकारी थोड़ी बहुत मिलने लगी तो हमलोग तो इस पर काफी सजग हुए, 13 को मीटिंग किया, 16 को इस हाउस में चर्चा हुई और उस समय जो बात थी ऐसा थोड़े ही लग रहा था कि इतने बड़े पैमाने पर ये स्थिति उत्पन्न होगी, जितनी बड़ी स्थिति आज उत्पन्न हुई है और उस समय तो इसके बचाव के लिए उस समय के जो एक्सपर्ट्स थे उनलोगों का ओपीनियन था मास्क के बारे में कि जिनकी तबीयत खराब है वो पहनेंगे और जो इलाज करते हैं वो पहनेंगे, लेकिन उसके कुछ ही समय के बाद क्या बात आयी । पूरी दुनिया से ये बात आयी कि मास्क पहनना चाहिए और तब से लगातार हमलोगों ने क्या सुझाव दिया है और आज तो बड़ी खुशी की बात है कि सब लोग मास्क पहने हैं और बीच में तो हम निकल कर के जो लॉकडाउन खत्म हुआ जो पूरे देश में लागू था । तो मैं अगले फ्लड को देखते हुए उसके कारण और बिहार में भी पटना में भी कई जगह काम जो हुआ था उसको हमको देखना था, निरीक्षण करना था । हम गए, रास्ते भर में हम देख रहे थे कि 10 परसेंट लोग भी मास्क नहीं पहने थे और इतने लोग कहीं भी जा रहे हैं बाई-रोड जा रहे हैं मालूम हो जाता है, भीड़ इतनी लग जाती है, एक-दूसरे के पास इकट्ठे हो जाते थे, ये देखकर के हमको लगा कि भाई अवेयरनेस नहीं आ रहा है इतना ज्यादा हमलोग बता रहे हैं और बार-बार हमलोग कह रहे हैं कि भाई मास्क पहनिये । दो मीटर, दो गज की दूरी रखिए, हाथ को साफ करिये और जो सबसे बड़ी बात है कि जो 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, गर्भवती महिलाएँ हैं, कोई अन्य बीमारी से ग्रस्त हैं और 10 साल की उम्र तक के बच्चे और बच्चियाँ जो हैं इनको घर के अंदर ही रखा जाए । इलाज के लिए और बहुत जरूरी काम के लिए बाहर निकलना है तो बाहर निकलें, लेकिन आमतौर पर लोगों को रखना चाहिए जब लॉकडाउन नहीं था । लॉकडाउन 31 मई महीने के बाद बंद हुआ तो उस समय भी सारी बातें की गई थी । हमलोगों को तो लग रहा था कि थोड़ा घटेगा लेकिन आप देख लीजिए कि क्या स्थिति आयी ? जून में थोड़ा बहुत लेकिन जुलाई महीने में और जून और जुलाई महीने में मिलाकर कितना हुआ और अभी कोई नहीं जानता है कि इसके आगे और क्या होने वाला है । आगे के महीने में क्या होगा और कब तक ये चलेगा ? जब दुनिया भर में इसके बारे में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी एक-एक चीज की जानकारी दे दी कि इसके बचाव के लिए सब तरह की बात हो रही है तो जब होगा उसके बाद होगा

लेकिन अभी तो ये पूरे दुनिया में फैला हुआ है और हर जगह बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका में बढ़ता जा रहा है, अपने देश की आबादी ज्यादा है और एक बात जान लीजिए कि अपने बिहार को निश्चित रूप से खतरा है, हम लोगों की जो आबादी है, आबादी बहुत ज्यादा है । हमलोगों का जो पोपुलेशन डेंसिटी है वह सर्वाधिक है, अपने देश से भी तीन गुना है, ऐवरेज से तीन गुना ज्यादा है इसलिए हम लोगों के लिए तो बहुत ही सजग रहने की जरूरत है । अब जितना काम किया जा सकता है एक-एक चीज की समीक्षा होती है हमलोग इस बात को बढ़ा रहे हैं और आर.टी.पी.सी.आर टेस्ट के लिए भी लोगों ने बता दिया जो शुरू-शुरू में ही बात आई थी तब जो हमने कहा था कि भाई मिनिमम, यह बात हम बता रहे हैं कब, मार्च के एंड और अप्रैल के शुरू माने उस समय कोई एक सप्ताह भी नहीं बचता था जिसमें डिटेल्ड चर्चा उस समय भी नहीं करते थे तो इन लोगों ने बताया हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमलोगों को 20 हजार टेस्ट करना चाहिए । हमने कहा कि इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है और उसके लिए काम बढ़ना शुरू हुआ । उसके अलावे आर.टी.पी.सी.आर के बाद जो टू नेट आया और अभी एंटीजन टेस्ट की बात आयी । अब टू नेट क्या है ? टू नेट में अगर किसी को निगेटिव मिलता है तो जरूर पक्का है और आपको एंटीजन टेस्ट में अगर पॉजिटिव है तो जरूर पक्का है । तो ये तो दुनिया भर में बात आयी है और जो कुछ भी इन्सट्रक्शन आता है उसके हिसाब से काम हो रहा है । एंटीजन टेस्ट की सबसे बड़ी खासियत है कि एक तो पॉजिटिव जिसका निकला वो पॉजिटिव है और इतना कम समय में 15 मिनट में टेस्ट हो जाता है, एक व्यक्ति के टेस्ट के लिए एक ही है तो अभी जब बन रहा है और इतने बड़े पैमाने पर लाखों में हमलोगों ने मंगाया है और हर जगह पर जो भी हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ तक इसको पहुँचा रहे हैं कि जो भी इच्छुक होगा उसकी जांच होगी, इस सब चीज की जानकारी दी गई है । मेरा तो यही निवेदन करना है कि हम सब लोगों का दायित्व है कि कॉंससनेस पैदा करें और डॉक्टर्स लोगों को भी बढ़ावा देने के लिए हमलोगों ने तो कह ही दिया है कि इन्होंने बताया । उनके लिए विशेष तौर पर हम लोग एक महीने की तनख्वाह और जो सुविधा है वह हर डॉक्टर्स को, पारामेडिकल स्टॉफ को, नर्सेस को और सब लोगों को देने का, वही नहीं उनके साथ जो हमारे अन्य कर्मचारी काम करते हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनको भी हमलोगों ने तय कर दिया और कल इसका डायरेक्शन, ऑर्डर निकल गया कि एक महीने का उनको हम दे दें एडिशनल, अगर किसी की डेथ होगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया है 50 लाख का, हमलोग तो ये कर चुके हैं कि अगर उस तरह की डेथ होगी तो उनके

परिवार में जो भी रहेगा, अब जिनको नौकरी मिलनी है वह तो मिलेगी ही, इसके अलावे वो पूरा जब तक उनकी नौकरी थी तब तक के लिए फुल तनख्वाह मिलेगी उनको । तो ये कई तरह की सुविधाएँ हमलोगों ने की है, कोशिश की है, वो तो करेंगे और इसके आगे जो भी करना है आप लोगों को भी लगता है क्यों नहीं करेंगे । आप एक करोड़ की बात कर रहे हैं ठीक है, क्यों नहीं हमलोग करेंगे, हमलोग को भी देख लीजिए कि हम लोगों ने कितना किया है वो जोड़ने के बाद भी अगर कुछ लगता है तो हम क्यों नहीं करेंगे, ये हम सब लोगों का दायित्व है । डॉक्टर्स को दूसरे हमारे नर्सिंग का जो भी मेडिकल स्टाफ्स हैं पारा मेडिकल स्टाफ हैं उन सब का ख्याल रखना होगा तो जो भी कहियेगा हमलोग उनको और भी अतिरिक्त सहायता देंगे ताकि वे मेहनत करें और मेहनत कर लोगों को बचायें । अब एक-एक चीज कैसी कैसी आ रही है, एक-एक चीज का रिसर्च हो रहा है। अब जो आपका आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट होता है तो कल हम देख रहे थे एक्सपर्ट लोग डॉक्टर ने बताया है और वह कह रहें सबको भई आप पूछ लीजिये कि कितना नंबर आया है, अभी क्या है 35 के ऊपर है तो वह हुआ निगेटिव और 35 के नीचे अगर आया तो वह होता है पोजिटिव, तो उनका कहना है कि नंबर पूछिये और उस पर रिसर्च कर के कहा है अगर 24 है तो पोजिटिव तो होगा 35 के नीचे 24 से ऊपर है लेकिन उसका असर दूसरे पर नहीं पड़ेगा । अब एक-एक चीज अनुसंधान कर के लोगों को बतला रहे हैं कि पूरी जानकारी ले लीजिये कि कितना आपका आया, अगर 24 या 24 के ऊपर है तो दूसरे पर असर नहीं पड़ेगा और अगर 24 के नीचे है तो उसका असर दूसरे पर पड़ेगा तो सब तरह का रिसर्च हो रहा है। एक एक रिसर्च के बाद जो गाईडलाईन हो उसका हम सब लोग उसका पालन करेंगे । सब का सहयोग चाहिए और अगर कोई कमी है तो मैं यही कहूंगा अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है आपलोगों ने जो सुझाव दिया है किसी भी जिले में कहीं भी कोई कमी है और आपको बतला दें अभी हमने एक दिन मीटिंग की है और जितने मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटल्स हैं सब जगह देखने की कोशिश हमलोगों ने की है कि भई किस तरह का इंतजाम है अभी तो हमारे तीन मेडिकल कॉलेज को किया गया था पहले इसके इलाज के लिए, लोगों को भर्त्ती करने के लिए इसको हेल्थ मिनिस्टर ने बतला दिया तो उसके बाद में तो एम्स में भी हो गया और उसके बाद फिर जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटल्स है सब में 100-100 बेड का इंतजाम तो एक-एक चीज देखा जा रहा है और अभी तो हमलोगों ने दे दिया है और फिर शुक्रवार को उसकी पूरी की पूरी उसी तरह से समीक्षात्मक बैठक होगी और एक-एक जगह का हाल देखेंगे । (क्रमशः)

टर्न–33/मधुप/03.8.2020

..क्रमशः..

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : एक चीज तो यह है और दूसरी चीज अब इसी समय फ्लड का सिचुएशन आ गया, अब बताइये यह जो पानी पड़ रहा है, पिछली बार तो आप ही ने सबको बुलाया था, सबलोग एक साथ बैठे और जल–जीवन–हरियाली अभियान की बात तय हो गयी और कर रहे थे । जिस दिन 13 जुलाई को हमलोग बात कर रहे थे उसी दिन फ्लड आ गया और उसके बाद अगले दिन हमलोगों ने उसको देखा जो कुछ भी हुआ, पिछली बार फ्लड आया तो ड्रॉट आया तो फिर फ्लड आया और इस बार देखिए रबी का नुकसान यानी फरवरी में एक बार वर्षा हो गयी फिर मार्च में तीन बार तीन–तीन दिन वर्षा हुई, कभी हुआ है आजतक । मार्च महीने में तीन–तीन दिन तीन बार वर्षा और कितना नुकसान हुआ और फिर अप्रील महीने में वर्षा से रबी को जो नुकसान हुआ उसके लिए तो हमलोगों को जो मदद करनी थी वह तो हमलोगों ने कर दिया, जो भी किया कृषि विभाग को दिया, कृषि विभाग ने एक–एक का पता करके कर दिया । यह अलग बात है, लेकिन अभी तो सबकी मदद हमलोग करेंगे ही लेकिन अभी तो आप समझ लीजिए, हमलोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तभी हमलोगों को यह जानकारी दी गयी और जानें कि 15 जून से शुरू होता है बरसात का समय । अब क्या हालत है, मानसून तो 15 जून से होता है इस बार देखिए 14 से ही शुरू हो गया और कितनी वर्षा हुई । आज तक के रेकॉर्ड से भी ज्यादे लगभग 40–45 परसेंट अधिक वर्षा दो महीने में हुई जो आजतक नहीं हुआ । आप जान लीजिए कि महीना जो यह अब शुरू हुआ है यह अगस्त का महीना और इसके बाद सितम्बर महीना का कुछ हिस्सा कभी–कभी हो जाता है इसमें भी, कभी–कभी अक्टूबर में भी हो जाता है । हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है अक्टबूर महीने में, पता नहीं, आज से 30–35 साल पहले की बात है 5 अक्टूबर को हमलोगों के इलाके में नालंदा जिले के हरनौत में इतना पानी हुआ कि हमलोगों को नाव से जाकर सब जगह देखना पड़ा था तो कब क्या हो जायेगा इसको कोई नहीं जानता । लेकिन इस दो महीने में इतनी वर्षा इतने दूर तक, अभी तो 14 जिला बुरी तरह प्रभावित हैं और आज का अभी सबेरे जो हमारे यहां भेजा है सुबह ही 9:30 बजे में 14 जिले के 114 प्रखंड प्रभावित हैं, 1079 पंचायत प्रभावित हैं और आबादी देख लीजिए 55,72,634 आबादी प्रभावित हैं और इसमें आप जान लीजिए जिनको निकाला गया, निष्क्रमित किया गया वो 4,19,340 हैं । कई जगह पर पानी चारों तरफ है वहां के लोग निकलते नहीं हैं ।

सबसे ज्यादा दरभंगा में है, सबसे अधिक दरभंगा का है सबलोगों को मालूम है 17,85,280 लोग प्रभावित हैं लेकिन निष्क्रमित कितने हुए हैं मात्र 850 तो जहां जो आवश्यकता है उसके हिसाब से वह करना पड़ता है, वह किया जाता है । निष्क्रमित हुए 4,19,340, राहत शिविरों की संख्या है 19 तथा कुल मिलाकर इसमें रह रहे हैं 26,734 लोग और सामुदायिक रसोई केंद्र बनाया गया है, यह चल रहा है करीब 1,385 और उसमें प्रतिदिन 9,50,047 लोग भोजन कर रहे हैं । एक-एक चीज का इंतजाम किया जा रहा है और जो भी आगे की जरूरत है, किया जायेगा। यही नहीं, जो परिवार, जितने लोग अबतक प्रभावित हुए हैं उसमें से 2,63,659 बाढ़ पीड़ित परिवारों को प्रति परिवार जो gratuitous relief है 6 हजार रुपया की राशि हमलोगों ने प्रदान कर दी है और ये काम किया जा रहा है । जितने अब तक के प्रभावित हैं 10 दिन के अंदर हमने लक्ष्य रख दिया है कि सबको उतना मिल जाय । अब इसके आगे भी होना है और जान लीजिए जब देखा कि फ्लड और कोरोना पहले से है तो हमने यही गाईड-लाईन दिया कि जो राहत केंद्र में लोग हैं, राहत केंद्र में सबकी जांच होनी चाहिए और सबकी जांच हो रही है । जान रहे हैं उसका क्या फायदा हुआ, राहत केंद्र में कई जगह चार-चार, मतलब है 25-30 आदमी, 40 आदमी, 50 आदमी उसमें 4 आदमी, 5 आदमी कहीं-कहीं पॉजेटिव निकल गये । अब ये जांच करवाना इसलिए जरूरी है कि जांच करवाने से जो पॉजेटिव हैं उसके लिए अलग इंतजाम किया जायेगा और अगर हमलोग यह जांच नहीं करें तो जितने लोग हैं इनको कब तक रहना पड़ेगा और राहत केंद्र और कितना बढ़ेगा इसको कोई नहीं जानता है । अभी की संख्या इतनी है, यह मानकर मत चलिए, यह संख्या बहुत बढ़ेगी जो भी संभावना होगी उसके मुताबिक तो वैसी स्थिति में अगर हमलोग जांच नहीं करेंगे तो बाकी सब लोग इफेक्टेड हो जायेंगे तो इसलिये एक-एक का जांच करना भी जरूरी है तो उस हिसाब से भी हमलोगों ने कर दिया है । हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए अब जरूरत इस बात की है, अब इस बार तो चुनाव का साल है अब क्या होगा इलेक्शन कमीशन जाने, कई तरह की बातें हैं जो ऐसी स्थिति है कब तक यह बढ़ता जायेगा कोई जान रहा है ? हमलोगों को तो इतना लगता भी नहीं था, लगता था कि बढ़ेगा जरूर लेकिन जो जून और जुलाई से जो बढ़ा है और प्रतिदिन जांच ज्यादा हो रही है तो पता चल रहा है अगर जांच कम होगी तो पता भी कम चलेगा इसलिए बात सही है और जांच हर जगह करा कर पॉजेटिव वाला, लेकिन अब तो इनलोगों ने कहा है और हेल्थ डिपार्टमेंट लगा हुआ है कि आर.टी.पी.सी.आर भी 20 हजार और अगर जरूरत पड़ेगी तो हमलोग और करायेंगे । हमलोगों का तो फर्ज और दायित्व यही है

कि सबकी रक्षा करें तो उसके लिए जरूरत इस बात की है कि हमलोग अगर टेस्ट करते चले जायेंगे, ठीक है नम्बर बढ़े लेकिन उसमें बढ़ने के बाद जो प्रभावित लोग होते हैं वे दो प्रकार के लोग होते हैं । अभी हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने बताया कि जितने लोगों का डेथ हुआ है उसमें से लगभग 200 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको अन्य प्रकार की भी बीमारियां थी । इस बात को जानते हुए एक-एक चीज का ख्याल रखना है । कितना दुखद है, हमलोगों के एम.एल.सी की डेथ नहीं हुई ? सुनील जी दरभंगा के थे उनकी डेथ हुई है । अब बताइये सेक्रेटरी थे सीपीआई के सत्य नारायण बाबू उनकी डेथ हो गयी, कब किसकी डेथ हो जायेगी, क्या स्थिति होगी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते इसके लिए हर तरह की तैयारी करनी है, लोग लगे हुए हैं और हम सबलोगों को.....

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : मुख्यमंत्री जी ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री: एक चीज सुन लीजिए बस मेरा, फिर सुनेंगे आपका । एक चीज हम कहेंगे अध्यक्ष महोदय, हाउस की जो भी अवधि है, अभी तो कम-से-कम लीगली कहिए कि यह नवम्बर तक है तो हम एक चीज कहेंगे जरूर कि आप कोरोना को ध्यान में रखते हुए, हमारे नेता विरोधी दल का ध्यान है, सबका ध्यान है तो आप एक कमेटी बना दीजिए ऑल पार्टी, उस कमेटी के साथ भी चर्चा होगी जैसे हमलोग अन्य के साथ करते हैं उनको भी बैठा करके हमलोग एक-एक बात की चर्चा करेंगे ताकि वे लोग भी अपना सुझााव दे सकें और भी बेहतर काम कर सकें । इसलिए ये सबकुछ कर दीजिए, मिलकर काम करना है । यह पॉलिटिकल चीज है ही नहीं, वैसे तो स्टेटमेंट के लिए सबको आजादी है, लेकिन सबकी रक्षा करनी है, इसका कोई मतलब किसी न इलाके से, न किसी धर्म-मजहब से, न किसी जात-बिरादरी से है, हर कोई इससे प्रभावित है ।

...क्रमशः...

टर्न-34 आजाद/03.08.2020

..... क्रमशः .....

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम सबलोग एकजुट होकर के लोगों की मदद करने के लिए कुछ कर सकते हैं, इसलिए मैंने कहा कि आप ऑल पार्टी एक बनवा दीजिए ताकि वो लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट सम्पर्क में स्टेट गवर्नमेंट भी और जब भी हमलोग कोई समीक्षा करेंगे तो आप तय कर दीजिए 15 दिन के अंदर एक बार कम से कम उनको वही वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए वे

सब लोग जुट जाएंगे और अपने अनुभव के आधार पर लोगों को बतायेंगे, मैं तो इसके लिए भी तैयार हूं । सब कुछ कीजिए और सब लोग मिल करके हमलोग लोगों की रक्षा करें यही हम सब लोगों का दायित्व है, इसलिए हम इतना ही कहेंगे । अब तो यह चूंकि अंतिम सत्र है और आज जो पहले से तय था बोलिए 4 दिनों का हमलोगों ने किया था, लेकिन जब हम इसको 3 तारीख को तय किये थे पिछले महीने, उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था, इतना नहीं खतरा था लग रहा था कि तब तक कुछ बेहतर होगा । अब बताइए आते-आते इस समय और स्थिति खराब हो गई है कि आपने सर्वसम्मिति से लोगों से तय करके एक दिन में सब कुछ किया लेकिन खैर यह तो अपनी जगह पर है । हम सबको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं और सब लोग मिल करके अभी सबका काम कीजिए और कल जब होना होगा चुनाव, जो भी होना होगा सो होगा लेकिन हमलोगों का दायित्व तो एक राजनैतिक कार्यकर्त्ता के नाते हम सब लोगों का जनहित में सब लोगों का हित देखना है, आपस में कोई चीज कहने का एक अलग है लेकिन मिल करके हमलोग अपने बिहार वासियों की रक्षा करें यह हमलोगों का दायित्व है । हम दुहराकर कहते हैं कि हमलोगों का पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी ज्यादा है । इसलिए हम सब लोगों को अपनी आबादी की रक्षा के लिए सबको मिल करके काम करना है और हम इतना ही आश्वस्त करेंगे कि हमलोगों के स्तर से जो भी संभव हो और आपदा के बारे में आप शुरू से जानते हैं कि हमने सबसे कहा है कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है तो जो हमारे चाहे बाढ़ से प्रभावित हों या कोरोना से प्रभावित हों, ये सब आपदा पीड़ित हैं, इनके लिए जो भी करना होगा, हम सब लोग मिलकर करेंगे और आज हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने उपमुख्यमंत्री जी ने बता दिया कि आखिरकार हमलोगों ने कितना खर्च 4 महीने में ही कर दिया, तो इसलिए इसके बारे में नहीं, हम सब लोग सजग हैं, हम सबलोगों को सचेत रहना चाहिए और मिल करके काम करना चाहिए । कोरोना के मामले में सबलोगों को जागृत करने के लिए जो 4 बातें है, उसके लिए जरूर प्रयास करना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को ह्रदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट भाई, मुख्यमंत्री जी ने जिन बातों का जिक्र किया ये बात तो हमलोग शुरूआत दिन से ही कह रहे हैं और आखिरकार हमारी बात जो है विपक्ष की बात मानते हैं लेकिन 1-2 महीने बाद मानते हैं, करना वही है तो हमारा जो है कि भाई जब तीन सदस्यीय टीम जब आयी वो कहती है कि कोविड पर आपलोग कोई खर्च ही नहीं कर रहे हैं पैसा

यह तो केंद्र सरकार की ही है । जब कहता है नीति आयोग कि आप फिसड्डी हैं तो ये तो केंद्र सरकार का ही है और महोदय, मजदूरों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि जो भी आएंगे उसको रोजगार दिलाना जो है मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है । लेकिन मुख्यमंत्री ने कोई रोजगार का जिक्र नहीं किया, मजदूरों का जिक्र नहीं किया, उस चिट्ठी का भी जिक्र नहीं किया जिनमें मजदूरों को अपमानित किया गया तो ये सारी चर्चाएं जो हैं ये होनी चाहिए, महोदय, भूखे लोग मर रहे हैं, रोजगार नहीं है रोजगार पर भी हम लोग चाहेंगे कि वह ठीक है मिल-जुल करके काम करना है हम तो कहते रहें लेकिन आप ही 45 दिन बाद जो है अध्यक्ष महोदय, आपने वीडियो कांफ्रेंसिग कराई थी और हमने आज भी कहा है कमेटी क्यों बनाई जाए, सब विधायक जितने, जितने जनप्रतिनिधि हैं सबको ड्यूटी में लगा दीजिए । सबलोग ड्यूटी में लगेंगे सबलोगों का सही फीडबैक आएगा ग्राउंड से, जो अधिकारी कहता है वो मानते हैं 3-3 प्रधान सचिव आप बदल देते हैं तो हम तो कह रहे हैं विधायकों की भी जिम्मेदारी और ड्यूटी लगाई जाए सब अपने-अपने क्षेत्र में अपने-अपने अधिकारी से समीक्षा कर सकें और सरकार को सही फीडबैक दे सकें खाली कमेटी से नहीं, हमलोग तो चाह ही यह रहे हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है । आपका क्या है महबूब जी । ...

(व्यवधान)

कौन बोल रहे हैं ? ठीक है, अब उत्तर समाप्त हुआ ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : अध्यक्ष महोदय .....

अध्यक्ष: नेमतुल्लाह जी अब क्या है ? आप पुराने सदस्य हैं ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, कोरोना जनित मृत्यु पर मुआवजा की घोषणा होनी चाहिए, महोदय, कोरोना के कारण से जितने मजदूरों की मौत हुई है कोरोना से तड़प-तड़प कर, उनको मुआवजा मिलना चाहिए .....

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सरकार का उत्तर समाप्त हुआ और आप कृपया गंभीर हो जाएं, इसलिए कि हम इस 16वीं विधान सभा के समापन के करीब हैं, समापन के समीप हैं । इसलिए अब जो अंतिम औपचारिकताएं होती हैं, वह हम आपके सामने रख रहे हैं ।

महबूबजी, बैठ जाइए । कोरोना की मृत्यु पर जो-जो होना है, उसपर तो बात हो गई । अब बैठिए ।

माननीय सदस्यगण, षोडश बिहार विधान सभा का 16वां एवं अंतिम सत्र आज समाप्त हो रहा है । आपको स्मरण होगा कि 30 नवंबर, 2015 को इस 16वीं

विधान सभा की पहली बैठक हुई थी और 02 दिसंबर, 2015 को आप सबों ने सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष के इस आसन पर बिठाया था । उस दिन आपके, हमारे और इस आसन के बीच एक भरोसे का रिश्ता कायम हुआ था । आप सबों ने मुझसे इस पद की गरिमा के अनुरूप व्यवहार की अपेक्षा की थी और मैंने भी आपको आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप आचरण करने का विश्वास दिलाया था ।

आज इस विधान सभा के आखिरी सत्र के आखिरी दिन का आखिरी समय आ गया है । इस अवसर पर अपनी तरफ से मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अपने कार्यकाल में मैंने आपके भरोसे को ईमानदारी से निभाने की कोशिश की है । संवैधानिक प्रावधानों एवं विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियमों के मुताबिक हमने सदन चलाने का प्रयास किया । राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हमने बिहार की विधायिका के सम्मान को आगे बढ़ाने की चेष्टा की ।

इन सब के बावजूद हो सकता है कि मेरे द्वारा कुछ ऐसे कार्य अथवा निर्णय हुए होंगे जिन से आप सहमत नहीं होंगे, मुझे इसका अफसोस है । हालांकि, इतना मैं फिर आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि वे निर्णय या तो मेरी वैधानिक मजबूरी होगी या फिर कोई गैर-इरादतन चूक रही होगी । संज्ञानपूर्वक संसदीय प्रणाली की उच्च परम्परा को मैंने कायम रखने की कोशिश की और कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहा जो सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं हो या जिससे आपकी भावना आहत हो ।

माननीय सदस्यगण, राजनीति करवटें बदलती हैं परंतु जनतांत्रिक प्रणाली में एवं इसके मूल्यों में हम और आप सभी का दृढ़ विश्वास इस सदन की मर्यादा और गरिमा को अक्षुण्ण रखता है । मेरे पूरे कार्यकाल में इस उच्च परम्परा को कायम रखने में सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों से मिले लगातार सहयोग के लिए मैं आपके प्रति ह्रदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं । आप सब ने अपने दायित्वों का बखूबी से निर्वहन किया है और राजनीतिक मतभेदों के बावजूद आपने जिस ढंग से संसदीय मर्यादाओं का पालन किया है, उसका निर्वहन किया है उससे इस सदन का मान बढ़ा है । आज आखिरी दिन है, चुनाव सामने है और हम एक बार फिर से जनता की अदालत में पेश होने वाले हैं । आने वाले समय के लिए मैं आप सबों को इस आसन की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही मुझे ऐसे वक्त में दो पंक्तियां कहने को जी कर रहा है-

''कल न जाने हम में से कौन यहां होगा,
फिर भी बीती यादों का सिलसिला होगा,

आइए इस लम्हे की दुआ मिल कर लें हम,

जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा''

अब इससे पहले कि मैं सदन स्थगित करूं कतिपय जननेताओं के निधन की सूचना मिली है जिनके प्रति शोक प्रकट करना हमारा कर्त्तव्य है :-

स्वर्गीय राम पदारथ महतो

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री राम पदारथ महतो का निधन दिनांक 08 अप्रैल, 2020 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 91 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय महतो समस्तीपुर जिला के दलसिंहसराय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2000 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे । वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय उपेंद्र प्रसाद वर्मा

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा का निधन दिनांक 09 अप्रैल, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 73 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय वर्मा मुंगेर जिले के जमालपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980, 1985, 1990, 1995 एवं 2000 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। वे एक समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

टर्न-35/शंभु-हेमन्त/03.08.20

अध्यक्ष : स्वर्गीय वीरेंद्र प्रसाद सिंह

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री वीरेंद्र प्रसाद सिंह का निधन दिनांक 13 अप्रील, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 67 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय सिंह औरंगाबाद जिला के ओबरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे एक सहृदय व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय देवानन्द कुंवर

बिहार के पूर्व राज्यपाल श्री देवानन्द कुंवर का निधन दिनांक 25 अप्रील, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 86 वर्ष की थी।

स्वर्गीय कुंवर बिहार के साथ-साथ पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के राज्यपाल भी रह चुके थे । बिहार में उनका कार्यकाल जून, 2009 से मार्च, 2013 तक था । वे एक कुशल राजनेता थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय योगेंद्र प्रसाद साहू

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री योगेंद्र प्रसाद साहू का निधन दिनांक 19 मई, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 90 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय साहू वैशाली जिला के लालगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1995 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का निधन दिनांक 24 मई, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 75 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय सिंह गिरीडीह जिला के बेरमो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1985, 1990, 1995 एवं 2000 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे । वह लोकप्रिय श्रमिक नेता एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय सरोज दूबे

लोकसभा एवं राज्यसभा की पूर्व सदस्या श्रीमती सरोज दूबे का निधन दिनांक 21 जून, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 82 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय दूबे वर्ष 1991 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा एवं वर्ष 1998 से 2004 तक बिहार से राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हुई थीं । वह मृदुभाषी एवं लोकप्रिय राजनेता थीं । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय विद्यासागर निषाद

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री विद्यासागर निषाद का निधन दिनांक 14 जुलाई, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 86 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय निषाद खगड़िया जिला के परबत्ता विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1990 एवं 1995 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे । वे वर्ष 2004 में राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय राम अवधेश सिंह

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री राम अवधेश सिंह का निधन दिनांक 20 जुलाई, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 83 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय सिंह आरा जिला के आरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1969 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे वर्ष 1977 में लोक सभा एवं 1986 में राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । समाज के शोषितों एवं पीड़ितों के उत्थान के लिए वे सदैव संघर्षरत रहे थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय लालजी टंडन

बिहार के पूर्व राज्यपाल श्री लालजी टंडन का निधन दिनांक 21 जुलाई, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 85 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय टंडन 23 अगस्त, 2018 से 28 जुलाई, 2019 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे । वर्तमान में वे मध्यप्रदेश के राज्यपाल थे । वे एक कुशल प्रशासक एवं लोकप्रिय राजनेता थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय सुनील कुमार सिंह

बिहार विधान परिषद् के वर्तमान सदस्य श्री सुनील कुमार सिंह का निधन दिनांक 21 जुलाई, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 70 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय सिंह दरभंगा जिला के दरभंगा क्षेत्रीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2015 में बिहार विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वह एक कर्मठ एवं मिलनसार व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय नरेश दास

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री नरेश दास का निधन दिनांक 22 जुलाई, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 80 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय दास बांका जिला के धोरैया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1972, 1977, 1980, 1990 एवं 1995 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे मृदुभाषी एवं मिलनसार व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन दिनांक 23 जुलाई, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 78 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय सिंह का औरंगाबाद जिला के नवीनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980, 1985 एवं 1990 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे लोकप्रिय एवं मिलनसार व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय विजय नारायण भारती

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री विजय नारायण भारती का निधन दिनांक 25 जुलाई, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 83 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय भारती बक्सर जिला के डुमरांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1981 के उप-चुनाव में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे लोकप्रिय एवं मिलनसार व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय सत्य नारायण सिंह

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री सत्य नारायण सिंह का निधन दिनांक 02 अगस्त, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 78 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय सिंह खगड़िया जिला के चौथम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1990 एवं 1995 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे प्रखर साम्यवादी विचारधारा के व्यक्ति थे । वे कर्मठ, मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

माननीय सदस्यगण, इस सबके अलावा प्रदेश में कोविड-19 महामारी से लोगों की लगातार असमय मृत्यु हो रही है । पूरा सदन इससे मर्माहत है । ईश्वर उन सभी दिवंगत आत्माओं को शान्ति एवं उनके शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

साथ ही ईश्वर से प्रार्थना है कि इस प्रदेश, राष्ट्र के साथ पूरे विश्व को इस महामारी से शीघ्र निजात दिलाएं ।

अब हमलोग एक मिनट तक मौन खड़े होकर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें ।

(एक मिनट का मौन)

मैं अपनी तथा सम्पूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भिजवा दूंगा ।

अंत में, इस मनोभाव के साथ कि--

अब तो चलते हैं इस बुतकदे से मीर,
फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट–1

बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

माननीय मंत्री के भाषण का अंश

बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 के मुख्य प्रावधान

1. दिनांक 01 जुलाई, 2017 से पूरे देश में माल और सेवा कर प्रणाली लागू है। तदनुरूप बिहार राज्य में भी बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अधिसूचित किया गया। इस प्रणाली से जुड़े विभिन्न पक्षों द्वारा अनुभूत समस्याओं पर विचारोपरान्त जीएसटी परिषद की 38 वी बैठक में माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन की अनुशंसा की गयी। परिषद की अनुशंसाओं के आलोक में संसद द्वारा यथा पारित Finance Act, 2020 के माध्यम से CGST Act में संशोधन किये गये है। तदनुरूप जीएसटी परिषद् द्वारा सभी राज्यों से राज्य अधिनियम में वांछित संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. जीएसटी एक राष्ट्रीय प्रणाली है एवं CGST Act तथा SGST Act एक दूसरे के प्रतिबिंब (Mirror Image) है। अतः केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम में किये गये उपरोक्त संशोधन के आलोक में बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन करते हुए बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या–09, 2020) प्रख्यापित किया गया है। बिहार अध्यादेश संख्या–09, 2020 द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किये गये संशोधन को बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 के द्वारा विधायित करने का प्रस्ताव है, जिसके द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 मुख्यतः निम्न संशोधन प्रस्तावित है –

- प्रशमन उदग्रहण (Composition Levy) की पात्रता की शर्तों को माल या सेवाओं की आपूर्ति में संलग्न व्यवसायियों के समरूप बनाने हेतु धारा 10 में संशोधन का प्रस्ताव है।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त करने हेतु डेबिट नोट जारी करने की तिथि को अन्तर्निहित विपत्र (underlying invoice) की तिथि से अलग (Delink) किये जाने हेतु धारा 16 की उप–धारा (4) में में संशोधन का प्रस्ताव है।
- अधिनियम की धारा 25 की उप–धारा (3) के अन्तर्गत स्वेच्छा से लिये गये निबंधन के सामने में रद्दीकरण के प्रावधान बनाने हेतु धारा 29 में संशोधन का प्रस्ताव है।
- निबंधन के रद्दीकरण का निरसन (Revocation) करने के लिए आवेदन देने की समय सीमा में विस्तार करने हेतु अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त/आयुक्त को शक्तियाँ दिये जाने हेतु धारा 30 में संशोधन का प्रस्ताव है।
- सरकार द्वारा सेवाओं या पूर्तियों के प्रवर्ग को अधिसूचित किये जाने, जिसके द्वारा ऐसे समय और रीति से, जो विहित की जाए, कर बीजक जारी किया जा सकेगा, हेतु धारा 31 में संशोधन का प्रस्ताव है।

- सरकार को श्रोत पर कर की कटौती से संबंधित प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रारूप एवं नीति संबंधी नियम बनाने की शक्तियाँ दिये जाने हेतु धारा– 51 में संशोधन का प्रस्ताव है।
- कुछ निश्चित सव्यवहारों के लाभार्थी जिन्होंने अनुमान्यता से अधिक क्रेडिट का लाभ लिया है एवं जिनके अनुरोध पर ऐसे सव्यवहार किये गये हैं का दंड हेतु दोषी बनाये जाने हेतु 122 में एक नई अध्याय 1(क) के अंतःस्थापन का प्रस्ताव है ।
- बिना बीजक या बिल के इनपुट टैक्स क्रेडिट का कपटपूर्वक उपयोग संज्ञेय एवं गैरजमानती अपराध बनाये जाने एवं ऐसे सव्यवहारों के लाभार्थी जिनके अनुरोध पर ऐसे सव्यवहार किये गये हैं को भी दंड हेतु बनाये जाने हेतु धारा– 132 में संशोधन का प्रस्ताव है ।
- दिनांक– 21 जुलाई, 2017 के प्रभाव से पुराने अधिनियमों (Existing Law) के तहत कतिपय उपयोग नहीं किये जो (Unavailed) इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त करने के लिये समय–सीमा एवं गति विहित करने की शक्ति सरकार को प्रदान किये जाने हेतु धारा– 148 में संशोधन का प्रस्ताव है ।
- कठिनाइयों के निवारण (Removed Of difficulty) हेतु प्रदान की गई समय–सीमा को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किये जाने हेतु धारा– 172 में संशोधन का प्रस्ताव है ।

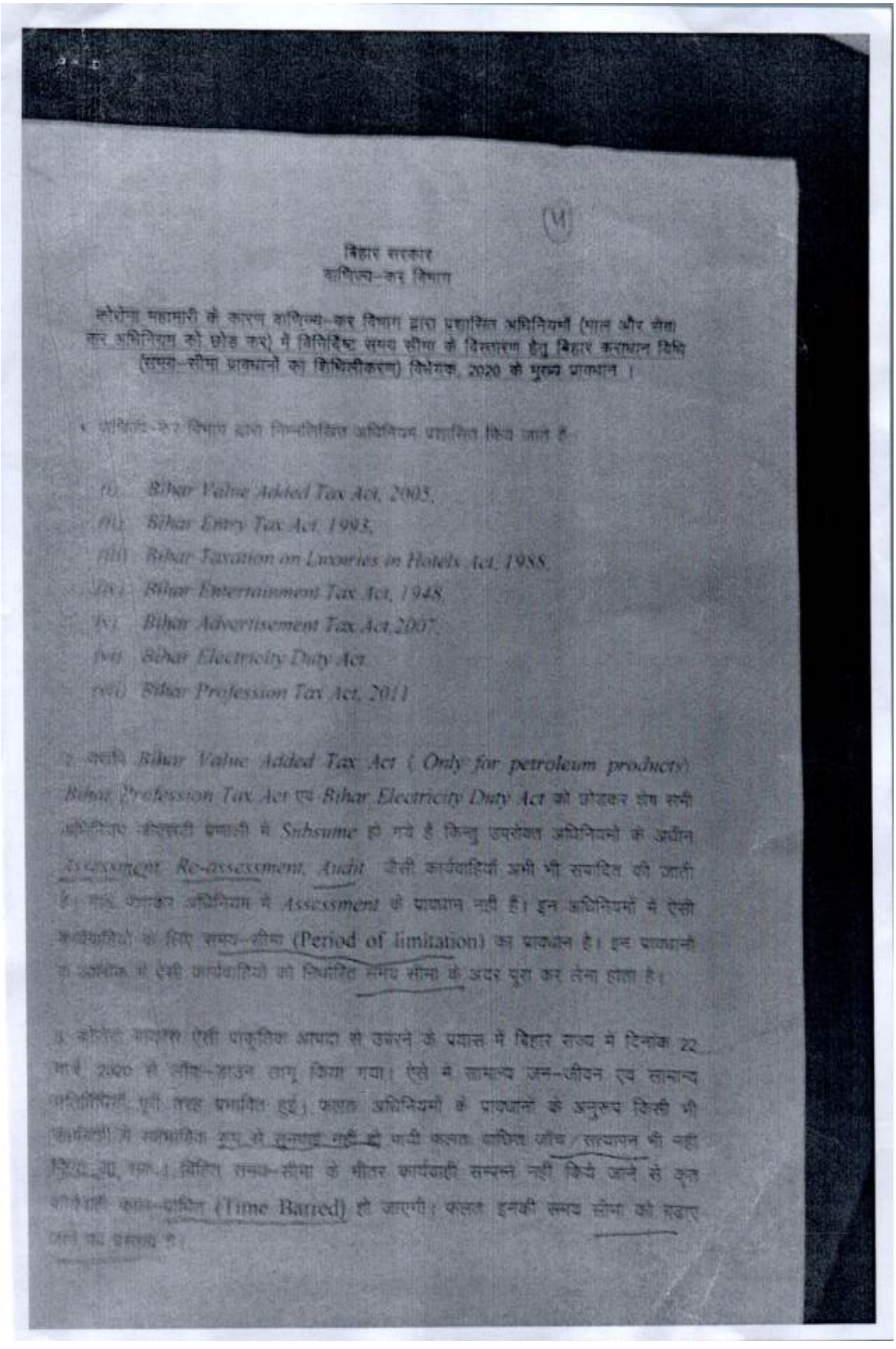

(५)

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

कोरोना महामारी के कारण वाणिज्य-कर विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियमों (माल और सेवा कर अधिनियम को छोड़ कर) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के विस्तारण हेतु बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2020 के मुख्य प्रावधान ।

1. वाणिज्य-कर विभाग द्वारा निम्नलिखित अधिनियम प्रशासित किये जाते हैं:-

(i) *Bihar Value Added Tax Act, 2005,*
(ii) *Bihar Entry Tax Act 1993,*
(iii) *Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988,*
(iv) *Bihar Entertainment Tax Act, 1948,*
(v) *Bihar Advertisement Tax Act,2007,*
(vi) *Bihar Electricity Duty Act*
(vii) *Bihar Profession Tax Act, 2011*

2. यद्यपि *Bihar Value Added Tax Act (Only for petroleum products)*, *Bihar Profession Tax Act* एवं *Bihar Electricity Duty Act* को छोड़कर शेष सभी अधिनियम जीएसटी प्रणाली में *Subsume* हो गये हैं किन्तु उपरोक्त अधिनियमों के अधीन *Assessment, Re-assessment, Audit* जैसी कार्यवाहियाँ अभी भी सम्पादित की जाती हैं। मात्र मनोरंजन अधिनियम में *Assessment* के प्रावधान नहीं हैं। इन अधिनियमों में ऐसी कार्यवाहियों के लिए समय-सीमा (Period of limitation) का प्रावधान है। इन प्रावधानों के आलोक में ऐसी कार्यवाहियों को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा कर लेना होता है।

3. कोरोना वायरस जैसी प्राकृतिक आपदा से उबरने के प्रयास में बिहार राज्य में दिनांक 22 मार्च 2020 से लॉक-डाउन लागू किया गया। ऐसे में सामान्य जन-जीवन एवं सामान्य गतिविधियाँ पूरी तरह प्रभावित हुईं। फलतः अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप किसी भी व्यवसायी से व्यक्तिगत रूप से सुनवाई नहीं हो पायी फलतः वांछित जाँच/सत्यापन भी नहीं किया जा सका। विहित समय-सीमा के भीतर कार्यवाही सम्पन्न नहीं किये जाने से कुल कार्यवाही काल-बाधित (Time Barred) हो जाएगी। फलतः इनकी समय सीमा को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।

4. उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 31.03.2020 को अध्यादेश जारी करते हुए कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केन्द्र द्वारा प्रशासित Income Tax Act, 1961, Wealth Tax Act, 1957 जैसे विभिन्न अधिनियमों में दिनांक 20 मार्च, 2020 से 29 जून 2020 के दौरान उत्पन्न होने वाले दायित्वों एवं अन्य समय-सीमाओं को दिनांक 30.06.2020 तक विस्तारित कर दिया गया है।

5. अतीत परिप्रेक्ष्य में वाणिज्य-कर विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियमों में कर-निर्धारण संबंधी आदेश, अपील एवं Tribunal द्वारा Remand case एवं अन्य आदेश जो विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंदर पूरे नहीं किए जा सके हैं, की समय-सीमा विस्तारित किये जाने का प्रस्ताव है।

6. किन्तु इन अधिनियमों के अधीन किसी विवरणी को दाखिल करने अथवा किसी कर, ब्याज, शास्ति अथवा फाईन के भुगतान की तिथि इससे विस्तारित नहीं होगी।

7. उक्त के आलोक में कंडिका-1 में उल्लेखित वाणिज्य-कर विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियमों (माल और सेवा कर अधिनियम को छोड़ कर) में

विवरणी दाखिल करने एवं किसी कर, ब्याज, शास्ति, फाईन अथवा अपेक्षित अन्य किसी राशि के भुगतान की गतिविधि को छोड़कर

अन्य किसी कार्यवाही को पूरा करने या किसी आदेश को पारित करने के लिए विनिर्दिष्ट अधिनियम के अधीन ऐसी समय सीमा जो 20 मार्च, 2020 से 29 जून, 2020 के दौरान आती हो, को पूरा करने या उसका अनुपालन करने के लिए इसे दिनांक 31.12.2020 तक विस्तारित करने एवं इन्हें 1 वर्ष से अनधिक अवधि हेतु पुनः विस्तारण का अधिकार राज्य सरकार को प्रदान करने हेतु विधेयक लाया गया है।

8. इस हेतु पूर्व में बिहार अध्यादेश संख्या-10, 2020 प्रख्यापित किया गया है ।

बिहार सरकार

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार राज्य के डीजल एवं पेट्रोल के दर में .....पुनर्निर्धारण हेतु बिहार ..विधि (संशोधन) विधेयक, 2020 के मुख्य प्रावधान

1. बिहार में पेट्रोल एवं डीजल पर.....

SL No.			
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Petrol	26%	If sale price dose not exceed Rs. 65 per litre
		22%	If sale price exceeds Rs. 63 per litre
2	Diesal	19%	If sale price does not exceed Rs. 64 per litre
		15%	If sale price exceed Rs. 64 per litre

2. इसके अलावा इनको बिक्री पर 30% की दर से सरचार्ज भी भुगतेय है ।
3. इससे पूर्व पेट्रोल पर देय वैट की दर 22.20% जबकि डीजल पर भुगतेय वैट की दर 55% थी जिसे दिनांक 24.10.2019 के संशोधित करते हुए उपरोक्त तालिका के अनुसार लागू किया जाय ।
4. उल्लेखनीय है कि अतंर्राष्ट्रीय बाजार में क्रुड ऑयल की गिरती हुई कीमतों एवं कोरोना महामारी के कारण डीजल एवं पेट्रोल से प्राप्त होनेवाले राजस्व में लगातार कमी हो रही थी । इन हालात को देखते हुए इनके भविष्य में और गिरने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता था ।

5. बिहार राज्य में पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल ऑयल, प्राकृतिक गैस, केमिकली [illegible] अथवा पेट्रोलियम तेल के विक्रय मूल्य के आधार पर करारोपण किये जाने के प्रावधान हैं जो निम्न प्रकार हैं:–

Tax shall be payable on the sale price of the goods at such rate not exceeding fifty percent and subject to such conditions and restrictions, as the State Government may, by notification specify."

6. जबकि देश के विभिन्न राज्यो में इनके विक्रय मूल्य अथवा प्रति लीटर दर एक निश्चित राशि के आधार पर करारोपण किये जाने के प्रावधान है।

7. वर्णित परिप्रेक्ष्य में बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 14, जिसमें करारोपण के प्रावधान हैं, में संशोधन किया गया। संशोधित प्रावधान निम्न प्रकार हैं –

"14. The tax payable under the Act shall be calculated on the basis of-

(a) The sale price of the goods at such rate not exceeding fifty percent; or

(b) The weight or volume of the goods at such rate not exceeding fifty rupees per litre; or

(c) Any combination of clauses (a) or (b),

as the State Government may, by notification, specify and subject to such conditions and restrictions as may be specified in the said notification."

8. कराधान की इस व्यवस्था को लागू करने के लिए बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 में वजन/मात्रा/परिमाण के आधार पर करारोपण हो सकेगा।

9. इस हेतु पूर्व में बिहार अध्यादेश संख्या–01, 2020 प्रख्यापित किया गया है।

जाने का निर्णय लिया गया तथा इस कार्यक्रम का नामकरण **कुशल युवा कार्यक्रम** रखा गया। राज्य में कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन का दायित्व बिहार कौशल विकास मिशन का है।

कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन हेतु राज्य सरकार के द्वारा सभी प्रखण्डों में एक एक कौशल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। 7 निश्चय के अधीन आर्थिक हल युवाओं को बल का शुभारम्भ बापू की जयंति के अवसर पर दिनांक 2 अक्तूबर 2016 को किया जा चुका है तथा दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 से आर्थिक हल युवाओ को बल का एक घटक कुशल युवा कार्यक्रम का संचालन प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रो में प्रारंभ कर दिया गया है ।

कुशल युवा कार्यक्रम का संचालन बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्मित प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों तथा विभिन्न प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों के स्वयं के द्वारा स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रो के माध्यम से किया जा रहा है। कुशल युवा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अबतक 1602 केन्द्रो की स्थापना की जा चुकी है। अबतक कुल 363994 अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है तथा लगभग 91036 प्रशिक्षणरत है।

बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा राज्य मे रोजगार के अवसर उत्पन्न करने तथा रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण प्रारंभ किए जाने के उद्देश्य से देश के नामचीन देशी एवं विदेशी एजेंसियों के साथ कई चरणो में विचार विमर्श किया गया तथा विमर्शोपरान्त राज्य ने **RTD (Recruit, Train & Deploy**–भर्ती प्रशिक्षण एवं तैनाती) योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया। यह योजना कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक अनूठी योजना है तथा राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ही प्रदेशों के द्वारा इस मॉडल को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। आमतौर पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी के द्वारा प्रशिक्षणार्थियो को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के पश्चात् उनका मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण कराकर तीन माह के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है लेकिन इस मॉडल मे देश एवं विदेश के नामचीन कंपनियों/संगठनों के द्वारा देश तथा विदेश में स्थापित अपने कंपनियो/संगठनों के लिए अपने मांग के अनुरूप सर्वप्रथम राज्य के युवाओं को चयनित किया जाएगा तथा अपने संगठन की आवश्यकता के अनुरूप अपने द्वारा स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों में 150 घण्टे से 600 घण्टे तक का आवासीय/गैर आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करते हुए अपनी संस्था के माध्यम से मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण कर सफल प्रशिक्षित युवाओं को अपने संगठनों में देश तथा विदेश में रोजगार मुहैय्या कराया जाएगा।

RTD Model के संचालन हेतु चयनित इन संगठनों के द्वारा राज्य में एवं देश के अन्य शहरों में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। प्रशिक्षण का माड्यूल तथा पाठ्यक्रम चयनित इन्हीं कंपनियों के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जिसकी स्वीकृति बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा प्रदान की गयी है। इस योजना के तहत ज्यादा वेतन देने वाले या विदेशो में रोजगार दिलाये जाने वाले कंपनियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने का भी प्रावधान है। इस योजना के तहत 1 वर्ष में राज्य के 10 हजार युवाओं को प्रशिक्षित एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। कार्यक्रमों की योजना तैयार करने, क्रियान्वयन एवं निगरानी हेतु पी एम यू एवं नॉलेज पार्टनर टीम स्थापित की गयी है जो राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर कार्यरत हैं। दोनो में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ अपना योगदान दे रहे हैं।

2. बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा चलाये जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों की उपलब्धियाँ–

1. राज्य सरकार के सात निश्चय के अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत कुशल युवा कार्यक्रम के केन्द्रो के चयन की प्रक्रिया का शुभारम्भ दिनांक–15 जुलाई, 2016 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रारम्भ की गयी थी। 15 दिसम्बर, 2016 से पहला प्रशिक्षण बैच प्रारम्भ हुआ जिसमे 48 केन्द्रो मे 1973 बच्चों का प्रशिक्षण प्रारम्भ हुआ।

2. सामान्यतया माह के पहली तारीख को बैच प्रारम्भ किया जाता है। अबतक कुल लगभग 831530 आवेदकों को प्रशिक्षण हेतु स्वीकृति दी जा चुकी है जिनमें से 363994 आवेदक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है एवं लगभग 91036 आवेदक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है।

3. कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन के लिए अब तक 1602 केंद्र स्थापित किये गए है जो बिहार के 38 जिले के लगभग सभी प्रखण्डों में स्थित है ।
4. डोमेन स्क्रीनिंग कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार के 16 विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत युवाओं के प्रशिक्षण दिया जा रहा है । इसके माध्यम से 15 से 59 आयु वर्ग के सभी युवाओं को जिनका पूर्व में किसी प्रक्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण का अनुभव नहीं है उन्हें प्रशिक्षण देकर संबंधित क्षेत्र में रोजगार या स्वरोजगार का अवसर दिया जा रहा है यह कार्यक्रम 23 सेक्टरों के 107 पाठ्यक्रमों में चलाया जा रहा है । अब तक 892 केंद्रों को बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा अंतिम रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है इनमें से 393 केंद्रों पर प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुका है । 11399 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है तथा 13807 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।
5. बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा राज्य में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने तथा रोजगार परख कौशल प्रशिक्षण प्रारंभ करने के उद्देश्य से भर्ति प्रशिक्षण एवं **उन्नति योजना प्रारंभ** की गई है जो राज्य सरकार की अनुठी पहल है । इस योजना में प्रशिक्षण प्रदत एजेंसी के द्वारा पहले प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाता है तथा उन्हें अपने मांग के अनुरूप अपने संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण कर सफल प्रशिक्षित युवाओं को अपने संगठनों में देश तथा विदेश में रोजगार मुहैया कराया जाता है इस योजना के अंतर्गत अब तक 1248 युवाओं को लाभ मिल चुका है जिसमें 123 दिव्यांग हैं तथा 349 की नियुक्ति विदेश में हुई है ।
6. सभी प्रकार के प्रशिक्षण की मॉनेटरिंग बिहार कौशल मिशन के पोर्टल के माध्यम से की जा रही है जिसकी शुरूआत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2016 में 15 जुलाई को किया गया था ।
7. बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा विभागों के सहयोग के लिए प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण के व्यय को भी संचालित किया जा रहा है एवं साथ ही साथ प्रशिक्षणार्थियों के लिए किताबों इत्यादी का भी व्यवस्था की प्रक्रिया प्रारंभ किया गया है ।
8. इस वर्ष से भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत राज्य कम्पोनेन्ट के अधीन बिहार के लिए 3 वर्षो में कुल 137 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है एवं प्रथम किस्त की 36 करोड़ रूपये की राशि भी विमुक्त की जा चुकी है । बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा इसके क्रियान्वयन के लिये प्रशिक्षण केंद्रों की चयन की कार्रवाई की गई है इसके तहत लगभग 90,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा ।
9. टी0भी0 एवं सिनेमा हॉल में विज्ञापन के माध्यम से भी कुशल युवा का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है । इसके अलावा बैनर, पोस्टर, सामग्रियों के द्वारा भी इसका प्रचार किया गया है एवं जीविका समुहों के माध्यम से भी बड़े पैमाने पर प्रचार करने की योजना है ।

3. दिनांक 15 जुलाई – 2018 को आयोजित होने वाले कार्यक्रम :–

1. राज्य में 16 विभागों के माध्यम से डोमेन स्क्रीनिंग में प्रशिक्षण दिया जा रहा है । इस विभाग के 6 उत्कृष्ट विभाग जिन्होंने डोमेन स्क्रीनिंग में योजना के प्रारंभिक समय से प्रमुखता से भाग लिया है तथा सबसे अधिक प्रशिक्षण बैचों के साथ–साथ बेहतर तरीके से संचालन एवं उनके नियोजन के लिए प्रयास किया है उन्हें पुरस्कृत किया जायेगा । ये विभाग – कृषि विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, समाज कल्याण विभाग, सूचना एवं प्राद्योगिकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग है ।
2. जिन 6 जिला के जिला पदाधिकारियों के नेतृत्व में जिले में कुशल युवा कार्यक्रम के उम्मीदवारों का सबसे अधिक पंजीकरण, कार्यक्रम का बेहतर संचालन एवं युवाओं को रोजगार दिलाने के लिये विशेष प्रयास किये गए हैं उन्हें भी सम्मानित किया जायेगा वे जिले शेखपुरा, मुंगेर,

बोर्ड आज के प्रबंधन के लिए जरूरी होने पर एक पूर्णकालिक परियोजना निदेशक या सीईओ या एक एक छोटी प्रबंधन समिति नामित कर सकता है ।

5.0 प्रकिया

1) पात्र संगठन संस्थान के तकनीकी क्षमता, वित्त के साधन, परियोजना के निष्पादन की पद्धति, औचित्य के साथ निश्चित परिसपत्तियों की आवश्यकता के साथ-साथ गतिविधियों के ब्योरे सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ अध्यक्ष - एमपीएसएसडीईजीबी को आवेदन करता है । परियोजना आदि के लिए अवश्यक तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मियों

2) एमओयू / समझौते की प्रति जमा करे, यदि अन्य संस्थान के साथ सहभागिता में CoE स्थापित किया जाना है ।

6.0 राज्य स्तरीय अधिकारित समिति (SLEC) एसएलईसी में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

MPSSDEGB के अध्यक्ष	अध्यक्ष
प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा और कौशलन विकासशील	सदस्य
क्षेत्र के विषेशज्ञ	सदस्य
MPSSDEGB के सी ए ओ	सदस्य सचिव

एमपीएसएसडीईजीबी सदस्य सचिव समिति को योग्य परियोजना की जांच और मंजूरी देने का अधिकार है । परियोजना को मंजूरी देते समय समिति कौशल विकास के लिए प्रस्तावित प्रौद्योगिकी के स्तर, उद्योग में उद्योग और कुशल जनशक्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखेगी और डीआईपीपी स्वीकृत मेगा परियोजना और फोकस क्षेत्रों को "भारत में बनाओं" राष्ट्रीय मिशन ।

7.0 अन्य शर्त्तें

1. संगठन की मंजूरी की तारीख से 3 साल की अधिकतम अवधि के भीतर अनुमोदित CoE को कार्यान्वित किया जाता है ।

2. CoE की स्थापना करने वाले संगठन को परियोजना के चालू होने के 5 साल बाद प्रस्तावित डिलिवरेबल्स (delievrables) देना होगा।

3. यदि परियोजना परियोजना में परिभाषित परिणामों को वितरित नहीं करती है, तो एसडीईजीबी और / या सरकार परियोजना की सभी संपत्तियों और परियोजना के आवेदक संगठन के कर्मचारियों और देनदारियों के साथ अन्य निश्चित परिसंपत्तियों के साथ परियोजना को लेने के लिए अधिकृत है। । समिति इस प्रस्ताव में उल्लिखित अन्य संस्थानों को परियोजना सौंप सकती है।

4. परियोजना के लिए आवेदन करने वाली एजेंसी को एमपी कौशल विकास और रोजगार बोर्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा कि नियम और शर्तें उनके लिए बाध्यकारी हैं और इस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद सहायता वितरित की जाएगी।

5. परियोजना लागत का 50% अधिकतम वितरण अग्रिम भुगतान के रूप में जारी किया जा सकता है और मशीनों और उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना के पूरा होने पर शेष 50% शेष राशि का भुगतान किया जा सकता है।

6. स्वीकृत परियोजना कार्यकाल सफलतापूर्वक खत्म होने के बाद, सरकार के पास निम्न लिखित विकल्प हो हो सकते हैं

ए) किसी भी विश्वविद्यालय या सरकारी एजेंसी को CoE दान करें

बी) एसएल इ सी से अनुमोदित राजस्व मॉडल के साथ CoE जारी रखें।

सी) इसे राजस्व मॉडल पर ऊष्मायन (incubation) केंद्र या स्टार्ट अप समर्थन केंद्र में परिवर्तित करें

<u>8.0 बजट</u>

प्रमुख मांग संख्या -

मेजर हेड -

उप-मेजर हेड -

माइनर हेड -

सब हेड -

योजना कोड -

सरकार के उप सचिव

मध्य प्रदेश कौशल विकास और रोजगार निर्माण विभाग सरकार

परिशिष्ट–2 for your information

कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए नीतीश सरकार को दो मोर्चो पर एक साथ काम करना चाहिए था !!

1)संक्रमण दर को कम करने

2)अस्पतालों की क्षमता वर्धन पर

नितीश सरकार के पास शुरू से ही कोई समग्र योजना नहीं रहा जिसका नतीजा ये हुआ की आज इस वायरस का फैलाव सामुदायिक स्तर पर हो चूका है।कांटेक्ट ट्रेसिंग में संक्रमण चेन को लिंक नहीं कर पा रहे।नीतीश सरकार की कार्यशैली और रवैया अगर देखे तो ये समझ आयेगा की उन्होंने सिर्फ प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण से ही काम किया है।

बिहार सरकार ने पहले दिन से ही जांच में लापरवाही बरती और देश में सबसे कम जाँच किया जो सिलसिला अभी तक चला आ रहा।जब प्रतिदिन जाँच की जरुरत 5000 थी तो बिहार 500 जाँच करता था और आज जब जरुरत 50,000 जाँच की है तो बमुश्किल 10,000 जाँच कर पा रहा।

हमने शुरू से ही जाँच की गति और दायरा बढ़ाने का मांग किया था ताकि सही समय पर संदिग्धों की पहचान हो पाए,मरीजों का इलाज हो पाए और संक्रमण चेन को तोड़ा जा सके लेकिन नीतीश जी कम केस दिखाने के चक्कर में जाँच ही नहीं करा रहे थे।नतीजन संक्रमण अनियंत्रित होकर बहुत तेज़ी से फैलता गया। आज देश भर में बिहार का TPR(Test Positivity Rate) जो कि लगभग 10 प्रतिशत है देश में सबसे ज्यादा है जो इस बात को प्रमाणित करता है की कम जाँच होने से संक्रमण में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। जाँच की संख्या बढ़ी तो मरीजों की संख्या भी बढ़ी।

हमने अप्रैल महीने में कहा की जाँच केंद्रों की संख्या बढ़ायी जाए और प्रत्येक जिले में इसकी व्यवस्था की जाए लेकिन नीतीश जी इसको भी टालते रहे और आज स्तिथि इतनी भयावह हो चुकी है की सरकार अनुमंडल/ब्लॉक स्तर पर जाँच करने की योजना बना रही।समय अगर ये भी किया होता तो अधिक से अधिक लोगों की जाँच हो सकती थी और उचित समय पर इलाज। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता की संक्रमण लोकल स्तर पर ही रहता,उसका फैलाव अन्य इलाकों में नहीं होता।

नीतीश कुमार ने अस्पतालों की क्षमता वर्धन (capacity building) के तरफ बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया जबकि WHO और ICMR ने सभी राज्यों को इस पर गंभीरता से काम करने के लिए कहा था। लॉकडाउन सभी सरकारों को इन्ही बिंदुओं पर काम करने का अतिरिक्त समय दिया था जिन्होंने काम किया वहाँ बीमारी पर बहुत हद तक काबू पाया और बिहार सरकार जो सोती रही आज हमारा राज्य कोरोना हाट्स्पॉट बन गया है।

फील्ड हॉस्पिटल बनाने के लिए मैंने लगातार आग्रह किया। 12.6 करोड़ आबादी वाले राज्य के लिए मात्र एक कोविड डेडिकेटेड अस्पताल से सरकार की कोरोना मैनजमेंट का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के बाद सरकार जागी है और इस दिशा मे काम करने जा रही और मेक्शिफ्ट हॉस्पिटल बनाने की तैयारी कर रही।

कमिशनरी और जिला स्तर पर कोविड अस्पताल स्थापित करने का भी मैंने नीतीश जी को कई बार आग्रह किया लेकिन वो इसको अनसुनी करते रहे। आज सरकार को देर-सवेर मेरी बात माननी पड़ रही और सरकार ने जिला/अनुमंडल स्तर पर कोविड अस्पताल स्थापित करने का निर्णय लिया है।

अस्पतालों में ICU beds,ऑक्सिजन युक्त बेड और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने का मैंने अनुरोध किया और लगातार मांग करते रहा। कई दफा मैंने केंद्र सरकार से भी इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया लेकिन किसी ने भी उस वक्त सुध नहीं ली। आज जब एक महीने में 40,000 नए केस आए है तो सरकार की आँखे खुली है केंद्र ने इन उपकरणों की आपूर्ति कराने का भरोसा दिलाया है।

अगर संक्षेप मे कहे तो नीतीश जी का उदासीन,दिशाहीन और उदंड रवैया ही आज बिहार को इतने बुरे स्थिति मे ढकेला है। बिहार कोरोना का नैशनल हाट्स्पाट बन गया है। इन सभी गलतियों को नीतीश जी जानबूझ लगातार करते गए सिर्फ इस बात से की इसका श्रेय मुझे ना मिल जाए,इसीलिए उन्होंने मेरे सकारात्मक सुझावों को दरकिनार किया। लेकिन आज संक्रमण की विस्फोटक स्थिति को देखते हुए मेरे द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल करने को विवश हुए हैं।

TSG Live

Home / News / Bihar losing to Covid-19 due to state govt 'apathy'

Bihar losing to Covid-19 due to state govt 'apathy'

Abhinandan Mishra

Published : July 25, 2020, 11:48 pm | Updated : July 25, 2020, 11:48 PM

A 3-member Central team sent to Bihar was 'aghast' at what it saw in the state.

पिछले हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय,भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री लव अग्रवाल के नेतृत्व में तीन सदस्य टीम बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और खतरे को देखते हुए NMCH तथा अन्य अस्पतालों का दौरा किया था। उसके बाद जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की उसमें मुख्यतः तीन बातों का जिक्र किया गया जिससे की बिहार में कोरोना संक्रमण अप्रत्याशित रूप से बढ़ता गया :-

1. कम जाँच होना
2. अस्पतालों में जरुरी सुविधाओं का नदारद होना
3. लॉकडाउन अवधि में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षमता वर्धन नहीं करना

ज्ञात हो की इन कमियों को मैं पहले दिन से ही नितीश जी से सुधारने के लिए लगातार आग्रह किया। अगर आप हमारा ट्विटर देखेंगे तो 14 मार्च को ही मैंने कोरोना को लेकर गंभीर होने की बात कही थी। मैंने कहा था की health screening शुरू कर देना चाहिए ,प्रत्येक जिला मुख्यालय में specialized labs और isolation wards स्थापित करना चाहिए, जाँच और इलाज को मुफ्त करने का सलाह दिया था ,मास्क और सैनिटाइजेर बाँटने के लिए कहा था

और आगाह किया था Preparation is half the battle "तैयारी ही युद्ध की आधी जीत होती है"

इस रिपोर्ट के कुछ मुख्य अंश आपको मैं बताना चाहूँगा

- इस रिपोर्ट में कहा गया है की 90% नए केस पिछले एक हफ्ते में सामने आये है और 13 जिले हॉटस्पॉट बनने की और अग्रसर हैं जहाँ संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। मतलब बिहार का एक तिहाई हिस्सा कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है।

- बिहार में जाच राष्ट्रीय औसत से कम और देश मे सबसे कम है जिसके कारण संक्रमण बढ़ता जा रहा,नए केसों का पहचान देर से हो रहा और फलस्वरूप संक्रमितों की स्तिथि गंभीर हो जा रही और वो देरी से हॉस्पिटल में भर्ती होने जा रहे जिससे उनके बचने की संभावना कम हो रही और मृत्यु दर बढ़ते जा रहा।

- इसके अलावा Case Positivity Rate का तेजी से बढ़ना भी चिंता का विषय है।

- Point 3 में सैंपलिंग को ICMR गाइडलाइन्स के अनुसार sample collect करने को कहा गया है। 21 अप्रैल को मैंने ट्वीट कर sampling protocol के बारे में सरकार को आगाह किया था। आप मेरा उस दिन का ट्वीट देख सकते हैं।

- Point No. 4-5 में RT-PCR को बढ़ाने और symptomatic antigen negative results को RT-PCR से validate करने को कहा गया है जिसकी मांग मैंने पिछले हफ्ते अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी RT-PCR टेस्ट में accuracy ज्यादा होती है और इसकी कैपेसिटी बढानी चाहिए।

- Point 7-8 में infrastructure बढ़ाने को और जिला स्तर पर इसका विस्तार करने के बारे में कहा गया है, केंद्रीय टीम ने अगले दो महीनों में कोरोन के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए makeshift temporary hospitals बनाने का सुझाव भी दिया है जिसका मैं पहले दिन से ही मांग कर रहा हूँ। यहां तक की मैंने मुख्यमंत्री से हुई पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा था की गुरु गोविन्द प्रकाशोत्सव में जिस प्रकार टेंट सिटी का निर्माण किया गया था उसी प्रकार हमें गाँधी मैदान में COVID dedicated अस्पताल बनाना चाहिए।

- मैंने डॉक्टर्स ,परमेडिकल्स की corona treatment के लिए ट्रेनिंग की मांग की थी जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में है।
- ऑक्सीजन सिलिंडर्स और वेंटिलेटर्स का पर्याप्त सप्लाई और प्रोक्योरमेंट पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिसका मैं लगातार मांग करते आ रहा हूँ।

- बिहार सरकार को महाराष्ट्र मॉडल को अपनाना चाहिए।

- मैं समझता हूँ सकारात्मक सुझावों को अमल करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, नितीश जी को अहंकार त्याग कर इन सभी सुझावों पर तुरंत काम करना शुरू कर देना चाहिए। मैं आज फिर दोहराता हूँ ये लम्बी लड़ाई है ,मैराथन है ,सरकार को एक समग्र योजना बना कर काम करना चाहिए। नितीश जी से आग्रह है की इलेक्शन मैनेजमेंट छोड़ कोरोना मैनेजमेंट में लगें बिहार वासियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बंद करें।

LAV AGARWAL, IAS
Joint Secretary

Tel. : 011-23061195
T/Fax : 011-23061842
E-mail : alav@ias.nic.in

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE
NIRMAN BHAVAN, NEW DELHI - 110011

D.O. F.No.Z.28015/165/2020-EMR

22/07/2020

Dear Sir,

Central team has visited Bihar on 19[th] and 20[th] July 2020. The team had visited COVID-19 designated hospitals, Isolation centres and containment zones in Patna and Gaya district. Subsequent to that, the team had debriefed Hon'ble Health Minister, Chief Secretary and other health officials on 20[th] July 2020.

A detailed presentation was made during the meeting. It was highlighted that cases in Bihar are showing an upsurge with almost 800-1,000 cases being reported daily & 90% of the active cases have been reported in the last 7 days. Districts which need specific and focused attention in view of larger number of cases and the surge include Patna, Nalanda, Nawada, Siwan, Pashchim Champaran, Jamui, Bhagalpur, Begusarai and Munger. Further, Purbi Champaran, Gaya, Rohtas and Muzaffarpur are emerging hotspots.

The overall testing ratio in Bihar is very low as compared to national average. Low testing may result in spread of infection, late identification and late arrival of cases in hospitals, which may in turn impact the case fatality rate and hence, need for increase in testing was reiterated. Further, increase in case positivity is also a cause of concern.

As discussed during the meeting, I would like to submit few areas of concern and suggestive course of action to be followed at state level for kind consideration;

i. While containment zones have been delineated and perimeter control is being monitored, it is suggested that the special teams for active house-to-house case search in these containment zones need to be increased at the rate of approximately 100 households and they should be able to physically visit at least on an alternate day all the houses allotted to them.
ii. Special focus has to be given to co-morbid and elderly population within the containment zones
iii. All contacts of positive cases need to be traced within first 72 hours and sampling shall be taken up as per ICMR guidelines
iv. To ensure capacity utilization of existing RT-PCR labs besides taking action to increase the RT-PCR testing capacity also
v. Antigen tests to be leveraged for undertaking samples in containment zones and hospitals. Symptomatic negative results of antigen tests shall be monitored through RT-PCR tests
vi. Home Isolation shall only be allowed after due verification by the treatment doctor duly following the guidelines for home isolation and a clearly defined mechanism be

also established for monitoring such cases. A clearly defined protocol for shifting such cases to hospitals shall also be put in place

vii. Ensure sufficient hospital infrastructure, including setting up temporary field hospitals, is created duly taking into consideration the case growth trajectory for at least next 2 months

viii. Ensure availability of infrastructure across all districts in view of widespread cases being reported across the state

ix. Undertake capacity building of health workforce across all Covid dedicated hospitals and ensure proper roster system for patient management

x. Ensure infection prevention practices including triaging & effective segregation of suspect & confirmed patients in all hospitals which are treating COVID patients. Government of India guidelines on the issue may be scrupulously followed.

xi. Ensure sufficient logistics availability, particularly oxygen cylinders and regular oxygen, in all health facilities

xii. State may consider designating a state level Covid-19 facility as Center of Excellence which shall on one hand, attend the webinars undertaken by AIIMS-Delhi and on the other hand, shall mentor all state level health facilities through VCs.

xiii. Ensure that all Covid dedicated facilities are sufficiently trained to manage cases at their end

xiv. State may also consider utilizing the model of temporary Covid-19 dedicated facilities prepared by DRDO/Maharashtra, etc. A team may also be sent to these states to study the model.

xv. A mechanism may be put in place to ensure seamless admission for Covid-19 patients in appropriate health facilities duly tieing up with ambulance and call centers. The bed utilization and vacancy position in all health facilities may also be brought online.

xvi. All health facilities may be monitored for their case management and case fatality on a weekly basis. Death audit may also be taken up to provide inputs to the health professionals for better case management.

While conveying my thanks to all health professionals in the state for their relentless efforts so far, I wish to convey that we need to on continued alert and maintain our efforts so as to manage Covid-19 effectively.

with regards,

Yours sincerely

(Lav Agrawal)

Shri Udai Singh Kumawat, IAS
Principal Secretary
Department of Health
Government of Bihar
Secretariat, Patna

पत्र सं०– 1.O.3/25-19/......93

बिहार पुलिस मुख्यालय
(विधि–व्यवस्था प्रभाग)

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक (रेल सहित),
बिहार।

दिनांक–29 मई 2020

विषय :– बिहारी प्रवासी मजदूरों की भारी आमद के कारण गंभीर विधि–व्यवस्था की समस्या होने की आशंका के संबंध में।

विगत 2 माह में बिहार राज्य में भारी संख्या में स्थानीय नागरिकों का आगमन हुआ है जो अन्य राज्यों में श्रमिक के रूप में कार्यरत थे। स्थानीय आर्थिक चुनौतियों के कारण वे सभी परेशान एवं तनावग्रस्त हैं। सरकार की अथक कोशिश के बावजूद राज्य के अंदर सभी को वांछित रोजगार मिलने की संभावना कम है। इस कारण स्वयं एवं अपने परिवार का भरण–पोषण करने के उद्देश्य से वे अनैतिक एवं विधि विरुद्ध गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इससे अपराध में वृद्धि हो सकती है तथा विधि–व्यवस्था की स्थिति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह समस्या सीमित क्षेत्र में अथवा व्यापक पैमाने पर उत्पन्न हो सकती है।

इस परिस्थिति का सामना करने के लिए अनुरोध है कि स्थानीय परिदृश्य को देखते हुए कार्य योजना तैयार कर ली जाए ताकि आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जा सके।

Amit Kumar
29/5/20
(अमित कुमार)
अपर पुलिस महानिदेशक (विधि–व्यवस्था)

प्रतिलिपि :–

1. सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / उप–महानिरीक्षक (रेल सहित), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई।
2. सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, बिहार को सूचनार्थ।
4. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ।

Amit Kumar
29/5/20
अपर पुलिस महानिदेशक (विधि–व्यवस्था)

ज्ञापांक 673 /वि०व० — जमालपुर, दिनांक– 02-06-2020

प्रतिलिपि : सभी रेल थानाध्यक्ष / पी०पी० प्रभारी रेल जिला जमालपुर को निर्देश दिया जाता है कि वर्णित तथ्य के आलोक में दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

रेल पुलिस उपाधीक्षक, जमालपुर / किउल को सूचनार्थ प्रेषित।

रेल पुलिस निरीक्षक जमालपुर / ... को सूचनार्थ प्रेषित।

रेल पुलिस अधीक्षक,
जमालपुर।

(64) WhatsApp

Sanjay

today at 9:13 PM

आंकड़ों की हेराफेरी का एक नमूना देखिये | दिनांक **31-07-2020** की जारी की कोविड बुलेटिन में कुल एक्टिव केसेस की संख्या **50987** है दिनांक **01-08 -2020** की जारी की कोविड बुलेटिन में कुल एक्टिव **cases** की संख्या **54508** है मतलब पिछले **24** घंटे में नए मरीजों की संख्या **3521** है लेकिन इसको **2502** बताया गया है |

07 जुलाई को उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ट्वीट कर कहते हैं की **9** हजार से ज्यादा जॉच हो रही है जबकि उसी दिन के बिहार सरकार के आधिकरिक प्रेस रिलीज में मात्र **5168** जाँच होने की पुष्टि की गयी थी |

01 July 2020 को **13**वां स्थान था कोरोना टेबल में और वही **01**अगस्त को **7** वा स्थान हो गया है | जिस प्रकार से संक्रमण फैला रहा और **TPR(Test positivity)** राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है इस महीने के आखिरी तक बिहार टॉप **3** में आ जायेगा | नितीश-मोदी की डबल इंजन सरकार में बिहार सिर्फ बीमारी में विकास कर रहा और हर नेगेटिव रिकॉर्ड में नंबर वन बन कर ही रहेगा |

July data

Bihar COVID Analysis-JULY	
No. Of Cases	40912
बढ़ने की दर Surge Rate	5 ● गुना
Positivity Rate	12.80%
कुल No. Of Deaths	225
मृत्यु दर→ Increase in Fatality Rate	4 ● गुना
Recovery Rate में कमी Decline in Recovery Rate	11.50%

Optimized by www.ImageOptimizer.net

Covid-19 situation in the state. As per the feedback,the state government missed the opportunity to prepare and create the necessary infrastructure to tackle Covid-19 during the 25 March-30 May nationwide lockdown period.The three-member team was sent by the Centre in view of the massive spike of Covid-19 cases in the state.

The team that went to Bihar on 19 July included Lav Agarwal, Joint Secretary, Health Ministry; Sujeet Singh, Director, National Centre for Disease Control, and Dr Neeraj Nischal of Medicine Department, AIIMS (Delhi). The Sunday Guardian reached out to Singh and Nischal for their comments on the story, but they did not comment.

Highly-placed sources in the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW), who are aware of the findings of the three-member team, said that the members were "aghast" at what they saw in Patna, as they visited multiple hospitals, including bodies of Covid-19 patients lying unattended on beds and in corridors, with attendants of the patients moving in and around the Covid-19 wards without any restrictions.

"The attendants are being forced to do everything on their own as medical attendants, including the doctors, are not going near the Covid-19 patients as the whole system has broken down and the doctors fear that if they get infected, no one will take care of them. And this is the situation in the state capital, you can imagine what is happening in the rural and remote parts of Bihar. The medical infrastructure in the state is perhaps the worst in the country and none of the public representatives (minister and bureaucrats) who are responsible for managing the affairs is active because of which the whole system has crumbled," a highly-placed source in the MoHFW, while quoting the feedback of the three-memberteam, told The Sunday Guardian.

As per Union government sources, the Bihar government is just not spending money on fighting Covid-19.

"They are not purchasing rapid antigen kits. The Central government recently gave 10,000such kits for free to the Bihar government, but they require at least 4 lakh such kits; the Central government cannot just keep focusing on Bihar as it has to take care of other states, too, and cannot spend all its resources on Bihar. The Nitish Kumar government is looking to the Central government for everything. The situation is worse in the rural areas," a ministry official, who is presently in Patna, said. Last week in a press release by the state government, it was stated that the state government had already spent Rs 8,538 crore to "defeat" Covid-19.

In an affidavit filed in the Patna High Court on Friday, ICMR, on behalf of the Central government, said that the Bihar state government had so far sought 20,000 antigen kits from the Central government. "How can they do mass testing when they only have 20,000 kits for a population of 12 crore? This shows the lack of seriousness of the state government in handling Covid-19. They are neither purchasing the required number of kits, nor are they seeking the same from the Central government," a Patna-based official familiar with the development said.

The three-member Central team had also visited Rajiv Nagar in western Patna and was surprised to see that the containment zone was made a no-go area by just using bamboo and sticks. At GB road in Gaya,120 km from Patna, one such containment zone was breached at several points, the team discovered.

"In such a difficult time, files related to appointment of 4,000 doctors and 6,000 nursing staff are shuttling between the minister and secretary of state health department for months," an official Delhi-based source lamented while giving an example of the callous approach of the state government.

already been delivered. Also delivered are 29 lakh HCQ tablets, 4.54 PPE kits and 8.32 N95 masks. "However, most of them are lying unused as no one is using them because the kind of hyper-active approach that should have been there on the ground with regards to medical attendants, is not there," the official added. The MoHFW is also imparting Covid-19 related training to doctors of Patna through video conferencing which has started this week.

As on 23 July, Bihar, with a population of more than 12 crore, only had 6,434 oxygen supported beds and 570 ICU beds in the entire state. In comparison, UP had 9,257 oxygen supported beds and 2,025 ICU beds, while the corresponding figure for Jharkhand and Madhya Pradesh was 3,375 and 494 and 6,200 and 1,650 respectively.

The Central government, which recently received 4,475 oxygen concentrators from Temasek Foundation, Singapore, gave the maximum number of it, 500 pieces, to Bihar. The Central government also gave 10,000 oxygen cylinders to the state as the state governmentcould not even arrange that. "If they had not wasted the lockdown period, the situation would have been different," the official said while adding that even contact tracking and tracing was very weak in the state.

As per the World Health Organization (WHO) guidelines, for every 10 lakh population, at least 140 Covid-19 tests should be done. Bihar, with a population of more than 12 crore, going by the WHO's guidelines, should have been doing 17,500 tests per day. However, as on 23 July, Bihar was only doing 2,368 tests per day which is not even 20% of the required tests.

"Bihar has got the dubious distinction of doing the least number of tests (per 10 lakh) all across India. They have wasted the 70 days that they got during the lockdown in which they could have prepared for Covid-19. Health being a state subject, we can only advise and augment, the real work has to be done by the people in the state. The team members were shocked to see the callousness regarding Covid-19 in the people responsible for the health infrastructure in Bihar," the source said.

The Sunday Guardian has also accessed multiple videos shot in "big" hospitals of Patna which show the utter mismanagement regarding Covid-19 in the state.

"The CM, the health minister and the deputy CM should have been visiting hospitals across the state as that would have given them a clear ground picture and forced the health authorities to start working, but surprisingly all the three of them have stayed inside their homes, thereby adding to the fear of Covid-19 among the common people. The doctors' fraternity, too, is scared as they feel that if they too catch Covid-19, no system is there to take care of them. Private hospitals are not admitting patients due to the fear of Covid-19 and the people have no one to go," a well-known doctor of Patna told The Sunday Guardian.

According to him, the state health department, after receiving instructions from the Central team, had notified 18 private hospitals in Patna for exclusive treatment of Covid-19 patients, but even after three days, these hospitals were refusing to admit such patients while claiming that the state government had not provided them infrastructure and PPE kits.

As per a Bihar-based senior BJP functionary, he had approached a senior minister of Bihar of his own party, seeking his intervention in getting a Covid-19 patient from his constituency a bed in the Patna Medical College Hospital (PMCH), but the minister refused by saying that PMCH was full. "I then reached out to a Union minister in Delhi after which the patient was admitted in PMCH. I used to read and hear about the poor state of Covid-19 infrastructure in Bihar; only when I experienced it myself did I realise how true and painful it is," the functionary said.

Related

China has built new structures in Pangong Tso area

1 August will be celebrated as Muslim Women's Rights Day

India's passport power improves by 24 ranks in 5 years

TSG Live

Disgruntled Mukul Roy pushes for bigger role in BJP

TSG Live

© SUNDAY GUARDIAN LIVE 2020 ALL RIGHTS RESERVED

van under the open sky as the hospital building was not sanitized even after the death of a Covid-19 patient. One of the doctors stationed at the hospital told The Sunday Guardian that they had informed the Patna Municipal Corporation (PMC) authorities about the death of the patients four hours ago and had requested sanitization of the building as per the protocols. However, despite the PMC office hardly being 50 meters from the hospital, no one had come, forcing the doctors to move out of the building.

Leave a Reply

Comment*

Name *

Email *

I'm not a robot

~~आज प्रेस कॉन्फ्रेंस~~ का मकसद बिहार की पिछले पंद्रह सालों में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्तिथि से अवगत कराना है |नितीश शासन में अगर सबसे उपेक्षित क्षेत्र कोई रहा है तो वो है "स्वास्थ्य"|

- चाहे निति आयोग(NITI AYOG) की रिपोर्ट हो या नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) इन संस्थानों के सारे मानकों पर बिहार नितीश राज के पंद्रह सालों में साल-दर -साल फिसड्डी होते चला गया| ऐसा होना भी लाज़िमी है जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी की स्वास्थ्य चिंता और जुगाड़ में लगा रहता हो उसको प्रदेश वासियों के स्वास्थ्य की चिंता क्यों होगी |
-
- हर साल चमकी बुखार से सैकड़ों बच्चों की मृत्यु होती है , इस कोरोना महामारी ने तो बिहार की मरणासन्न स्वास्थ्य व्यवस्था का पर्दाफाश कर दिया | अस्पतालों की कमी, उनमें beds की कमी, ICU beds की कमी,ventilator की कमी जो की देश में सबसे कम बिहार में ही है | इन सब के ऊपर डॉक्टर ,नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की कमी से बिहार जूझ रहा है| स्तिथि इतनी भयवाह है की district health centres भी रेफरल अस्पताल बन कर रह गए हैं | **Public healthcare के मामले में बिहार पुरे देश में सबसे पीछे है | इसी का नतीजा है की बाहरी राज्यों में इलाज के लिए हमारे बिहारी भाई-बहन जाने को मजबूर होते हैं |**

- 2005 में कुल 101 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे आज 15 साल में महज 49 नए केंद्र स्थापित किये गए मतलब प्रतिवर्ष सिर्फ 3 केंद्रों की स्थापना की गयी|पिछले २ सालों में कोई नई स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना नहीं की गयी|
- **2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में चालू स्वास्थ्य केंद्रों(SCs,PHCs,CHCs) की कुल संख्या 12086 थी जो की 2019 में घटकर 11998 हो गयी**
- मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है| शिशु मृत्यु दर(38/1000) भी राष्ट्रिय औसत से ज्यादा है|
-
- **पाँच साल से कम उम्र के बच्चों में stunting और underweight का प्रतिशत 42% है जो की पुरे देश में सबसे ज्यादा और ख़राब है|**
- **बिहार में (0 -4 years) age ग्रुप में 40 % से अधिक बच्चों को खून और आयरन की कमी है|**
-
- पुरे देश में सबसे ज्यादा medical infrastructure develop करने की जरुरत बिहार में है
- स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तय मानक health centre per thousand population (आबादी पर स्वास्थ्य केंद्र) पर बिहार आखरी पायदान पर है|डॉक्टर मरीज अनुपात पुरे देश में सबसे ख़राब है , जहाँ WHO standards के अनुसार प्रति एक हज़ार आबादी एक डॉक्टर होना चाहिए (1 :1000) बिहार में ये 1 :3207 है | ग्रामीण क्षेत्रों में तो और भी दयनीय स्तिथि है जहाँ प्रति 17685 व्यक्ति पर महज 1 डॉक्टर बिहार में है |

- Backlogs Status in Bihar 2019

Name of Post	Required	Vacant Seats / Percentage
Pharmacists	2049	1762 86% vacant
Specialists at CHC	600	518 86.3% vacant
Radiographer	150	149 99.3% vacant
Laboratory Technician	2049	1438 70.1% vacant
Nursing Staff	2949	1319 44.7% vacant

- National Rural Health Mission (NHRM) द्वारा जारी रिपोर्ट कार्ड में पिछले 15 सालों में बिहार का सबसे ख़राब प्रदर्शन रहा है |बिहार को जो राशि आवंटित हुई उसका आधा भी खर्च नहीं कर पायी सरकार|
- कुपोषण सबसे अधिक बिहार में है | *If malnutrition is still a problem today then only mal-administration is to be blamed.*अगर कुपोषण एक समस्या है तो कु प्रशासन इसका कारण है|
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सबसे ख़राब प्रदर्शन बिहार का रहा है जिसके वजह से केंद्र सरकार ने एक भी पैसा इस साल आवंटित नहीं किया है अभी तक 75 % आबादी का इ-कार्ड नहीं बन पाया है|
- स्वास्थ्य per capita खर्च सबसे कम बिहार में ही है
- प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती सबसे अधिक मरीज बिहार के ही हैं जो सरकार की विफलता को दर्शाता है|
- निति आयोग के स्वास्थ्य मानकों पर बिहार सबसे ख़राब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से है | जहाँ केरल का 74.01 स्कोर है वहीं बिहार का मात्र 32. 11 है|बिहार का रैंक भी आखरी में है 20 out of 21 large states जो की base year 2015-16 से और एक पायदान निचे खिसका है|
- Overall Performance Score में बिहार ने सुधार की जगह गिरावट दर्ज किया और निचली पायदान पर है|निति आयोग के अनुसार बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हुआ है|
- Key input / process index मानक में भी बिहार का प्रदर्शन सबसे ख़राब रहा और पिछले वर्ष के तुलना में 17.6 points घटा है जो की बहुत शर्मनाक है|
- बिहार की टीकाकरण की स्तिथि भी कुछ ठीक नहीं है अब भी 10 प्रतिशत शिशुओं का टीकाकरण नहीं होता है|सुरक्षित प्रसव के मामले में भी बिहार पीछे है|टीबी इलाज के मामले में बिहार का निराशजनक प्रदर्शन रहा है|

- नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार बिहार अब भी ASPIRANT राज्यों के केटेगरी में है | इस केटेगरी में उन्ही राज्यों को रखा गया है जिन्होंने तय लक्ष्य प्राप्त नहीं किये हैं और सबसे ख़राब प्रदर्शन रहा है|
- 2015-16 से 2017-18 में कोई सुधार नहीं हुआ बल्कि -6. 35 points स्कोर कम हुआ|

Shortfall in Health Facilities as per estimation as on July,1,2019 in rural areas

Name of Centres	Required	In Position	Shortfall	% Shortfall
Sub Centres	21337	9949	11388	53
PHC	3548	1899	1649	46
CHC	887	150	737	83

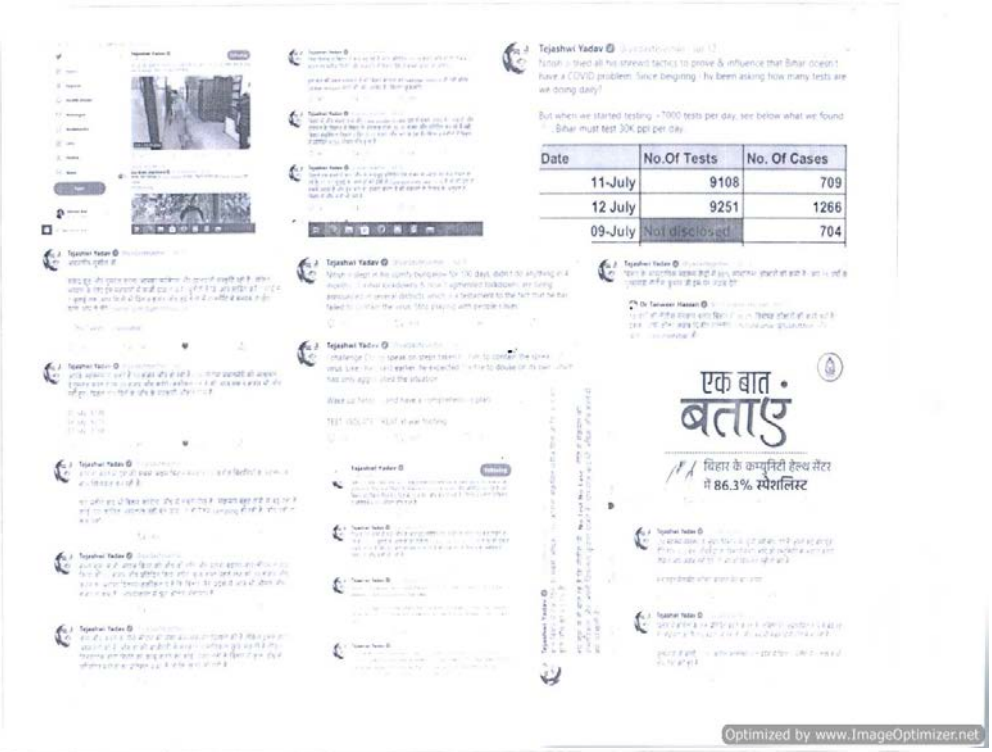

Tejashwi Yadav

Nitish ji tried all his shrewd tactics to prove & influence that Bihar doesn't have a COVID problem. Since begining i hv been asking how many tests are we doing daily?

But when we started testing ~7000 tests per day, see below what we found. Bihar must test 30K ppl per day

Date	No.Of Tests	No. Of Cases
11-July	9108	709
12 July	9251	1266
09-July	Not disclosed	704

एक बात बताएं

बिहार के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 86.3% स्पेशलिस्ट

कोरोना संक्रमित टॉप 14 राज्यों में प्रति 10 लाख आबादी पर सबसे कम 313 जांच बिहार में, इनमें 7 पॉजिटिव मिल रहे

Tejashwi Yadav

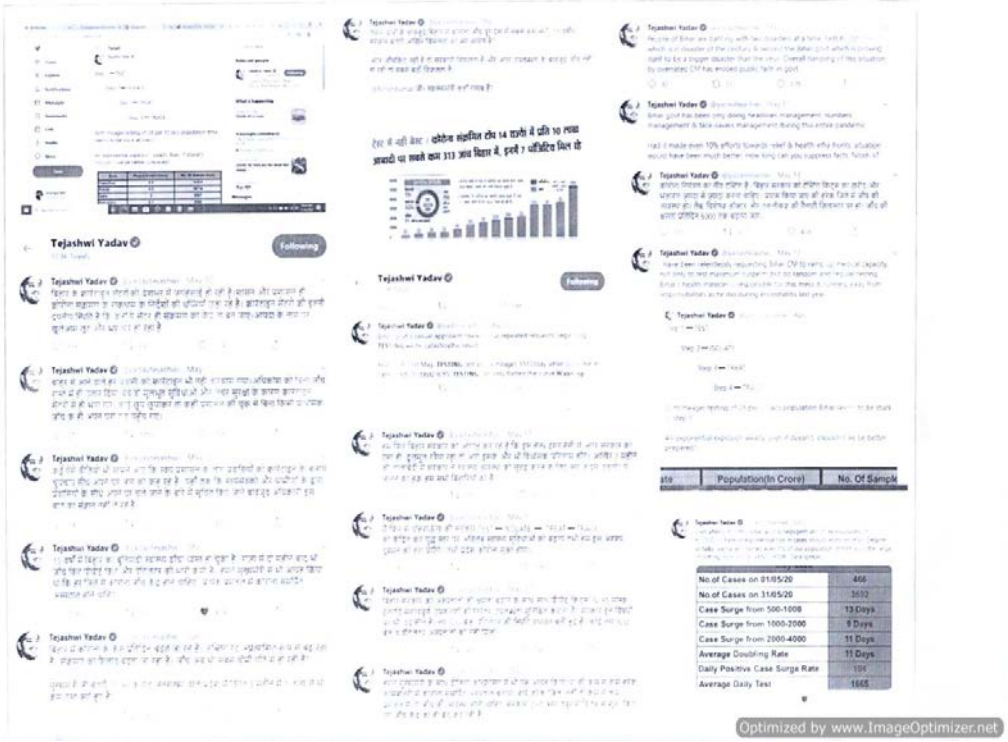

No of Cases on 01/05/20	466
No of Cases on 31/05/20	3692
Case Surge from 500-1000	13 Days
Case Surge from 1000-2000	9 Days
Case Surge from 2000-4000	11 Days
Average Doubling Rate	11 Days
Daily Positive Case Surge Rate	10%
Average Daily Test	1665

Optimized by www.ImageOptimizer.net

Optimized by www.ImageOptimizer.net

Optimized by www.ImageOptimizer.net

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · Jul 11
बिहार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 86% स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। क्या 15 वर्षों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस पर जवाब देंगे?

Dr Tanweer Hassan @DrTanweerHassan · Jul 11
15 वर्षों की नीतीश सरकार बताए बिहार में 86.3% विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी क्यों है? इसका दोषी कौन? जवाब दिजीए माननीय @NitishKumar @SushilModi और @mangalpandeybjp जी?

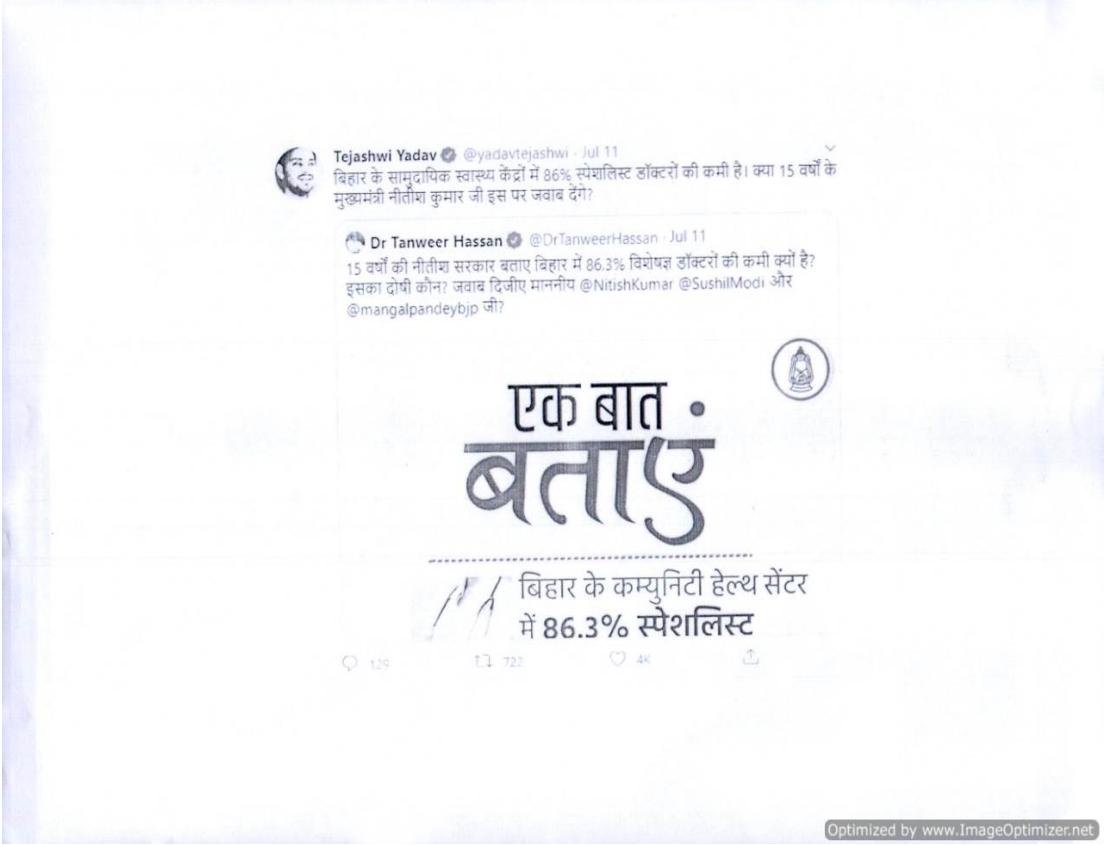

129 722 4K

Optimized by www.ImageOptimizer.net

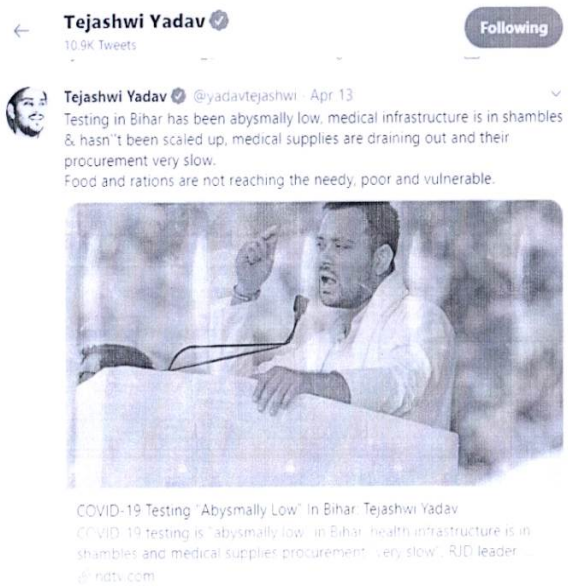

Optimized by www.ImageOptimizer.net

Optimized by www.ImageOptimizer.net

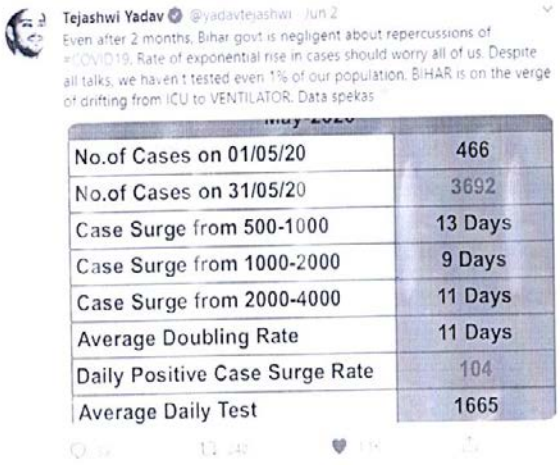

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · Jun 2

Even after 2 months, Bihar govt is negligent about repercussions of #COVID19. Rate of exponential rise in cases should worry all of us. Despite all talks, we haven't tested even 1% of our population. BIHAR is on the verge of drifting from ICU to VENTILATOR. Data speaks

No.of Cases on 01/05/20	466
No.of Cases on 31/05/20	3692
Case Surge from 500-1000	13 Days
Case Surge from 1000-2000	9 Days
Case Surge from 2000-4000	11 Days
Average Doubling Rate	11 Days
Daily Positive Case Surge Rate	104
Average Daily Test	1665

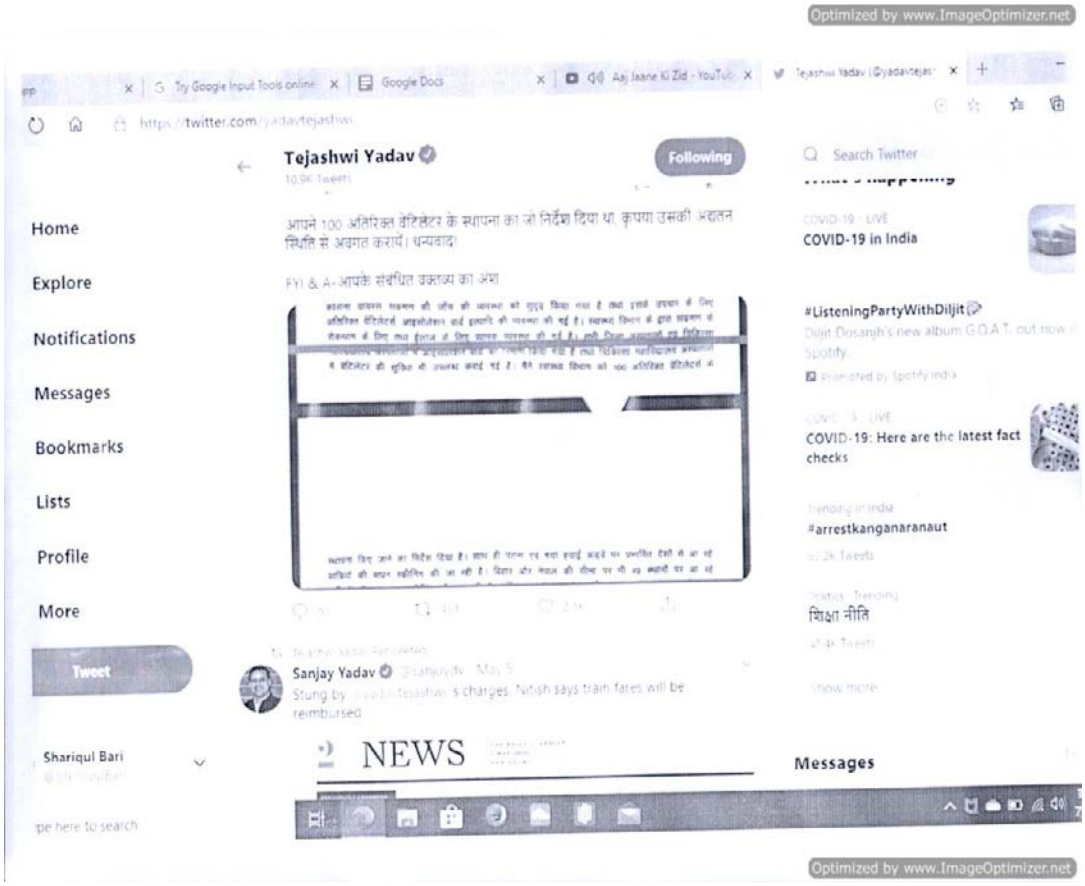

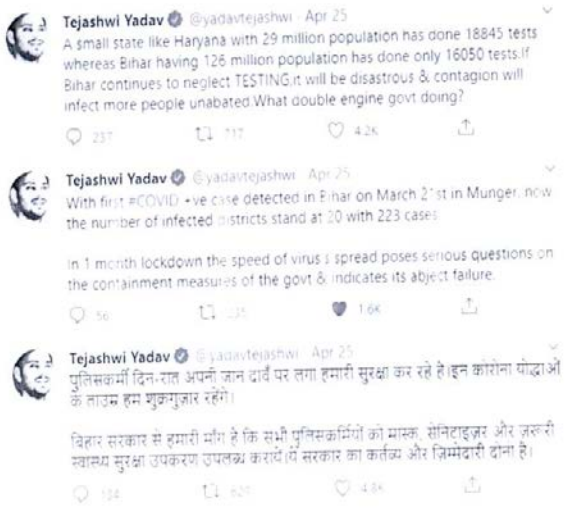

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · Apr 25

A small state like Haryana with 29 million population has done 18845 tests whereas Bihar having 126 million population has done only 16050 tests.If Bihar continues to neglect TESTING,it will be disastrous & contagion will infect more people unabated.What double engine govt doing?

237 · 717 · 4.2K

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · Apr 25

With first #COVID +ve case detected in Bihar on March 21st in Munger, now the number of infected districts stand at 20 with 223 cases

In 1 month lockdown the speed of virus's spread poses serious questions on the containment measures of the govt & indicates its abject failure.

56 · 1.6K

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · Apr 25

पुलिसकर्मी दिन-रात अपनी जान दावँ पर लगा हमारी सुरक्षा कर रहे है।इन कोरोना योद्धाओं के ताउम्र हम शुक्रगुज़ार रहेंगे।

बिहार सरकार से हमारी माँग है कि सभी पुलिसकर्मियों को मास्क, सेनिटाइज़र और ज़रूरी स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करायें।ये सरकार का कर्तव्य और ज़िम्मेदारी दोनों है।

Optimized by www.ImageOptimizer.net

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · Apr 21

AIIMS-Patna director has made out a strong point. I request you all to revise the sampling protocol. Assign sample collections to trained ENT specialists only.
@NitishKumar @drharshvardhan @MoHFW_INDIA

> **ht Hindustan Times** @htTweets · Apr 20
>
> #COVID—19 | "Improper methodology of sample collection could be a reason for the large number of negative cases in the state," AIIMS-Patna director Dr Prabhat Kumar Singh said
>
> (reports @journoruchir)
>
> hindustantimes.com/india-news/imp...

Optimized by www.ImageOptimizer.net

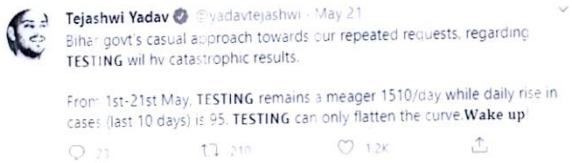

Optimized by www.ImageOptimizer.net

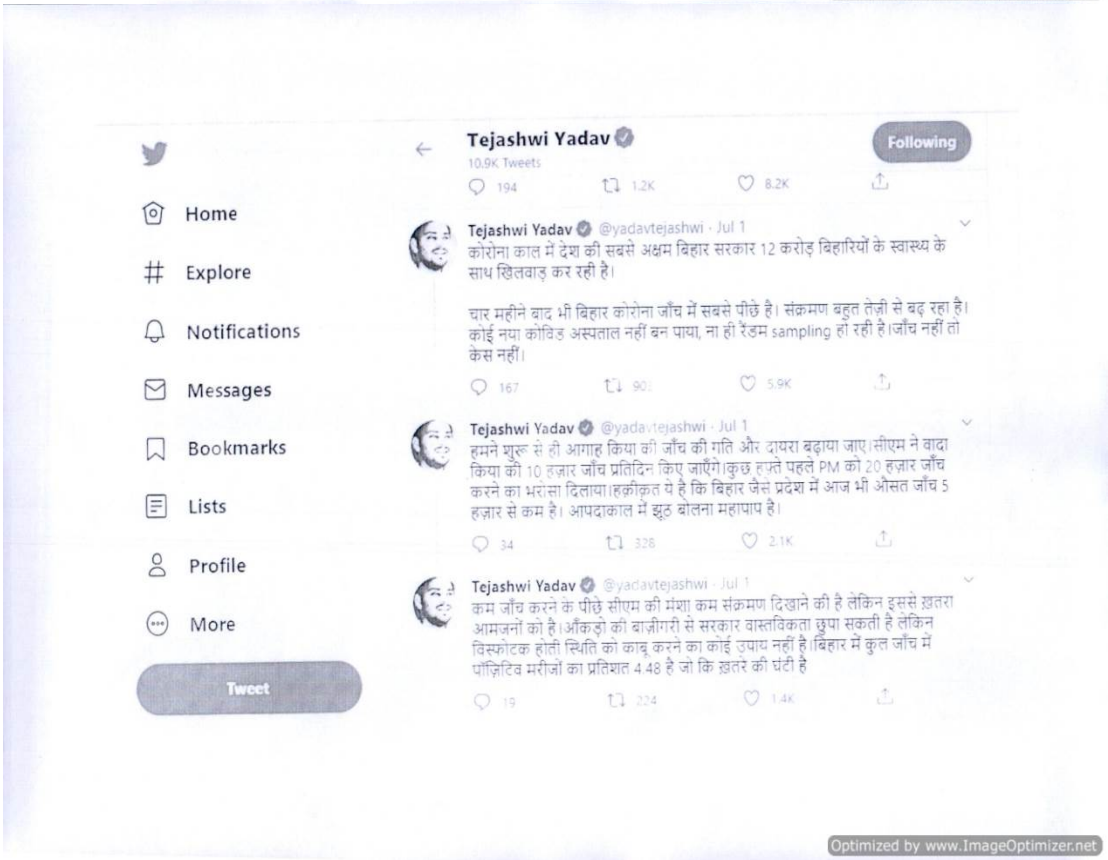

Optimized by www.ImageOptimizer.net

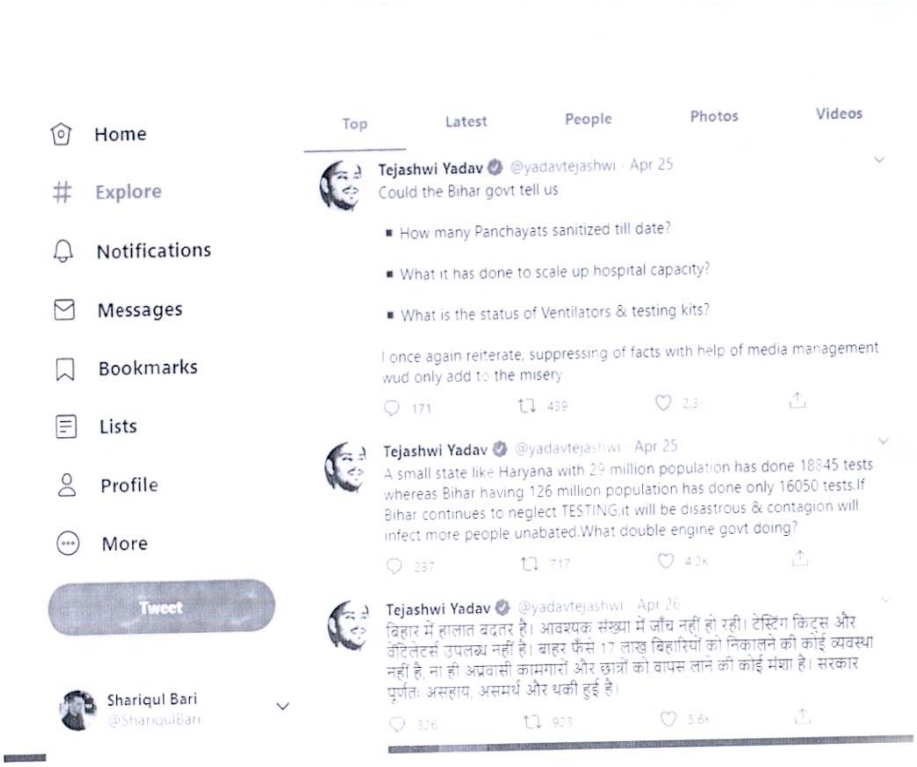

Optimized by www.ImageOptimizer.net

Optimized by www.ImageOptimizer.net

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · Apr 25
Could the Bihar govt tell us

- How many Panchayats sanitized till date?
- What it has done to scale up hospital capacity?
- What is the status of Ventilators & testing kits?

I once again reiterate, suppressing of facts with help of media management wud only add to the misery.

171 439 2.3K

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · Apr 25
A small state like Haryana with 29 million population has done 18845 tests whereas Bihar having 126 million population has done only 16050 tests.If Bihar continues to neglect TESTING,it will be disastrous & contagion will infect more people unabated What double engine govt doing?

257 717 4.2K

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · Apr 25
With first #COVID +ve case detected in Bihar on March 21st in Munger, now the number of infected districts stand at 20 with 223 cases.

In 1 month lockdown the speed of virus s spread poses serious questions on the containment measures of the govt & indicates its abject failure.

56 1.6K

Optimized by www.ImageOptimizer.net

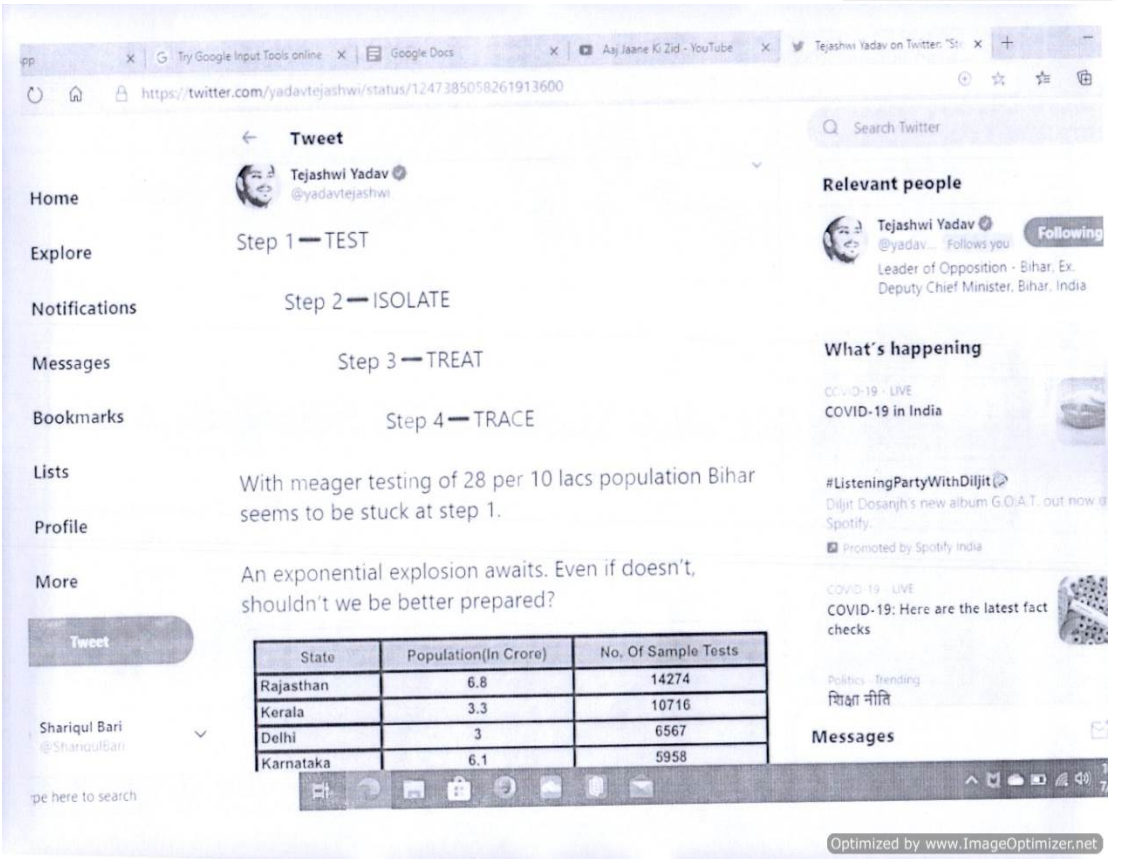

Optimized by www.ImageOptimizer.net

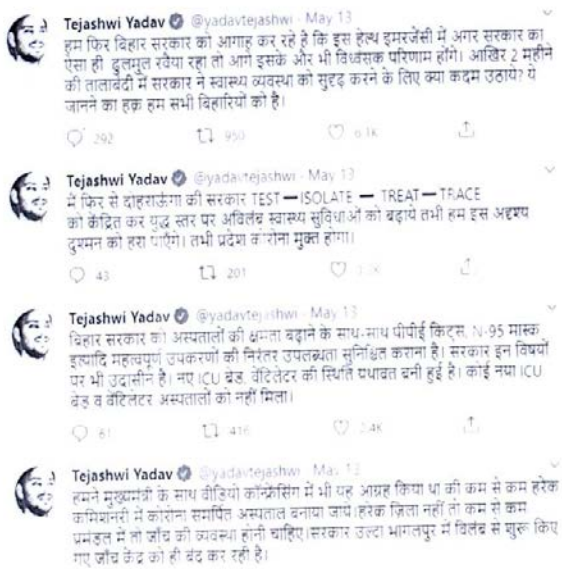

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · May 13
हम फिर बिहार सरकार को आगाह कर रहे है कि इस हेल्थ इमरजेंसी में अगर सरकार का ऐसा ही ढुलमुल रवैया रहा तो आगे इसके और भी विध्वंसक परिणाम होंगे। आखिर 2 महीने की तालाबंदी में सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाये? ये जानने का हक हम सभी बिहारियों को है।

292 950 6.1K

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · May 13
मैं फिर से दोहराऊंगा की सरकार TEST — ISOLATE — TREAT — TRACE को केंद्रित कर युद्ध स्तर पर अविलंब स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाये तभी हम इस अदृश्य दुश्मन को हरा पाएंगे। तभी प्रदेश कोरोना मुक्त होगा।

43 201

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · May 13
बिहार सरकार को अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ पीपीई किट्स, N-95 मास्क इत्यादि महत्वपूर्ण उपकरणों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। सरकार इन विषयों पर भी उदासीन है। नए ICU बेड, वेंटिलेटर की स्थिति यथावत बनी हुई है। कोई नया ICU बेड व वेंटिलेटर अस्पतालों को नहीं मिला।

61 416 2.4K

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · May 13
हमने मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी यह आग्रह किया था की कम से कम हरेक कमिश्नरी में कोरोना समर्पित अस्पताल बनाया जाये।हरेक ज़िला नहीं तो कम से कम प्रमंडल में तो जाँच की व्यवस्था होनी चाहिए।सरकार उल्टा भागलपुर में विलंब से शुरू किए गए जाँच केंद्र को ही बंद कर रही है।

Optimized by www.ImageOptimizer.net

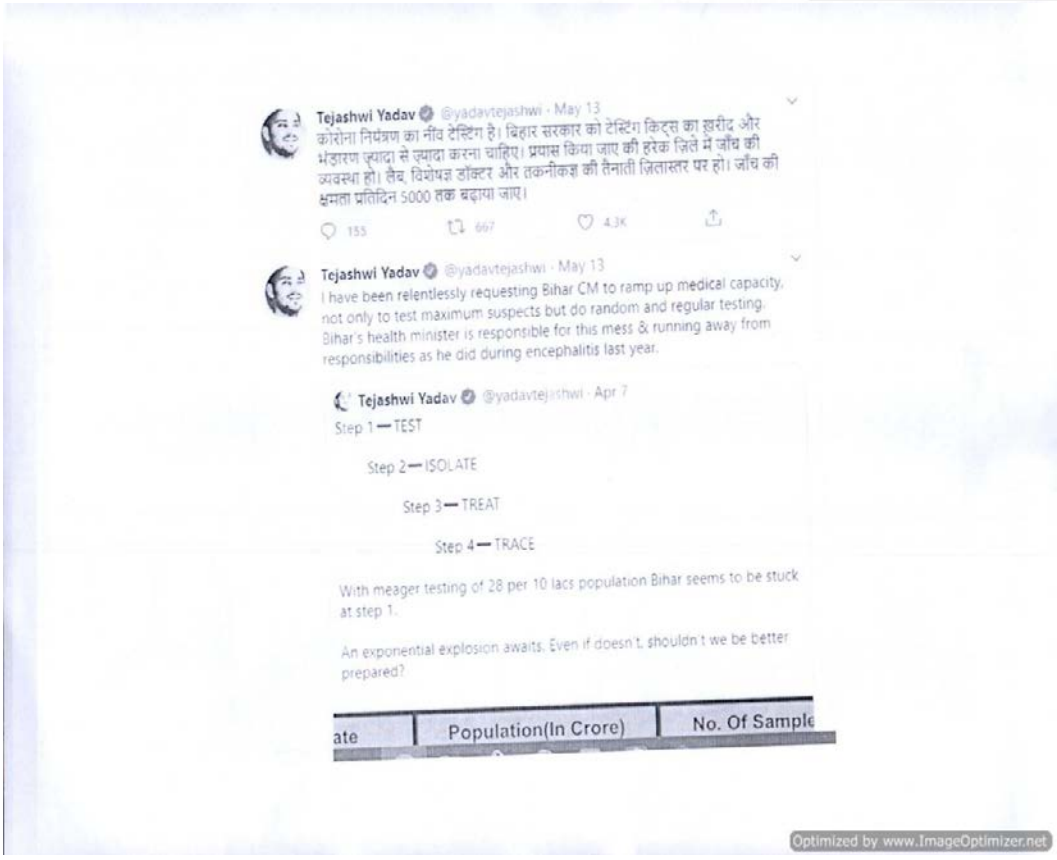

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · May 13
कोरोना नियंत्रण का नींव टेस्टिंग है। बिहार सरकार को टेस्टिंग किट्स का खरीद और भंडारण ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। प्रयास किया जाए की हरेक ज़िले में जाँच की व्यवस्था हो। लैब, विशेषज्ञ डॉक्टर और तकनीकज्ञ की तैनाती ज़िलास्तर पर हो। जाँच की क्षमता प्रतिदिन 5000 तक बढ़ाया जाए।

155 667 4.3K

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · May 13
I have been relentlessly requesting Bihar CM to ramp up medical capacity, not only to test maximum suspects but do random and regular testing. Bihar's health minister is responsible for this mess & running away from responsibilities as he did during encephalitis last year.

> Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · Apr 7
> Step 1 — TEST
> Step 2 — ISOLATE
> Step 3 — TREAT
> Step 4 — TRACE
>
> With meager testing of 28 per 10 lacs population Bihar seems to be stuck at step 1.
>
> An exponential explosion awaits. Even if doesn't, shouldn't we be better prepared?

ate	Population(In Crore)	No. Of Sample

Optimized by www.ImageOptimizer.net

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · May 17

People of Bihar are battling with two disasters at a time. First,#COVID19 which is d disaster of the century & second the Bihar govt which is proving itself to be a bigger disaster than the virus. Overall handling of this situation by overrated CM has eroded public faith in govt

92 533 2.7K

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · May 17

Bihar govt has been only doing headlines management, numbers management & face-savers management during this entire pandemic.

Had it made even 10% efforts towards relief & health infra fronts, situation would have been much better. How long can you suppress facts, Nitish Ji?

Optimized by www.ImageOptimizer.net

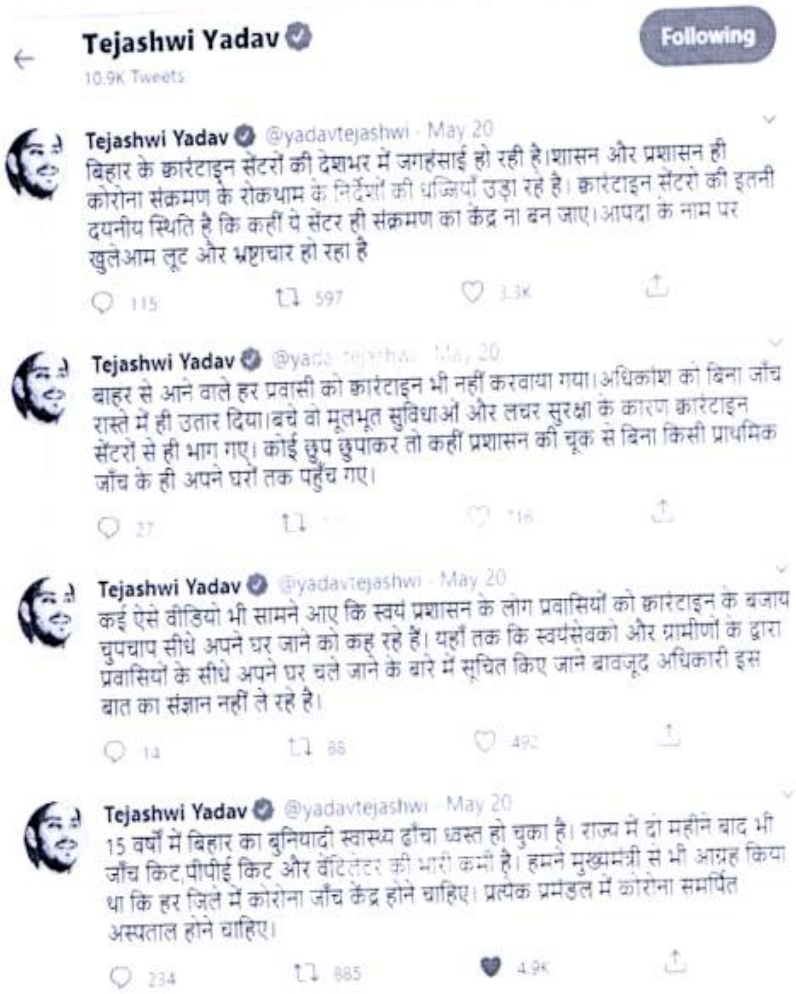

Tejashwi Yadav

10.9K Tweets

Following

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · May 20

बिहार के क्वारंटाइन सेंटरों की देशभर में जगहंसाई हो रही है।शासन और प्रशासन ही कोरोना संक्रमण के रोकथाम के निर्देशों की धज्जियाँ उड़ा रहे है। क्वारंटाइन सेंटरो की इतनी दयनीय स्थिति है कि कहीं ये सेंटर ही संक्रमण का केंद्र ना बन जाए।आपदा के नाम पर खुलेआम लूट और भ्रष्टाचार हो रहा है

115 597 3.3K

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · May 20

बाहर से आने वाले हर प्रवासी को क्वारंटाइन भी नहीं करवाया गया।अधिकांश को बिना जाँच रास्ते में ही उतार दिया।बचे वो मूलभूत सुविधाओं और लचर सुरक्षा के कारण क्वारंटाइन सेंटरों से ही भाग गए। कोई छुप छुपाकर तो कहीं प्रशासन की चूक से बिना किसी प्राथमिक जाँच के ही अपने घरों तक पहुँच गए।

27 716

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · May 20

कई ऐसे वीडियो भी सामने आए कि स्वयं प्रशासन के लोग प्रवासियों को क्वारंटाइन के बजाय चुपचाप सीधे अपने घर जाने को कह रहे हैं। यहाँ तक कि स्वयंसेवको और ग्रामीणों के द्वारा प्रवासियों के सीधे अपने घर चले जाने के बारे में सूचित किए जाने बावजूद अधिकारी इस बात का संज्ञान नहीं ले रहे है।

14 86 492

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · May 20

15 वर्षों में बिहार का बुनियादी स्वास्थ्य ढाँचा ध्वस्त हो चुका है। राज्य में दो महीने बाद भी जाँच किट,पीपीई किट और वेंटिलेटर की भारी कमी है। हमने मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया था कि हर जिले में कोरोना जाँच केंद्र होने चाहिए। प्रत्येक प्रमंडल में कोरोना समर्पित अस्पताल होने चाहिए।

234 885 4.9K

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · Jun 8

बिहार में कोरोना के केस प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है। डबलिंग रेट अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा है। संक्रमण का फैलाव बढ़ता जा रहा है। जाँच अब भी सबसे धीमी गति से हो रही है?

मुख्यमंत्री जी बताएँ, 12.60 करोड़ जनसंख्या वाले प्रदेश में विगत 3 महीने में 1 लाख से भी कम टेस्ट क्यों हुए है?

353 1.5K 9.2K

Optimized by www.ImageOptimizer.net

Tejashwi Yadav

10.9K Tweets

Following

53 358 1.8K

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · May 21

Bihar govt's casual approach towards our repeated requests, regarding **TESTING** will hv catastrophic results.

From 1st-21st May, **TESTING** remains a meager 1510/day while daily rise in cases (last 10 days) is 95. **TESTING** can only flatten the curve.**Wake up**!

23 210 1.2K

Optimized by www.ImageOptimizer.net

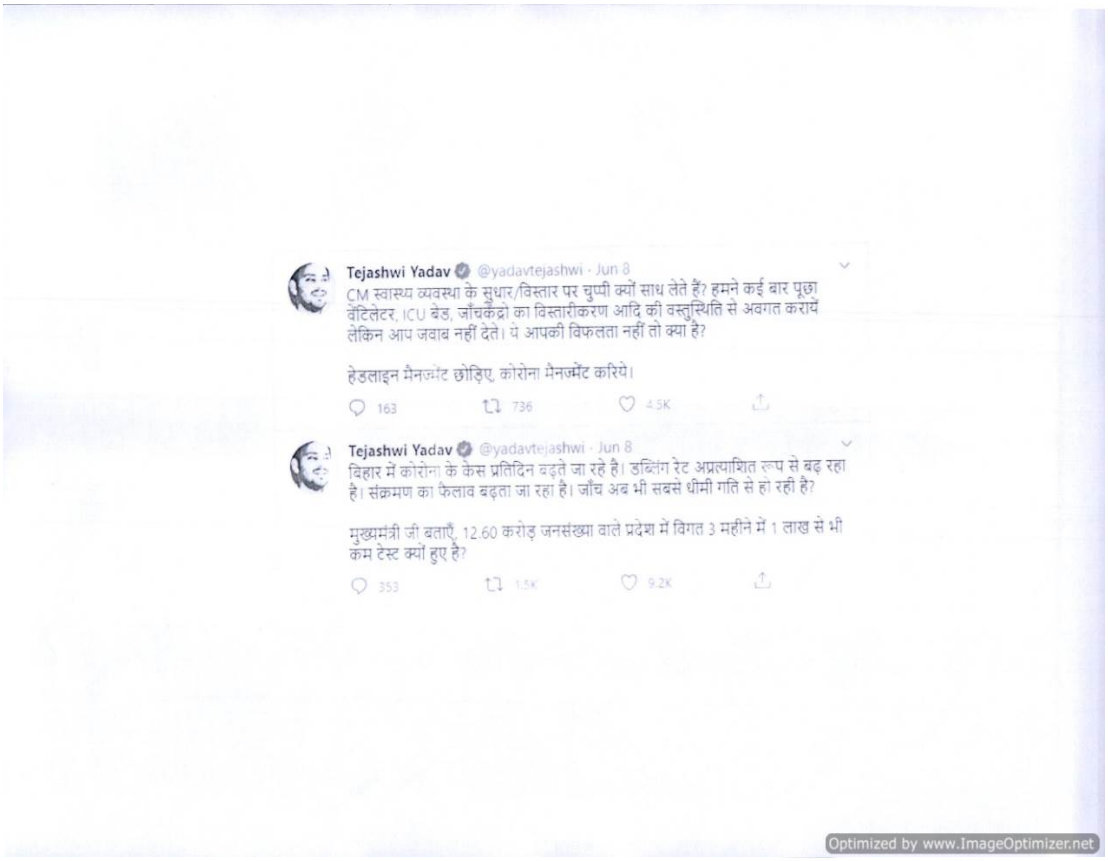

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · Jun 8

CM स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधार/विस्तार पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं? हमने कई बार पूछा वेंटिलेटर, ICU बेड, जाँचकेंद्रों का विस्तारीकरण आदि की वस्तुस्थिति से अवगत करायें लेकिन आप जवाब नहीं देते। ये आपकी विफलता नहीं तो क्या है?

हेडलाइन मैनजमेंट छोड़िए, कोरोना मैनजमेंट करिये।

163 736 4.5K

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · Jun 8

बिहार में कोरोना के केस प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है। डबलिंग रेट अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा है। संक्रमण का फैलाव बढ़ता जा रहा है। जाँच अब भी सबसे धीमी गति से हो रही है?

मुख्यमंत्री जी बताएँ, 12.60 करोड़ जनसंख्या वाले प्रदेश में विगत 3 महीने में 1 लाख से भी कम टेस्ट क्यों हुए है?

353 1.5K 9.2K

Optimized by www.ImageOptimizer.net

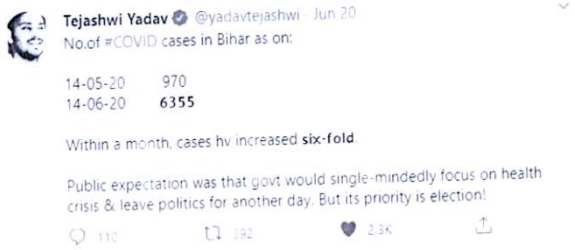

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · Jun 20

No.of #COVID cases in Bihar as on:

14-05-20 970
14-06-20 **6355**

Within a month, cases hv increased **six-fold**.

Public expectation was that govt would single-mindedly focus on health crisis & leave politics for another day. But its priority is election!

110 392 2.3K

Optimized by www.ImageOptimizer.net

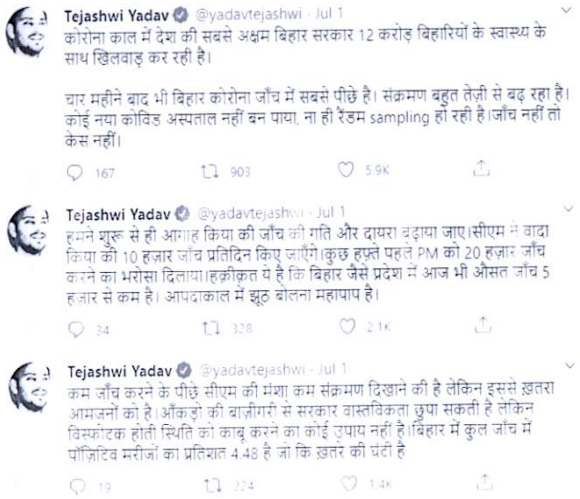

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · Jul 1

कोरोना काल में देश की सबसे अक्षम बिहार सरकार 12 करोड़ बिहारियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।

चार महीने बाद भी बिहार कोरोना जाँच में सबसे पीछे है। संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कोई नया कोविड अस्पताल नहीं बन पाया, ना ही रैंडम sampling हो रही है।जाँच नहीं तो केस नहीं।

167 903 5.9K

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · Jul 1

हमने शुरू से ही आगाह किया की जाँच की गति और दायरा बढ़ाया जाए।सीएम ने वादा किया की 10 हज़ार जाँच प्रतिदिन किए जाएँगे।कुछ हफ़्ते पहले PM को 20 हज़ार जाँच करने का भरोसा दिलाया।हक़ीक़त ये है कि बिहार जैसे प्रदेश में आज भी औसत जाँच 5 हज़ार से कम है। आपदाकाल में झूठ बोलना महापाप है।

34 328 2.1K

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · Jul 1

कम जाँच करने के पीछे सीएम की मंशा कम संक्रमण दिखाने की है लेकिन इससे ख़तरा आमजनों को है।आँकड़ों की बाज़ीगरी से सरकार वास्तविकता छुपा सकती है लेकिन विस्फोटक होती स्थिति को काबू करने का कोई उपाय नहीं है।बिहार में कुल जाँच में पॉज़िटिव मरीजों का प्रतिशत 4.48 है जो कि ख़तरे की घंटी है

19 224 1.4K

Optimized by www.ImageOptimizer.net

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · Jul 4

कल बिहार में एक दिन के सबसे अधिक 716 कोरोना संक्रमित मरीज़ मिले जो कि कल की कुल जाँच का 9.97% है।

हम शुरू से ही बोल रहे है कि नीतीश जी "No Test No Case" नीति से संक्रमण की वास्तविकता और अपनी विफलता छुपाना चाहते हैं। चार माह बाद भी अधिक जाँच करने में क्या परेशानी है?

247 1.5K 10K

Optimized by www.ImageOptimizer.net

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · Jul 7

आदरणीय सुशील जी,

सफ़ेद झूठ और गुमराह करना आपका व्यक्तित्व और ख़ानदानी संस्कृति रही है। लेकिन भगवान के लिए इस महामारी में फ़र्ज़ी दावा न करें। चुनौती है कि आप साबित करें 7 मार्च से 7 जुलाई तक अगर किसी भी दिन 9 हज़ार जाँच हुई है तो मैं राजनीति से सन्यास ले लूँगा वरना आप ले लेंगे। twitter.com/SushilModi/sta...

This Tweet is unavailable.

285 1.3K 6.2K

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · Jul 7

आपके स्वास्थ्यमंत्री कहते है 10 हज़ार जाँच हो रही है।CM नीतीश प्रधानमंत्री को आश्वासन दे गुमराह करते है कि 20 हज़ार जाँच करेंगे। हक़ीक़त यह है की आज तक 9 हज़ार भी जाँच नहीं हुए। पिछले तीन दिनों के जाँच के सरकारी आँकड़े निम्न हैं:

05 July : 6799
06 July : 6213
07 July : 5168

58 497 2.6K

Optimized by www.ImageOptimizer.net

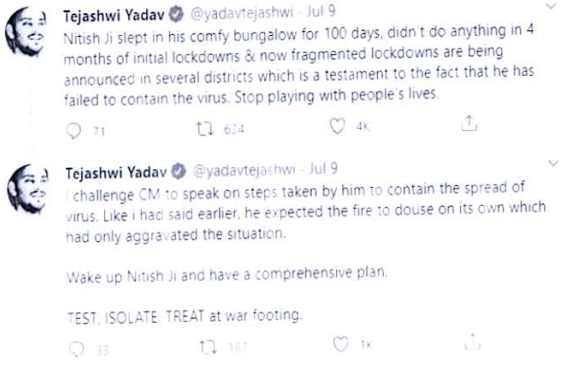

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · Jul 9

Nitish Ji slept in his comfy bungalow for 100 days, didn t do anything in 4 months of initial lockdowns & now fragmented lockdowns are being announced in several districts which is a testament to the fact that he has failed to contain the virus. Stop playing with people s lives.

71 624 4K

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · Jul 9

I challenge CM to speak on steps taken by him to contain the spread of virus. Like i had said earlier, he expected the fire to douse on its own which had only aggravated the situation.

Wake up Nitish Ji and have a comprehensive plan.

TEST, ISOLATE, TREAT at war footing.

33 387 1K

Optimized by www.ImageOptimizer.net

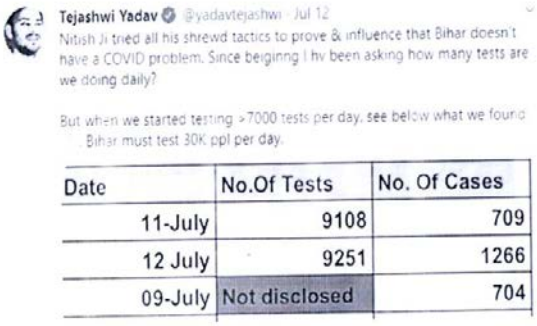

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · Jul 12

Nitish Ji tried all his shrewd tactics to prove & influence that Bihar doesn't have a COVID problem. Since beginning I hv been asking how many tests are we doing daily?

But when we started testing >7000 tests per day, see below what we found
Bihar must test 30K ppl per day.

Date	No.Of Tests	No. Of Cases
11-July	9108	709
12 July	9251	1266
09-July	Not disclosed	704

Optimized by www.ImageOptimizer.net

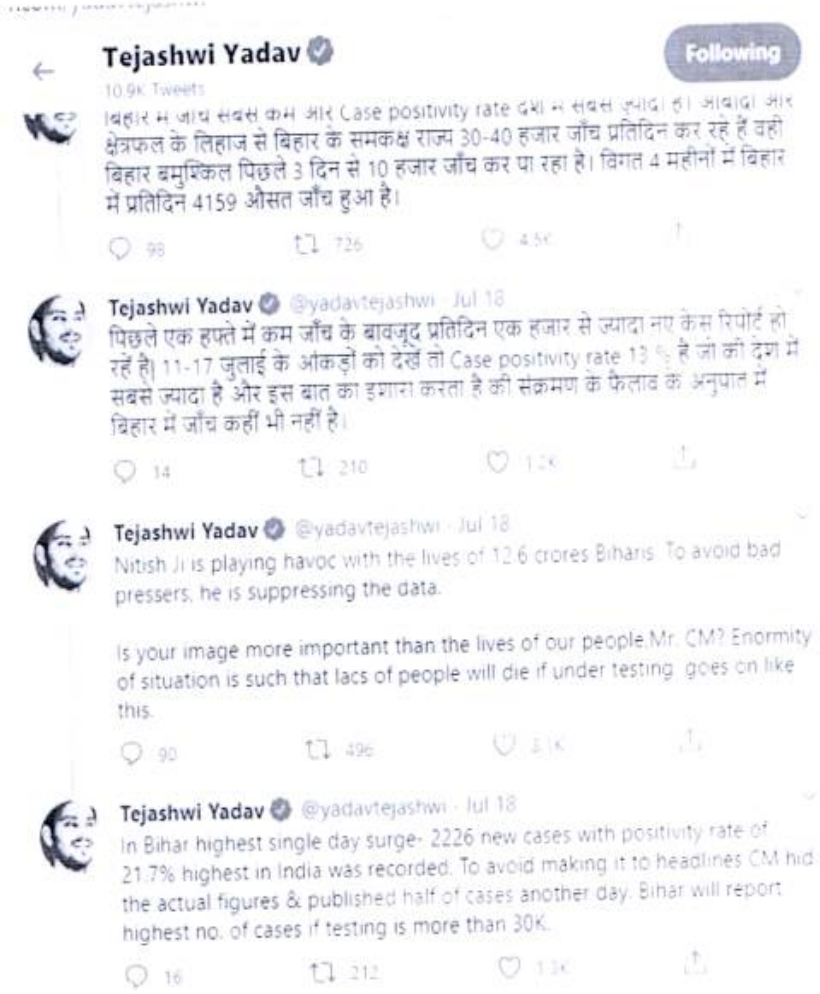

Tejashwi Yadav

Following

10.9K Tweets

बिहार में जाँच सबसे कम और Case positivity rate देश में सबसे ज्यादा है। आबादी और क्षेत्रफल के लिहाज से बिहार के समकक्ष राज्य 30-40 हजार जाँच प्रतिदिन कर रहे हैं वहीं बिहार बमुश्किल पिछले 3 दिन से 10 हजार जाँच कर पा रहा है। विगत 4 महीनों में बिहार में प्रतिदिन 4159 औसत जाँच हुआ है।

98 726 4.5K

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · Jul 18

पिछले एक हफ्ते में कम जाँच के बावजूद प्रतिदिन एक हजार से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हो रहें है। 11-17 जुलाई के आंकड़ों को देखें तो Case positivity rate 13 % है जो की देश में सबसे ज्यादा है और इस बात का इशारा करता है की संक्रमण के फैलाव के अनुपात में बिहार में जाँच कहीं भी नहीं है।

14 210 1.2K

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · Jul 18

Nitish Ji is playing havoc with the lives of 12.6 crores Biharis. To avoid bad pressers, he is suppressing the data.

Is your image more important than the lives of our people,Mr. CM? Enormity of situation is such that lacs of people will die if under testing goes on like this.

90 496 2.1K

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · Jul 18

In Bihar highest single day surge- 2226 new cases with positivity rate of 21.7% highest in India was recorded. To avoid making it to headlines CM hid the actual figures & published half of cases another day. Bihar will report highest no. of cases if testing is more than 30K.

16 212 1.3K

Tejashwi Yadav
Following
10.9K Tweets
पेट दर्द और खांसी की शिकायत पर मरीज को अस्पताल लाया गया था लेकिन कई घंटे बीत जाने के बावजूद डॉक्टर ने इलाज नहीं किया।
0:28
182.3K views
Tejashwi Yadav Retweeted
Zee Bihar Jharkhand @ZeeBiharNews · Jul 18
पटना: नेता प्रतिपक्ष @yadavtejashwi ने कहा- बिहार कोरोना का Global Hotspot बन जाएगा.
@RJDforIndia

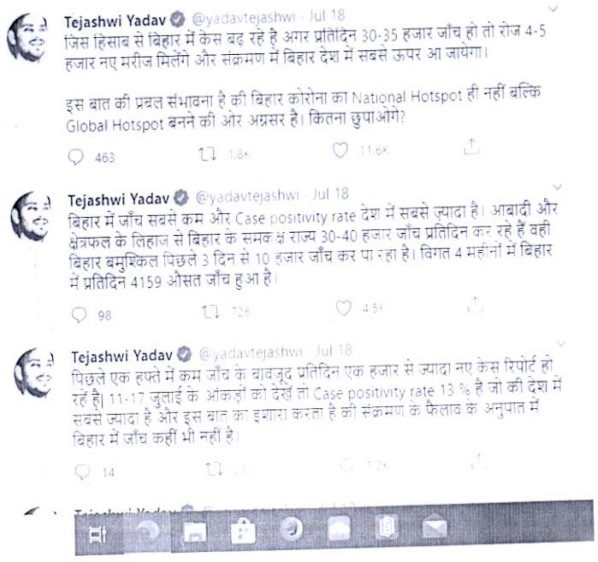

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · Jul 18
जिस हिसाब से बिहार में केस बढ़ रहे है अगर प्रतिदिन 30-35 हजार जाँच हो तो रोज 4-5 हजार नए मरीज मिलेंगे और संक्रमण में बिहार देश में सबसे ऊपर आ जायेगा।

इस बात की प्रबल संभावना है की बिहार कोरोना का National Hotspot ही नहीं बल्कि Global Hotspot बनने की ओर अग्रसर है। कितना छुपाओगे?

463 1.8K 11.6K

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · Jul 18
बिहार में जाँच सबसे कम और Case positivity rate देश में सबसे ज्यादा है। आबादी और क्षेत्रफल के लिहाज से बिहार के समक्ष राज्य 30-40 हजार जाँच प्रतिदिन कर रहे हैं वही बिहार बमुश्किल पिछले 3 दिन से 10 हजार जाँच कर पा रहा है। विगत 4 महीनों में बिहार में प्रतिदिन 4159 औसत जाँच हुआ है।

98 726 4.5K

Tejashwi Yadav @yadavtejashwi · Jul 18
पिछले एक हफ्ते में कम जाँच के बावजूद प्रतिदिन एक हजार से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हो रहें है। 11-17 जुलाई के आकड़ों को देखें तो Case positivity rate 13 % है जो की देश में सबसे ज्यादा है और इस बात का इशारा करता है की संक्रमण के फैलाव के अनुपात में बिहार में जाँच कहीं भी नहीं है।

14 2.1K 7.2K

Optimized by www.ImageOptimizer.net

LAV AGARWAL, IAS
Joint Secretary

Tel. : 011-23061195
T/Fax : 011-23061842
E-mail : alav@ias.nic.in

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
निर्माण भवन, नई दिल्ली - 1

GOVERNMENT OF INDI
MINISTRY OF HEALTH & FAMILY
NIRMAN BHAVAN, NEW DELHI -

D.O. F. No. Z.28015/167/2020-

22/07/

Dear Sir,

Central team has visited Bihar on 19th and 20th July 2020. The team had visited COVID designated hospitals, Isolation centres and containment zones in Patna and Gaya dist. Subsequent to that, the team had debriefed Hon'ble Health Minister, Chief Secretary and ot health officials on 20th July 2020.

A detailed presentation was made during the meeting. It was highlighted that cases in Bihar showing an upsurge with almost 800-1,000 cases being reported daily & 90% of the active cases h been reported in the last 7 days. Districts which need specific and focused attention in view of la number of cases and the surge include Patna, Nalanda, Nawada, Siwan, Pashchim Champa Jamui, Bhagalpur, Begusarai and Munger. Further, Purbi Champaran, Gaya, Rohtas Muzaffarpur are emerging hotspots.

The overall testing ratio in Bihar is very low as compared to national average. Low testing result in spread of infection, late identification and late arrival of cases in hospitals, which ma turn impact the case fatality rate and hence, need for increase in testing was reiterated. Fur increase in case positivity is also a cause of concern.

As discussed during the meeting, I would like to submit few areas of concern and suggestive co of action to be followed at state level for kind consideration:

i. While containment zones have been delineated and perimeter control is b monitored, it is suggested that the special teams for active house-to-house case s in these containment zones need to be increased at the rate of approximatel households and they should be able to physically visit at least on an alternate da the houses allotted to them.
ii. Special focus has to be given to co-morbid and elderly population within containment zones
iii. All contacts of positive cases need to be traced within first 72 hours and samp shall be taken up as per ICMR guidelines
iv. To ensure capacity utilization of existing RT-PCR labs besides taking actio increase the RT-PCR testing capacity also
v. Antigen tests to be leveraged for undertaking samples in containment zones hospitals. Symptomatic negative results of antigen tests shall be monitored thro RT-PCR tests
vi. Home isolation shall only be allowed after due verification by the treatment do duly following the guidelines for home isolation and a clearly defined mechanis

also established for monitoring such cases. A clearly defined protocol for s such cases to hospitals shall also be put in place

vii. Ensure sufficient hospital infrastructure, including setting up tempora hospitals, is created duly taking into consideration the case growth trajector least next 2 months

viii. Ensure availability of infrastructure across all districts in view of widesprea being reported across the state

ix. Undertake capacity building of health workforce across all Covid dedicated h and ensure proper roster system for patient management

x. Ensure infection prevention practices including triaging & effective segreg suspect & confirmed patients in all hospitals which are treating COVID Government of India guidelines on the issue may be scrupulously followed.

xi. Ensure sufficient logistics availability, particularly oxygen cylinders and oxygen, in all health facilities

xii. State may consider designating a state level Covid-19 facility as Center of Exc which shall on one hand, attend the webinars undertaken by AIIMS-Delhi an other hand, shall mentor all state level health facilities through VCs.

xiii. Ensure that all Covid dedicated facilities are sufficiently trained to manage their end

xiv. State may also consider utilizing the model of temporary Covid-19 de facilities prepared by DRDO/Maharashtra, etc. A team may also be sent t states to study the model.

xv. A mechanism may be put in place to ensure seamless admission for Covid-19 in appropriate health facilities duly tieing up with ambulance and call cent bed utilization and vacancy position in all health facilities may also be online.

xvi. All health facilities may be monitored for their case management and case fa a weekly basis. Death audit may also be taken up to provide inputs to th professionals for better case management.

While conveying my thanks to all health professionals in the state for their relentless efforts wish to convey that we need to on continued alert and maintain our efforts so as to manage effectively.

with regards,

Yours s ly

(La)

Shri Udai Singh Kumawat, IAS
Principal Secretary
Department of Health
Government of Bihar
Secretariat, Patna

(64) WhatsApp

Sanjay

today at 9:13 PM

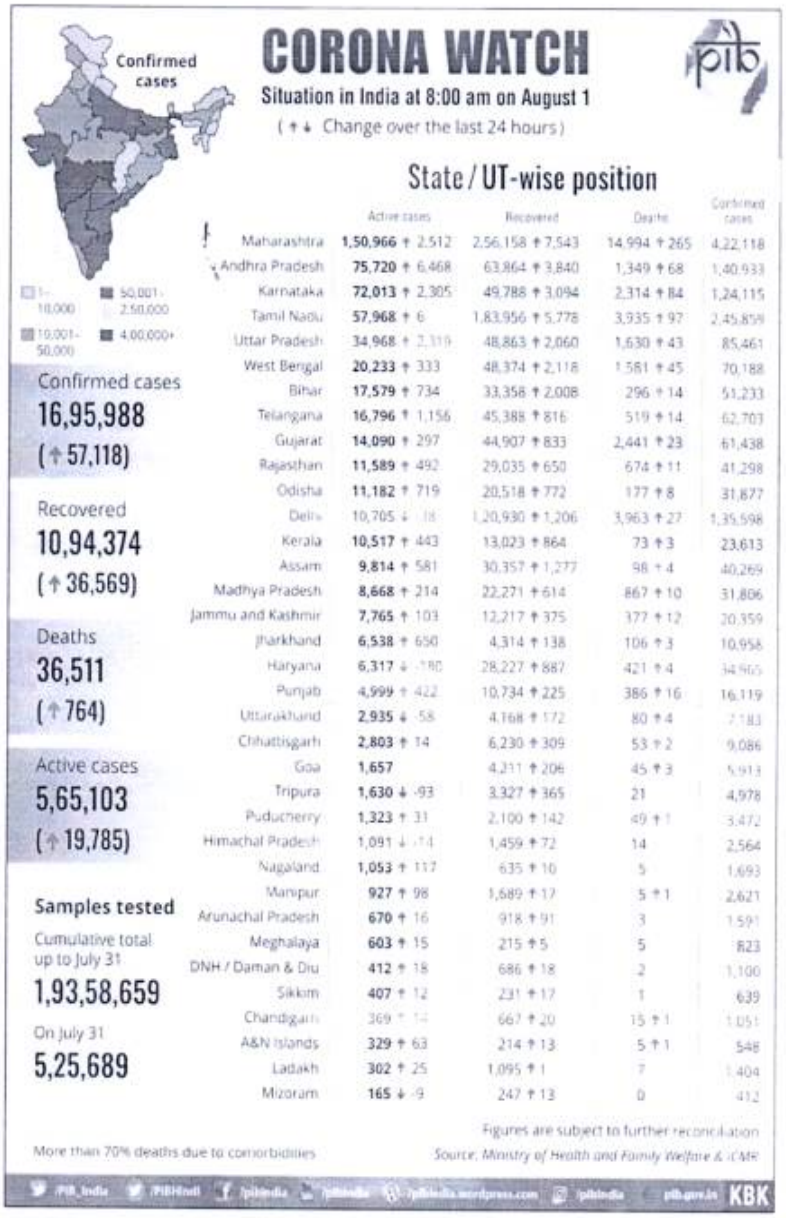

	Active cases	Recovered	Deaths	Confirmed cases
Maharashtra	1,50,966 ↑ 2,512	2,56,158 ↑ 7,543	14,994 ↑ 265	4,22,118
Andhra Pradesh	75,720 ↑ 6,468	63,864 ↑ 3,840	1,349 ↑ 68	1,40,933
Karnataka	72,013 ↑ 2,305	49,788 ↑ 3,094	2,314 ↑ 84	1,24,115
Tamil Nadu	57,968 ↑ 6	1,83,956 ↑ 5,778	3,935 ↑ 97	2,45,859
Uttar Pradesh	34,968 ↑ 2,319	48,863 ↑ 2,060	1,630 ↑ 43	85,461
West Bengal	20,233 ↑ 333	48,374 ↑ 2,118	1,581 ↑ 45	70,188
Bihar	17,579 ↑ 734	33,358 ↑ 2,008	296 ↑ 14	51,233
Telangana	16,796 ↑ 1,156	45,388 ↑ 816	519 ↑ 14	62,703
Gujarat	14,090 ↑ 297	44,907 ↑ 833	2,441 ↑ 23	61,438
Rajasthan	11,589 ↑ 492	29,035 ↑ 650	674 ↑ 11	41,298
Odisha	11,182 ↑ 719	20,518 ↑ 772	177 ↑ 8	31,877
Delhi	10,705 ↓ 18	1,20,930 ↑ 1,206	3,963 ↑ 27	1,35,598
Kerala	10,517 ↑ 443	13,023 ↑ 864	73 ↑ 3	23,613
Assam	9,814 ↑ 581	30,357 ↑ 1,277	98 ↑ 4	40,269
Madhya Pradesh	8,668 ↑ 214	22,271 ↑ 614	867 ↑ 10	31,806
Jammu and Kashmir	7,765 ↑ 103	12,217 ↑ 375	377 ↑ 12	20,359
Jharkhand	6,538 ↑ 650	4,314 ↑ 138	106 ↑ 3	10,958
Haryana	6,317 ↓ 180	28,227 ↑ 887	421 ↑ 4	34,965
Punjab	4,999 ↑ 422	10,734 ↑ 225	386 ↑ 16	16,119
Uttarakhand	2,935 ↓ 58	4,168 ↑ 172	80 ↑ 4	7,183
Chhattisgarh	2,803 ↑ 14	6,230 ↑ 309	53 ↑ 2	9,086
Goa	1,657	4,211 ↑ 206	45 ↑ 3	5,913
Tripura	1,630 ↓ 93	3,327 ↑ 365	21	4,978
Puducherry	1,323 ↑ 31	2,100 ↑ 142	49 ↑ 1	3,472
Himachal Pradesh	1,091 ↓ 74	1,459 ↑ 72	14	2,564
Nagaland	1,053 ↑ 117	635 ↑ 10	5	1,693
Manipur	927 ↑ 98	1,689 ↑ 17	5 ↑ 1	2,621
Arunachal Pradesh	670 ↑ 16	918 ↑ 91	3	1,591
Meghalaya	603 ↑ 15	215 ↑ 5	5	823
DNH / Daman & Diu	412 ↑ 18	686 ↑ 18	2	1,100
Sikkim	407 ↑ 12	231 ↑ 17	1	639
Chandigarh	369 ↑ 14	667 ↑ 20	15 ↑ 1	1,051
A&N Islands	329 ↑ 63	214 ↑ 13	5 ↑ 1	548
Ladakh	302 ↑ 25	1,095 ↑ 1	7	1,404
Mizoram	165 ↓ 9	247 ↑ 13	0	412

8/2/2020 (64) WhatsApp

Sanjay
today at 9:13 PM

CORONA WATCH

Situation in India at 8:00 am on July 1

(↑ ↓ Change over the last 24 hours)

Confirmed cases
5,85,493 (↑ 18,653)

Recovered*
3,47,979 (↑ 13,157)

Deaths
17,400 (↑ 507)

Active cases
2,20,114 (↑ 4,989)

Confirmed cases

Samples tested

Cumulative total up to June 30: 88,26,585

On June 30: 2,17,931

State / UT-wise position

	Confirmed cases	Recovered	Deaths	Active cases
Maharashtra	1,74,761 ↑ 4,878	90,911	7,855	**75,995** ↑ 2,682
Tamil Nadu	90,167 ↑ 3,943	50,074	1,201	**38,892** ↑ 1,558
Delhi	87,360 ↑ 2,199	58,348	2,742	**26,270** ↑ 24
Gujarat	32,557 ↑ 619	23,662	1,846	**7,049** ↑ 178
Uttar Pradesh	23,492 ↑ 664	16,084	697	**6,711** ↑ 61
West Bengal	18,559 ↑ 652	12,130	668	**5,761** ↑ 226
Rajasthan	18,014 ↑ 354	14,220	413	**3,381** ↓ -256
Telangana	16,339 ↑ 945	7,294	260	**8,785** ↓ -274
Karnataka	15,242 ↑ 947	7,918	246	**7,078** ↑ 692
Andhra Pradesh	14,595 ↑ 704	6,511	187	**7,897** ↑ 418
Haryana	14,548 ↑ 338	9,972	236	**4,340** ↓ -136
Madhya Pradesh	13,593 ↑ 223	10,395	572	**2,626** ↑ 19
Bihar	10,043 ↑ 403	7,687	67	**2,289** ↑ 101
Assam	8,227 ↑ 475	5,647	12	**2,568** ↑ 160
Jammu & Kashmir	7,497 ↑ 260	4,722	101	**2,674** ↑ 117
Odisha	7,065 ↑ 206	5,189	25	**1,851** ↓ -39
Punjab	5,568 ↑ 150	3,867	144	**1,557** ↑ 41
Kerala	4,442 ↑ 253	2,306	24	**2,112** ↑ 97
Uttarakhand	2,881 ↑ 50	2,231	41	**609** ↓ -72
Chhattisgarh	2,860 ↑ 99	2,250	13	**597** ↑ 22
Jharkhand	2,490 ↑ 64	1,884	15	**591** ↑ 25
Tripura	1,388 ↑ 8	1,086	1	**301** ↑ 7
Goa	1,315 ↑ 117	596	3	**716** ↓ -1
Manipur	1,234 ↑ 7	553	0	**681** ↓ -52
Ladakh	973 ↑ 9	648	1	**324** ↓ -23
Himachal Pradesh	953 ↑ 11	580	10	**363** ↓ -14
Puducherry	714 ↑ 95	272	12	**430** ↑ 42
Nagaland	459 ↑ 25	168	0	**291** ↑ 25
Chandigarh	440 ↑ 5	364	6	**70** ↓ -10
DNH and Daman & Diu	213 ↑ 10	82	0	**131** ↑ 5
Arunachal Pradesh	191 ↑ 4	62	1	**128** ↑ 3
Mizoram	160 ↑ 12	122	0	**38** ↓ -55
A&N Islands	97 ↑ 7	50	0	**47** ↑ 3
Sikkim	89 ↑ 1	52	0	**37** ↓ -1
Meghalaya	52 ↑ 5	42	1	**9** ↑ 5

6,915 cases being reassigned to states

Figures are subject to further reconciliation

Source: Ministry of Health and Family Welfare & ICMR

*One migrated case included in recovered

More than 70% deaths due to comorbidities

/PIB_India /PIBHindi /pibindia /pibindia /pibindia.wordpress.com /pibindia pib.gov.in KBK

8/2/2020 (64) WhatsApp

Sanjay
today at 9:13 PM

16.	बगहिया	1210	838	5	367
17.	किशनगंज	785	438	4	343
18.	मझौलिया	789	550	3	236
19.	मधेपुरा	745	490	1	254
20.	मधुबनी	1186	727	2	457
21.	मुंगेर	1123	852	15	256
22.	मुजफ्फरपुर	2459	1530	13	916
23.	नालंदा	2266	1363	16	887
24.	नवादा	1408	1107	7	294
25.	पश्चिम चंपारण	1476	994	10	472
26.	पटना	9358	5650	44	3664
27.	पूर्वी चंपारण	1299	982	13	304
28.	पूर्णिया	1284	874	4	406
29.	रोहतास	2178	1273	17	888
30.	सहरसा	706	465	1	240
31.	समस्तीपुर	1326	841	10	475
32.	सारण	1656	985	10	661
33.	शेखपुरा	590	389	1	200
34.	शिवहर	319	207	1	111
35.	सीतामढ़ी	634	346	4	284
36.	सिवान	1558	1235	8	315
37.	सुपौल	970	644	1	325
38.	वैशाली	1384	847	7	529
	Total	**54508**	**35473**	**312**	**18722**

8/2/2020 (64) WhatsApp

Sanjay
today at 9:13 PM

18.	तखीसराय	767	525	3	239
19.	मधेपुरा	694	458	1	235
20.	मधुबनी	1097	723	2	372
21.	मुंगेर	1063	852	12	199
22.	मुजफ्फरपुर	2123	1428	11	684
23.	नालंदा	2144	1278	16	850
24.	नवादा	1331	1074	7	250
25.	पश्चिम चंपारण	1393	970	10	413
26.	पटना	8764	5297	41	3426
27.	पूर्वी चंपारण	1222	953	12	257
28.	पूर्णिया	1185	790	4	391
29.	रोहतास	2081	1165	16	900
30.	सहरसा	683	462	1	220
31.	समस्तीपुर	1221	819	10	392
32.	सारण	1610	924	10	676
33.	शेखपुरा	557	375	1	181
34.	शिवहर	299	194	1	104
35.	सीतामढ़ी	478	334	4	140
36.	सिवान	1498	1184	7	307
37.	सुपौल	925	621	1	303
38.	वैशाली	1301	765	7	528
	Total	**50987**	**33650**	**298**	**17038**

8/2/2020 (64) WhatsApp

Sanjay
today at 9:13 PM

COVID-19 UPDATE

Dated: 31-07-2020

- विगत 24 घंटे में COVID-19 से ठीक हुए व्यक्ति : 1977
- अब तक कुल ठीक हुए व्यक्ति : 33650
- बिहार राज्य में रिकवरी का दर : 66.00%
- विगत 24 घंटे में COVID-19 के नये मामले : 2986
- वर्तमान में COVID-19 के Active मरीज़ की संख्या : 17038
- विगत 24 घंटे में बिहार राज्य में किए गये कुल जाँच : 22742
- अब तक बिहार राज्य में किये गये कुल जाँच : 548172

S No.	District	Positive Cases	Discharged	Dead	Active Case
1.	अररिया	620	395	6	219
2.	अरवल	539	324	2	213
3.	औरंगाबाद	940	598	4	338
4.	बांका	616	428	2	186
5.	बेगूसराय	1710	1209	10	491
6.	भागलपुर	2551	1943	28	580
7.	भोजपुर	1571	1044	12	515
8.	बक्सर	1022	582	3	437
9.	दरभंगा	837	546	10	281
10.	गया	2083	1253	21	809
11.	गोपालगंज	946	729	1	216
12.	जमुई	834	472	1	361
13.	जहानाबाद	880	608	5	267
14.	कैमूर	498	330	4	164
15.	कटिहार	1082	787	3	292
16.	खगड़िया	1094	800	5	289
17.	किशनगंज	728	411	4	313

8/2/2020 (64) WhatsApp

Sanjay
today at 9:13 PM

COVID-19 UPDATE

Dated: 01-08-2020

- विगत 24 घंटे में COVID-19 से ठीक हुए व्यक्ति : 1823
- अब तक कुल ठीक हुए व्यक्ति : 35473
- बिहार राज्य में रिकवरी का दर : 65.08%
- दिनांक 31/07/2020 को COVID-19 के अब तक पॉजिटिव नए मामले : 2502
- वर्तमान में COVID-19 के Active मरीज की संख्या : 18722
- विगत 24 घंटे में बिहार राज्य में किए गये कुल जाँच : 28624
- अब तक बिहार राज्य में किये गये कुल जाँच : 576796

S No.	District	Positive Cases	Discharged	Dead	Active Case
1.	अररिया	674	398	7	269
2.	अरवल	581	371	2	208
3.	औरंगाबाद	1018	611	4	403
4.	बांका	681	428	2	251
5.	बेगूसराय	1849	1221	10	618
6.	भागलपुर	2638	2030	30	578
7.	भोजपुर	1623	1103	12	508
8.	बक्सर	1102	649	3	450
9.	दरभंगा	885	584	10	291
10.	गया	2209	1327	21	861
11.	गोपालगंज	1038	752	1	285
12.	जमुई	863	561	1	301
13.	जहानाबाद	924	644	5	275
14.	कैमूर	538	336	4	198
15.	कटिहार	1176	831	3	342

परिशिष्ट –3

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

बाढ 2020

माननीय मंत्री के भाषण का अंश

आपदा प्रबंधन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को ससमय राहत पहुँचाने के लिए राज्य सरकार कटिवद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिमत है कि आपदा पीड़ितों का राज्य सरकार के खजाने पर पहला हक है।

आपदा प्रबंधन विभाग का मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन के संस्थागत ढाँचे को अधिक सुदृढ़ करना एवं कारगर बनाते हुए विभिन्न प्रकार के आपदाओं से प्रभावित लोगों को तत्काल एवं पारदर्शी तरीके से सहायता प्रदान करना तथा उनसे न्यूनतम क्षति हो, उसका उपाय करना है।

विभाग द्व माननीय मंत्री के भाषण का अंश को आनुग्रहिक राशि (GR) के अतिरिक्त फसल क्षति अनुदान, गृह क्षति अनुदान, पशु क्षति अनुदान देने की व्यवस्था की जाती है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2015–16 से वज्रपात, लू, अतिवृष्टि असमय भारी बारिश, नाव दुर्घटना नदियों, तालाबों, गड्ढों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित दुर्घटना, सामूहिक दुर्घटना यथा– सड़क, वायुयान, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना को दिनांक 20.03.2015, आंधी–तुफान एवं नहरों में डूबने से हुई मृत्यु को दिनांक 16.07.2018 तथा किसी भी जलस्रोत से हुई मृत्यु को दिनांक 01.02.2019 के प्रभाव से विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा के रूप में अधिसूचित करते हुए उन आपदाओं से होने वाली जान–माल की क्षति में भी SDRF/NDRF द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश्य पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराया जाता है।

सरकारी कर्मियों एवं समुदाय के प्रशिक्षण क्षमता संवर्द्धन एवं जागरूकता कार्यक्रम भी विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं।

Flood 2020 :- Deployment of NDRF & SDRF

Date:- 25.06.2020 Time:- 11:00 A.M.

Sl. No.	District	No. of Teams		
		NDRF	SDRF	Remarks
1.	Supaul	02		Deployed
2.	Madhepura		01	Deployed
3.	Saharsa		01	Deployed
4.	Purnea		02	Deployed
5.	Kishanganj	01		Deployed
6.	Araria	01		Deployed
7.	Katihar	01		Deployed
8.	Darbhanga	02	01	Deployed
9.	Madhubani	01	01	Deployed
10.	Muzaffarpur	01	01	Deployed
11.	Vaishali		01	Deployed
12.	Sitamarhi		01	Deployed
13.	East Champaran	03		Deployed
14.	West Champaran	01	01	Deployed
15.	Khagaria		02	Deployed
16.	Bhagalpur		01	Deployed
17.	Gopalganj	03	01	Deployed
18.	Saran	03		Deployed
19.	Siwan	01	01	Deployed
20.	Samastipur		01	Deployed
21.	Patna	01	01	Deployed
22.	Reserve	03	02	Deployed
23.	Shivhar		01	Deployed
Total		**24**	**20**	

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

बाढ़ 2020

1. माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के द्वारा 13 जून 2020 को बाढ़ से संबंधित पूर्व तैयारियों की समीक्षात्मक बैठक की गयी एवं कोविड संक्रमण के आलोक में बाढ़ की तैयारी के लिए आवश्यक निर्देश दिया था :

- बाढ़ राहत शिविरों की संख्या में वृद्धि
- पर्याप्त संख्या में मास्क एवं सैनिटाईजर की व्यवस्था
- सोशल डिस्टेंसिंग के आलोक में निष्क्रमण हेतु NDRF एवं SDRF की टीमों की संख्या में भी वृद्धि।
- निष्क्रमण में वृद्ध, दिव्यांग, गर्भवती एवं धात्री महिला, बच्चों को प्राथमिकता।

2. मॉनसून अवधि के दौरान जून माह में सामान्य वर्षापात **167.70 mm** की अपेक्षा **305.90 mm** वास्तविक वर्षापात दर्ज की गयी, जो **82 प्रतिशत** अधिक है। पुनः जुलाई माह में सामान्य वर्षापात **349.00 mm** की अपेक्षा **443.50 mm** वास्तविक वर्षापात दर्ज की गयी, जो **27 प्रतिशत** अधिक है। स्पष्ट है कि इस वर्ष राज्य में अब तक सामान्य से अधिक वर्षापात दर्ज किया गया है।

SDRF

3. इस वर्ष जुलाई माह के द्वितीय सप्ताह में उत्तर बिहार एवं नेपाल के तराई क्षेत्रों में हुई भारी वर्षापात के कारण उत्तर बिहार से हो कर गुजरने वाली अधिकांश नदियों यथा गंडक, बागमती, कमला बलान, बूढ़ी गंडक, लखनदेई, ललबकिया आदि के जल स्तर में काफी वृद्धि हुई। फलस्वरूप दिनांक 13.07.2020 को **सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल एवं किशनगंज** के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी। पुनः जुलाई माह के तृतीय सप्ताह में भी नेपाल के तराई क्षेत्रों, विशेषकर गंडक नदी के जलग्रहण क्षेत्र, में काफी अधिक वर्षापात दर्ज की गयी, जिसके कारण 14.07.2020 से 17.07.2020 के बीच पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, गोपालगंज जिला बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए। बागमती, बूढी गंडक, अधवारा समूह एवं कमला बलान आदि नदियों के जलस्तर में भी काफी वृद्धि हुई, जिसके कारण दिनांक 14.07.2020 को दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

4. वर्तमान में राज्य के 14 जिलों, यथा **शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, प0 चम्पारण, किशनगंज, सुपौल, गोपालगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सीवान एवं मधुबनी** में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है।

5. दिनांक–01.08.2020 तक कुल 14 जिलों के 112 प्रखण्डों के अन्तर्गत 1043 पंचायतों की लगभग 49,05,007 जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित हुई है। राज्य सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय आपदा रिस्पौंस फोर्स (NDRF) एवं राज्य आपदा रिस्पौंस फोर्स (SDRF) के सहयोग से बाढ़ में फँसे लगभग 4.90 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निष्क्रमित किया गया। गोपालगंज, दरभंगा एवं पूर्वी चम्पारण के वैसे इलाके, जहाँ स्थानीय तौर पर नाव एवं मोटरबोट के माध्यम से पहुँचने में कठिनाई थी, वहाँ लोगों तक सहायता पहुँचाने के लिए भारतीय वायुसेना के 3 हेलिकॉप्टर की मदद ली गई। दिनांक 25.07.2020 से 27.07.2020 तक 30 Sorties के द्वारा 16598 सूखा राहत पैकेट का Air Dropping कराया गया। बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए अबतक कुल 38 राहत शिविर खोले गये थे, जिसमें 27402 लोगों को आवासित किया गया था। वर्तमान में 19 राहत शिविर संचालित हैं, जिसमें 26732 लोग रह रहे हैं। इन शिविरों में सुबह का नाश्ता तथा दिन एवं रात का भोजन, शुद्ध पेयजल, साफ–सफाई और शौचालय की व्यवस्था की गयी है। राहत शिविर में रहने वाले लोगों के लिए वस्त्र तथा भोजन करने के लिए बर्तन की व्यवस्था की गयी है। कोविड संक्रमण को देखते हुए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि राहत शिविरों में अनिवार्य रूप से मास्क का

उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग तथा भोजन की व्यवस्था में staggering का अनुपालन हो।

6. जो लोग राहत शिविरों में नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए उनके गाँव/मुहल्ले के नजदीक ही किसी उँचे स्थल पर **सामुदायिक रसोई** की व्यवस्था की गयी, **कुल 1340** सामुदायिक रसोई का संचालन किया जा रहा है, जिसमें **आठ लाख बेरासी हजार लोगों को भोजन कराया जा रहा है।**

7. राहत शिविर तथा सामुदायिक रसोई का उपयोग कर रहे लोगों के लिए विशेष रूप से Rapid Antigen Tests की कार्रवाई की जा रही है।

8. राज्य आपदा रिस्पांस निधि (SDRF) के निर्धारित मानदर के अनुसार बाढ़ प्रभावित परिवारों को **आनुग्रहिक साहाय्य राशि (GR)** देने का प्रावधान है। वर्ष 2019 में राज्य में आये बाढ़ के कारण व्यापक जान–माल की क्षति हुई थी, जिसके आलोक में राज्य सरकार के द्वारा पहली बार PFMS (Public Financial Management System) के माध्यम से सीधे राज्य स्तर से सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों के खाते में GR की राशि अंतरित (Direct Beneficiary Transfer) की गयी। इस उपलब्धि के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी किया गया।

9. इस वर्ष भी बाढ़ से प्रभावित सभी परिवारों को ससमय निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप रू० 6000 प्रति परिवार की दर से **आनुग्रहिक साहाय्य राशि (Gratuitous Relief)** का अंतरण सीधे उनके बैंक खातों में करने का निर्णय लिया गया है। **दिनांक–01.08.2020 तक 1,93,889 (एक लाख तिरानबे हजार आठ सौ नबासी) बाढ़ पीड़ित परिवारों को 6000/– रु0 की दर से कुल 116.33 करोड़ रु0 की राशि अंतरित की जा चुकी है। शेष बाढ़ पीड़ित परिवारों को अगले 10 दिनों के अन्दर GR की राशि भुगतान करने का निदेश दिया गया है।**

10. अबतक बाढ़ से **13** व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, दरभंगा–**7**, पश्चिम चम्पारण–**4**, मुजफ्फरपुर–**2**

11. बाढ़ के पश्चात SOP के अनुसार क्षति का आकलन कराया जायेगा। फसल क्षति हेतु सर्वेक्षण के पश्चात कृषि इनपुट अनुदान का वितरण की जायेगी।

12. माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के द्वारा दिनांक 29 जुलाई 2020 को बाढ़ प्रभावित जिलों के जिला पदाधिकारियों तथा सरकार के संबंधित विभागों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गयी एवं आवश्यक निदेश दिये गये थे। समीक्षा के क्रम में विभिन्न जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संचालित बाढ़ राहत केन्द्र

एवं सामुदायिक रसोई की भी जानकारी ली गयी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कतिपय बाढ़ राहत केन्द्र/सामुदायिक रसोई में उपस्थित बाढ़ पीड़ितों से बात–चीत की गई एवं वहाँ उपलब्ध सुविधाओं एवं भोजन आदि के संबंध में वस्तुस्थिति की जानकारी ली गयी। मौसम के हिसाब से सभी संबंधित को अगस्त एवं सितम्बर माह में संभावित बाढ़ हेतु सजग रहने के लिए निदेशित किया गया है।

II. राज्य में वज्रपात के पूर्व चेतावनी की स्थापना हेतु अर्थ नेटवर्क इंक एवं कीहू सॉल्यूशन के साथ समझौता ज्ञापन सम्पन्न हुआ है। जिसके माध्यम से वज्रपात के खतरों वज्रपात के अवधि में शरण लेने के विषय में व्यापक प्रचार–प्रसार प्रस्तुत करना है तथा वज्रपात/ओलापात के विषय में पहले ही एक मोबाईल एप के द्वारा संदेश भेज कर सर्वसाधारण को सतर्क कर देना है कि वो सुरक्षित शरण में चले जाये।

विदित है कि आपदा प्रबंधन विभाग ने वज्रपात के विरूद्ध पूर्व चेतावनी प्रणाली को कार्यरत करने के लिए इंद्रवज्र मोबाईल एप का विकास किया है जिसको अपने मोबाईल पर डाउनलोड करने के बाद लगभग 20 कि0मी0 की परिधी में ठनका गिरने की स्थिति में मोबाईल यूजर को 40–45 मिनट पूर्व अलार्म टोन के साथ चेतावनी संदेश प्राप्त होगा।

राज्य सरकार ने कई प्रशासनिक कार्यकारी माध्यमों एवं सूचना माध्यमों के द्वारा इंद्रवज्र एप को अपने मोबाईल में डाउनलोड कर प्रयोग करने के लिए सर्वसाधारण को जागरूक करने का व्यापक प्रयास की है।

बिहार राज्य के अन्तर्गत पूर्व चेतावनी वज्रपात के विरूद्ध एक कारगर उपाय है। राज्य सरकार में प्रभावी संचालन के क्रम में तृणमूल स्तर पर अधिकारियों यथा पंचायत सेवक/राजस्व कर्मचारी/पर्यवेक्षकीय अधिकारियों/अंचल अधिकारी एवं त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का राज्य के प्रत्येक प्रखंडों में एक व्यापक संजाल का अधिष्ठापन किया है जिसके माध्यम से सर्वसाधारण को सम्बद्ध किया जा रहा है ताकि वज्रपात की सूचना का व्यापक पहूँच बढ़ाया जा सके। विदित है कि राज्य के अधिकारीगण भी वाट्सअप के माध्यम से इस Application से भी जोड़ दिये गये हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि इन्द्रवज्र एप से राज्य की सभी जनता को सम्बद्ध कर दिया जाय ताकि सर्वसाधारण को वज्रपात के सम्बंध में

8

पूर्व सूचना प्राप्त हो सके और जानमाल की कम–से–कम हानि हो, इसको सुनिश्चित किया जा सके।

वज्रपात से अबतक राज्य में 387 व्यक्तियों की मृत्यु कारित हुई है जिसके विरूद्ध सभी पीड़ितों के मध्य प्रति परिवार चार लाख की दर से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार 387 वज्रपात से पीड़ित परिवारों के मध्य रू0 1,548,00000 (पंद्रह करोड़ अड़तालिस लाख) का वितरण किया जा चुका है।

परिशिष्ट–4

बिहार विधान मंडल में दिनांक 03 अगस्त, 2020 को माननीय मंत्री, स्वास्थ्य द्वारा कोविड–19 Novel Corona Virus के संदर्भ में दिया गया वक्तव्यः–

1. कोविड–19 Novel Corona Virus एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है और भारत समेत दुनिया के 200 से अधिक देश इस से प्रभावित हैं। विश्व की सभी अग्रणी अर्थव्यवस्थाएँ इस संकट से जूझ रहीं हैं। विश्व में कोविड–19 का पहला मामला दिनांक–30.12.2019 को चीन के वुहान प्रांत से प्रतिवेदित हुआ था। भारत में सबसे पहले केरल राज्य में दिनांक 30.01.2020 को पहला मामला प्रकाश में आया।

2. बिहार सरकार प्रारम्भ से ही इस वैश्विक महामारी के संभावित प्रकोप को भांपते हुये प्रयत्न शील रही है एवं तदनुसार उपाय भी किये जा रहे हैं। बिहार में कोई भी मामला प्रतिवेदित माननीय मंत्री के भाषण का अंश 13 मार्च को ही सभी शैक्षिणिक संस्थान, सिनेमा हॉल, खेल–कूद के आयोजन, सभी सरकारी पार्क एवं सभी सांस्कृतिक महोत्सव को बंद करने का आदेश दिया गया। बिहार विधान मंडल के बजट सत्र को भी 16 मार्च, 2020 को ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। दिनांक–22 मार्च को देश में कोविड संक्रमण के मामलों को देखते हुये बिहार सरकार द्वारा सभी जिला मुख्यालय, सभी अनुमण्डल मुख्यालय, सभी प्रखण्ड मुख्यालय एवं नगर निकायों में लॉकडाउन का आदेश निर्गत किया गया।

3. भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत 25 मार्च 2020 को प्रथम लॉकडाउन लागू किया गया जिसे चार चरणों में 31 मई 2020 तक लागू किया गया। बिहार सरकार द्वारा भारत सरकार के लॉकडाउन से संबंधित आदेशों का सख्ती से

अनुपालन किया गया। भारत सरकार द्वारा कुछ कतिपय ढील के साथ 01 जून से 30 जून 2020 तक ऑनलॉक–1 का आदेश दिया गया जिसका बिहार सरकार द्वारा पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया गया। भारत सरकार ऑनलॉक–2 01 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2020 तक लागू किया गया परन्तु बिहार राज्य में संक्रमण को देखते हुये विभिन्न जिला पदाधिकारियों द्वारा 08 जुलाई से 15 जुलाई के बीच की अवधि में कतिपय शर्त्तों के साथ लॉक डाउन लागू किया गया एवं बिहार सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा लागू अनलॉक–2 के शर्त्तों को और कठोर करते हुये 16 से 31 जुलाई 2020 तक विशेष रूप से लॉक डाउन लागू किया गया। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा 1 अगस्त 2020 से लागू अनलॉक–3 के शर्त्तों को और कठोर करते हुये विशेष रूप से बिहार राज्य में आदेश निर्गत किया गया है।

4. बिहार राज्य में पहला कोविड–19 का मामला 22 मार्च 2020 को प्रतिवेदित हुआ। कोविड–19 के शुरूआती मामलों में प्रायः वही मामले थे, जिनका बाहर से यात्रा का इतिहास था। इस स्थिति को समझते हुये बिहार सरकार द्वारा सबसे पहले 15 मार्च 2020 के बाद विदेश से बिहार राज्य आये सभी व्यक्तियों का सत्यापन किया गया एवं ऐसे सभी व्यक्तियों की जाँच हेतु सैम्पल ली गई। जो व्यक्ति भी पॉजेटिव पाये गये उनकी गहन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की गई एवं सभी कॉन्टेक्ट की जाँच करायी गयी– मुगेंर (जमालपुर), पटना (खजपुरा), सीवान (पंजवार), बेगूसराय (कादिराबाद), नवादा (अंसारनगर)। इन सभी जगहों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सराकर द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में Containment Zone की स्थापना की गयी। इस प्रकार जो शुरूआती संक्रमण

के मामले आये उनका एक चेन बना जिसमें लगभग प्रत्येक चेन में संक्रमण का स्त्रोत बाहर से आया हुआ व्यक्ति ही था।

5. पूरे बिहार राज्य में कोविड–19 के लक्षण की खोज करने एवं लक्षण युक्त व्यक्तियों की जांच कराने हेतु घर–घर सर्वेक्षण का कार्य पल्स पोलियो अभियान के तर्ज पर कराया गया । उक्त सर्वेक्षण में मात्र लगभग 3849 लक्षणयुक्त पाये गये जिसमें जाँचोंपरांत 22 व्यक्ति संक्रमित पाये गये।

6. 3 मई, 2020 के बाद बिहार के निवासी जो अन्य प्रदेशों में रह रहे थे उनका आगमन विशेष ट्रेन एवं अन्य माध्यमों से प्रारम्भ हुआ। उस समय बिहार राज्य की तुलना में अन्य प्रदेशों में संक्रमण का दर ज्यादा था, जिसे ध्यान में रखते हुए बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए प्रखण्ड स्तर पर क्वारन्टीन सेन्टर की व्यवस्था की गई। प्रखण्ड क्वारन्टीन सेन्टर में कोविड–19 के सभी दिशा–निर्देशों का पालन करते हुये सभी सुविधायें मुहैया कराई गई। कुल **15036 क्वारन्टीन सेन्टरों में 15,20,000 से अधिक** व्यक्तियों के रहने की समुचित व्यवस्था की गयी यथा–Social Distancing को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक किचेन, शौचालय, योग प्रशिक्षण इत्यादि। यहाँ रह रहे व्यक्तियों का लक्षण के आधार पर एवं रैण्डम आधार पर कोविड–19 की जांच कराई गई। जांच के फलाफल के आधार पर इन्हें विभिन्न शहरों को श्रेणी–क एवं श्रेणी–ख में विभक्त किया गया ताकि इन शहरों से आने वाले व्यक्तियों के संबंध में विशेष सावधानी बरती जा सके एवं संक्रमण के श्रृंखला को तोड़ा जा सके। ये प्रखण्ड क्वरान्टाईन सेन्टर 21 जून 2020 तक क्रियाशील रहे इस अवधि में कुल 59832 बाहर से आये व्यक्तियों की जांच कराई गई एवं उनमें उनमें 5405 व्यक्ति कोविड–19 पॉजिटिव पाये गये।

अर्थात पॉजिटिविटी का प्रतिशत 9 रहा । जबकि इसी अवधि में पूर्व से बिहार राज्य में रह रहे 107582 व्यक्तियों की जांच कराई गई और इनमें 3580 व्यक्ति पॉजिटिव पाये गये अर्थात् पॉजिटिविटी का प्रतिशत 3.3 रहा । इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि बाहर से आये व्यक्तियों को प्रखण्ड क्वारन्टाईन सेन्टर में रखे जाने का निर्णय संक्रमण की रोकथाम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

7. अब तक बिहार में कुल 612415 सैम्पल की जांच की गई है। कुल 57270 संक्रमित वयक्तियों में से 36637 संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं इस प्रकार बिहार राज्य का रिकवरी प्रतिशत लगभग 64% है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर भी रिकवरी लगभग 64 प्रतिशत ही है। बिहार राज्य में अब तक कुल 322 व्यक्तियों की कोविड–19 संक्रमण से मृत्यु हुई है। इस प्रकार बिहार में कोविड–19 संक्रमित व्यक्तियों में मृत्यु का दर 0.57 प्रतिशत है जबकि उक्त का राष्ट्रीय प्रतिशत 2.15 है। कोविड–19 से संक्रमित मृत वयक्तियों में 199 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें कोविड–19 संक्रमण के अलावा विभिन्न प्रकार की अन्य गंभीर बीमारियाँ भी रहीं हैं। उक्त को ध्यान में रखते हुये बिहार सरकार द्वारा बृद्ध, बच्चे, गर्भवती महिलायें एवं अन्य बिमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु जागरूकता उत्पन्न करने के लिये विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं।

8. कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने की एक महत्वपूर्ण कड़ी कन्टेनमेन्ट जोन का गठन एवं उसमें सघन सर्वेक्षण एवं जांच आदि गतिविधियों का क्रियान्वयन है।

9. भारत सरकार के निदेश के आलोक में कोविड–19 के सम्पुष्ट मरीजों के ईलाज हेतु राज्य में त्रिस्तरीय चिकित्सा सुविधा केन्द्र स्थापित की गयी है। हल्के लक्षण वाले

पॉजिटिव मरीजों के इलाज हेतु कुल 290 कोविड केयर सेंटर (CCC) की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों में Beds की क्षमता 33437 है तथा वर्तमान में 18357 बेड सभी सुविधाओं सहित उपलब्ध है। इन केन्द्रों पर चिकित्सक, नर्स एवं पारा मेडिकल कर्मी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। इस केन्द्र में भर्ती मरीजों हेतु भोजन, पानी, दवाईयाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर, पल्स ऑक्सीमीटर इत्यादि की भी समुचित व्यवस्था की गयी है। भर्ती मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तथा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु प्रतिदिन प्रति मरीज भोजन का दर 100/– रूपये से बढ़ाकर 175/– रूपये तथा शुद्ध पेयजल हेतु प्रति दिन 50/– रूपये अतिरिक्त व्यय का प्रावधान किया गया है।

10. Moderate लक्षण वाले मरीजों हेतु 93 Dedicated Covid Health Centre (DCHC) की स्थापना की गयी है। DCHC में कुल 6304 Beds की क्षमता है तथा सभी सुविधाओं के साथ 4688 Beds वर्त्तमान में कोरोना मरीजों की चिकित्सका हेतु उपलब्ध है। इन केन्द्रों पर सभी Beds के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर अथवा गैस पाईप के माध्यम से मेडिकल ऑक्सीजन देने की व्यवस्था की जा रही है। सभी अनुमंडल स्तर पर अनुमंडलीय अस्पताल के अतिरिक्त ऑक्सीजन युक्त 100 Beds वाले Dedicated Covid Health Center की स्थापना की जा रही है। प्रत्येक जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों के सघन ईलाज हेतु Ventilator युक्त 4 ICU bed स्थापित किया जा रहा है।

11. गंभीर रूप से बीमार मरीजों हेतु 10 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में Dedicated Covid Hospital (DCH) की व्यवस्था की गयी है। जिसमें 3850 Beds की क्षमता है तथा 2840 Beds वर्त्तमान में उपलब्ध है। इन Dedicated Covid Hospitals में

मरीजों के ईलाज हेतु कुल **270 ICU Bed** तथा **383** Ventilators उपलब्ध है। अतिरिक्त ICU Bed तथा Ventilator की उपलब्धता हेतु कार्रवाई की जा रही है, ताकि आपात स्थिति में गंभीर रूप से बीमार मरीजों को गहन चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायी जा सके।

12. राज्य सरकार द्वारा कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर कोरोना संक्रमित मरीजों के ईलाज की अनुमति दी गयी है। अद्यतन **153** निजी अस्पतालों में **3237** बेडों की व्यवस्था की गयी है। राज्य में स्थापित **6** निजी चिकित्सा महाविद्यालय को Isolation Centre के रूप में चिन्हित कर कुल **720** Beds को कोरोना के मरीजों के ईलाज हेतु आरक्षित किया गया है। निजी अस्पतालों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में मरीजों के नामांकन तथा सुगम इलाज हेतु प्रशासनिक पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

13. COVID Positive पाये गये ऐसे मरीज जिनमें किसी प्रकार का कोई रोगात्मक लक्षण नहीं (अलक्षणात्मक) है, उन्हें Home Isolation में रहने की सलाह दी जा रही है। Home Isolation में रह रहे मरीजों के स्वास्थ्य का निरंतर अनुश्रवण आशा एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से कराया जा रहा है। Home Isolation के दौरान उन्हें आवश्यक दवाओं, दो मास्क, चिकित्सकीय सलाह पर्ची आदि का एक किट दिया जा रहा है तथा दूरभाष के माध्यम से उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त कर टेलिमेडिसीन की सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है। सभी जिलों में ऐसे मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श एवं सहायता उपलब्ध कराने हेतु टॉल फ्री नम्बर के साथ मेडिकल हेल्प लाईन की भी स्थापना की गयी है। मेडिकल हेल्प लाईन में **102** नम्बर वाले एम्बुलेंस के अतिरिक्त निजी एम्बुलेंस को भाड़े पर रखकर गर्भवती महिला एवं गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को चिकित्सकीय

सुविधा हेतु अस्पताल पहुँचाने, जाँच हेतु निर्धारित जाँच केन्द्र पर पहुँचाने तथा कोरोना जाँच में पॉजिटिव पाये जाने पर लक्षण के आधार पर Isolatioan Center पर पहुँचाने की व्यवस्था की गयी है।

14. इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर चिकित्सकीय परामर्श तथा शिकायत निवारण हेतु टॉल फ्री नंम्बर **104** संचालित है। कोरोना संक्रमण अवधि में Calls की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुये **20 Call** ऑपरेटर वाले सेंटर में **30** अतिरिक्त यानि कुल **50** कॉल ऑपरेटर की व्यवस्था की गयी है। 104 कॉल सेंटर में मार्च 2020 से जुलाई 2020 तक **15 लाख** से अधिक कॉल प्राप्त हुये हैं। इनमें से **एक लाख बत्तीस हजार** कोरोना से संबंधित कॉल प्राप्त हुये तथा लगभग **24 हजार** लोगों को चिकित्सकीय परामर्श दिया गया है। राज्य स्तर से Institutional Isolation तथा Home Isolation में रहने वाले कोरोना पीड़ित मरीजों को उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं का निरंतर पर्यवेक्षण किया जा रहा है तथा सुधारात्मक कार्रवाई भी की जा रही है।

15. कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु राज्य के सभी जिलों में मरीजों एवं स्वास्थ्य कर्मियों हेतु PPE Kit, 3 Ply Mask, N95 mask, Sanitizer आदि प्रतिरक्षक समागियों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है। चिकित्सकों एवं front line worker सहित स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना संक्रमित होने पर उन्हें सरकार द्वारा Paid Isolation की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल को बनाये रखने हेतु सरकार द्वारा एक महीने के समतुल्य वेतन प्रोत्साहन राशि के रूप में तथा

कर्त्तव्य के दौरान कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने की स्थिति में **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत पचास लाख रूपये का इंश्योरेन्स का भी प्रावधान किया गया है।**

16. कोरोना से पीड़ित मरीजो के ईलाज में ऑक्सीजन थेरेपी एक महत्वपूर्ण अवयव है। ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढाने हेतु सरकार द्वारा सभी अनुमंडलीय अस्पताल तथा जिला अस्पताल एवं विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में कुल **3631** Beds को **मेडिकल गैस पाईप लाईन** से जोडने तथा सभी **9 मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन जेनेरेशन प्लांट** निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। राज्य में पूर्व में जिला स्तर पर **5389 ऑक्सीजन सिलेंडर** ही उपलब्ध थे, सरकार द्वारा इसकी आवश्यकता को देखते हुए **10921** अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गयी है। इसी प्रकार अब राज्य में **16310** (बी0 टाईप ऑक्सीजन सिलेंडर **9484** एवं डी0 टाईप सिलेंडर **6826**) ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है। पूर्व में जहाँ राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं जिला अस्पताल में कुल **341 Ventilators** उपलब्ध थे वर्त्तमान में उसे बढ़ाकर **861** की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है। इन सभी **Ventilators** को आवश्यकता अनुसार कोरोना से पीड़ित मरीजों को उपचार हेतु उपयोग में लाया जा रहा है।

17. ऑक्सीजन की वैक्लपिक व्यवस्था हेतु लगभग **6500 ऑक्सीजन कन्सट्रेटर** की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। ऑक्सीजन कन्सट्रेटर के माध्यम से अतिरिक्त **6500 ऑक्सीजन** युक्त बेड मरीजों को उपलब्ध हो पायेगा।

18. Covid मरीजों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से Essential Drug List (EDL) को पुनरीक्षित कर कुल **36 अतिरिक्त दवाओं को EDL में सम्मिलित किया गया**

है तथा इसकी उपलब्धता सभी स्तरों पर सुनिश्चित की जा रही है। इसी प्रकार कोविड के चिकित्सकीय प्रबंधन हेतु 36 प्रकार के आवश्यक उपकरणों एवं 20 प्रकार के Consumables को Essential equipment List के रूप में चिन्हित करते हुए इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है।

19. संदिग्ध मरीजों को कोविड की जाँच के परिणाम की जानकारी SMS के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है तथा जिला स्तर पर कॉल सेंटर के माध्यम से उन्हें सूचित भी किया जा रहा है। साथ ही जाँच को सुगम बनाने तथा अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी देने हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा **संजीवन मोबाईल ऐप विकसित किया गया है।** मोबाईल ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जाँच हेतु पंजीकृत हो सकते हैं तथा निकटतम जाँच केन्द्र पर जाकर कोरोना की जाँच न्यूनतम समय में करा सकते हैं। साथ ही मोबाईल ऐप के माध्यम से निकटतम Covid Care Center तथा Dedicated Covid Care Health Centre में उपलब्ध Beds के बारे में भी जानकारी दी जा रही है।

20. कोरोना के परिप्रेक्ष्य में पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता हेतु सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों स्तर पर पूर्व से उपलब्ध मानव संसाधन के अतिरिक्त एक–एक चिकित्सक, लैब टेकनिशियन एवं पारा मेडिकल कर्मी को नियोजित कर माह अक्टूबर, 2020 तक रखने का प्रावधान किया गया है। चिकित्सा हेतु आवश्यक मानव बल की संख्या में भी वृद्धि के प्रयास किये गये हैं। राज्य में **929 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है** तथा राज्य के सभी जिलों में एपिडेमियोलॉजिस्ट की भी नियुक्ति का कार्य सम्पन्न किया गया है। राज्य में उपलब्ध मानव संसाधन का कोविड–19 की चिकित्सा के संबंध में

कई चरणों में एम्स, नई दिल्ली, एन0सी0डी0सी0, नई दिल्ली आदि के माध्यम से प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया है।

21. कोविड–19 के रोकथाम के प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रथम चरण कोविड–19 की जॉच है, इस हेतु राज्य में 7 मार्च 2020 के पहले कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी और सैम्पल को जाँच हेतु NIV, पुणे भेजना पड़ता था। राज्य में 7 मार्च को आर0एम0आर0आई0, पटना में कोविड–19 की जॉच प्रारम्भ हुई और चरणवार वर्तमान में राज्य के सभी जिलों एवं मेडिकल कॉलेजों में कोविड–19 की जाँच की सुविधा उपलब्ध है। राज्य में वर्तमान में कोविड–19 की जाँच हेतु उपलब्ध सभी माध्यमों यथा– RT-PCR, True Nat, Rapid Antigen Kit आदि के माध्यम से जाँच कार्य सम्पन्न किया जा रहा है और वर्तमान में इसे राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी मांग के आधार पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में राज्य में 8 केन्द्रों– RMRI Patna, IGIMS Patna, AIIMS Patna, PMCH Patna, SKMCH Muzaffarpur, ANMCH Gaya, DMCH Darbhanga, JLNMCH Bhagalpur में RT-PCR मशीन के माध्यम से, एक केन्द्र– RMRI Patna में COBAS मशीन के माध्यम से जाँच के अलावा सभी **38 जिलों में 42 केन्द्रों पर 105 True Nat** मशीनों के माध्यम से जाँच कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है। राज्य में कोविड–19 की जाँच हेतु निजी क्षेत्रों का सहयोग भी लिया गया है और 6 निजी चिकित्सा संस्थानों/प्रयोगशालाओं– नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, सासाराम, सरल पाथ लैब पटना, सेन डायगनोस्टिक पटना, पाथ काइंड लैब पटना, लाल पैथ लैब पटना एवं इंदिरा डायगनोस्टिक पटना द्वारा भी कोविड–19 जाँच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कोविड–19 के इलाज में संलग्न निजी चिकित्सा संस्थानों को भी राज्य सरकार द्वारा

Rapid Antigen Kit के माध्यम से जाँच की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही निजी क्षेत्र में RTPCR जाँच हेतु 2500 रूपये मोबाईल वैन रहित एवं 2800 रूपये मोबाईल वैन सहित तथा Rapid Antigen Kit से जाँच हेतु अधिकतम 700 रू0 का दर निर्धारित किया गया है।

22. सरकार के प्रयासों का यह प्रतिफल है कि जहाँ राज्य में कोविड–19 की पहली जाँच 7 मार्च को शुरू हुई थी वहीं 31 जुलाई तक यह आँकड़ा 35 हजार से ऊपर पहुँच चुका है। कोविड–19 के सभी कन्टेन्मेन्ट जोन में सघन रूप से सर्वे कराते हुये संदिग्ध मरीजों की अनवरत पहचान की जा रही है। लॉक डाउन अवधि के दौरान एवं बाद में राज्य में प्रवेश किये व्यक्तियों हेतु चिन्हित क्वारनटाईन केन्द्रों में भी जाँच की व्यवस्था की गई थी। सरकार द्वारा जाँच की सुविधा को हर जन तक सुगम करने के लिये आई0सी0एम0आर0 एवं भारत सरकार के जाँच हेतु समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों से बढ़ कर भी सरकार द्वारा लगातार हाउस टू हाउस सर्वे के माध्यम से भी कोविड के संदिग्ध मरीजों की पहचान करते हुये इनका जाँच कराया गया है। इसमें खास तौर पर वृद्ध जनों, महिलाओं एवं बीमार व्यक्तियों की जांच पर भी ध्यान दिया गया है। वर्तमान में कई जिले बाढ़ प्रभावित हैं जिसमें आपदा राहत केन्द्रों में भी आवासित व्यक्तियों/सामुदायिक रसोई से संबंधित सभी व्यक्तियों की सघन जाँच कराई जा रही है। ऐसा करने से संक्रमण पर प्रभावी रोक लगाने में काफी सहुलियत हो रही है। यह पुनः स्पष्ट किया जा रहा है कि जाँच हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। सरकार की स्पष्ट मंशा है कि जिन व्यक्तियों को भी यह महसूस होता है कि उन्हें कोविड की जाँच करानी है उनके लिये जाँच की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है।

23. विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार प्रति एक लाख व्यक्ति पर 14 जाँच प्रतिदिन किये जाने का मानक है। वर्तमान में बिहार सरकार इस मानक से काफी आगे बढ़कर मानक से दो गुने से अधिक जाँच कर रही है जिसे और अधिक बढ़ाये जाने का निदेश दिया गया है।

24. कोरोना के संक्रमण से बचाव एवं जाँच की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु सरकार द्वारा लगातार विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षक सामग्रियों एवं जाँच किट आदि उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी क्रम में:–

कोविड संक्रमण से बचाव हेतु प्रतिरक्षक सामग्री के रूप में **PPE Kit** की 6,84,693 अदद् की आपूर्ति प्राप्त की गयी है, जिसमें से 4,52,146 **PPE Kit** जिलों तथा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

3-Ply Surgical Mask की 40,87,000 अदद् की आपूर्ति प्राप्त की गयी है, जिसमें से 39,89,095 **3-Ply Surgical Mask** जिलों तथा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

N-95 Mask की 11,18,466 अदद् की आपूर्ति प्राप्त की गयी है, जिसमें से 5,15,849 **N-95 Mask** जिलों तथा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

राज्य में RTPCR जाँच हेतु 6,37,370 अदद् **VTM** की आपूर्ति प्राप्त की गयी है, जिसमें से अभी तक 4,97,975 **VTM** जिलों तथा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

Rapid Antigen जाँच हेतु 4,47,750 अदद् **Testing Kit** की आपूर्ति प्राप्त की गयी है, जिसमें से अभी तक 4,27,100 **Kits** जिलों तथा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में 10452 **Pulse Oximeter** उपलब्ध कराया गया है।

25. <u>एम्बुलेंस एवं शववाहन</u>

राज्य में 102 एम्बुलेंस सेवा अतर्गत पूर्व से परिचालित एम्बुलेंस के Fleet में **90 नये एम्बुलेंस** शामिल किया गया है तथा निजी एम्बुलेंस भी आवश्यकता अनुसार भाड़े पर रखने का प्रावधान किया गया है।

राज्य में **49 शव वाहन** उपलब्ध है। कोविड के परिप्रेक्ष्य में पटना में अतिरिक्त **10 शव वाहन** उपलब्ध कराये गये हैं। वर्त्तमान में पटना जिला में विभिन्न मेडिकल कॉलेज हेतु कुल **14 शववाहन** का परिचालन किया जा रहा है। साथ ही, सभी जिलें एवं मेडिकल कॉलेज हेतु कुल **39 नये अतिरिक्त शववाहन** के क्रय की स्वीकृति दी गयी है।

26. <u>वैक्सीन का ट्रायल</u>

पूरेदेश में कोविड वैक्सीन के ट्रायल के लिये **ICMR द्वारा 12 सेन्टर** का चयन किया गया है, जिसमें AIIMS, Patna भी एक सेन्टर है। AIIMS, Patna में 08.07.2020 को वैक्सीन ट्रायल का प्रथम चरण शुरु हुआ था। वैक्सीन ट्रायल का दूसरा चरण दिनांक 30.07.2020 से AIIMS, Patna में चल रहा है। 50 से 100 Volunteers का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 30 Volunteers को पहला खुराक दिया जा चुका है, जिसमें कोई भी Side effect नही पाया गया है। 14 दिन के बाद 02 Volunteers को दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है।

27. <u>Plasma Therapy</u>

ICMR द्वारा देश के चुनिंदा स्वास्थ्य संस्थानों में Plasma Therapy के माध्यम से मरीजों के ईलाज हेतु प्राधिंकृत किया गया है। बिहार राज्य में AIIMS, Patna भी इसमें शामिल है। अभी तक कोरोना से ठीक हुये **100 लोगों द्वारा Plasma Donate किया गया है तथा 90 मरीजों को Plasma Therapy से ईलाज किया गया है।** Plasma Donate करने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है।

Supplies from Central Government Till Today			
Sl. No.	Product	Items	Supplied by Govt. of India
1	PPE KIT	Cover All	**430226**
		Goggles	**448800**
		Gloves	**167500**
		N95	**610000**
2	N95		**242651**
3	VTM		**151720**
4	3 PLY MASK		**200000**
5	RNA Extraction Kit		**6912**
6	Oxygen Concentrator		**750**
7	Antigen Kit		**20000**
8	Ventilator		**514**